टीकमगढ़ जनपद (म० प्र०) के सेवाकेन्द्रों का भौगोलिक विश्लेषण

A GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF SERVICE CENTRES IN TIKAMGARH DISTRICT OF MADHYA PRADESH

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

भूगोल विषय में

पी-एच. डी. उपाधि हेतु

प्रस्तुत

शोध प्रबंध

निर्देशक

डॉ० आर. एस. त्रिपाठी

रीडर, भूगोल विभाग

अतर्रा परास्नातक महाविद्यालय, अतर्रा

बाँदा (उ० प्र०)

द्वारा

शिव कुमार तिवारी

शोध छात्र, भूगोल विभाग

अतर्रा परास्नातक महाविद्यालय अतर्रा

बाँदा (उ० प्र०)

1996

Dr. R.S. Tripathi,
Reader, Dept. of Geography,
Atarra P.G. College, Atarra,
Banda (U.P.)

Naraini Road,
Atarra -210201,
Banda, (U.P.)

CERTIFICATE

This is to certify that ***Shri Shiv Kumar Tiwari*** *has completed the* ***Ph.D. Thesis*** *on the topic* ***" A Geographical Analysis of Service Centres in Tikamgarh District of Madhya Pradesh "*** *under my supervision. The thesis is submitted for the* ***Ph.D. Degree*** *in* ***Geography*** *to* ***Bundelkhand University, Jhansi.*** *The thesis presented by Shri Tiwari is an original piece of work.*

According to the rules of the University, Shri Tiwari has worked under my supervision for more than two hundred days.

R.S. Tripathi

11th November, 1996

(R.S. Tripathi)

प्राक्कथन
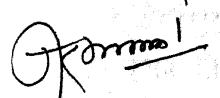
विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में सेवाकेन्द्र, या बाजार स्थानीय सामजिक परिवेश को आवश्यक आवश्यकतओं की प्रतिपूर्ति करने में सतत योगदान देते हैं। यही कारण है कि सभी सेवाकेन्द्र व्यापारिक क्रियाकलापों को सम्पादित करने के लिये क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक विश्लेषण के साथ सेवाओं के वंशानुगत केन्द्र या अंग बन गये है। यद्यपि नगर अपने अन्दर प्राप्त नगरीय कार्यो के कारण सेवाकेन्द्र कहे जाते हैं किन्तु ग्रामीण सेवाओं की प्रतिपूर्ति नगरीय वातावरण के अभाव के उपरान्त भी ग्रामीण सेवाकेन्द्रों को इनसे अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक बृहत भू-भाग पर छोटी-छोटी स्थानिक सेवा इकाई का आधार, विनमय एवं माँग की पूर्ति नगरीय क्षेत्रों की भाँति इनमें निहित होती हैं। यद्यपि इन सेवाकेन्द्रों में कृषि या उससे सम्बन्धित सेवाओं का विनमय ही महत्वपूर्ण होता हैं। और धीरे-धीरे यातायात की सेवाओं एवं अन्य सहायक सेवाओं के इन केन्द्रों के विकसित हो जाने से ये ग्रामीण सेवा स्थल पूर्ण विकसित सेवाकेन्द्र का स्वरुप धारण करते हैं।

सेवाकेन्द्रों के विकास में सर्वाधिक प्रेरक तत्व उस सेवाकेन्द्र का कार्यात्मक आधार उत्तरदायी होता है। नगर या ग्राम के आवासी अपने लिये भोजन, वस्त्र, निर्माण सामग्री एवं उद्यम से संलग्न वस्तुओं को अपने ही केन्द्र से प्राप्त करते हैं। " **च्वाइस** " का आधार प्रति सेवाकेन्द्र अलग अलग व्यक्तियों और केन्द्रों के रुप में भिन्न-भिन्न होता है। इस हेतु उनका अर्थिक तंत्र महत्वपूर्ण एवं उपयोगी भूमिका का निर्वाह करता है। तकनीकि विकास के कारण मानव समाज में सेवाकेन्द्रों की वस्तु विनमय एवं क्रियात्मकता में प्रभावशाली परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। यही कारण है कि सेवाकेन्द्रों की क्रियात्मक विशेषता, गुण, प्रकार एवं क्रियाओं की गहनता अपना सतत स्वरुप बदलती रहती है। समान सेवाकेन्द्रों में भी क्रियात्मक अन्तर उनकी विविधताओं के परिणाम स्वरुप दिखाई देता है। मानवीय समाज में आवास हेतु विभिन्न क्रियात्मक इकाईयों द्वारा स्थानिक वितरण प्रतिरुप एवं क्षेत्रीय कार्यात्मक

संगठन विकसित होते हैं और क्रियात्मक इकाइयों का अभिज्ञान उनके पदानुक्रम स्तर द्वारा लगाया जाता है। क्षेत्रीय क्रियात्मक संगठन की प्राथमिक इकाइयाँ आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सेवा स्थलों में विभाजित होती हैं।

सेवाकेन्द्रों के विकास हेतु सूक्ष्मस्तर पर नियोजित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थानिक प्राकृतिक एवं केन्द्रीय स्थिति के साथ विशिष्ट सांस्कृतिक क्रियाकलापों को सेवास्तर की अधिकतम सीमा द्वारा सीमांकित कर प्रस्तुत अध्ययन को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जिला टीकमगढ़ पठारी उच्चभूमि पर स्थित होने के कारण औद्योगिक एवं आधारभूत संरचनात्मक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ा हआ है। प्रति व्यक्ति आय की कमी (जो 90 प्रतिशत से अधिक कृषि तथा उससे संलग्न कार्यक्रमों पर ही केन्द्रित है), खनिज संसाधनों की कमी, राजनैतिक चेतना का अभाव ओर योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन न होने के कारण क्षेत्रीय विकास की समुचित गति आज भी प्राप्त नहीं कर सकी है। यही कारण है कि सेवाकेन्द्रों की क्रियाशीलता कृषि उत्पाद के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये पूर्णतया अन्य प्रदेशों पर निर्भर करती हैं।

मैं मानता हूँ कि सेवाकेन्द्रों का समुचित सीमांकन विविध आंकड़ों के अभाव के कारण एक कठिन कार्य है। किन्तु उपलब्ध सेवाओं और समंकों की वर्तमान स्थिति के अनुसार मेरा यह शोध प्रबंध जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में सेवाकेन्द्रों का एक भौगोलिक विश्लेषण आपकी ओर सविनय प्रस्तुत हैं।

(शिव कुमार तिवारी)

प्रस्तुत शोध प्रबंध मेरे गुरुवर **डॉ. आर.एस. त्रिपाठी, रीडर, भूगोल विभाग, अतर्रा परा स्नातक महाविद्यालय, अतर्रा, बाँदा (उ.प्र.)** के कुशल मार्गदर्शन एवं सतत प्रदत्त प्रेरणाओं का प्रतिफल है। मैं उनके उत्साह-वर्धन व कुशल निर्देशन के लिये आजीवन ऋणी रहूँगा।

मैं अपन अग्रज **डॉ. आर.पी. तिवारी, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़ म.प्र.** का भी ऋणी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मेरी शोध संम्बधी कठिनाईयों के निवारण में अमूल्य योगदान दिया।

मैं **प्राचार्य, अतर्रा परा स्नातक महाविद्यालय, अतर्रा, बाँदा का** आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने महाविद्यालय में शोध संबंधी सभी सुविधायें प्रदान कीं। मैं महाविद्यालय के भूगोल विभाग के सभी शिक्षकों का भी आभारी हूँ जिनका सहयोग मुझे सदैव प्राप्त होता रहा है।

मैं भूगोल विषय के उन सभी पंडितों का आभारी हूँ जिनके शोध अध्ययनों से मुझे इस शोध कार्य को पूरा करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा हैं।
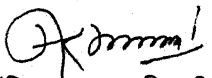
मैं जिला टीकमगढ़ के कार्यालयों के विभाग प्रमुखों को भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने शोध के लिये आवश्यक आकड़े व सूचनायें प्रदान कर मुझे सहयोग प्रदान किया।

मैं अपने सभी परिवारी जनों एवं मित्रों का आभारी हूँ जो मुझे शोध कार्य पूरा करने के लिये सदैव प्रेरित करते रहे।

अंत में मैं ओमना अलैक्ट्रॉनिक टाइपिंग, टीकमगढ़ के संस्थापक को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निर्धारित अवधि में उत्कृष्ट रुप से शोध प्रबंध टंकित किया।

10 नवम्बर, 1996,

दीपावली.

(शिव कुमार तिवारी)

शोध छात्र, भूगोल विभाग,

अतर्रा परा स्नातक महाविद्यालय,

अतर्रा, बाँदा (उ.प्र.)

-: अनुक्रमणिका :-

सारणी सूची

LIST OF ILLUSTRATIONS

अध्याय एक

विषय वस्तु का सामान्य परिचय ।

- सेवा केन्द्रों की संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि
- सेवा केन्द्रों के विकास के भौगोलिक तथ्य
- शोध डिजाइन
- उद्देश्य
- शोध प्राविधि
- साहित्य का पुनरावलोकन
- सन्दर्भ ग्रान्थों की सूची

विकास शील अर्थव्यवस्था में आवासित जन समूह को बेहतर जीवन स्तर विकसित किये बगैर ग्रामीण एवं नगरीय प्रदेशों को उन्नत नहीं कहा जा सकता।[1] क्योंकि सकल राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कृषि आर्थिकी द्वारा विकासशील अर्थ व्यवस्था को प्राप्त होता है।[2] यह कटु सत्य है कि ऐसे अर्थतंत्र में आर्थिक दृष्टि से विपन्न जनसंख्या का 70% से अधिक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाया जाता है। यही कारण है कि स्थानीय जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार तथा विकास प्रक्रिया को सक्रिय बनाये रखने हेतु क्षेत्रीय कार्यों का विश्लेषण और सेवा केन्द्रों को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित विविध कार्यक्रमों और तत्सम्बधित प्रयासों में अनेक समस्यायें स्वाभाविक रुप से उत्पन्न हुई हैं। समन्वय के अभाव में विकास प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विषमतायें अपेक्षाकृत अधिक प्रखर हुई हैं।[3] अस्तु क्षेत्रीय कार्यों के विश्लेषण की संकल्पना में न केवल कृषि उत्पादकता में अभिवृद्धि तथा नगरीयकरण ही है अपितु क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से है।[4] सेवाकेन्द्रों का विश्लेषण इसलिये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विद्यमान दोषपूर्ण आर्थिकि नीति और अनावश्यक अनियोजित राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण केन्द्रीय स्थानों में कृषियेत्तर क्रिया कलापों में अभिवृद्धि न होकर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के मध्य विकास के अन्तर को और अधिक बढ़ा दिया है।[5]

विकासशील अर्थव्यवस्था में ग्रामीण बाजार और कस्बे सेवाकेन्द्रों का कार्य करते हैं। तथा व्यापारिक क्रियाओं को सम्पादित करने हेतु स्थानिक, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक कार्यों के विश्लेषण में सेवा केन्द्रों के बंशानुगत अंग बन गये हैं। अस्तु इन्हें आवरती केन्द्र स्थल भी कहा जाता है।[6] सामान्यतः नगरों का सेवा केन्द्रों के रुप में अध्ययन आज नगरीय भूगोल का महत्वपूर्ण अंग होता है जो नगरों के निर्माण, अस्तित्व, समीपवर्ती क्षेत्र की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वस्तुओं के विनिमय केन्द्र के रुप में कार्य करने के लिये होता है।[7]

सेवाकेन्द्र - आशय :

आन्तरिक जनसंख्या की आवश्यक आवश्यकताओं की प्रति पूर्ति ग्रामीण बाजार, कस्बे, शहर तथा नगर अपने चारों ओर स्थित क्षेत्रों को अपनी सेवायें प्रदान करते तथा प्राप्त करते है। अर्थात जब कोई स्थान या केन्द्र अपनी आधारभूत और प्राथमिक सुविधायें अपने समीपवर्ती क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक कार्यों की पूत्रि के लिये करते हैं उन्हें केन्द्रीय स्थल कहा जाता है।[8] आस पास के सभी क्षेत्र अपनी किसी न किसी आवश्यकता के लिये अथवा सेवा प्राप्ति के लिये इन केन्द्रों पर पूर्णतया या आंशिक रुप से निर्भर करते हैं। अतः इन केन्द्रीय स्थानों को सेवा केन्द्र (Service Centre) की संज्ञा दी जाती है। नगरों द्वारा सेवित केन्द्रीय/क्षेत्रीय कार्यों को नगर के आधारभूत कार्य या प्राथमिक कार्य कहा जाता है। इसी लिये नगरों का जन्म एवं विकास होता है। प्रायः एक प्रदेश के सभी नगर अपने निकटवर्ती क्षेत्रों के केन्द्र में स्थित होने के नाते " सेवा केन्द्र स्थल " होते है। और केन्द्रीय संसाधनों एवं इकाइयों द्वारा सेवायें प्रदान करते और प्राप्त करते हैं। अतः

" ऐसी स्थाई मानव बस्तियों जो सामाजिक और आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं और आवश्यकताओं का विनिमय प्राथमिक या आधारभूत संसाधनों के रुप में अस्थानीय या अकेन्द्रीय जनसंख्या के लिये करती है। और अप्रत्यक्ष रुप से चारों ओर के समीपवर्ती क्षेत्रों/भू-भागों/ बस्तियों पर जिनका अपने प्रदेश के रुप में अधिकार तथा नियंत्रण होता हे " सेवाकेन्द्र " कहलाते है।[9]

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि केवल नगर ही नहीं अपितु ग्रामीण बस्तियाँ भी सेवा केन्द्र के रुप में कार्य करती है। ये सेवा केन्द्र बहुधा अपने अपने क्षेत्र में लगभग मध्य/या केन्द्र में स्थित होते हैं। किन्तु यह केन्द्रीय अवस्था होना अनिवार्य नहीं हैं।[10] यद्यपि सभी नगर या नगरीय बस्तियाँ केन्द्रीय स्थिति के कारण सेवा केन्द्र होते हैं किन्तु उत्खनन कार्य वाले नगर, सैनिक छावनियाँ, रेल वस्तियाँ विनिमय-केन्द्र न होने के कारण 'सेवा

केन्द्र' नहीं कहलाते। सेवा केन्द्रों के रुप में नगरों और ग्रामीण बस्तियों को अलग करना यद्यपि संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में जब गाँवों में भी नगरीय सुविधाओं की तरह पक्के मकान, सड़कें, शिक्षाकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समाचार पत्र, रेडियो, मोटरकार, विद्युत व्यवस्था आदि उपलब्ध हो रही हैं। बाजारों की सुविधा भी ग्रामीण क्षेत्रों में विगत समय में बढ़ी है। किन्तु इन्हें व्यवसाय, जनसंख्या की सघनता और भूमि उपयोग के आधार पर दोनों में विभाजन किया जा सकता है। नगरों को ऐसे मानव आवास के स्थाई एवं सघन समूह के रुप में जहाँ प्राथमिक मानवीय आवश्यकतायें, व्यवस्थायें, व्यवसाय एवं निर्माण कार्यों की प्रधानता होती है। ग्रामीण सेवाकेन्द्रों में इस प्रकार की व्यवस्था या सुविधायें न्यून होती है या इनका अभाव भी हो सकता है।[11]

(क) सेवा केन्द्रों की संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि :

एक बृहत क्षेत्र या प्रदेश छोटी-छोटी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। इन इकाइयों की मूल-भूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके अलग-अलग विनिमय केन्द्र होते हैं। समस्त लघु एवं बृहत केन्द्र सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रकीर्णित रहते हैं। और प्रत्येक केन्द्र का अपना सेवित क्षेत्र होता है। इनकी आर्थिक राजधानी इन्हीं केन्द्रों पर होती है।[12] ये सभी छोटे बड़े केन्द्र तथा क्षेत्र (सेवा) उनके छोटे बड़े सेवाकेन्द्रों या सेवा क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित होते हैं। क्योंकि क्षेत्र तथा कार्य आपस में एक दूसरे से आबद्ध होकर सम्बन्धित होते हैं। जिससे एक बृहत क्षेत्रीय सम्बद्धता या इकाई निर्मित होती है। प्रदेश का बृहत्तम नगर प्रादेशिक राजधानी होता है जिसे प्राथमिक नगर की संज्ञा दी जाती है।[13]

कृषि उत्पादन तथा अन्य प्राथमिक व्यवसाय मानव जीवन निर्वाह के लिये अत्यंत आवश्यक होते हैं। यही कारण है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेवा केन्द्र किसी न किसी ग्रामीण सेवा केन्द्र से प्राथमिक उत्पादकों का विनिमय करने को वाध्य होते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य में लगे मनुष्य ऐसी वस्तुओं के लिये बृहत्त सेवा केन्द्रों (जैसे

कस्बा, नगर तथा महानगरों) पर निर्भर करते हैं या इन वस्तुओं का विनिमय करते हैं जिनका उत्पादन वे स्वयं नहीं कर पाते तथा वो उनके लिये आवश्यक भी होते हैं। इसी आदान प्रदान की प्रवृत्ति के कारण ग्रामीण सेवा क्षेत्र नगरीय सेवाओं द्वारा अनयोन्ये आश्रित होते है।[14] नगरों का उद्‌भव और विकास विनिमय केन्द्रों के रुप इसी प्रवृत्ति के आधार पर होता है। इसी आधार पर धीरे धीरे यातायात सेवाओं और उनके सहायक तत्वों के विकसित हो जाने से स्थान या केन्द्र पूर्व विकसित सेवा केन्द्रों में बदल जाते हैं। तथा आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य उद्‌देश्य के लिये विकसित क्षेत्र-स्थान या नगर स्थानीय, क्षेत्रीय या नगर की केन्द्रीय राजधानी में बदल जाते हैं।[15] यहाँ तक कि खानों की बस्तियाँ, रेल्वे जंक्शन, शैक्षिक केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र, सैनिक आवास, हवाई अड्डों के निकट की वस्तियाँ और बन्दरगाह भी किसी न किसी सेवाओं से जुडकर केन्द्रीय कार्य में लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण या अर्धनगरीय बस्तियाँ भी केन्द्रीय कार्यों का सम्पादन कर सेवाकेन्द्र का रुप धारण कर लेती है जैसे ग्रामीण या कस्बाई बाजार आदि।[16]

(ख) सेवा केन्द्रों के विकास के भौगोलिक तथ्य :

सेवा केन्द्रों विकास से हमारा तात्पर्य उनकी उत्पत्ति अथवा आधार स्थापना, विकास, वृद्धि/विस्तार समृद्धि और ह्रास की भौगोलिक या क्रमबद्ध अवस्थाओं से होता है। इन सेवाकेन्द्रों को पूर्ण इकाई के रुप में तथा आन्तरिक प्रारुप के भौगोलिक तथ्यों एवं विशेषताओं के सन्दर्भ में स्वतंत्र एवं तुलनात्मक दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाता है।[17] प्रत्येक पूर्ण विकसित केन्द्र या बृहत नगर एक छोटी बस्ती या स्थान के रुप में प्रारम्भ होता है। जिसका विकास और अस्तित्व विभिन्न जटिल भौतिक एवं मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। किसी सेवाकेन्द्र के एक बार विकसित होने पर बहुत से राजनैतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सामाजिक तथ्य उस सेवा केन्द्र के विकास को निर्धारित करने हेतु उस पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। फलतः सेवा केन्द्र विभिन्न भौगोलिक अवस्थाओं से गुजर कर विकास की ओर या ह्रास की ओर अग्रसर होता है। भौतिक कारक एक सेवा केन्द्र के विकास के प्रारम्भिक

आधार को प्रदान करता है। धरातलीय बनावट, मिट्टियाँ, जल की उपलब्धता, अनुकूलतम जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन इन भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त सीमाओं एवं सुविधाओं पर सांस्कृतिक और मानवीय तथ्य अपनी प्रतिक्रिया करना प्रारम्भ करते हैं। प्रशासकीय व्यवस्था, यातायात मार्ग; आर्थिक विकास का स्वरुप और अवस्था जैसे मानवीय कारक परस्पर समन्वित ढंग से कभी पूर्वगामी तथा कभी अनुगामी होकर क्रियायें करते हैं। उन सेवाकेन्द्रों पर दो तरह की मानव शक्तियाँ प्रभावी होती है। प्रशासकीय मुख्यालय, सुरक्षाकेन्द्र, किला, महल, क्षेत्रीय राजधानियाँ, औद्योगिक आवास स्थल और राजनैतिक प्रभाव केन्द्र सभी कृतिम शक्तियों के रुप में और भिन्न भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक क्रिया कलाप स्वतः प्रेरित शक्तियों के रुप में प्रभाव डालते हैं। ऐसे स्थान सामान्यतया क्षेत्र के केन्द्र में होकर क्षेत्रीय सेवायें प्रदान करते है अस्तु केन्द्र स्थल या सेवाकेन्द्र कहलाते है। ऐसे केन्द्रों का जन्म सम्भवतया मेले के स्थान, साप्ताहिक बाजार, मन्दिर या धर्मिक स्थल, तिराहे (तीन ओर जाने वाला मार्ग) तथा चौराहे के रुप में होते है। इन स्थलों की स्थिति का निर्धारण सेवा पूर्ति के परिणाम या मात्रा पास के केन्द्रों की सेवा या क्षमता, आधार धरातल अवस्थिति के कारकों तथा क्षेत्रीय राजनैतिक एवं प्रशासकीय वातावरण से होता है। ऐसे स्थान की स्थिति मध्यवर्ती होनी चाहिये एवं ऐसे स्थान पर स्थिति हों जहाँ पर किसी नये केन्द्र को जन्म देने के लिये सेवापूर्ति की माँग हो। अर्थात किसी केन्द्र की अनुपस्थिति या दूर स्थिति के कारण आवश्यक पूर्ति प्रभावित नहीं हो। हम जानते है कि वस्तुओं ओर आवश्यकताओं का विनिमय एक प्राथमिक आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति के लिये सेवाकेन्द्र या केन्द्र स्थल का जन्म होता है।[18] कोई भी क्षेत्र/प्रदेश ऐसा नहीं हो सकता जहाँ की जनसंख्या वैयक्तिक रुप से अपनी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक आवश्कताओं के लिये अत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र हो। अतएवं वस्तुओं एवं सेवाओं के परस्पर विनिमय का क्रम प्रारम्भ होना निश्चित हो जाता है। जिस हेतु एक बहुगम्य सेवाकेन्द्र की आवश्यकता होती है। मध्यवर्ती संगम स्थल की उत्पत्ति स्थानीय बाजार के रुप में इसी प्रकार से होती है। क्रिस्टालर [19] के अनुसार एक बड़े प्रदेश में जहाँ सेवा केन्द्र पूर्व में ही कार्य कर रहे है। नवीन केन्द्र उन्हीं मध्यवर्ती बिन्दुओं पर जन्म ले सकते हैं। जो वर्तमान केन्द्रों से काफी दूर सेवापूर्ति की प्रभावकारी सीमा के बाहर स्थित

होते है। जब छोटे केन्द्र या वर्तमान केन्द्र बढ़ती हुई आवश्यकताओं या उच्चस्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति सफलता पूर्वक करने में असमर्थ होते हैं तो बृहत या नये सेवा केन्द्रों का जन्म स्वाभाविक रुप से होता है। क्षेत्र की आर्थिक आवश्यकताओं में वृद्धि या परिवर्तन के साथ साथ केन्द्र में भी परिणामतः परिवर्तन होना अनिवार्य है।[20] आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय वस्तुओं और सेवाओं की माँग अधिक तथा ऊँचे किस्म की भी होती है इसीलिये क्षेत्रीय सेवाकेन्द्र अधिकाधिक सम्पन्नता को प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे वस्तुओं की माँग केन्द्रीय भाग से बढ़ती जाती है या वर्तमान सेवाकेन्द्र से दूरी बढ़ती जाती है तो या तो पुराने केन्द्रों की सेवा क्षमता बढ़ जाती है या सीमावर्ती बिन्दुओं पर जो दूरी के कारण अपनी सेवायें अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं। नये केन्द्रों का विकास होता है। इसी प्रकार प्रशासकीय कारक न केवल खुद सेवा केन्द्रों की उत्पत्ति के लिये उत्तरदायी होते हैं बल्कि ये सेवा केन्द्र के भावी विकस में भी सहायक होते है। प्रशासकीय बस्तियाँ आज बृहत सेवा केन्द्रों का रुप धारण कर चुकी है। जबकि कुछ केन्द्र स्थल केवल राजधानी या प्रशासकीय मुख्यालय होने के कारण ही अधिक विकास पा सके हैं। सेवा केन्द्रों की उत्पत्ति एवं विकास दोनों के लिये यातायात मार्गों के संगम या केन्द्रीय भाग में बाजारों या विपणन केन्द्रों या पर्यटन स्थलों का प्रायः जन्म होता है। यदि किसी केन्द्र या सेवा स्थल के लिये गमनागमन की सुविधा बढ़ा दी जाती है तो उसकी सेवित क्षमता (Service Efficiency)से केन्द्रीय वस्तुओं के विक्रय का दायरा (क्षेत्र) भी बढ़ जाता है। जिससे दूरस्थ क्षेत्र भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। क्योंकि इससे उनकी सेवा केन्द्र से आर्थिक दूरी (Economic Distance) कम हो जायेगी। परिवहन के मार्ग अन्तस्थ केन्द्रीय (Inter Regional) अन्तर क्षेत्रीय और अन्तर केन्द्रीय (Inter Central)धमनियों के रुप में कार्य करते है। जिनकी अनुपस्थिति में सेवा केन्द्र और उनके प्रभाव क्षेत्र प्रभावी ढंग से एक दूसरे से अन्तर्सम्बंधित नहीं रह पाते है।

सेवा केन्द्रों के सतत विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है उनका "कार्यात्मक आधार" जो प्रायः सेवाकेन्द्र के जन्म या निर्माण के लिये भी उत्तरदायी होता है।

प्राचीन राजनैतिक क्षेत्रों का समापन इसीलिये आज हो गया हे कि उनके कार्यात्मक आधार या आर्थिक कारक समाप्त हो चुके है। सेवा केन्द्रों के विकास हेतु उत्तरदायी आर्थिक कारकों को दो रुपों में समझा जा सकता है।

1. प्राचीन सेवा केन्द्रों में से अधिकांश का जन्म और विकास -

प्रशासकीय प्रभाव केन्द्रों, धार्मिक स्थलों, क्षेत्रीय केन्द्रों और राजनीतिक राजधानियों के रुप में हुआ। इन केन्द्रों को समाजिक एवं आर्थिक आधार कालान्तर में प्रदान किये गये। इन सेवा केन्द्रों की स्थितियों का निर्धारण अधिकांशत: आधार धरातल और अवस्थिति की भौतिक सीमाओं से हुआ।

2. आधुनिक नगरों में से अधिकांश नगरों का जन्म एक विशेष प्रकार की बस्ती (जिसमें अर्थिक कारक प्रारम्भ से ही प्रभावशाली रहे है) के रुप में हुआ है। तथा जिनमें केन्द्रीय कार्यो का विकास कालान्तर में हुआ। इस प्रकार के नगर पर्यटनस्थल, औद्योगिक नगर, रेलवे जंक्शन, व्यापार केन्द्र, बाजार केन्द्र आदि प्रमुख है।

उपरोक्त दोनों रुपों द्वारा सेवा केन्द्रों के प्रमुख उपागम निम्नानुसार होते है।

(क) सेवा केन्द्र में उपलब्ध वस्तुयें तथा सेवायें जिस हेतु उसके निकटवर्ती क्षेत्र उन पर निर्भर करते हे।

(ख) समय, कीमत और लाभ से सम्बंधित किसी स्थान की दूरी उस सेवा केन्द्र से उसकी आर्थिक दूरी (Economic Distance) कहलाती है।

(1) सेवा केन्द्रों के अध्ययन का लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

यदि हम विकास समग्र प्रक्रिया का अध्ययन करें तो भारतीय समाज में क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विषमतायें पाई जाती है जो वास्तविक लक्ष्य से वंचित करती

है। इसके साथ ही कार्यक्रमों की प्रकृति और विषय वस्तु दोषपूर्ण नीति से बुरीतरह प्रभावित है। अतएव कार्यक्रमों के योजनाबद्ध क्रियान्वयन के लिये सर्व प्रथम प्रयास किये जाने चाहिये। जिससे निर्धारित लक्ष्य तक कार्यक्रमों की सुलभ अभिगम्यता हेतु वातावरण का निर्माण तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्षमताओं में अभिवृद्धि की जा सके। इसके साथ ही टूटी कड़ियों को जोड़ने तथा व्याप्त व्यवधानों को दूर करने के लिये अनुश्रवण कक्षिका केन्द्रों की स्थापना अपरिहार्य है, जिससे लक्ष्य समूह के लिये अन्तरण पद्धति अनुकूल बनाई जा सके। विभिन्न विकास कार्याक्रमों ऐसी रचनावृत्ति का समावेश होना चाहिये जिससे निर्धारित क्षेत्रीय कार्यत्मक संगठन के विविध लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। और कार्यकारण सहित लक्ष्य के अनुसार सामाजिक योजनाओं को भी सम्मिलित किया जा सके। अतः यह आवश्यक है कि विकास के कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला स्तरीय विकास कार्यक्रमों द्वारा योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किये जायें। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु योजनाबद्ध स्थिति के साथ विशिष्ट सांस्कृतिक संस्थानों का निर्माण किया जा सके।

जिला टीकमगढ़ कृषि उद्योग, परिवहन ओर व्यापार एवं वाणिज्यिक क्रियाओं में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को सुमुचित ढंग से अध्ययन क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है। जबकि बीसवी शताब्दी के सातवें दशक के उपरान्त सांस्कृतिक सुविधाओं जैसे -पेय जलापूर्ति, सिंचाई के साधनों की अभिवृद्धि, विद्युतीकरण, यातायात के साधनों, संचार सेवाओं और विस्तार सेवाओं में आशातीत वृद्धि हुई है। किन्तु आज भी अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। अस्तु विकास कार्यक्रमों को त्वरित गति प्रदान कराने के लिये अध्ययन के निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

1) क्षेत्रीय जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं, सेवाओं, सुविधाओं ओर बाहय् सम्बधों का विशिष्ट प्रतिरुप तैयार करना।

2) प्राप्त स्थानीय संसाधनों द्वारा अवत्सरचानात्मक विकास का विश्लेषण करते हुये अधिकतम विकास को प्रोत्साहित करने के लिये संसाधनों एवं आधार भूत संरचना में अर्न्तसम्बंध स्थापित करना।

3) क्षेत्रीय सेवा केन्द्रों के अनुसार उनके समुचित विकास की योजना प्रस्तुत करना जिससे वे ओर अच्छी सेवायें प्रदान कर सकें।

4) कृषि क्षेत्र में अत्याधिक विकास हेतु कार्यत्मक स्थानिक विशलेषण के साथ योजना प्रस्तुत करना क्योंकि कृषि ही एक मात्र स्थानीय आर्थिकी का सबसे बृहत आधार है।

5. सेवा केन्द्रों को कार्यात्मक पदानुक्रम के अनुसार विश्लेषित करना ओर उनकी वास्तविक स्थिति के अनुसार विशिष्ट सेवाओं का निर्धारण करना।

6) औद्योगिक विकास के भौगोलिक वितरण के अनुसार उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हुये स्थानिक संसाधनों की उपलब्धता द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और प्रतिष्ठनों को निरुपित करना।

7) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आधार-भूत सुविधाओं के विकास के लिये सेवा केन्द्रों की वितरण प्रणाली प्रस्तुत करना।

8) समाज के कमजोर, पिछड़े और आर्थिक रुप से विपन्न वर्ग के उत्थान के लिये संभावित कार्यक्रम प्रस्तुत करना जिससे वे अपने रहन सहन और संस्कृति को सुरक्षित रख सकें।

9) स्थानीय पर्यावरण को विकसित करने ओर पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्राप्त संसाधनों के अनुसार विकास की योजना प्रस्तुत करना तथा ग्रामों को नगरों की भाँति आत्मनिर्भर करने के लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम सुझाना।

10) क्षेत्रीय संतुलन के अनुसार त्वरित विकास के लिये सूक्ष्मस्तर पर नियोजित कार्यक्रम प्रस्तुत करना।

11. सेवा केन्द्रों में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिये तथा स्थानीय जनसंख्या को अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट करने की योजना प्रस्तुत करना।

12) अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिवेश विश्लेषित करना।

(2) सेवा केन्द्रों के अध्ययन में वर्तमान तक किये गये कार्यों की समीक्षा एवं साहित्य का पुनरावलोकन :-

प्रत्येक अधिवास का आकार, मात्रा की केन्द्रीयता या उसका प्रभाव आपस में कभी मेल नहीं खाते इसीलिये सेवा केन्द्रों की क्रियाओं के पदानुक्रम का विशलेषण आवश्यक होता है।[21] क्रिस्तालर सहित अनेक भूगोल वेत्ताओं ने विभिन्न देशों की बस्तियों या केन्द्रों का अध्ययन किया जो सेवा क्रन्द्रों की क्रियाओं पर आधारित है। तथा लघु एकचित अधिवास में भी सम्मिलित है।[22] जैसे जीन बून्स ने दक्षिणी पश्चिमी विसकांसिन के सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम का अध्ययन (The Hierarchy of Service Centres in South Western Wisconsine) में छोटे नगरों (हैमलेट) को भी सम्मिलित किया है। ट्रिवार्थ ने भी अमेरिका के ग्रामीण नगरों को क्रियाओं का विश्लेषण किया है। इन सभी शोधों में जनसंख्या श्रेणी आकार (**Rank Size**)ही सेवा केन्द्रों की सम्पूर्ण कियाओं के वर्गीकरण का आधार थी। **Agricultural Land Sehaft** के अध्ययन में हैरिक[24] ने प्रदेश के क्रमबद्ध विश्लेषण द्वारा सेवा केन्द्रों की क्रियाओं का पदानुक्रम व्यक्तिगत कृषि भूमि से लेकर सातवेंक्रम तक के महानगर तक निरुपित किया है। रोनाल्ड [25] ने सेवाकेन्द्रों के प्राथमिक विचार पर क्षेत्रीय कार्यत्मक संगठन किये विना विश्लेषण प्रस्तुत किये ही प्रकाश डाला है। सन् 1957 में फिलब्रिक[26] ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों एवं सेवाकेन्द्रों का अध्ययन किया तथा उनके क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन पर विंहगम दृष्टिपात किया। ब्जोर्कलुण्ड[27] ने फिलाब्रिक के सिद्धान्त एवं तकनीकि का प्रयोग आस्ट्रेलिया में किया जिसमें उन्होंने सेवा

केन्द्रों के क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन का सैद्धान्तिक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया। इसी तरह फिलब्रिक को विचारों को ब्राऊन[28] ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लेकरमैन[29] ने आफ्रीका में तथा स्माइल्स[30] एवं रैली[31] ने यूरोप में इसका परीक्षण किया।

ग्रामीण कृषि आर्थिकी का पक्ष विकास के क्रियाकलाप को मूल आधार प्रस्तुत करता है। रोविन्सन[32] के अनुसार स्थानिक संगठन की रणनीति में यह उपागम परिवर्तित प्रभावों की उच्च सम्भावना भी प्रस्तुत करती है। फ्रीडमैन[33] के अनुसार विभिन्न प्रभावों के आधार पर ये विस्तृत प्रभाव कभी कभी भिन्न भिन्न कारणों से सीमित होते है। जैसे -

(1) कृषि संगठन के रुप में जो नगरीय बाजारों के निकट स्थित होते है।

(2) गरीब क्षेत्रीय दूरी को बढ़ाते है।

(3) ये चारों ओर के क्षेत्र के लिये सभी का प्रभाव दर्शाते है तथा

(4) कृषि क्षेत्र में प्राचीन टूटी श्रंखला का अभाव पाया जाता है।

इसी कारण से स्कीनर[34] ने कहा कि सेवा क्रन्द्रों और क्षेत्रीय कार्यत्मक संगठन के लिये भूगोल में द्वितवीर प्रारम्भ हुआ। यमन[35] ने आर्थिक वृद्धि के पर्याय प्रस्तुत किये। सेवा केन्द्रों की संकल्पना हमारी योजनाओं के अभ्यास और अनुभवों की प्राप्ति है जो इस शताब्दी के पांचवे दशक से प्रारम्भ हुआ और आज क्षेत्रीय विकास ने सेवा केन्द्रों के साथ मिलकर नवीन स्वरुप धारण कर लिया है। यही कारण है कि 1950 से 1995 तक ग्राम तथा नगरीय विकास को एक नई दिशा मिली है।

छठे दशक की प्रगति :

केन्द्र स्थल के साथ क्षेत्रीय विकास प्रयोग के तौर पर सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के

द्वारा प्रारम्भ किया गया जिससे सभी क्षेत्रों का विकास समान सेवित क्षेत्र के रुप में हो सके। समूहगत वर्गो में केन्द्रीय कार्यों की भूमिका को सर्वप्रथम बोस[35] ने स्वीकार किया। केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त और अवस्थिति के उपयोग के लिये सर्वप्रथम क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत यूरोप के देशों में यह कार्यक्रम स्वीकार किया गया और समन्वित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ।[36]

सातवें दशक की प्रगति :

छठे दशक के बाद ग्रामीण तथा नगरीय विकास योजनायें नवीन तकनीकि द्वारा फ्रांस तथा जर्मनी में समाकलित क्षेत्रीय विकास के रुप में प्रयुक्त की गई। शास्त्री[37] ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये दो मॉडल तैयार किये जिसमें एक राष्ट्रीय तथा दूसरा प्रादेशिक स्तर का था। भारत में 1965 में भारतीय अर्थशास्त्र शोध संगठन द्वारा क्षेत्रीय योजना तथा कस्बे के बाजारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई[38] जो भारत में समन्वित क्षेत्रीय विकास की योजनाओं के लिये प्रथम प्रयास था। थामसन[39] ने क्षेत्रीय विकास की योजनाओं हेतु एक राष्ट्रीय वातावरण निर्मित करने के लिये उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किये। हीलिग[40] ने वैल्स के लिये, क्लाऊट[41] ने यूरोप के लिये तथा स्कीनर[42] ने चीन के बाजार कन्द्रों के समानान्तर विकसित सेवा केन्द्रों के लिये अपने कार्य एवं नियोजन प्रस्तुत किये।

आठवें दशक की प्रगति :

भारत में विभिन्न पाँच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चौथी योजनावधि में भूगोल वेताओं, क्षेत्रीय योजनाविदों, अर्थशास्त्रियों ओर समाज शास्त्रियों ने नियोजन के लिये समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की। वास्तव में चौथी पंचवर्षीय अवधि में सेवा केन्द्रों के क्षेत्रीय कार्यात्मक विश्लेषण हेतु प्रथम वार निश्चित कदम उठाये गये और नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ रुरल डिवलपमेंट (एन.आई.आर.डी.) हैदराबाद ने सन् 1970 से समाकालित

क्षेत्रीय विकास पर कार्य प्रारम्भ किया। वनमाली[43] ने सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं को क्षेत्रीय योजनान्तर्गत कार्य करने के लिये केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त निर्मित किया जो भारतीय वातावरण के लिये परीक्षण के तौर पर प्रारम्भ किया गया। बोस[44] ने इन्स्टीटयूशनल बाटलनैक के अन्तर्गत भारत में अविकसित क्षेत्र के विकास के लिये लक्ष्य निर्धारित किये। बनमाली[45] ने 1971 में सेवाकेन्द्रों के नियोजित कार्यक्रम को श्रेणीबद्ध किया। सेन[46] ने अपने शोधकर्ताओं के साथ सेवा केन्द्रो के अन्तर्गत ग्रामीण वृद्धि केन्द्रों की समस्याओं से निपटने के लिये क्षेत्रीय कार्यात्मक रणनीति तैयार की ओर विकसित क्षेत्रीय नियोजन के सुझाव प्रस्तुत किये। इस कार्य में बर्मन[47] तथा चन्द्रशेखर[48] का योगदान सराहनीय रहा। तदुपरान्त चक्रवर्ती[49], सेन[50], दास तथा सरकार[51] सेवाकेन्द्रों के सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर बल दिया। इसी प्रकार पाठक[52], सेन तथा मिश्रा[53] ग्रामीण विद्युतीकरण के विकास के साथ कृषि एवं सामाजिक कार्यपर शोध किये। मानव अधिवास तथा सेवा केन्द्रों के सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर भाट तथा शर्मा[54] ने अपना शोध कार्य किया। इसी प्रकार पटेल[55] ने मध्य प्रदेश आदिवासी विकास के लिये संतुलित क्षेत्रीय विकास की योजना प्रस्तुत की। 1976 में सेन[56] तथा अन्य शोध कर्ताओं ने प्रथम जन पर स्तरीय योजनायें बनाई जिसे कालान्तर में योजना आयोग ने स्वीकार किया। क्षेत्रीय विकास हेतु 1976 में ही एन.आई.सी.डी. हैदराबाद[57] द्वारा पर्याप्त कार्य किया गया जिसके अन्तर्गत समन्वित आदिवासी विकास योजना, जिला क्योंझर[58] (उड़ीसा) और जिला पश्चिमी मणिपुर[59] के लिये योजना निर्मित की गई। इसी वर्ष भाट[60] के साथ अन्य शोधकर्ताओं ने हरियाणा के करनाल क्षेत्र पर सरल सांख्यिकी तथा तकनीकि द्वारा कार्य किया जो संकलपनाओं से प्रेरित है। इसके बाद मंडल[61] तथा कावरा[62] ने क्षेत्रीय विकास में सूक्ष्मस्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आनेवाली समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किये। 1979 में सिंह[63] ने गोरखपुर क्षेत्र के संभावित विकास के लिये सिंह[64] ने समन्वित क्षेत्रीय विकास तथा केन्द्रीय स्थानों के पदानुक्रम हेतु सूक्ष्म स्तर पर विधितंत्र विकसित किया।

नवें दशक से 1995 तक की प्रगति :

नवें दशक और उसके बाद जैसे सेवाकेन्द्रों के अध्ययन की जैसे पूरे देश में

बाढ़ सी आ गयी। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में केन्द्रीय स्थानों के परानुक्रम, क्षेत्रीय कार्यात्मक विश्लेषण तथा सेवाकेन्द्रों के नियोजन के लिये सतत शोध हुये ओर आज भी चल रहे हैं उनमें सिन्हा[65], सिंह तथा पाठक[66], अग्निहोत्री [67], चतुर्वेदी [68], तिवारी [69], तथा अन्य के नाम उल्लेखनीय है। आज सेवाकेन्द्रों का क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन और उनका विश्लेषण अध्ययन की दृष्टि से नवीन स्वरुप धारण कर रहा है। जिससे क्षेत्रके निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु उन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो क्षेत्रीय विषमता को कम कर सकें इस हेतु त्रिपाठी एवं तिवारी [70] के नाम उल्लेखनीय है।

(3) शोध कला :

1. समंकों का संकलन :

सेवाकेन्द्रों के निर्धारण, भौगोलिक जानकारी एवं अन्य समंक शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों से प्राप्त कर प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त किये गये है। अध्ययन का मूल उद्देश्य कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं/कार्यों द्वारा क्षेत्रीय विस्तार एवं कार्यात्मक विश्लेषण के लिये नियोजित रुपरेखा प्रस्तुत करना है अतः जिला टीकमगढ़ के सेवा केन्द्रों और अन्य प्रभावशील क्षेत्रों को संयुक्त करने के लिये परिवहन तंत्र, के साथ अन्य सेवाओं का नवीन स्वरुप निर्धारित करना है।[71]

अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों का स्थानिक कार्यात्मक विश्लेषण ओर नियोजन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का एकत्रीकरण किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग-क्षेत्रीय, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन के लिये, जनसंख्या के आंकड़ों को जिला टीकमगढ़ प्राथमिक जनगणना सार तथा ग्राम एवं नगर निदर्शनी [73] 1991 की कम्प्यूटर द्वारा प्राप्त प्रतियों से सहायता ली गई है। क्षेत्रीय आर्थिकी के लिये विभिन्न शासकीय कार्यालयों जैसे सांख्यिकी विभाग, अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला उद्योग कार्यालय, कृषि एवं सिंचाई विभाग आदि की सहायता ली गई है। उन कार्यालयों से प्राप्त किये गये समकों द्वारा

सेवा केन्द्रों का निर्धारण एवं सेवा स्तर का आंकलन किया गया है। अन्य आकड़ों का संकलन प्रतिचयन द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है जिसे पाँच प्रमुख कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, विद्युत सेवायें एवं विपणन आदि प्रमुख है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी स्थानीय नागरिकों से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं उचित समाधान हेतु उपाय प्रस्तुत किये गये है तथा प्रश्नावली को परिशिष्ट में संलग्न किया गया है।

(2) सांख्यिकीय प्राविधि :

सेवा केन्द्रों का निर्धारण एवं विश्लेषण क्षेत्रीय आर्थिकी एवं सामाजिक क्रियाओं के द्वारा ही सम्भव होती है। इसे केवल सांख्यिकीय उपभागों द्वारा ही समुचित रुप से दर्शाया जाता है। विगत दो तीन दशकों में भौगोलिक अध्ययन की सांख्यिकीय प्राविधि में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुये हैं। इसी सांख्यिकी की परिवर्तित प्राविधि के कारण क्षेत्रीय विश्लेषण एवं उपादानों द्वारा नवीनतम मानचित्र-प्रणाली में प्रयुक्त किया गया है। सेवा केन्द्रों के नियोजन और सम्बंधित समस्याओं को नवीनतम प्राविधि द्वारा अपेक्षित एवं उपयुक्त समाधान सुझाये गये है। सांख्यिकीय प्राविधि को इकाई निर्धारण, मानचित्र तकनीकि एवं अध्ययन योजना में विभक्त किया गया है।

(क) इकाई निर्धारण :

अध्ययन क्षेत्र को धरातलीय बनावट, भू-वैज्ञानिक संरचना, तथा अन्य प्राकृतिक तथ्यों के विश्लेषण के लिये समग्र क्षेत्र को एक इकाई माना गया है। जिला टीकमगढ़ के सेवा केन्द्रों का क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक संगठन निर्धारित करने के लिये आवश्यक इकाईयों में बाँटा गया है। आर्थिक जनसंख्या का आधार एवं सेवा केन्द्रों की स्थिति के लिये राजस्व निरीक्षक मण्डल अथवा पटवारी हल्का को एक इकाई में आवद्ध किया गया है। और उन्हें

सारणी बद्ध कर मानचित्रों को निर्मित किया गया है। बृहत सारणियों को अनुपयुक्त समझकर उन्हें परिशिष्ट में रखा गया है।

(ख) मानचित्र तकनीकि :

अध्ययन में अधिकाधिक माचनित्रों का समावेश करने के लिये मिलियन सीट स्थलाकृतिक मानचित्र जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित हैं[74] का प्रयोग किया गया है। इनसे उच्चावच, ढाल विश्लेषण, अपवाह तन्त्र तथा भौतिक विभाग के मानचित्र बनाये गये है। इसके साथ ही प्राकृतिक वनस्पति एवं अधिवासों के वितरण प्रतिरुप को धरातल पत्रक द्वारा ज्यों का त्यों दियागया है।[75] आवश्यकतानुसार सांख्यिकीय आरेखों का निर्माण किया गया है। विभिन्न, शासकीय/अशासकीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त समंकों को सारणी बद्ध कर सूचकांकों द्वारा आंकलित कर मानचित्रांकन के भौगोलिक प्रयोग किये गये है। इस हेतु प्रकाशित भौगोलिक शेध्य पत्रिकाओं, शेघ प्रबंधों और पुस्तकों की सहायता ली गई है।

(ग) अध्ययन योजना :

जिला टीकमगढ़ के सेवा केन्द्रों का विश्लेषण अध्ययन की सुविधा हेतु ग्यारह अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में अध्ययन क्षेत्र एवं समस्या का परिचय, संकल्पनात्मक पृष्ठ-भूमि के साथ शोध्य कला का विश्लेषण है। दूसरे अध्याय में अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त भौगोलिक परिचय जिसमें संसाधन आधार एवं सेवायें सम्मिलित है। तृतीय अध्याय में सेवा केन्द्रों का अभिज्ञान, चौथे अध्याय में सेवाकेन्द्रों का उद्भव एवं विकास, पाँचवे अध्याय में सेवा केन्द्रों का अध्ययन क्षेत्र में वर्गीकरण जबकि छठे अध्ययाय में सेवाकेन्द्रों के कार्य एवं उनकी कार्यात्मक परानुक्रम का विश्लेषण है। अध्ययन के सातवें अध्याय में सेवाकेन्द्रों का स्थानिक विरण और श्रेणी आकार सम्बद्धता, आठवे अध्याय में सेवा केन्द्रों की आकारिकी, नवें अध्याय में सेवा क्षेत्र का निर्धारण और दसवें अध्याय में संतुलित प्रादेशिक

विकास के लिये सेवा केन्द्रों की रणनीति निर्मित की गई है। और अंतिम अध्याय में सारांश तथा संस्तुतियों का समावेश किया गया है।

: REFERENCES:

1. Singh, J. (1979) : Central Places and Spatial Organisation in a Backward Economy : Gorakhpur Region- A study in Integrated Regional Development, Uttar Bharat Bhoogal Parishad, Goraphpur, PP: 1-3.

2. अवस्थी, एन.एम. (1986) : जिला टीकमगढ़ में सिंचित कृषि ग्रामीण विकास पर प्रभाव- अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (अप्रकाशित शोध प्रबंध) पृ: 149.

3. Tripathi, R.S. & Tiwari, R.P. (eds) (1993): Regional Disparities and Development in India- Ashish Publishing House, New Delhi -P: Editorial.

4. Bronger, D. (1978) : Centre Place System, Regional Planning and Development in Developing countries- case of India in- R.L.Singh et.al. (Ed.) Transformation of Rural Habitat in India perspective- A Geographical Dimensions, N.G.S.I., Varanasi.

5. Singh, R.L. and Rana, P.B. Singh (1980): Socio - Economic Processes in Transforming Indian Rural Habitat, Perspective and Strategy, Okayama Proceedings, PP : 25-30.

6. Shanei, P.V. (1975) : Agricultural Development in India - A New Strategy in Management, New Delhi, Vikas Publication House, P : 246.

7. श्रीवास्तव, के.आर. (1974): बाजार केन्द्र स्थल एक मॉडल अध्ययनविधि - उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, गोरखपुर अंक 10, संख्या - 1, पृ.: 80-89.

8. सिंह, औ.पी. (1973) : केन्द्र स्थल और उनकी उत्पत्ति तथा विकास उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, गोरखपुर अंक 9, संख्या -1, पृ : 30-35.

9. शुक्ला आर.के.एवं त्रिपाठी, आर.एस.(1988) : ' समंवित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक युवा संगठनों की अन्तर्गस्तता एक सृजनात्मक सुझाव'. Geo Science Journal Vol. III, Pt. I, NGSI, Varanasi PP : 24-29.

10. Berry, B.J.L. (1958) a, : A note on Central Place Theory and the Range of Goods, Economic Geography P : 24.

11. Bronger, D. (1978) : Central Place System, Regional Planning and Development in Deve-oping Countries - A case of India in R.L. Singh (Ed.) Transformation of Rural Habitat in India a Perspective - A Geographical Dimensions NGSI Varanasi.

12. Friedmann, J. (1966): Regional Development Policy A case study of Venenjuela M.I.T. Press Cambridge - Mass, P : 48.

13. Hansen, N.M. (1972) : On Urban Hierarchy Stability and Spatial Polarization, A Note, Urban Studies, P : 7.

14. Jain, N.G. (1971): Urban Hiererchy and Telephone Services in Vidarbha (Maharastra) National Geographical Journals of India XII.

15. Mishra, G.K. (1977): Rural Urban Contiomum, India Journal of Regional Service, IX.

16. Shrivastava, R.P. (1974) : A Model for the study of an Individual Market Place : Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. X, No. 4, PP : 80-89.

17. Hermansen, T. (1972): Development poles and Development centres in National and Regional Development, Elements of a Theoritical Framework in A. Kukulinski (Ed.` Growth Poles and Growth Centres in Regional Planning) ; Mouton, Paris.

18. Morril, R.L. (1970): The Spatial Organisation of Society, Duxberry Press, Belmort calif PP : 175-189.

19. Christaller, W. (1933) : Die Sewrateu Orte Suddensch Land Gustor Fisher, Jeus, Translated by C.W. Baskin, Printice Hall, Inc. Eglewood Cliffs N.P. (1966) P : 2.

20. Davis, W.K.D.(1966):The Ranking of Service Centres A critical Review, Institute of British Geographers, Transactions 40.

21. Bhadauria, B.L.S. (1989): Micro Level Development and Planning Rural Growth Centres Strategy, Common wealth Publishers, New Delhi PP : 191 - 202.

22. Christaller, W. (1933): Ibid 19. PP : 2-11.

23. Trewartha, G.T. (1953) : A case of population Geography Associations of American Geographers (Annals), P: 18.

24. Harris, C.D. (1943) : A Functional Classification of Cities in United States, Geographic Review - P : 33.

25. Jones Ronald (1975) : Central Place Theory and the Hierarchy and Location of shoping Centres in a City : Edinbury I.B.G. Conference Papers: Durban; Plott. K. Geography and Retailing University, London.

26. Philbrick, A.K. (1957): Principles of A real Functional Human Geography, 33 PP : 299-336.

27. Chaturvedi, K.K. (1993): Micro-Level Planning A case study of Prithvipur Block, Unpublished Ph.D. Thesis, A.P.S. University, Rewa PP : IX - XII.

28. Brown, L.A. and E.G. Moorie (1969): Diffusion Research in Geography: A Perspective, Vol.I, PP 119-59.

29. Luckermann, F. (1966): Emperical Expressions of Nodality and Hierarchy in a Circular Manifold, East Lakes, Geographers 2, PP : 17-44.

30. Smailes, A.E. (1970): "Geography of Towns" Hufehins University and Co. London.

31. Reilly, W.J. (1929) : Methods of the Study of Retail Relationship Europe: Monograph No.4 Beaurau of Business Research, University of Texas, PP: 314:40.

32. Robinson, R.(Ed.) (1971): Developing Countries of the IIIrd World, The Cambridge University Press P : 66.

33. Friedmann, J. (1972) : The General Theory of Polarised Development, Hausen, N.M.(Ed.) Regional Economic Development, The free press Newyork, P: 59.

34. Skinner, C.W. (1970): Marketing and Social Structure Including Journal of Asian Studies Vol. XXVI No. 1 P.67

35. Bose, A.N. (1970): Institutional Bottleneck, The Main Barrier to the Development of Backward Areas, Indian Journal of Regional Science Vol.II, No. 1 P : 259.

36. Thompson, I.V. (1966) : Some Problem of Regional Planning in Predominantly Rural Environment, the French Experience in Concise Scottish Geographical Magazine, Vol. 25 PP : 119 - 129.

37. Shashi, M.V.R. (1965) : Integration of National and Economic Models in the United States; The Indian Economic Journal Vol. XVI, No.1, P : 44.

38. Shastri, M.V.R. (1965) : Op. Cit., P : 142.

39. Thompson, I.V. (1966) : Op.cit. P : 144.

40. Hilling, J.B. (1968) : A Plan for the Regional Journal of Town Planning, Institute of Midwell Vol. 1 No.54, PP : 70-74.

41. Clout, H.D. (1969) : Preliminary Report on Pilot Project for Integrated Area Development Ford Foundation and Council of Social Development, New Delhi PP : 182 - 202.

42. Skinner, C.W. (1969) : Marketing and Social Structure in China, Journal of Asian Studies, Vol. XXVI, No.1. P: 33.

43. Wanmali, S. (1970): Regional Planning For Social Facilities : An Examination of Central Place concepts and their Application. A Case Study of Eastern Maharastra - NICD Hyderabad 6, PP : 1-10.

44. Bose, A.N. (1970): Institutional Bottlenecks, the Main Barrier to the Development of Backward Areas, Indian Journal of Regional Science, Vol. II, No.1, P : 45.

45. Wanmali, S. (1971): Central Place and their Tributary Population, Some observation, Science and Community Development, NICD Hyderbad-6 PP : 11 - 39.

46. Sen, L.K. (1971) : Planning for Rural Growth Centres For Integrated Area Development, A Case study of Miryalguda Taluka of Andhra Pradesh, NICD, Hyderabad, PP: 1-14.

47. Burman Roy, B.K. (1972): Towards an Integrated Regional Frame, Economic and Socio-Culture Dimensions of Regionalisations Census of India, Monograph, No.7, New Delhi P: 27-50.

48. Chandra Shekhar, C.S. (1972) : Balanced Regional Development and Regions, Census of India, Monograph No.7. New Delhi PP : 59-74.

49. Chakravarty, S.C. (1972) : Some considerations of Research Objectives for Rural Area Development, Indian Journal of Regional Science Vol. IV, No.1, PP : 6 -11.

50. Sen, L.K. (1972) : Growth Centres in Raichur, An

Integrated Area Development Plan for a District in Karnataka, NICD, Hyderabad.

50. Das, B.N. and Sarkar, A.K. (1972): Rural Area Development Karnal Area, A case study, Indian Journal of Regional Science, Vol.IV No.2, PP : 164 - 179.

52. Pathak, C.R. (1973) : Integrated Area Development, A Study for Rural Agricultural Development Geographical Review in India, Vol. 35, No.3, PP : 222-31.

53. Sen, L.K. and G.K. Mishra (1974): Regional Planning For Rural Electrification, A case study of Suryapet Taluka, Nalganda District, Andhra Pradesh, NICD, Hyderbad, PP : 112 - 15.

54. Bhat, L.S. and Sharma, A.N. (1974); Functional and Spatial Organisation of Human Settlements of Integrated Area Study, 13 Indian Economic Conference PP : 45 - 52.

55. Patel, M.L. (1975): Dilemma of Balanced Development in India, Bhopal, PP : 33 -34.

56. Sen, L.K. et. al. (1975) : Growth Centres in Raichur, An Integrated Area Development Plan for a District in Karnataka, NICD, Hyderabad.

57. Sen, L.K. and Sharma, A.K. (1976): Regional Planning for Hill Areas, A case study of Pauri Tehsil of Garhwal District, (U.P.) NICD, Hyderabad.

58. Patnaik, N. and Bose, S. (1976): An Integrated Tribal Development Plan for Keon Jhar District (Orissa), NICD, Hyderabad.

59. Khan, H. and Romesh, K.S. (1976): Integrated Area Development Plan for West District of Manipur, NICD, Hyderabad.

60. Bhat, L.S. (1976): Micro Level Planning, A Case study of Karnal Area India, New Delhi.

61. Mundle, S. (1977): District Planning In India, I.J.P.A., New Delhi.

62. Kabra, K.N. (1977): Planning Processes in a District II, P.A. New Delhi.

63. Singh, J. (1979) : Central Place Organisation in a Backward Economy - Gorakhpur Region, A study in Integrated Regional Development, Uttar Bharat Bhoogol Parishad, Gorakpur, (U.P.)

64. Singh, L. (1979) : Integrated Rural Development, A Case Study of Patna District (Bihar) National Geographical Vol. XIV, No.2 PP : 193-203.

65. Sinha, R.L.P. (1981) : Rural Development Approach Its Application at Taluk Level in L.R. Singh (ed.) New Perspective in Geography, Thinkers Librarey, Allahabad, PP : 103-22.

66. Sinha, B.N. and Pathak, R.K. (1980): Integrated Area Development Planning, Concept and Background National Geographer, Vol. XV No.2, PP : 157-171.

67. Agnihotri, M.C. (1987): Integrated Area Development of Karwi Tehsil of Banda District (U.P.) unpublished Ph.D. Thesis, Bundelkhand Vishwavidyalaya, Jhansi, (U.P.).

68. Chaturvedi, K.K. (1993): Micro Level Planning A case study of Prithvipur Block of Tikamgarh District (M.P.) Unpublished Ph.D. Thesis A.P.S. University, Rewa, (M.P.).

69. Tiwari, P.D. and Tripathi, R.S. (1991): Dimensions of Scheduled Castes Development in India, Uppal Publications New Delhi.

70. Tripathi, R.S. and Tiwari, R.P. (19930: Regional Disparities and Development in India Ashish Publishing house, New Delhi.

71. Singh, J. (1979) : Op. Cit. PP : 1-21.

72. Primary Census Abstract, Census of India, Tikamgarh District, (M.P.) (Computer Data) Part-II-A-1991.

73. Village & Town Directory - Census of India, District Tikamgarh, Madhya Pradesh, (Computer Data) pt. II - B. 1991.

74. Survey of India Toposheet No. 54 $\frac{L}{P}$.

75. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, टीकमगढ़, जिला सांख्यिकी कार्यालय, टीकमगढ़ (म.प्र.)।995.

----0-----

अध्याय दो

अध्ययन क्षेत्र : एक संक्षिप्त परिचय

- अवस्थिति एवं विस्तार
- भू-वैज्ञानिक संरचना एवं धरातलीय बनावट
- अपवाह तंत्र
- जलवायु
- प्राकृतिक वनस्पति
- प्राकृतिक संसाधन - मिट्टियाँ, वन, खनिज एवं अन्य
- कृषि
- उद्योग
- जनसंख्या
- अधिवास
- संचार सेवायें
- बैंक सेवायें
- संदर्भित ग्रन्थों की सूची
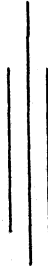
1. स्थिति एवं विस्तार : (LOCATION AND EXTENT)

बुन्देलखण्ड उच्च भूमि के उत्तरी मध्य भाग में स्थित जिला टीकमगढ़ $24^0$26'00" उत्तर अक्षांश से $25^0$33'15" उत्तरी अक्षांश तक एवं $78^0$25'15" से $79^0$20'45" पूर्वी देशान्तर[1] के मध्य स्थित मध्य प्रदेश राज्य एक प्रशासनिक भाग है। इसका कुल क्षेत्रफल 5048 वर्ग कि.मी. तथा जनसंख्या 928954 (1991)[2] है। म.प्र. में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का यह 39 वाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से 7 वाँ स्थान रखाता है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 125 कि.मी. एवं पूर्व से पश्चिम में 60 कि.मी. विस्तृत है।[3] जिला पूर्व में छतरपुर, दक्षिण एवं पश्चिम में ललितपुर तथा उत्तर में झाँसी जिले की सीमाओं से घिरा हुआ है। बुन्देलखण्ड उच्च भूमि के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओरछा उच्च भूमि पर स्थित पहाड़ियों एवं पठारों का यह क्षेत्र दक्षिण में विन्ध्यन तथा नारहट स्कार्पलैंड और उत्तर में ओरछा जलोढ़ मैदान से जुड़ा है। नदियों ने जिले की अधिकांश सीमायें निर्मित की है। इनमें पूर्व में धसान, उत्तर में बेतवा, पश्चिम में जामनी तथा दक्षिण में रोहणी तथा जमरार नदियाँ प्रमुख है। जिला टीकमगढ़-प्रशासनिक दृष्टिकोण से 5 तहसीलों, 6 विकास खण्डों, 17 राजस्व निरीक्षण मण्डलों, 12 नगरीय अधिवासों, 295 पटवारी हल्कों तथा 875 आवासीय बस्तियों में विभाजित है।[4] मानचित्र एवं सारणी 2.1 में जिले का प्रशासनिक, क्षेत्रफल व जनसंख्या तथा आवासित वस्तियों के आकार को निरुपित किया गया है।

2. भूवैज्ञानिक संरचना एवं उच्चावच : (GEOLOGICAL STRUCTURE & RELIEF)

भू-वैज्ञानिक संरचना द्वारा किसी क्षेत्र की शैलो की बनावट और उनकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मिट्टी निर्माण में भू-वैज्ञानिक संगठन अहम भूमिका निभाता है क्योंकि मिट्टी की उत्पादकता उसमें उपलब्ध खनिजो पर निर्भर करती है।[5] जिला टीकमगढ़ दक्षिणी बुन्देलखण्ड का एक भाग है। जो उत्तर में जलोढ़ मैदान और दक्षिण में मालवा के पठार (प्रायदीपीय आद्यकालीन पठार) के मध्य सेतु के रूप में स्थित है।

सारणी क्रमांक 2.1 : जिला टीकमगढ़ का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का वितरण (1991)

	राजस्त निरीक्षक मण्डल	तहसील मुख्यालय	विकासखण्ड मुख्यालय	आवासित बस्तियाँ	नगर	पटवारी हल्के की संख्या	क्षेत्रफल (% में)	जन संख्या (% में)
1.	ओरछा	निवाड़ी	निवाड़ी	40	-	8	3.08	3.20
2.	निवाड़ी	निवाड़ी	निवाड़ी	40	1	15	4.25	5.74
3.	तरीचरकलाँ	निवाड़ी	निवाड़ी	53	1	21	5.94	6.49
4.	नैगुवाँ	पृथ्वीपुर	पृथ्वीपुर	44	-	10	3.14	3.00
5.	सिमरा	पृथ्वीपुर	पृथ्वीपुर	30	1	10	2.67	3.51
6.	पृथ्वीपुर	पृथ्वीपुर	पृथ्वीपुर	54	1	20	6.07	6.77
7.	मोहनगढ़	जतारा	जतारा	76	-	19	7.40	6.53
8.	लिधौरा	जतारा	जतारा	56	1	20	7.47	7.16
9.	दिगौड़ा	जतारा	जतारा	44	-	18	6.47	6.12
10.	जतारा	जतारा	जतारा	67	1	24	8.68	8.81
11.	पलेरा	पलेरा	पलेरा	58	1	20	7.43	6.28
12.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	60	2	20	7.00	11.02
13.	समर्रा	टीकमगढ़	टीकमगढ़	50	-	18	5.52	4.30
14.	बड़ागाँव	टीकमगढ़	टीकमगढ़	49	1	19	.27	4.83
15.	बल्देवगढ़	बल्देवगढ़	बल्देवगढ़	55	1	18	5.57	5.62
16.	कुड़ीला	बल्देवगढ़	बल्देवगढ़	51	-	17	6.06	4.42
17.	खरगापुर	बल्देवगढ़	पलेरा	48	1	18	6.98	6.20

स्रोत : प्राथमिक जनगणना सार - जिला टीकमगढ़ म.प्र. 1991.

Location of Tikamgarh District in M.P.
Madhya Pradesh
District Tikamgarh
R.I.Circle
Orchha
Taricharkalan
Niwari
Prithvipur
Simara
Lidhora
Mohangarh
Palera
Jatara
Degora
Khargapur
Tikamgarh
Baldeogarh
Kudila
Samarra
Badagaon
District Jhansi
District Lalitpur
District Chhatarpur
Boundary
State
District
Tahsil
R.I. Circle
Patwari Halka
River (Major)
F Forest (Reserved)
Headquarter
Patwari Halka Headquarter
R.I. Circle Headquarter
Tahsil Headquarter
District Headquarter
K.M.

FIG 2.1

इसी केन्द्रीय स्थिति के कारण इस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना में आद्यकल्प की शैलों से लेकर अतिनूतन कल्प के जमाव पाये जाते है। कालक्रमानुसार इन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

1. आद्य कल्पीय शैल समूह
2. विन्ध्याचन शैल समूह
3. जलोढ़ अवसादी शैल समूह

आद्यकल्पीय शैलों की उत्पत्ति आग्नेय एवं अवसादी शैलों के साथ इस क्षेत्र में फैली है; जिनका निर्माण प्रारम्भिक काल की शैलों के जमाव से प्रारम्भ हुआ। आज ये शैलें कायांतरित होकर संरचनात्मक निरुपण एवं निक्षेपों द्वारा विभिन्न रुपों में परिवर्तत हो चुकी है। अध्ययन क्षेत्र में नीस तथा ग्रेनाइट की प्रधानता के कारण इसे ***Granatic Country*** कहा गया है। बुन्देलखण्ड नीस, शिष्ट और ग्रेनाइट शैलें बिखरे प्रारुप में मिलती है। सिल, डाइक एवं वनस्पतिहीन गोलाकार मोरम की पहाड़ियों के कारण यह क्षेत्र अलग भौगोलिक प्रदेश के रुप में जाना जा सकता है। उत्तरी पशिचमी भाग में ओरछा के निकट नीस तथा ग्रेनाइट की पहाडियाँ और जामनी, जमड़ार तथा धसान नदियों के भागों में आस्थोक्लेज चट्टानों का मिश्रण, विक्रमपुर के निकट नीस तथा आस्थेक्लेज की रवे युक्त शैले और बेतवानदी में ओरछा के आसपास लौहयुक्त नीस चट्टानें फैली हुई है। बुन्देलखण्ड नीस की स्तरित शैलें धसान नदी के समीप, मोहनगढ़ के निकट भूरे तथा काले रंग के फैल्सपार शैलें, जतारा एवं बम्हौरी बराना के पास नीले एवं काले रंग के फैल्सपार तथा क्लोराइड् युक्त शेलों की प्रधानता पाई जाती है।

सम्पूर्ण क्षेत्र में मोरम की पहाड़ियाँ विखण्डित क्रम में पाई जाती है ये समढाल एवं समतल शिखरयुक्त, बलुवा पत्थर, चूना तथा शेल से निर्मित है। यहाँ की लाल पीली, रॉकड पडुआ ओर कंकरीली मिट्टी के निर्माण में इन शैलों की प्रधानता पाई जाती है। इन

पहाड़ियों को टोर या टौरिया कहते है।

अध्ययन क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी नदियों के किनारे अति नूतन कला की जलोढ़ मिट्टी के जमाव मिलते है। इस भू-भाग में भूमिगत जल स्तर बहुत ऊपर है।

जिला टीकमगढ़ बुन्देलखण्ड क्षेत्र के इस भू-भाग में विखरी पहाड़ियों की ऊँचाई स्थानिक आधारों पर लगभग 100 मी. है। सामान्यतः भू-दृश्य समतल धरातल के बीच जहाँ-तहाँ विखण्डित पहाड़ियाँ जिनका निर्माण क्वार्टज डोलोराइट, डाइक एवं छोटे छोटे कंकर पत्थर से हुआ है। जिला में ककरवाहा की पहाड़ी सर्वोच्च शिखर 486.79 मी.(एम.एस.एल.) ऊपर है। और न्यून्तम ऊचाई (एम.एस.एल.) निवाड़ी तहसील में सेंदरी गाँव के निकट है। जिले की औसतन ऊचाई 328 मी. (एम.एस.एल.) है। यहाँ के उच्चावच को निम्न तीन भागों में भू-तल के सामान्य लक्षणों के आधार पर विभाजित किया जा कता है।[6]

1. उत्तरी जलौढ़ मिट्टी का मैदान.
2. मध्यवर्ती उर, धसान तथा बैतवा का समप्रायः मैदान.
3. दक्षिणी पश्चिमी ओरछा उच्च भूमि का विषम धरातलीय क्षेत्र.

जिला टीकमगढ का अधिकांश ढाल उत्तरी-पूर्वी है। किन्तु बेतवा नदी के दक्षिण में ढाल उत्तर की ओर; जामनी नदी के निकट पश्चिम की ओर तथा धसान नदी के किनारे यह ढाल पूरव की ओर है। विन्ध्याचल की निम्न मोरम की पहाड़ियाँ, आग्नेय शैलों की टेकरी, पैटलैण्ड क्षेत्र और समतल जलोढ़युक्त मैंदान के कारण इस भाग में ढाल प्रवढ़ता उत्तर की ओर अधिक पायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में ककरवाहा तथा मड़िया की पहाड़ियों और महेवा के पठार पर औसत ढाल 2^0 से 3^0 तक, बल्देवगढ़, जतारा एवं निवाड़ी

Physical Features
TIKAMGARH DISTRICT
(A)
Relief
N
Height From M.S.L. In Mts
Below 400
201 300
301 400
Over 400
(B)
Slope
Slope
2°-3°
1°-2°
30'-1°
Below 30'
0 30
KMS.
(C)
Natural Regions
Basin
(1) Dhasan Basin
(2) Ur Basin
(3) Sukhnai Saprar Basin
(4) Low Land of Northern Batwa Basin
(5) Orchha Up Land
(6) Vindhyan Up Land
(D)
Drainage System
Catchment Area of Drainage Regions
(1) Betwa Basin
(2) Jamni Basin
(3) Dhasan Basin
(4) Saprar Basin
(5) Ur Basin
(6) Inland Drainage
River / Nala
Reservoir
Water Divide

तहसील के मध्य में ढाल 1^0 से 2^0 तक, तथा अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी एवं नदी घाटी के किनारे ढाल 30' से कम पाया जाता है।

3. **अपवाह तंत्र : (DRAINAGE SYSTEM)**

किसी भू-भाग का अपवाह तंत्र उसकी संरचना, ढाल, जल की पूर्ति आदि से सीधे प्रभावित होता है। क्षेत्र की सभी नदियाँ विन्ध्यन की श्रेणियों से निकलकर वृक्षाकार अपवाह का निर्माण करती है जो यमुना नदी अपवाह का एक भाग है। जामनी बेतवा एवं धसान यहाँ की प्रमुख नदियाँ है जो जिले की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाओं को निर्धारित करती है। इन नदियों में अधिक अपरदन से कठोर पठारी सतह स्पष्ट दिखाई देती है। जिससे उर्ध्वाधर कटाव या नदी घाटी का गहराना बहुत धीमी गति से हो रहा है मानचित्र 2.2 तथा सारणी 2.2 में जिला टीकमगढ़ का अपवाह तंत्र दर्शाया गया है।

4. **जलवायु : (CLIMATE)**

किसी स्थान का मौसम और जलवायु सर्वाधिक महत्वूपर्णू कारक है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से सम्पूर्ण भौगोलिक वातावारण को प्रभावित करती है। मनुष्य पर इसका प्रभाव उसके व्यक्तिगत सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। जिला टीकमगढ़ की उपमहाद्वीपीय स्थिति के कारण ग्रीष्म एवं शीत काल में तापमान में भारी अन्तर पाया जाता है। क्योंकि गर्मियाँ बहुत गर्म और शीत-ऋतु बहुत सर्द हो जाती है। 15 अप्रेल से प्रथम वर्षा के पूर्व तक प्रातः 10 बजे से 'लू' चलती है तो शीतकाल में शीतलहर, पाला, तुषार, और कदाचित उपल वृष्टि भी होती है। जिला टीकमगढ़ के मौसम को ऋतु के अनुसार वर्षा ऋतु (जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक) शीत ऋतु (मध्य अक्टूबर से फरवरी तक) तथा ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के अंतिम सप्ताह के पूर्व तक) तीन भागों में बांटा जा सकता है।

सारणी क्रमांक 2.2 : जिला टीकमगढ़ की अपवाह प्रणाली (1995)

नदी	सतत प्रवाहिनी	लम्बाई कि. मी. में:
1.	बेतवा	30 कि.मी.
2.	घसान	100 कि.मी.
3.	सपरार	30 कि.मी.
4.	उर	75 कि.मी.
5.	जामनी	125 कि.मी.
6.	वारभी	30 कि.मी.
7.	सुरार	25 कि.मी.

नदी	मौसमी	लम्बाई कि.मी. में :
1.	डुमरई	20 कि.मी.
2.	रोउर	5 कि.मी.
3.	सुखनई	25 कि.मी.
4.	जमरार	20 कि.मी.
5.	बवेड़ी	10 कि.मी.
6.	सतार	5 कि.मी.
7.	धुरोई	10 कि.मी.

स्रोत : जल संसाधन विभाग से साभार

CLIMATIC CHARTS
Adjusted Temperature Curves
Temp°C
Maximum
Minimum
Kundeshwar
Orchha
Adjusted Means
(Temperature Curves)
Average
Kundeshwar
Orchha
% Relative Temperature Curves
Increase
Decrease
Increase
Decrease
Average Water Deficiency and Surplus
CMS.
(Niwari)
Precipitation
Evaptranspiration
(Jatara)
Deficiency
Surplus
(Tikamgarh)
Soil Moisture Utilization
Climograph
Scorching
Muggy
Keen
Raw
Wet Bulb Temp in °C
Relative Humidity in %
Accumulated Percentage Deviations
Years
Soures: N M Awasthi, 1986.

FIG 2.3

तापमान : (TEMPERATURE)

यहाँ तापमान वितरण सामान्य पाया जाता है। समस्त क्षेत्रों में एक जैसे वितरण से उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम में अधिक विभिन्नता नहीं मिलती। सारणी 2.3 से स्पष्ट है कि निवाड़ी, जतारा एवं टीकमगढ़ तीनों स्थानों पर इसकी विलोमता 1^0 - 1.5^0 से.ग्रे.तक है। पूरे वर्ष भर तापक्रम की विषमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि मई तथा जून के महीनों में दिन का अधिकतम तापमान 45^0 से.ग्रे. से अधिक हो जाता है तो दिसम्बर एवं जनवरी में यह न्यूनतम 5^0 से.ग्रे. तक नीचे आता है। सन् 1973 में कुण्डेश्वर बेधशाला में 2^0 से.ग्रे. तापमान रिकार्ड किया गया जो इस शताब्दी का न्यूनतम तापमान कहा जा सकता है। औसतन जनवरी माह सर्वाधिक शीतल एवं मई माह सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं। यहाँ तापमान की अधिकता से बाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है जिससे स्थानीय जलाशय, नदियाँ प्राय: सूख जाती है और कुओं का जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। किसी वर्ष यदि सामान्य वर्षा से कम वर्षा होती है तो सूखे के कारण स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है। रेखा चित्र 2.3 में तापमान की विभिन्नता दर्शाई गई है।

वर्षा : (RAIN FALL)

जिला टीकमगढ़ की वार्षिक वर्षा 1000 मि.मी. है। निवाड़ी तहसील की अपेक्षा टीकमगढ़ तहसील में अपेक्षाकृत वर्षा का औसत (प्रतिदशक) बढ़ा है अर्थात उत्तर में दक्षिणी भाग की तुलना में कम वर्षा होती है। मानचित्र 2.3 तथा 4 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में वर्षा की विषमतायें अधिक है। सन् 1973-74 में 798 मि.मी. वर्षा हुई जबकि 1975-76 में इससे दो गुनी अर्थात 1408 मि.मी. वारिश रिकार्ड की गई जो औसतन 1000 मि.मी. से पर्याप्त अन्तर/विषमता दर्शाती है। सारणी 2.3 में जिला टीकमगढ़ की तीन केन्द्रों पर हुई वर्षा को दर्शाया गया हे जो 20 वर्ष के औसत पर आधारित है। यहाँ अधिकांश वर्षा जुलाई तथा अगस्त माह में होती है जो कुल वर्षा का 80% है। 5% वर्षा शीतकालीन चक्रवातों द्वारा होती है। शेष वर्षा वर्ष के शेष महीनों में होती है।

सारणी क्रमांक 2.3 : जिला टीकमगढ़ में तापमान, वर्षा तथा सापेक्षिक आर्द्रता (50 वर्ष के औसत पर आधारित)

माह	तापमान (डिग्री सेल्सियस में)						वर्षा मि.मी. में			सस्पेक्षिक आर्द्रता %		
	कुण्डेश्वर		ओरछा		जतारा		कुण्डेश्वर	ओरछा	जतारा	कुण्डेश्वर	ओरछा	जतारा
	अधिक-तम	न्यूनतम	अधि-कतम	न्यून-तम	अधि-कतम	न्यून-तम						
जनवरी	22.6	6.8	21.9	6.9	22.1	6.8	16	20	12	66	68	70
फरवरी	25.2	8.8	24.6	8.6	24.9	8.7	15	14	4	56	59	68
मार्च	30.1	12.3	30.0	12.2	30.1	12.2	6	8	7	37	39	44
अप्रैल	35.2	14.2	34.8	14.0	35.0	14.1	4	4	3	27	30	31
मई	43.2	24.6	42.9	24.5	43.1	24.4	6	9	7	26	28	31
जून	41.8	21.8	40.3	21.8	41.3	21.6	114	102	10	48	50	52
जुलाई	33.6	21.5	32.8	21.7	33.4	21.5	328	295	299	78	81	79
अगस्त	31.3	19.7	31.0	20.1	31.0	20.3	300	283	283	84	86	83
सितम्बर	30.9	19.3	30.3	19.2	30.7	19.0	159	175	150	78	80	80
अक्टूबर	29.2	17.0	28.7	17.0	28.9	16.9	31	56	28	60	63	69
नवम्बर	27.2	12.8	27.1	12.6	27.1	12.7	13	6	9	51	53	67
दिसम्बर	23.7	8.1	23.5	8.0	23.6	8.1	7	9	8	61	63	77

स्रोत : कुण्डेश्वर, जतारा तथा ओरछा केन्द्रों से आभार सहित.

STRUCTURE OF RAINFALL
Isomers
Interval
Total
(August 1961-80)
in Fall in CMS.
Below 40
41 50
51 60
61 70
Over 70
No of Rainy Days
KMS.
5 0 5 10 15 20
KMS.
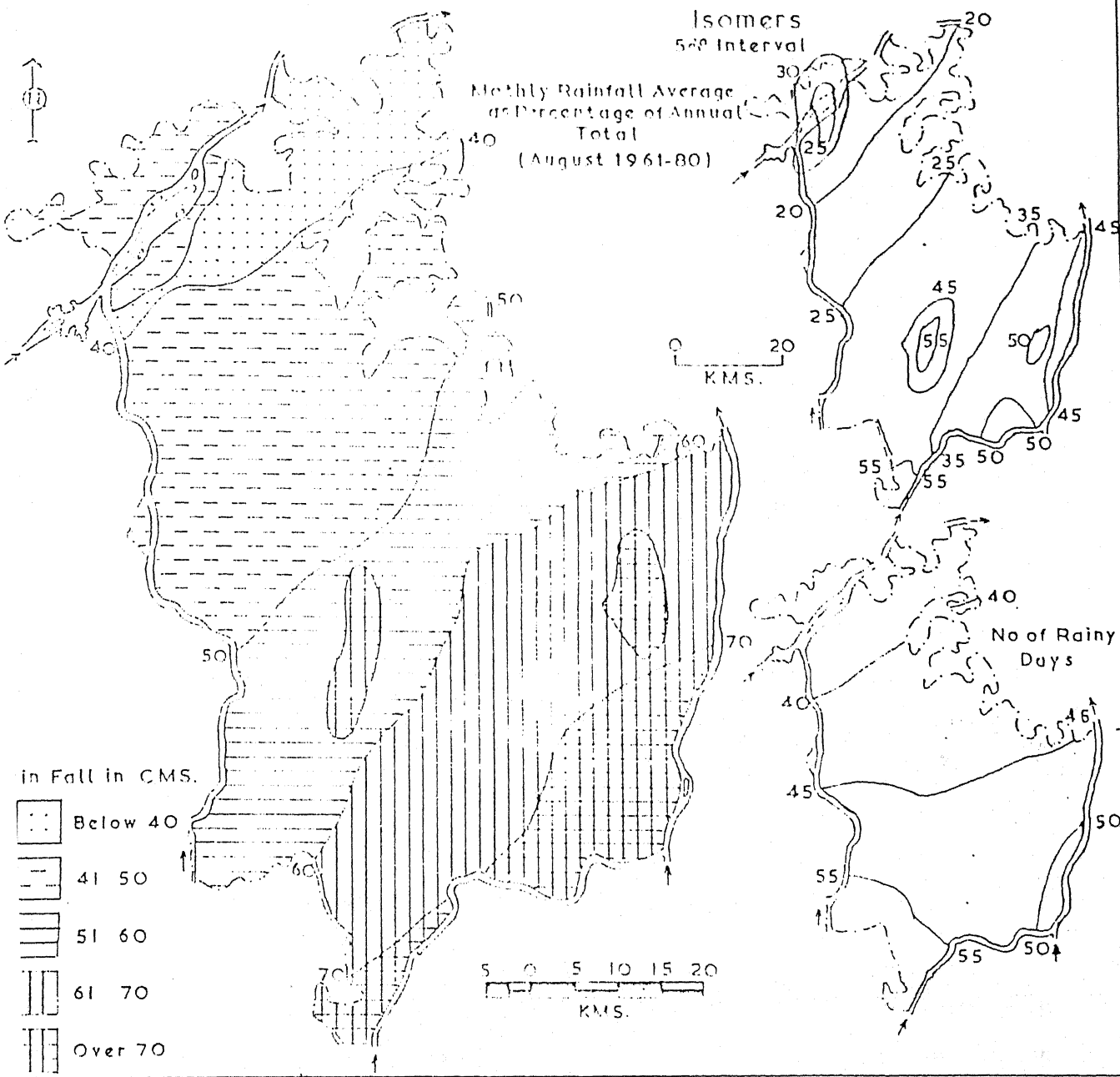
FIG 2.4

आद्रता : (HUMIDITY)

जलवायू के अन्य घटकों की भाँति आर्द्रता में भी पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है। आर्द्रता, तापमान और वर्षा पर प्रत्यक्षतः आधारित होती है यहाँ सर्वाधिक 85% आर्द्रता अगस्त के महीने में पाई जाती है। सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर में क्रमशः 78%, 68%, 59% तथा 64% आर्द्रता पाई जाती है। तापमान की अधिकता, गर्म हवाओं के प्रकोप के कारण मई (28%) तथा अप्रैल (38%) न्यून आर्द्रता पाई जाती है।

हवायें : (WINDS)

अध्ययन क्षेत्र में शीतकाल में चक्रवातीय प्रभाव को छोड़कर तथा ग्रामीण काल में मई तथा जून माह में तेज हवायें नहीं चलती। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जाती है। हवाओं की गति भी बढ़ती जाती है। सामान्यतया वर्षा भर यहाँ 3-5 कि.मी. प्रति घंटे की गति से हवायें चलती है। मई तथा जून के महीनों में दोपहर के बाद अति गर्म हवा 10-15 कि.मी. प्रति घंटे की गति से चलती है जिसे 'लू' कहते हैं। यह हवा मानसून के आने तक चलती रहती है। वारिष होने के आधे घंटे पूर्व 50-60 या कभी-कभी 100 कि.मी. प्रति घंटे की गति से आँधी चलती है। इसके अतिरिक्त वर्षा भर क्षेत्र में हवायें शान्त रहती है।

5. प्राकृतिक - वनस्पति : (NATURAL VEGETATION)

किसी भू-भाग को प्राकृतिक वनस्पति हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। यह प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने पर आश्चर्य और न्यून मात्रा में होने पर दुखः पहूँचाती है।[9] जो मानव से नैसर्गिक संबंध स्थापित करती है। अतः पर्यावरण के संतुलन के लिये किसी क्षेत्र में एक निश्चित अनुपात में प्राकृतिक वनस्पति होनी चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति उस प्रदेश की जलवायु की कुंजी होती है।[10] तथा वातावरण के विभिन्न स्वरुपों

एवं उच्चावचों से सामंजस्य स्थापित करती है।

जिला टीकमगढ़ में वनों का 5.27 प्रतिशत है जो बहुत कम है। कृषि के विस्तार ने पिछले दशकों में वन्य भूमि को बड़ी तेजी से समाप्त किया है। प्राप्त कुल वनों में वनस्पति की विविधता दिखाई देती है। इसमें साल, सागौन, शीशम, महुआ, आम, बबूल, खेर आदि प्रमुख है। स्थानीय माँग के कारण यहाँ के वनों की अंधाधुंध कटाई की गई जिससे जंगली क्षेत्र समाप्त हो गये है। यहाँ वन विकास के लिये नौ स्थानों पर नर्सरी विकासित की गई है। अध्ययन क्षेत्र में वनों से तेन्दूपत्ता, आयुर्वेदिक औषधियाँ, गौंद, खेर, अचार आदि लकड़ी के अतिरिक्त महत्वपूर्ण उत्पाद मिलते हैं।

6. मिट्टी संसाधन : (EDAPHIC RESOURCES)

शैलों का वह परिवर्तित रुप जो टूट फूटकर मुलायम ओर असंगठित कणों एवं सड़े गले वनस्पतिक/जैविक पदार्थों से निर्मित होती है।[8] अध्ययन क्षेत्र की मिट्टियों को चार भागों में विभाजित किया गया है। जो मुख्य रुप से ओरछा उच्चभूमि (विन्ध्यन के पठार) के अपरदन द्वारा विकसित हैं या स्थानीय क्षेत्रों पर अपरदन का परिणाम हैं। जो घाटी या निम्न क्षेत्रों के तल पर जम गई है। मानचित्र 2.5 में मिट्टियों के स्थानीय वितरण को दर्शाया गया है।

1. आद्य कालीन तथा धारवाड़ युगीन शैलों पर निर्मित मिश्रित काली तथा पीली मिट्टियाँ।
2. लाल एवं भूरी मिट्टियाँ।
3. पुनर्निक्षेपित घाटियों वाली मिश्रित काली, लाल तथा पीली मिट्टियाँ।
4. बालू काश्म तथा शैल की क्षेत्रीय लाल एवं भूरी मिट्टियाँ।
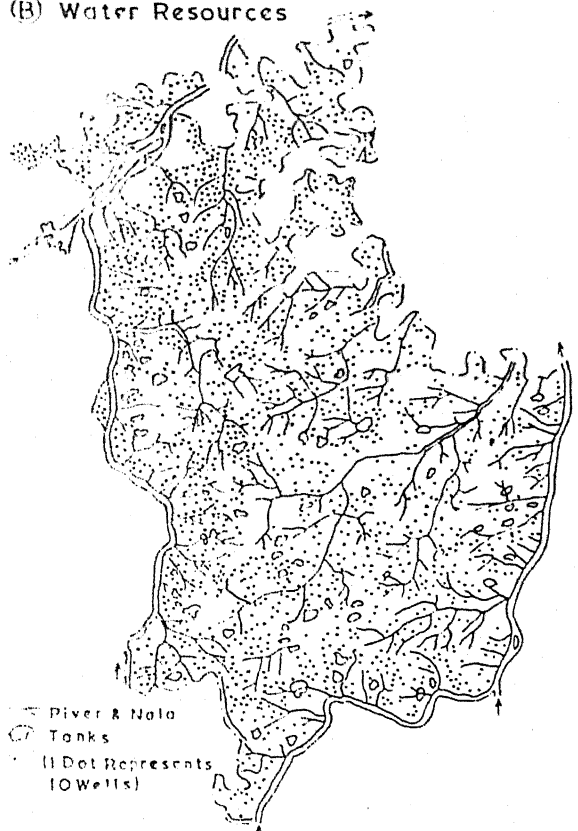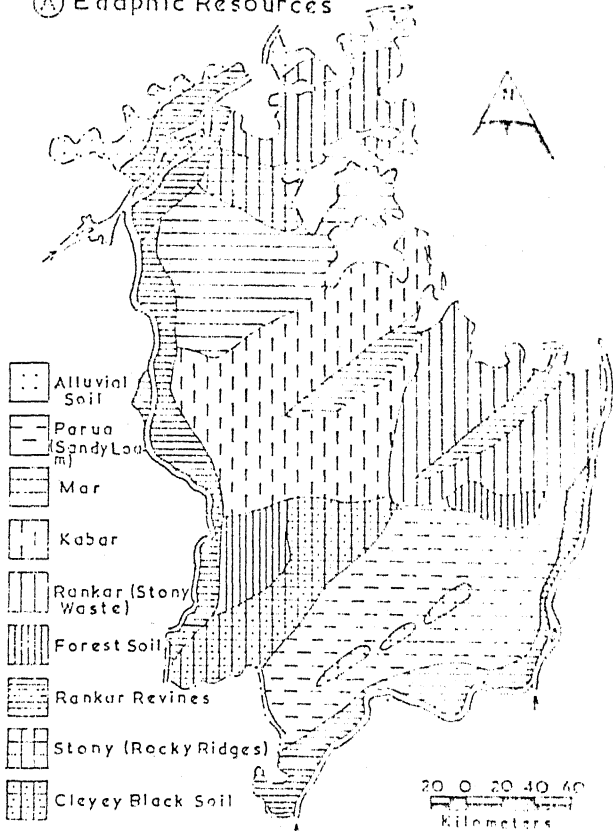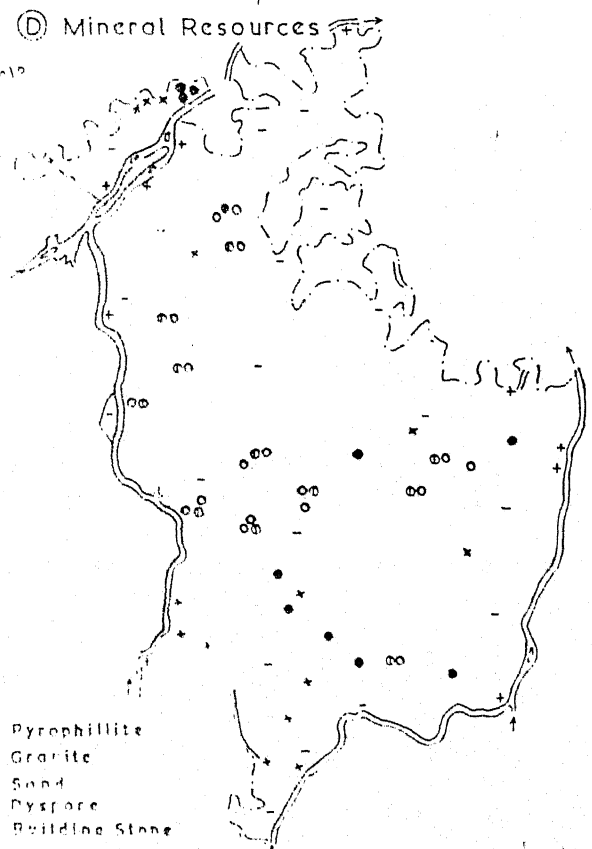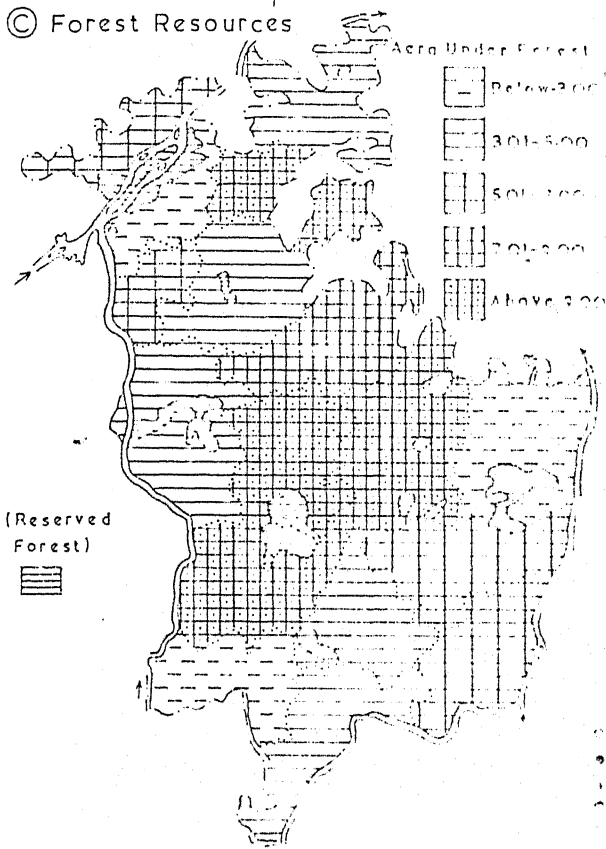
अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में आद्यकालीन व धारवाड़ युगीन मिट्टियाँ पाई जाती है। जिन्हें स्थानीय भिन्नता के अनुसार मार एवं काबर के नाम से जाना जाता है। लाल तथा भूरी मिट्टियाँ यहाँ सबसे बड़े क्षेत्रफल पर वितरित हैं। ये अपेक्षाकृत कम ऊपजाऊ है। क्षेत्र की पठारी स्थिति होने के कारण इनकी गहराई ज्यादा नहीं है। लेकिन क्षेत्र के तीन चौथाई भू-भाग पर इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। स्थानीय विभिन्नता के अनुसार इन्हें वनक्षेत्र की मिट्टियाँ तथा राकड़ मिट्टी में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र में नदी घाटी के निकट एवं उत्तरी भाग में जलोढ़ मिटिटयाँ पाई जाती है।

सामन्यतः जिला टीकमगढ़ की मिट्टियों की पर्त पतली होने के कारण इनमें अपरदन बहुत अधिक हुआ है।

7. खनिज : (MINERALS)

अध्ययन क्षेत्र में निम्न खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों का अभाव पाया जाता है। यहाँ पाइरोंक्लाइट, डाइस्पोर, ग्रेनाइट, रेत एवं मोरम प्रचुरता में उपलब्ध हैं। पाइरोफ्लाइट एवं डाइसपोर उस क्षेत्र में कांरी, खुमानगंज, गुड़ापाली, बैरवारा, महेन्द्र महेवा, धामना, देवरदा, खैरा, नदनवारा, मड़खेरा, राजापुर, लड़वारी, मऊ, चन्द्रपुरा रामगढ़, कूँवरपुरा, अहार आदि ग्रामों की पहाड़ियों में पाये जाते है। गेनाइट की प्रधानता के कारण सम्पूर्ण भूभाग में ग्रेनाइट पत्थर आसानी से उपलब्ध है। जिसका उपयोग भवन, सड़क तथा पुलों के निर्माण में किया जाता है। रेत अध्ययन क्षेत्र की उर, धसान तथा अन्य मौसमी नदियों से प्राप्त होती है और मुरम यहाँ सर्वथा उपलब्ध है जो कच्चे मकानों के निर्माण, ईट बनाने में काम आती है।

8. कृषि : (AGRICULTURE)

1) भूमि उपयोग : (LAND UTILIZATION)

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र की भूमि उपयोग की ऐसी रुपरेखा प्रस्तुत करना है। जिसमें स्थानीय भूमि का प्रत्येक भाग अधिकतम बहु प्रयोजित उपयोग है। और स्थानीय भूमि का कोई भाग बेकार न पड़ा रहे।[9]

अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग का अध्ययन राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर किया गया है जिसके अन्तर्गत वन, (5.27%), कृषि के लिये अयोग्य भूमि (35.79%), कृषि योग्य भूमि (4.0%), पड़ती भूमि (6.26%) तथा फसल का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (48.68%) पाया जाता है। सरणी 2.4 तथा मानचित्र 2.5 में अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग का वितरण दर्शाया गया है।

जिला टीकमगढ़ में वर्ष 1992-93 में वनों के अन्तर्गत मात्र 5.27% क्षेत्र आता है। यहाँ सर्वाधिक वन दिगौड़ा (12.04%) तथा सब से कम वन क्षेत्र समर्रा (0.66%) राजस्व निरीक्षक मण्डलों में है। जिले में कृषि के लिए अयोग्य भूमि 35.79% पाई जाती है। इसके अन्तर्गत जलाशय/तालाब, अधिवास, सड़कें एवं पर्वतीय भू-भाग शामिल है। बड़ागाँव में इस प्रकार की भूमि सर्वाधिक तथा जतारा रा.नि.मण्डल में सबसे कम पाई जाती है। जिले में पड़ती भूमि का प्रतिशत 6.26% है। जिसमें वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत जिले के 48.68% भाग शामिल है। जिसमें सर्वाधिक जिले का उत्तरी क्षेत्र तथा न्यूनतम दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र आता है। अध्ययन क्षेत्र में 1,93,994 हेक्टेयर भूमि खरीफ फसलों के अन्तर्गत, जिसमें मोटे अनाजों के साथ धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली की फसलें प्रमुखता में बोई जाती है। जबकि रबी फसलों में गेहूँ की फसल का सबसे बड़ा भाग आता है। अध्ययन क्षेत्र 85% कृषि योग्य भूमि में दोहरी फसल के रुप

सारणी 2.4 : जिला टीकमगढ़ में भूमि उपयोग 1995

क्रम संख्या	राजस्वत नि. मण्डल	वन भूमि	कृषि केलिए अयोग्य भूमि	कृषि योग्य भूमि	पड़ती भूमि	शुद्ध बोया गया क्षेत्र
1.	ओरछा	5.27	35.27	4.0	6.26	48.68
2.	निवाड़ी	9.36	32.55	2.05	8.61	47.53
3.	तरीचरकलॉ	4.25	22.74	3.27	4.16	65.58
4.	नैगुवॉ	1.07	36.35	5.62	6.11	50.85
5.	सिमरा	5.12	33.85	7.45	6.76	46.82
6.	पृथ्वीपुर	4.05	34.78	4.07	5.0	52.10
7.	मोहनगढ़	4.20	35.89	4.20	7.13	48.58
8.	लिधौरा	8.15	28.02	6.48	7.05	50.30
9.	दिगौड़ा	12.04	29.77	5.18	5.33	47.68
10.	जतारा	9.11	22.47	6.12	5.91	56.39
11.	पलेरा	2.65	25.88	3.28	3.87	64.32
12.	टीकमगढ़	10.83	25.57	6.22	8.03	49.35
13.	समर्रा	5.66	22.85	4.20	7.84	63.46
14.	बड़ागाँव	3.03	37.45	2.58	11.93	45.01
15.	बल्देवगढ़	4.10	31.35	2.04	10.11	52.40
16.	कुड़ीला	5.26	30.05	7.27	14.12	43.30
17.	खरगापुर	5.11	28.23	5.05	8.64	52.97
	जिला टीकमगढ़	**5.27**	**35.79**	**4.0**	**6.26**	**48.68**

स्रोत : कार्यालय भू-राजस्व, जिला टीकमगढ़ से साभार

District Tikamgarh
LAND UTILIZATION 1991-92
N
Region as a Whole
Not To The Scale
Categories
Forests
Area Not Available For Cultivation
Other Agricultural Land
Fallow Land
Net Area Sown
Area in Hectare
34001 - 41000
27001 - 34000
20001 - 27000
13000 - 20000
5 0 5 10 15
Kilometers
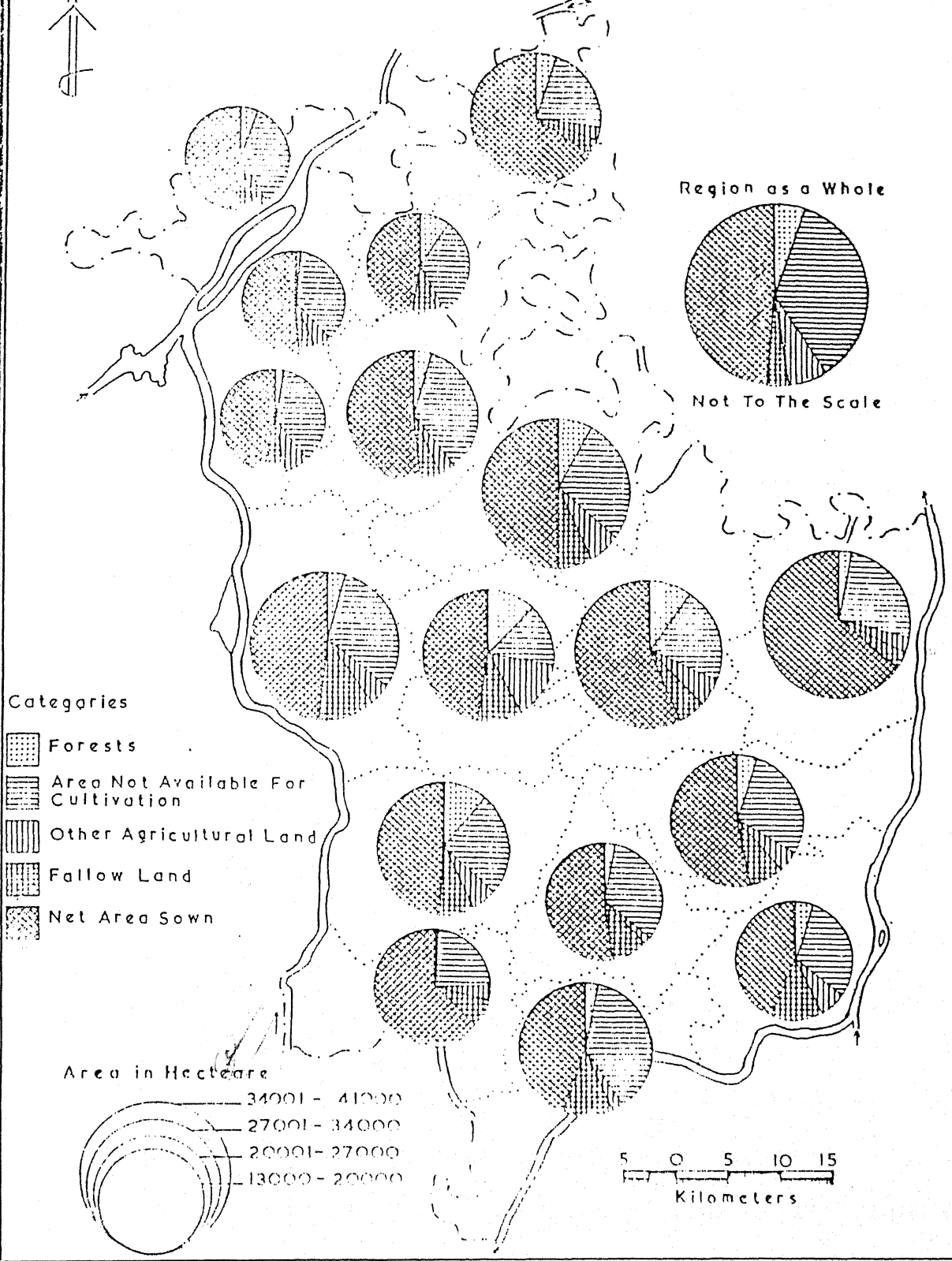
FIG 2.6

में रबी में बोई जाती है इसके अतिरिक्त, तिलहन (सरसों), दलहन- मक्का, चना तथा मसूर आदि उल्लेखनीय फसलें है। मानचित्र 2.6 में रबी तथा खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रीय वितरण को राजस्व मण्डल वार दर्शाया गया है।

2) भूमि उपयोग क्षमता : (LAND USE EFFICIENCY)

भूमि संसाधन उपयोग किस चातुर्य एवं तत्परता से किया जा रहा है, यह उस स्थान के आपसी तत्वों ओर क्रिया कलापों के अन्र्तसम्बन्धों पर आधारित होती है।[10] वग[11] ने भूमि उपयोग क्षमता से आशय भूमि संसाधन इकाई की उत्पादन क्षमता से लिया है। जिसमें उत्पादन लागत की अपेक्षा शुद्ध कार्य किया जाता है। जोनसन[12] ने के अनुसार

सारणी क्र. 2.5 : जिला टीकमगढ़ में भूमि उपयोग क्षमता (1995)

भूमि उपयोग क्षमता का क्रम	कोटि गुणांक	राजस्व निरीक्षक मण्डलों की संख्या	प्रतिशत
1. उच्चतम क्षमता	4 - 8	3	17.65
2. उच्च क्षमता	8 - 10	5	29.41
3. सामान्य क्षमता	10 - 12	4	23.53
4. न्यून क्षमता	12 - 14	2	11.76
5. न्यूनतम क्षमता	14 - 16	3	17.65
		17	**100.00**

कृषिगत भूमि उपयोग क्षमता से तात्पर्य उस प्रभावोत्पादक क्रिया से है जहाँ पूँजी तथा श्रम के क्रमिक उपयोग के आधार पर भूमि उत्पादन मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती है। जसवीर सिंह[13] के अनुसार भूमि उपयोग क्षमता से तात्पर्य कुल उपलब्ध भूमि में बोई गई भूमि के प्रतिशत से

है। इसी प्रकार वी.पी.सिंह[14] ने एक ओर कृष्य भूमि अथवा कृषिगत तथा दूसरी ओर सिंचित एवं वृद्धि फसल क्षेत्र से तुलना की है। आर.बी.सिंह[15] ने भूमि उपयोग क्षमता का प्रत्यक्ष कोटि गुणांक विधि के आधार पर आंकलन किया है। जिसमें कृषिगत क्षेत्र, अकृष्य क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, द्वि-फसली क्षेत्र तथा शस्य-तीव्रता को कोटि गुणंक गणना हेतु चुना है। सिंह के उसी आधार पर जिला टीकमगढ़ में भूमि उपयोग क्षमता का परिकलन किया गया है। जिसे सारणी 2.5 तथा मानचित्र 2.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.5 तथा मानचित्र 2.7(ए) से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के लिधौरा, तरीचरकलाँ तथा सिमरा राजस्व निरीक्षक मण्डलों में उच्चतम भूमि उपयोग क्षमता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र की अधिकता के कारण उच्चतम भूमि उपयोग क्षमता पाई जाती है। निम्न तथा न्यूनतम भूमि उपयोग क्षमता खरगापुर, कुड़ीला, जतारा तथा टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डलों में पाई जाती है। शेष क्षेत्र में सामान्य भूमि उपयोग क्षमता पाई गई है।

3) शस्य तीव्रता : (CROPPING INTENSITY)

एक वर्ष में इकाई कृषिगत भू-भाग पर बोई गई कुल फसलों के पारस्परिक संबंध को शस्य तीव्रता कहते हैं। जोशी[15] ने शस्य तीव्रता की धारणा को निम्न लिखित सूत्र द्वारा निरुपित किया है।

$$\text{शस्य तीव्रता सूचकांक} = \frac{\text{कुल फसली क्षेत्र (TCI)}}{\text{शुद्ध फसली क्षेत्र (NCI)}} \times 100$$

(यहाँ सूचकांक 100 से तात्पर्य एक वर्ष में एक फसल बोये जाने से है) 100 से अधिक सूचकांक होने पर दो या दो से अधिक फसल क्षेत्र का होना है। जिला टीकमगढ़ में (मान चित्र 2.7 सी) शस्य तीव्रता दर्शायी गई है जिसके अनुसार अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग में शस्य तीव्रता कम पाई जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र में बेतवा, जामनी और उनकी

Tikamgarh District
(A) Efficiency of Land Use
Very High
High
Moderate
Low
Very Low
(B) Crop Diversity
High
Moderate
Low
Very Low
N
(C) Crop Combination Regions
Wheat+Jowar+Paddy+Soyabean+Gram+
Gram+Wheat+Oilseed+Soyabean+Paddy
Jowar+Paddy+Wheat+Gram+Pulses
Paddy+Gram+Pulses+Jowar+Wheat
(D) Cropping Intensity
Very High
High
Moderate
Low
Very Low
10 0 10 20
Kilometers
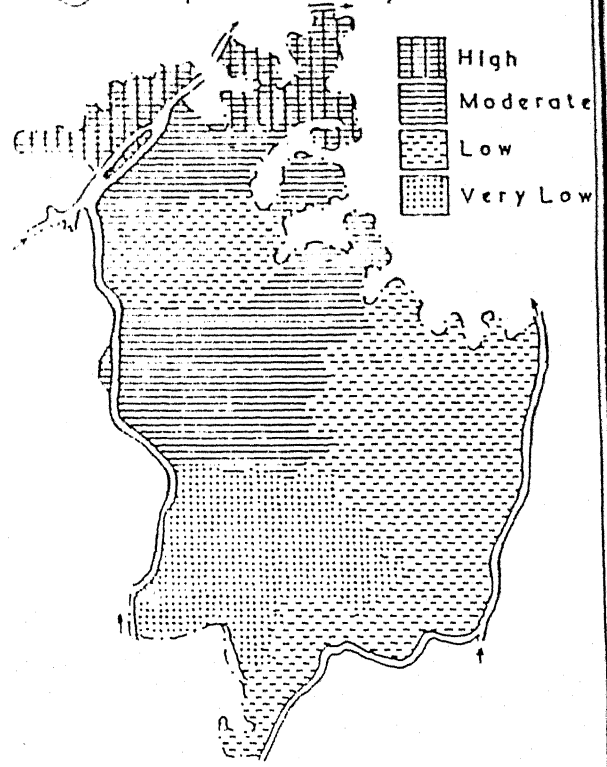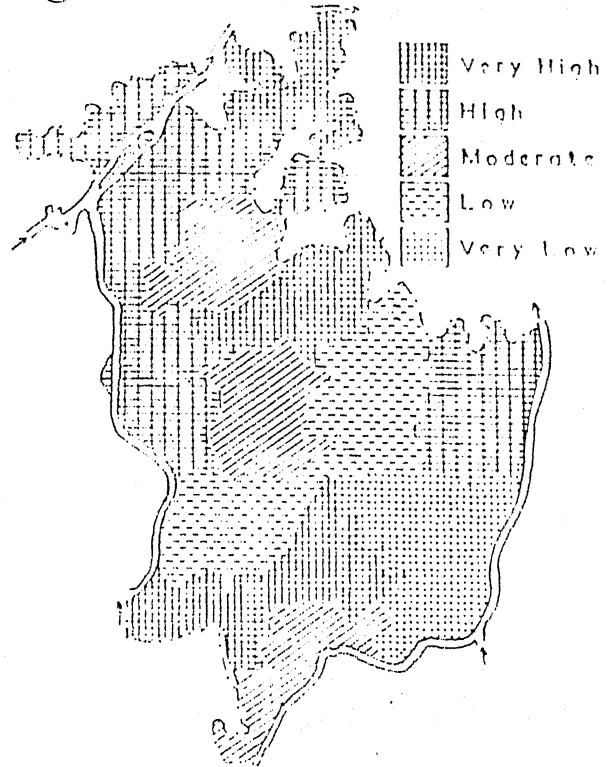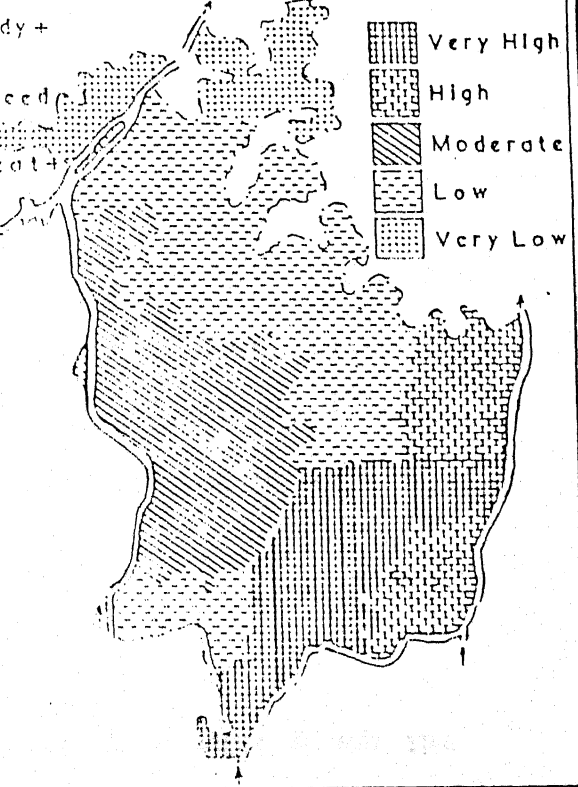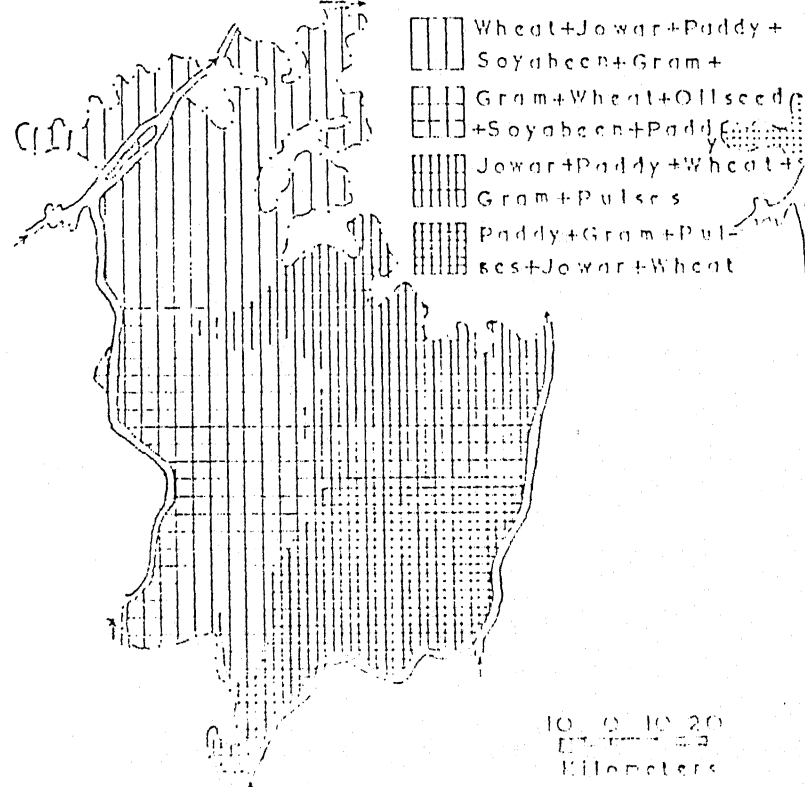
FIG 2.7

सहायक नदियों में भारी मात्रा में अपरदन किया है जिससे सिंचाई की सुविधा सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। इसके विपरीत दक्षिणी मध्य भाग में सिंचाई के साधनों की प्रचुरता के कारण शस्य तीव्रता अधिक पाई जाती है।

4) शस्य विविधता : (CROP DIVERSITY)

इकाई भू-भाग पर एक वर्ष में कुल बोई गई फसलों की संख्या को शस्य विविधता कहते है। कुल बोई गई फसलों की संख्या के बढ़ने से शस्य विविधता भी बढ़ती जाती है। भाटिया[16] ने इस हेतु निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया है।

$$\text{शस्य विविधता सूचाकांक} = \frac{\text{क्ष फसलों के अन्तर्गत कुल फसली क्षेत्र का प्रतिशत}}{\text{कुल फसलों की संख्या}} \times 100$$

यहाँ क्ष फसलों से तात्पर्य ऐसी फसलों से है जिनका प्रतिशत 10 से अधिक है। शस्य विविधता शस्य तीव्रता की व्युक्रमानुपाती होती है। अर्थात सूचकांक जितना अधिक होगा शस्य विविधता उतनी ही कम होगी। मानचित्र 2.7 ब के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में शस्य विविधता कम तथा उत्तरी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। यहाँ के किसान मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाये रखने के लिये शस्यावर्तन के रुप में एक ही खेत में फसलों के क्रम को बदल देते है। इसके विपरीत सिंचाई की सुविधाओं के निरंतर विस्तार के कारण क्षेत्र में शस्य विविधता की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

5) शस्य संयोजन प्रदेश : (CROP COMBINATION REGION)

किसी क्षेत्र की कृष्य विषमताओं को स्पष्ट रुप से समझने के लिये शस्य

संयोजन प्रदेशों का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। जेम्स तथा जोंस[17] ने शस्य संयोजन के अभाव में क्षेत्रीय कृषि प्रणाली की विशेषताओं को ठीक से न समझे जाने और क्षेत्रीय कल्पना के विना कृषि प्रदेश विभाजन की दशा में संतोषजनक विश्लेषण न होने की बात की है। इसी तरह किसी प्रदेश/क्षेत्र का शस्य संयोजन वहाँ की प्राकृतिक, सामजिक और आर्थिक वातावरण की देन हेाता है।[18] अभी तक बेकर[19], जोनासन[20], वीवर[21] ने इस विषय पर कार्य किया है वीवर ने शस्य संयोजन के निर्धारण हेतु मानक विचलन विधि का प्रयोग किया। वीवर के उपरान्त कोपोक[22], जोनासन[23], स्कार्ट[24] और पावेल[25] ने शस्य प्रतिरुपों को निर्धारित करने का कार्य किया इसके अतिरिक्त बनर्जी[26], सिंह[27], अय्यर[28] पाण्डे[29], रफी उल्लाह[30] तथा दोई[31] ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को शस्य संयोजन प्रदेश विभाजित किया है। प्रस्तुत अध्ययन में दोई द्वारा प्रयुक्त विधितंत्र को अपनाया गया है। तथा शस्य संयोजन की गणना चतुर्थकोणीय फसलों को ही गणना में किया गया है। अन्य मोटे अनाजों को चतुर्थ कोटि में, गेहूँ एवं ज्वार को प्रथम कोटि में, दलहन को द्वितीय तथा तिलहनों को तृतीय कोटि में रखा गया है। जिसे मानचित्र 2.7 सी में दर्शाया गया हे ।

6) शस्य श्रेणीकरण : (CROP RANKING)

किसी क्षेत्र के शस्य प्रतिरुप में संबंधित फसल की महत्ता ज्ञात करने के लिये फसलों का श्रेणीकरण किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में सारणी 2.6 तथा मानचित्र 2.8 में फसलों के श्रेणीकरण को दर्शाया गया है। इस श्रेणीकरण में 1% से कम में बोई गई फसल को शामिल नहीं किया गया है।

District
CROP RANKING
A
B
Second Rank
C
Third Rank
D
Fourth Rank
E
F
Sixth Rank
N
Soyabeen
Gram +
40
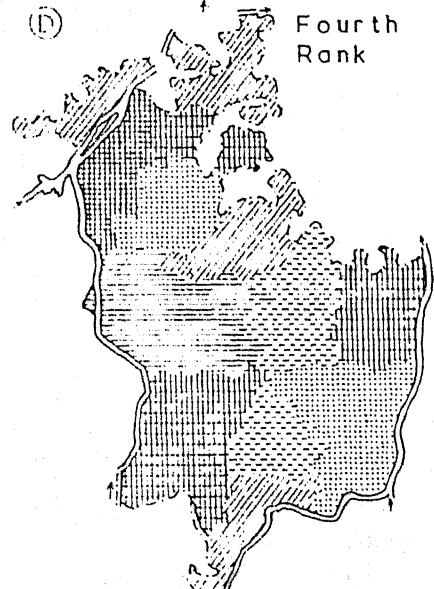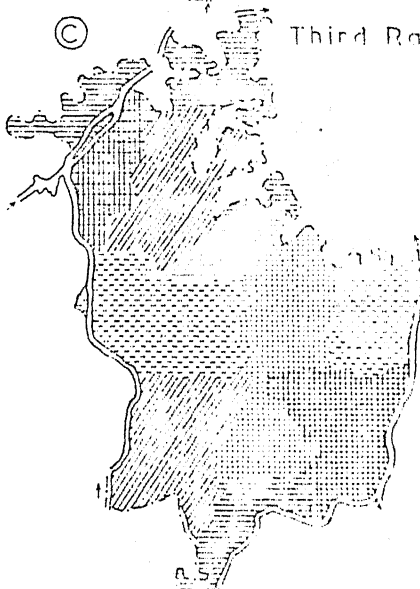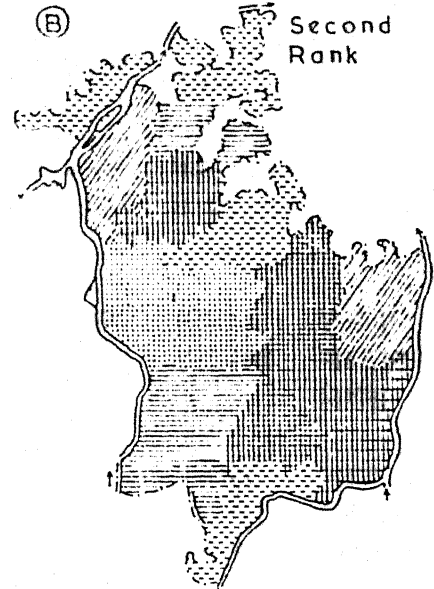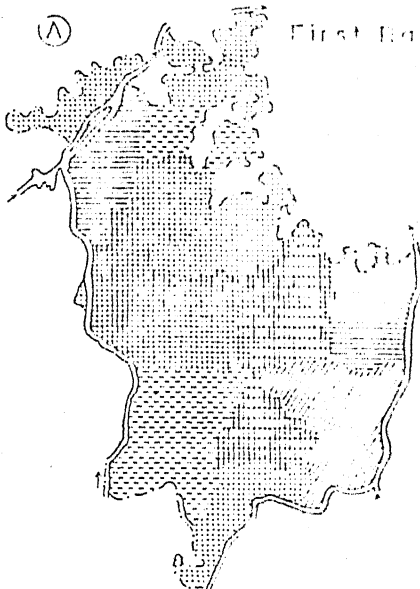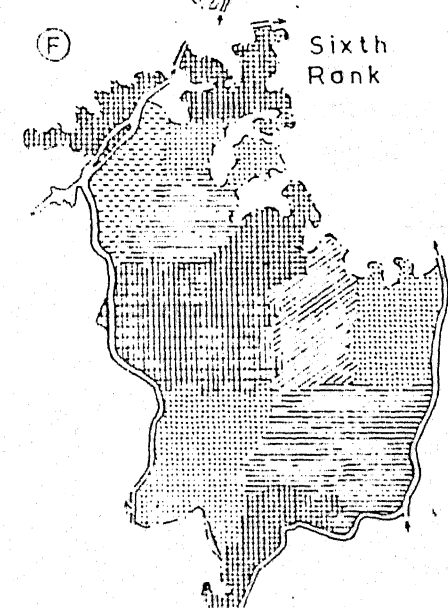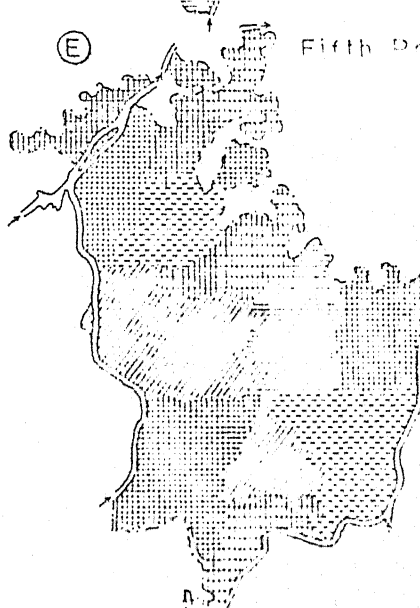
सारणी क्रमांक 2.6 : जिला टीकमगढ़ में शस्य श्रेणीकरण 1995.

क्र.सं.	श्रेणी	गेहूँ	सोयाबीन	धान	गेहूँ+चना	मक्का,ज्वार व मूँगफली	चना,मटर मसूर
1.	प्रथम	ओरछा, लिधोरा बड़ागॉव	टीकमगढ़ निवाड़ी समर्रा	नैगुवॉ सिमरा पलेरा	खरगापुर कुडीला	जतारा बल्देवगढ़	पृथ्वीपुर मोहनगढ़ दिगोड़ा
2.	द्वितीय	मोहनगढ़ दिगौड़ा	ओरछा तरीचरकलॉ लिधोरा बड़ागाँव	निवाड़ी टीकमगढ़ समर्रा	नैगुवाँ सिमरा पलेरा	पृथ्वीपुर खरगापुर कुड़ीला	जतारा बल्देवगढ़ बल्देवगढ़
3.	तृतीय	जतारा बल्देवगढ़ पलेरा	मोहनगढ़ दिगौड़ा	ओरछा तरीचरकलॉ लिधौरा बड़ागाँव	निवाड़ी टीकमगढ़ समर्रा पृथ्वीपुर	नैगूँवा सिमरा	खरगापुर कुड़ीला
4.	चतुर्था	पृथ्वीपुर खरगापुर कुड़ीला	जतारा बल्देवगढ़	मोहनगढ़ दिगौड़ा समर्रा	ओरछा तरीचलकलॉ लिधौरा बड़ागाँव	निवाड़ी पलेरा टीकमगढ़	नैगुवाँ सिमरा
5.	पंचम	नैगुवा सिमरा	पृथ्वीपुर खरगापुर कुड़ीला	जतारा बल्देवगढ़	मोहनगढ़ दिगौड़ा	ओरछा तरीचरकलॉ लिधौरा बड़ागाँव	निवाड़ी पलेरा टीकमगढ़ समर्रा
6.	षष्ठम	निवाड़ी टीकमगढ़ समर्रा	नैगुवॉ सिमर्रा	पृथ्वीपुर खरगापुर कुड़ीला	जतारा पलेरा लिधौरा	मोहनगढ़ दिगौड़ा	ओरछा तरीचरकलॉ बड़ागाँव

स्रोत : अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त समंकों पर आधारित।

7) कृषि उत्पादकता : (CROP PRODUCTIVITY)

प्रति इकाई या हेक्टेयर से प्राप्त होने वाली कृषि उत्पादन मात्रा को कृषि उत्पादकता कहते है। यह उपज या उत्पादकता, स्थानीय मिट्टियों उनमें दी गई उर्वरकों की मात्रा, सिंचाई तथा अन्य लागत जैसे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का उपयोग मशीनीकरण से सीधे तौर पर प्रभावित होती है। कृषि उत्पादकता भौतिक, आर्थिक एवं अन्य कारकों से प्रभावित होकर स्थानीय कृषि क्षमता को निर्धारित करती है।[32] कृषि उत्पादकता निर्धारित करने के लिये कैन्डाल[33], वक[34], स्टाम्प[35], शफी[36], भाटिया[37], हुसैन[38], सप्रे तथा देशपाण्डे[39], एन्थेडी[40], शफी[41], शिन्दे[42] तथा विद्यानाथ [43] ने अलग विधितंत्रों का निर्माण किया है। अध्ययन क्षेत्र की उत्पादकता का परिकल्पना शफी द्वारा प्रयुक्त सूत्र द्वारा की गई है। जो भारतीय क्षेत्र के लिये सर्वथा उपयुक्त है।

$$\text{उत्पादकता सूचकाँक} = \frac{YW}{t} + \frac{Yn}{T} \; \ldots n$$

$$\text{अथवा} \quad \frac{YWi}{t} + \frac{Yrt}{T} \; \ldots n$$

$$\text{अथवा} \quad \frac{y}{t} : \frac{Y}{t}$$

Y/Yw अथवा **Ywi** = इकाई क्षेत्र फसलों का उत्पादन

Y/Yr अथवा **Yri** = सम्पूर्ण प्रदेश में उत्पादन

t = इकाई क्षेत्र में फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल

T = सम्पूर्ण प्रदेश के फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल

अध्ययन क्षेत्र में न्यून कृषि उत्पादन प्रमुख समस्या है जो स्थानीय कृषि आर्थिकी को प्रभावित करती है। न्यून उत्पादन के कारण यहाँ के 60% कृषक एवं कृषि मजदूर गरीब है यही कारण हे कि उन्नति शील कृषि में पर्याप्त विनियोग नहीं कर पाते है। अस्तु क्षेत्रीय कृषि विकास न्यून उत्पादन बिन्दु से प्रारम्भ होता हे। परिणामस्वरुप

Tikamgarh District
Indices For Level of Agricultural Development
A
Irrigational Index (It)
Q3
M
Q1
105·27
89·96
73·99
B
Double Cropped Area Index (Di)
Q3
M
Q1
151·63
122·64
100·19
Forest
N
C
Mechanisational Index (Mi)
Q3
M
Q1
93
77
59
D
Fertilizer Index (Fi)
Q3
M
Q1
142·22
101·94
81·31
0
30
KM
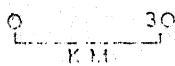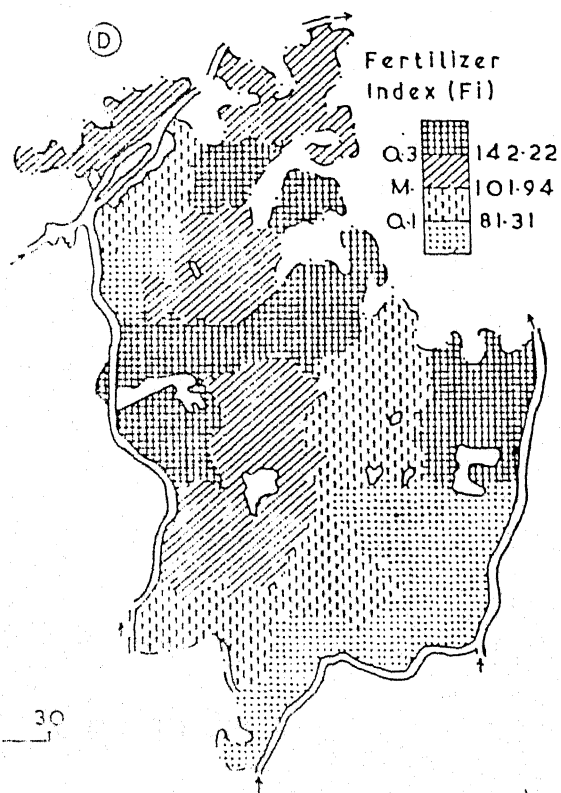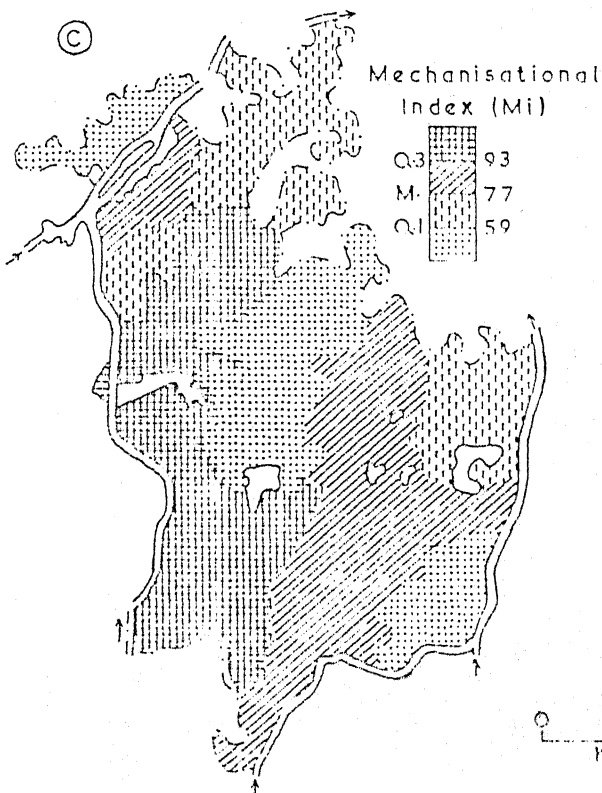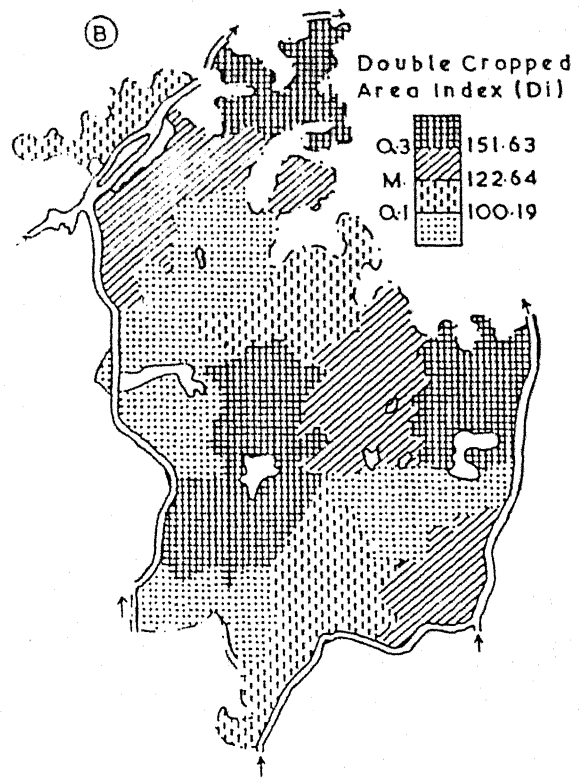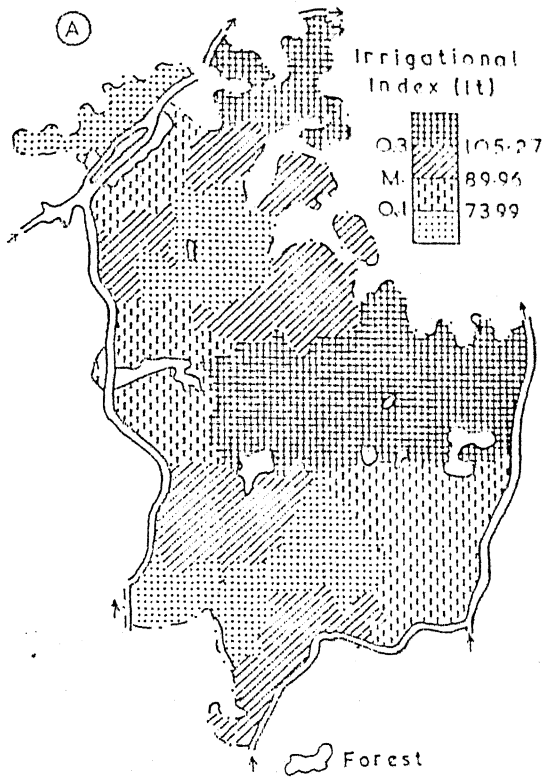
FIG 2.9

स्थानीय बाजारों में कृषि उत्पादों की पर्याप्तता समुचित नहीं रहती। जिला टीकमगढ़ में राजस्व निरीक्षक मण्डलवार कृषि उत्पादकता का आंकलन प्रदेश औसत को आधार मानकर किया गया है। जिसमें तरीचरकलाँ, सिमरा, मोहनगढ़, दिगौड़ा, पलेरा, समर्रा, बड़ागाँव, खरगापुर, रा.नि. मण्डल में उच्च कृषि उत्पादकता, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, लिधोरा, बल्देवगढ़ तथा कुड़ीला रा.नि.म. मध्यम तथा शेष में न्यून उत्पादकता पाई जाती है। मान चित्र 2.9 (ए) में कृषि उत्पादकता को दर्शाया गया है।

8) कृषि विकास स्तर : (LEVEL OF AGRICULTURE DEVELOPMENT)

कृषि भूमि विकास, स्थानीय भूमि उपयोग क्षमता, उत्पादकता एवं लागत की सीमा के आधार पर स्थानीय कृष्य विकास स्तर का आंकलन किया जा सकता है। किन्तु वांछित आंकड़ों के अभाव में यह एक कठिन कार्य है।[44] जिला टीकमगढ़ में निम्न कारकों के सम्मिलित सूचकांक द्वारा कृषि विकास स्तर का आकलन किया गया है।

1. सिंचित क्षेत्र सूचकांक =

$$\frac{\dfrac{\text{इकाई क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र}}{\text{इकाई क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र}}}{\dfrac{\text{कुल प्रदेश में सिंचित क्षेत्र}}{\text{कुल प्रदेश में बोया गया क्षेत्र}}} \times 100$$

2. बहुल फसली सूचकांक =

$$\frac{\dfrac{\text{इकाई क्षेत्र का द्विफसली क्षेत्र}}{\text{इकाई क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र}}}{\dfrac{\text{कुल प्रदेश में द्विफसली क्षेत्र}}{\text{इकाई क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र}}} \times 100$$

3. मशीनीकृत सूचकांक

$$= \frac{\dfrac{\text{इकाई क्षेत्र में यंत्रों और मशीनों की संख्या}}{\text{इकाई क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र}}}{\dfrac{\text{समग्र प्रदेश में यंत्रों और मशीनों की संख्या}}{\text{समग्र प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र}}} \times 100$$

4. उर्वरक सूचकांक

$$= \frac{\dfrac{\text{इकाई क्षेत्र में उर्वरकों की मात्रा}}{\text{इकाई क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र}}}{\dfrac{\text{समग्र प्रदेश में उर्वरकों की मात्रा}}{\text{समग्र प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र}}} \times 100$$

5. उपज सूचकांक

$$= \frac{\text{इकाई क्षेत्र में प्रति एकड़ उत्पादन}}{\text{समग्र प्रदेश में प्रति एकड़ उत्पादन}} \times 100$$

कृषि विकास स्तर का संयुक्त सूचकांक

$$= \frac{\text{सिंचित क्षेत्र सूचकांक + बहुफसली सूचकांक + मशीनकीकृत + उर्वरक + उपज}}{\text{कुल सूचकांक}}$$

उपरोक्त सूत्रानुसार जिला टीकमगढ़ के कृषि विकास स्तर का आंकलन किया गया तथा विकास के तुलनात्मक स्तर को सारणी 2.7 एवं मानचित्र 2.9 (बी) में दर्शाया गया है।
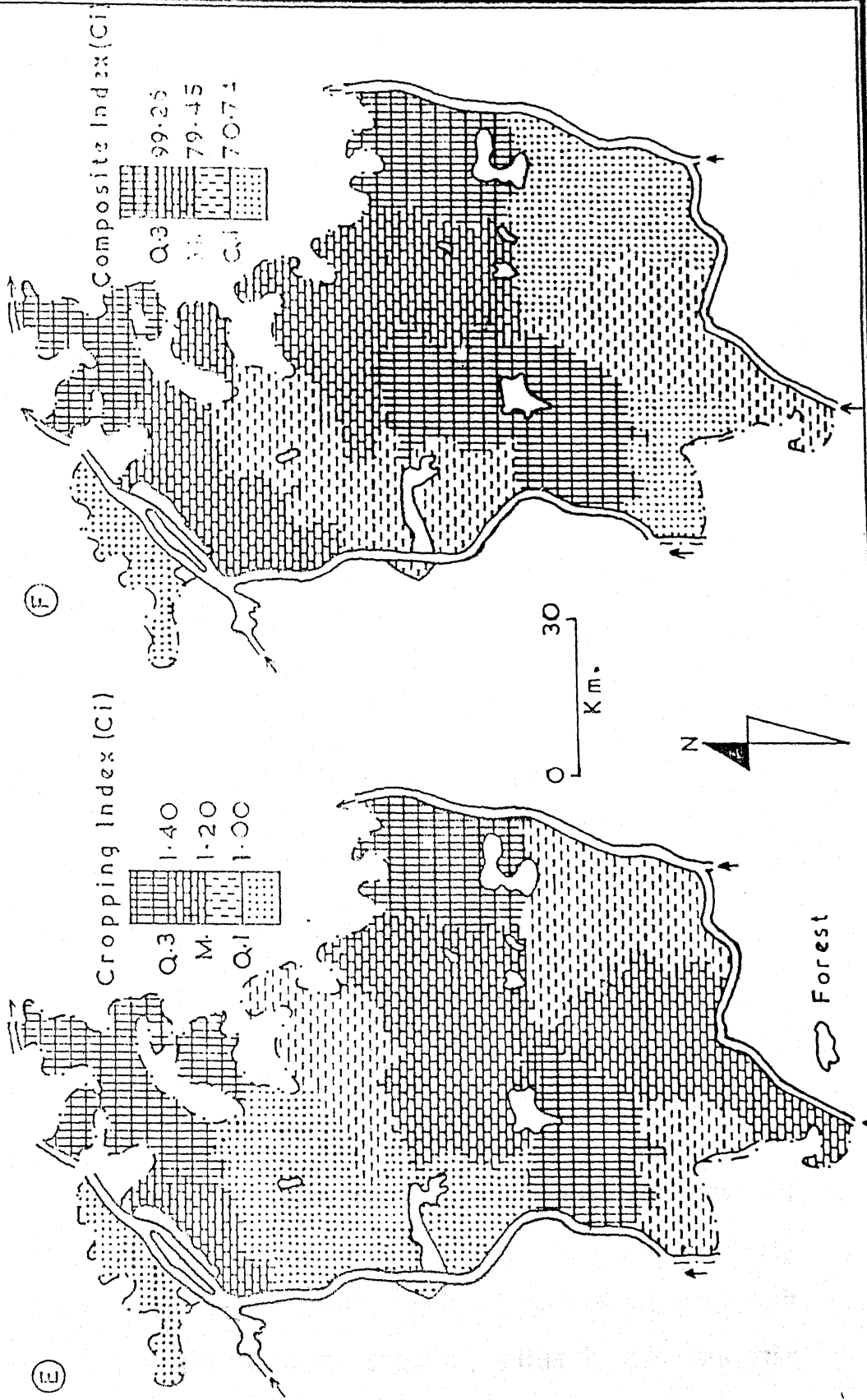
सारणी क्रमांक 2.7 : जिला टीकमगढ़ का कृषि विकास स्तर

स्तर	औसत संयुक्त सूचकांक	राजस्व निरीक्षक मण्डल	
		संख्या	नाम
उच्चतम स्तर	190 से अधिक	3	पलेरा, टीकमगढ़, तरीचरकलाँ
उच्च स्तर	90 से 100	2	निवाड़ी, दिगौड़ा
मध्य स्तर	80 से 90	3	नैगुवाँ, लिधौरा, जतारा
न्यून स्तर	70 से 80	5	सिमरा, पृथ्वीपुर, मोहनगढ़, बड़ागाँव, बल्देवगढ़
न्यूनतम स्तर	70 से कम	4	ओरछा, समर्रा, खरगापुर, कुड़ीला

उपरोक्त सारणी एवं मानचित्र से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में विकास का क्रम टूटा हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की तीव्रता, जहाँ कृषि को उद्योग का स्तर दिये जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है , वहाँ कृषि विकास अधिक है। इसके विपरीत जहाँ मिट्टियाँ अनुपजाऊ एवं कृषि को विकास का आधार बनाने हेतु कृषकों में जागरुकता या पूंजी की कमी है वहाँ कृषि विकास स्तर न्यून तथा न्यूनतम पाया जाता है।

9. उद्योग : (INDUSTRIES)

वर्तमान में किसी क्षेत्र की विशेष प्रगति उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है।[45] जिला टीकमगढ़ में आन्तरिक संसाधनों की नगण्य उपलब्धता के कारण यहाँ बृहत उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकी है। अध्ययन क्षेत्र में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना और स्थापित इकाईयों के संचालन में कच्चेमाल की कमी के कारण बड़ी अडचने सामने आ रहीं हैं। वर्तमान में कृषि पर आधारित इकाईयाँ ही, संचालित है यद्यपि जिला उद्योग

Tikamgarh District
Spatial Distribution of Industries & Industrial Workers
N
% Of Industrial Workers
Below - 4 %
4 - 6 %
6 - 8 %
8 - 10 %
Above - 10 %
1. Agro Based Industries
2. Forest Based Industries
3. Chemical Based Industres
4. Mineral Based Industres
5. Coton & Fibre Based Industries
6. Engineering Based Industres
7. Animal Based Industres
8. Other Industres
No of Industres Per/ Circle
300
200
100
No of Industries
6 0 6 12 18 24
KMS.
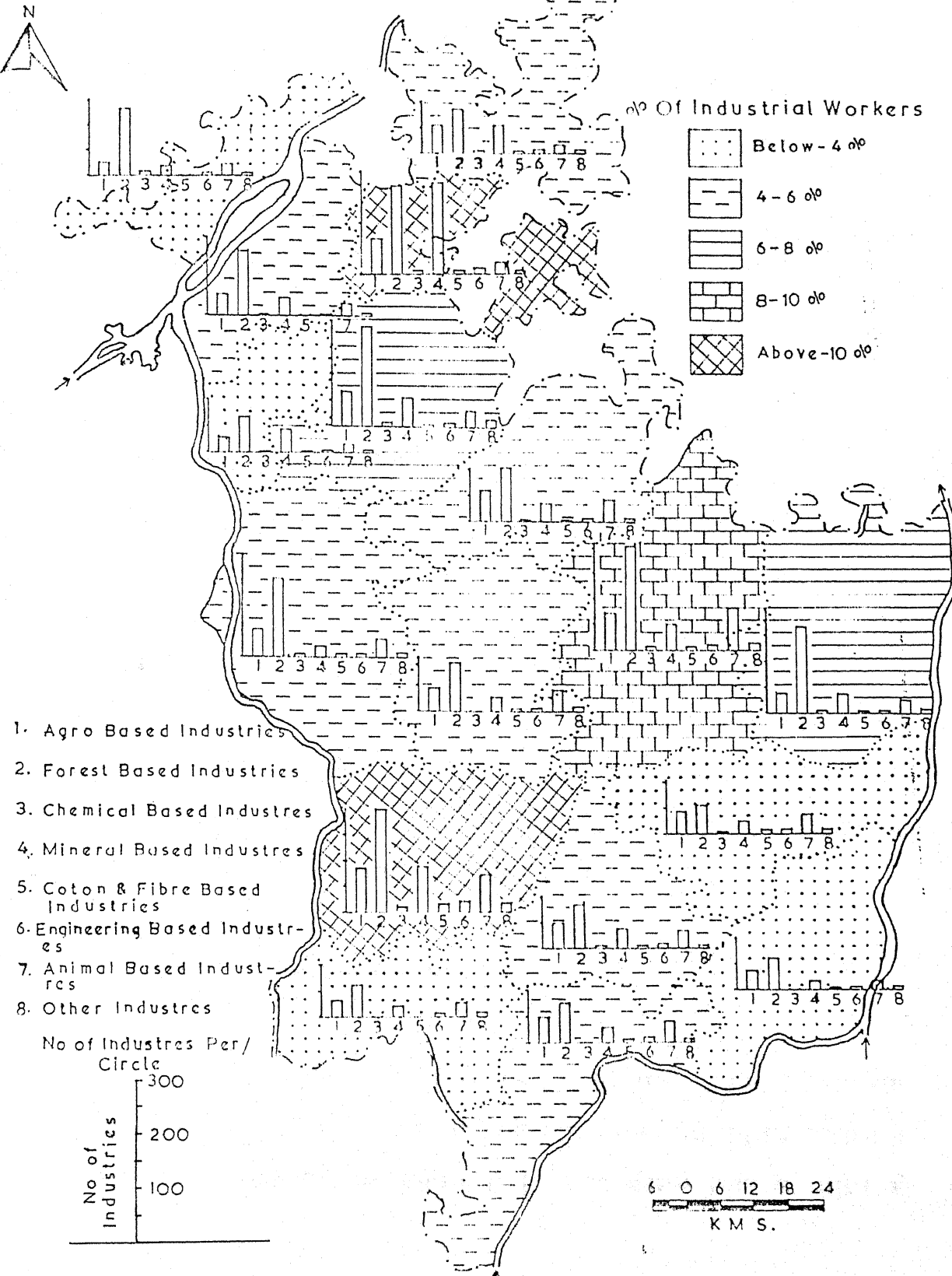
Fig 2.11

केन्द्र इस ओर प्रयासरत है कि जिले को अधिक से अधिक औद्योगिक आवरण से ढका जाय इस हेतु छोटे और मझौले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निवाड़ी विकास खण्ड के प्रतापपुरा ग्राम को औद्योगिक प्रक्षेत्र के रुप में चुना गया जहाँ उद्योगों की स्थापना निरन्तर बढ़ रही है।

जिला टीकमगढ़ के उद्योगों को स्थिति एवं धारातलीय संरचना, जलवायु, वन, जल खनिज और पशु सम्पदा के रुप में प्राकृतिक संसाधन तथा कृषि, परिवहन व्यापार एवं वाणिज्य, श्रम एवं पूंजी वैज्ञानिक समौन्नति आदि सामाजिक व्यवस्था समान रुप से प्रभावित करती है। जिला टीकमगढ़ में कृषि पर आधारित उद्योगों में गुड एवं खांडसारी, दालमिल, तेल घानी, पापड़, राईसमिल, ब्रैड एवं डबल रोटी निर्माण विशेष रुप से संचालित हैं। उद्योगों की संख्या टीकमगढ़ में 87 तथा ओरछा में 24 के मध्य पाई जाती है। वनों पर आधारित उद्योगों के अन्तर्गत लकड़ी चीरना, फर्नीचर बनाना आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण, बांस की टोकरी निर्माण लकड़ी के खिलौने एवं बीड़ी उद्योग विकसित हुये हैं। खनिजों पर आधारित उद्योगों के अन्तर्गत गिट्टी क्रेसर, गौरा पत्थर पाउडर, पत्थर हस्तकला और ईट एवं गुम्मा निर्माण सम्मिलित है इसी प्रकार वस्त्र उद्योग के अन्तर्गत रेडीमेड् वस्त्र हथकरघा सूती वस्त्र में जनता साड़ी, हैण्डलूम की चादरें एवं पावरलूम स्थापित हैं। अध्ययन क्षेत्र में वस्त्र उद्योगों की इकाई एवं उनमें रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से निवाड़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल अग्रणी है। जबकि कुड़ीला में यह उद्योग पूर्णतः अविकसित है मानचित्र 2.10 में उद्योगों का स्थानिक वितरण और औद्योगिक श्रमिकों को दर्शाया गया है।

10. जनसंख्या : (POPULATION)

मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभावी संसाधन है और मानव भूगोल के केन्द्र में स्थित है।[46] इसी लिये किसी प्रदेश की जनसंख्या प्राकृतिक पर्यावरण के समस्त प्रभाव को दर्शाती है। यह जनसंख्या ही है जो कि गतिशील प्रकृति के अस्तित्व को

अधिवासों के रुप में सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है।

1) जनसंख्या वृद्धि : (POPULATION GROWTH)

जिला टीकमगढ़ में जनसंख्या वृद्धि 1901 के उपरांत 326139 से बढ़कर 1991 में 940609 अर्थात् लगभग तीन गुनी बढ़ गई है। यह वृद्धि नगरीय जनसंख्या के रुप में 10 गुने से अधिक वृद्धि हुई। नगरीय जनसंख्या में 1971 से 1981 के बीच शामिलकर किया गया है। सर्वाधिक 210.41% वृद्धि हुई क्योंकि 8 बड़े ग्रामों को इसमें 1991 की जनगणना में जबकि ग्रामीण जनसंख्या में लगभग 2.5 गुनी वृद्धि आंकी गई है। 1901 के दशक से लेकर 1991 तक जनसंख्या वृद्धि में केवल 1921 में जनसंख्या ह्रास हुआ है अर्थात् 1921 में 13.66% कुल नकारात्मक वृद्धि; इस समय जनसंख्या में ऋणत्मक वृद्धि का प्रमुख कारण 1917 एवं 1918 में भारत के अनेक क्षेत्रों की भाँति यहाँ पर भी दुर्भिक्ष अकाल एवं महामारी का प्रसार है। नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणत्मक जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि 1961 तथा 1971 के दशक में हुई। यहाँ यह वृद्धि क्रमशः 25.81 तथा 24.31% हुई। मानचित्र 2.11 तथा सारणी 2.8 में जनसंख्या वृद्धि को दर्शाया गया है।

जिला टीकमगढ़ की जंनसंख्या वृद्धि की वार्षिक वृद्धि दर का आकलन निम्न लिखित सूत्र द्वारा इसका आंकलन किया जा सकता है।

$$P_1 = P_o \left(1 + \frac{R}{100}\right) n$$

R = जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि ।
P_1 = 1991 की जनसंख्या ।
P_o = 1901 में जनसंख्या और
n = वर्षो की संख्या । (1901 से 1991) अर्थात 90 वर्ष ।

जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि उक्त सूत्र के अनुसार उत्तर में (निवाड़ी तहसील) 2.14% तथा दक्षिण-पश्चिम में (टीकमगढ़ तहसील) 2.56% तक रही।

A
Growth of Population
Urban Population
Rural Population
Population in Laks
Decade
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
B
Total
Males
Females
Population in Laks
Decade
C
Distribution of General Population
N
% General Population To Total Population
Below-72.00
72.01-77.00
Above-77.00
Forest
0
30
KMS
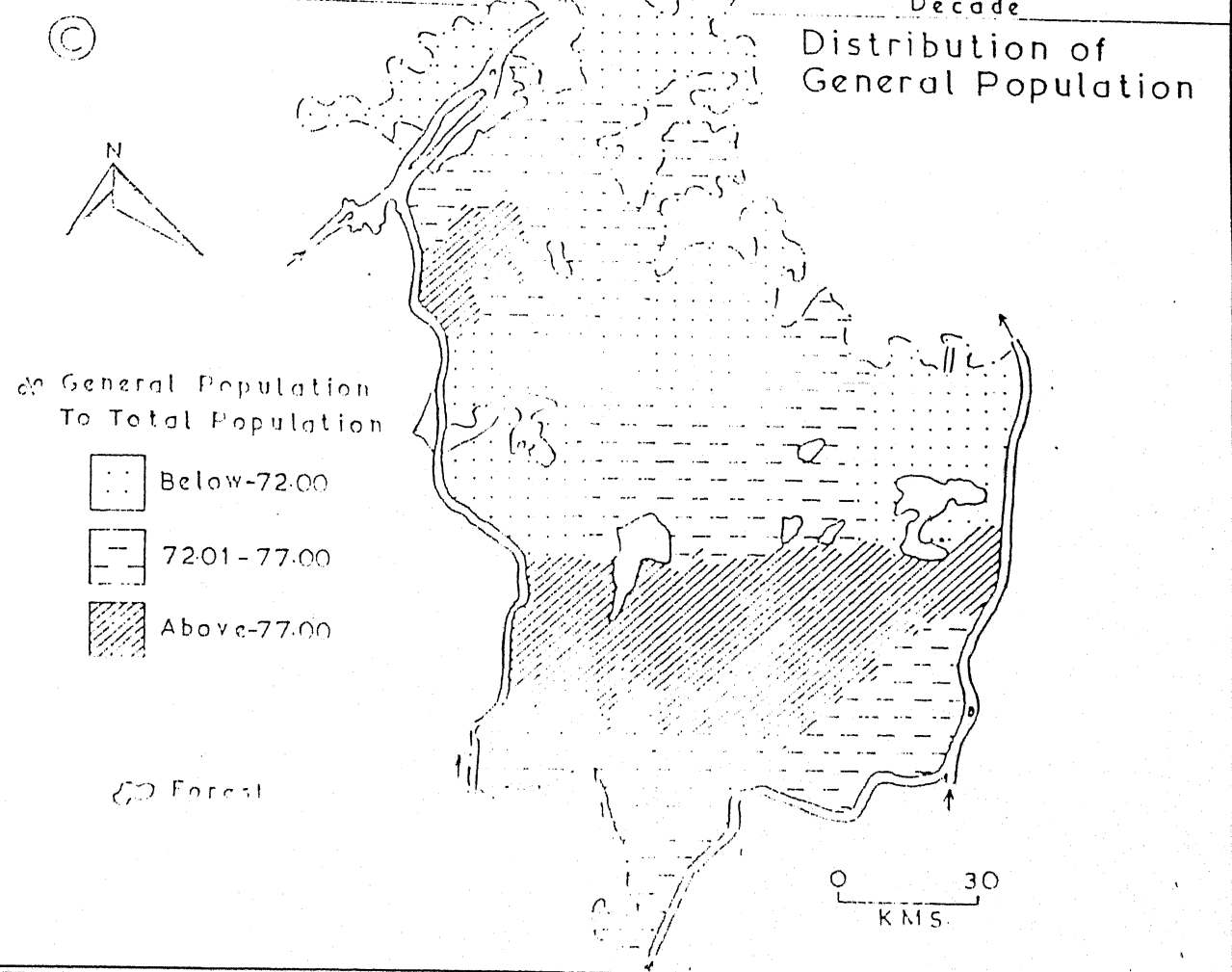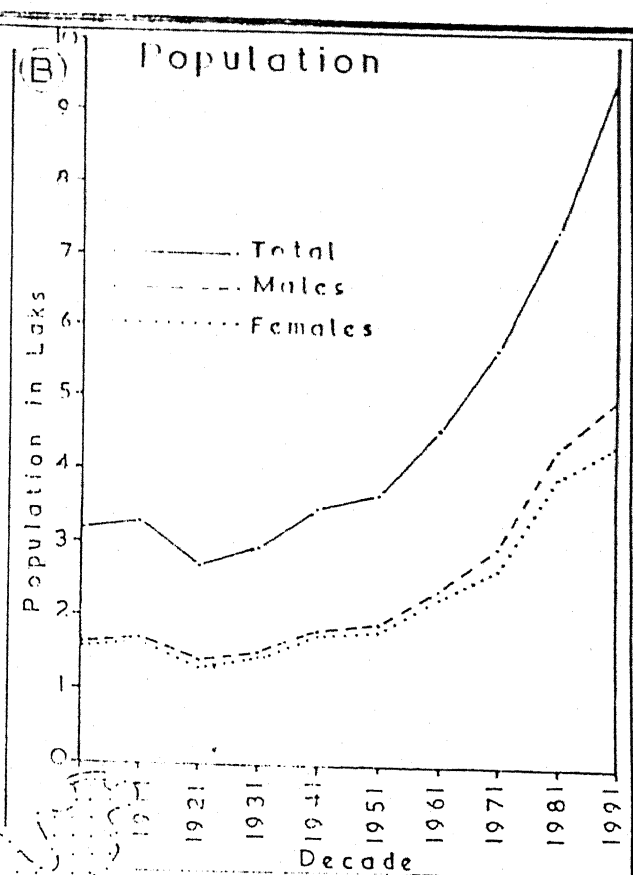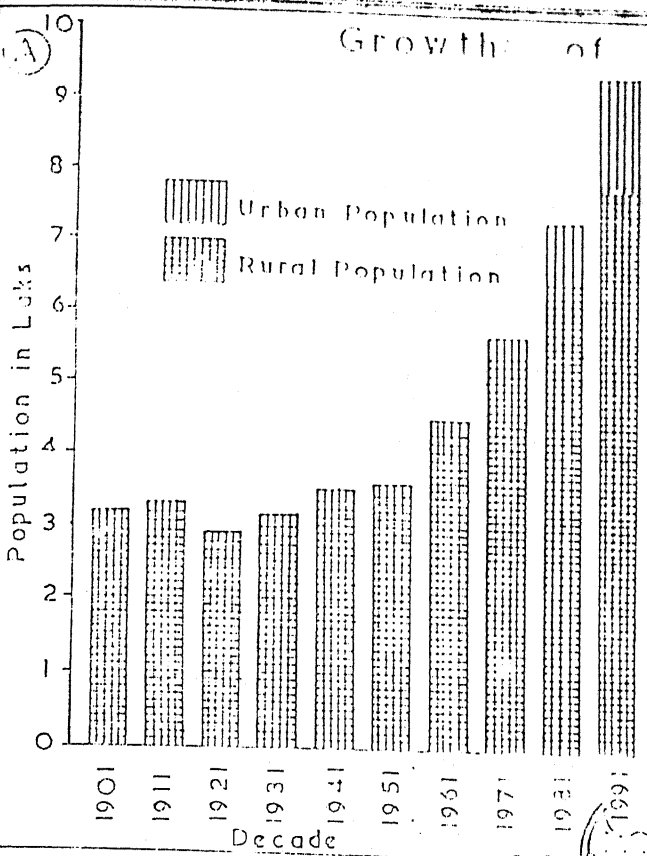
सारणी क्रमांक 2.8 : जिला टीकमगढ़ में जनसंख्या वृद्धि 1901-1991

दशक	जनसंख्या	वृद्धिदर प्रतिशत	नगरीय जनसंख्या	वृद्धिदर प्रतिशत	ग्रामीण जनसंख्या	वृद्धि दर %
1901	326139		14050	-	312089	-
1911	344609	+ 2.69	15495	+ 10.28	319114	+ 2.25
1921	288901	- 13.66	14096	- 9.03	274805	- 13.89
1931	317059	+ 9.75	14366	+ 1.22	302693	+ 10.15
1941	354952	+ 11.96	16122	+ 12.15	338870	+ 11.95
1951	366165	+ 3.15	20242	+ 25.59	345923	+ 2.08
1961	455662	+ 24.44	20469	+ 52.42	435193	+ 25.81
1971	568885	+ 24.85	27905	+ 36.33	540980	+ 24.31
1981	736981	+ 29.55	89410	+210.41	647571	+ 19.70
1991	940609	+ 27.63	158959	+177.79	781650	+ 20.70

स्रोत : प्राथमिक जनगणना सार एवं ग्राम व नगर निर्देशनी, जिला टीकमगढ़ 1981 तथा 1991.

2) जनसंख्या का वितरण : (DISTRIBUTION OF POPULATION)

जनसंख्या का वितरण एक गतिक प्रक्रिया है जो समय व स्थान पर अपना प्रभाव एवं कारण द्वारा लगातार परिवर्तन को दर्शाती है।[47] जनसंख्या के वितरण में जिला टीकमगढ़ में प्राकृतिक व सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया गया है। जिला टीकमगढ़ में जनसंख्या का वितरण ग्रामीण एवं नगरीय, दोनों क्षेत्रों में पूर्णतः असमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का वितरण अनेक भौगोलिक कारकों द्वारा सीधा प्रभावित हुआ है, जैसे मैदानी क्षेत्र के निकट अपेक्षाकृत जनसंख्या की सघनता और अनुपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों और पठारी भू-भाग पर जनसंख्या का वितरण विरल पाया जाजा है। वितरण की दृष्टि से जिले के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जनसंख्या कम है। जबकि उत्तरी-पश्चिमी एवं दक्षिणी-पश्चिमी भाग में सघन वितरण पाया जाता है।

3) जनसंख्या घनत्व : (DENSITY OF POPULATION)

क) गणितीय घनत्व (ARITHMATIC DENSITY)

जनसंख्या घनत्व जिला टीकमगढ़ में 160 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. पाया जाता है जो कि (भारत 221) से कम तथा मध्य प्रदेश 118 राजय से अधिक है। जिला टीकमगढ़ में जनसंख्या घनत्व में पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है। इसमें ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में अलग-अलग घनत्व दिखाई देता है। न्यूनतम घनत्व 115 कुडीला राजस्व निरीक्षक मण्डल में तथा 249 अधिकतम् टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में पया जाता है। जिला टीकमगढ़ के गणितीय घनत्व को निम्नलिखित मानक विचलन सूत्र द्वारा पाँच भागों में बाँटा गया है।

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma Fd \frac{2}{x}}{N} - \left(\frac{\Sigma Fdx}{N}\right)^2}$$

STRUCTURE OF POPULATION
(A) Males
N
o/o of Males Population To Total Population
Below 52·50
52·50-53·00
Over 53·00
Forests
(B) Females
o/o of Females Population To Total Population
Below46·50
46·50-47·0
Over 47·00
(C) Scheduled Casted
o/o of Scheduled Castes To Total Population
17-19
19-23
23-27
(D) Scheduled Tribes
o/o of Scheduled Tribes To Total Population
2-4
4-6
6-8
0
30
KM
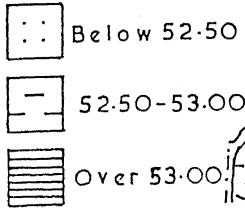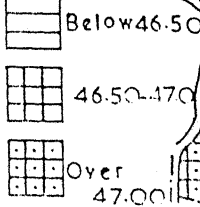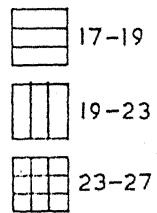
Fig 2.13

जहाँ :
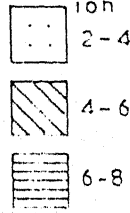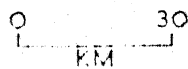
σ = मानक विचलन ।

Fdx^2 = राजस्व निरीक्षक मण्डलों के घनत्व के वर्ग का योग ।

Fdx = राजस्व निरीक्षक मण्डलों का घनत्व ।

N = राजस्व निरीक्षकों मण्डलों की संख्या ।

न्यूनतम घनत्व के क्षेत्र: (150 व्यक्ति से कम)

जिला टीकमगढ़ में न्यून घनत्व के क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अन्तर्गत कुडीला 115, बड़ागाँव 122, समर्रा 123, खरगापुर 140, पलेरा 134, मोहनगढ़ 139 आदि है।

मध्यम घनत्व के क्षेत्र : (150 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)

अध्ययन क्षेत्र के ओरछा, तरीचरकलाँ, नैगुंवाँ, पृथ्वीपुर, लिधौरा, दिगौड़ा जतारा एवं बल्देवगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डलों में पाया जाता है।

अधिक घनत्व के क्षेत्र : (200 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक)

अधिक घनत्व के क्षेत्रों में टीकमगढ़, निवाड़ी, सिमरा राजस्व निरीक्षक मण्डलों में पाया जाता है।

ख) कार्यिकी घनत्व :

कुल जनसंख्या के कृषि योग्य भूमि पर अनुपातिक क्रियाशीलता को कार्यकी

घनत्व कहते हैं। अध्ययन क्षेत्र में 377 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. कार्यिक घनत्व है। यह घनत्व सर्वाधिक 638 और कम 222 प्रति वर्ग कि.मी. कुड़ीला में पया जाता है। माचचित्र 2.12 में घनत्व को दर्शाया गया है।

ग) कृषि घनत्व : (AGRICULTURAL DENSITY)

कुल कृषि योग्य जनसंख्या के कृषि योग्य भूमि की निर्भरता के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। अध्ययन क्षेत्र में कृषि घनत्व अधिकतम् निवाड़ी 153, सिमरा 171, तथा पृथ्वीपुर 146 है। इन क्षेत्रों में कृषि घनत्व अधिक होने का कारण कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या का पूर्णतः कृषि कार्यों में संलग्न न होना है।

घ) पोषण घनत्व : (NUTRITIONAL DENSITY)

जिला टीकमगढ़ में पोषण घनत्व में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देता है। यह घनत्व 278 से 689 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. पाया जाता है। सर्वाधिक पोषण घनत्व निवाड़ी 689, टीकमगढ़ 540 आदि उल्लेखनीय हैं।

4) ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वितरण : *(DISTRIBUTION OF RURAL-URBAN POPUL-TION)*

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण का नगरीय जनसंख्या में पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है। क्योंकि गाँवों के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि उतनी अधिक नहीं है। नगरों में जनसंख्या का कुल प्रतिशत 12.13 तथा 87.87 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है।

जिला टीकमगढ़ में औसत 21.39% अनुसूचित जाति और 4.44% अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति पाये जाते हैं। जनसंख्या का वितरण व घनत्व भिन्न-भिन्न कारकों की

Tikamgarh District
Density of Population
(Persons Per Sq. K.M.)
Arithmatical
Q.3 176
M. 152
Q.1 139
Physiological
Q.3 449
M. 327
Q.1 304
Forests
N
Agricultural
Q3 125
M. 105
Q.1 98
Nutritional
Q.3 459
M. 433
Q.1 363
0 30
Kilometers
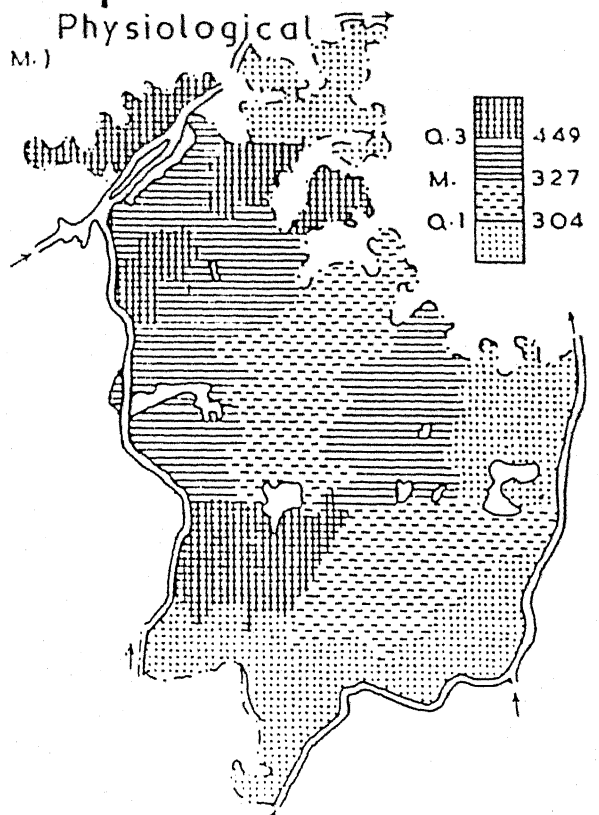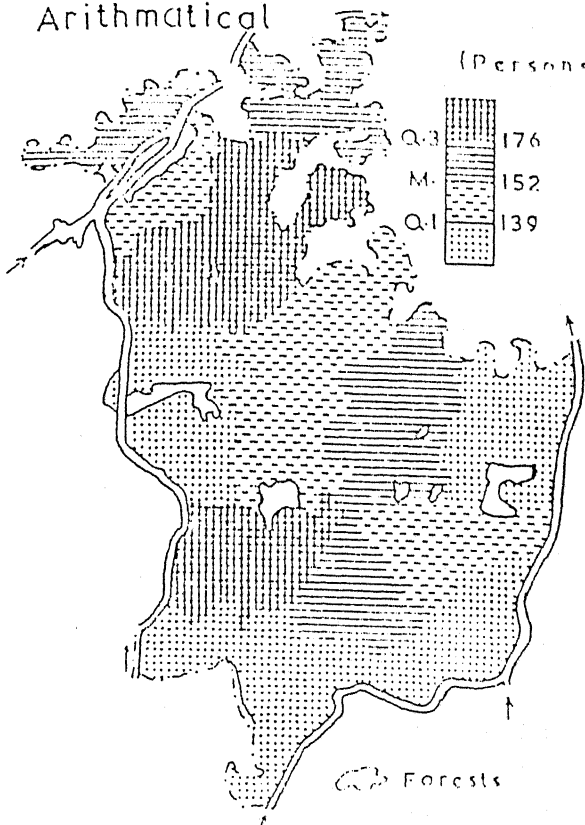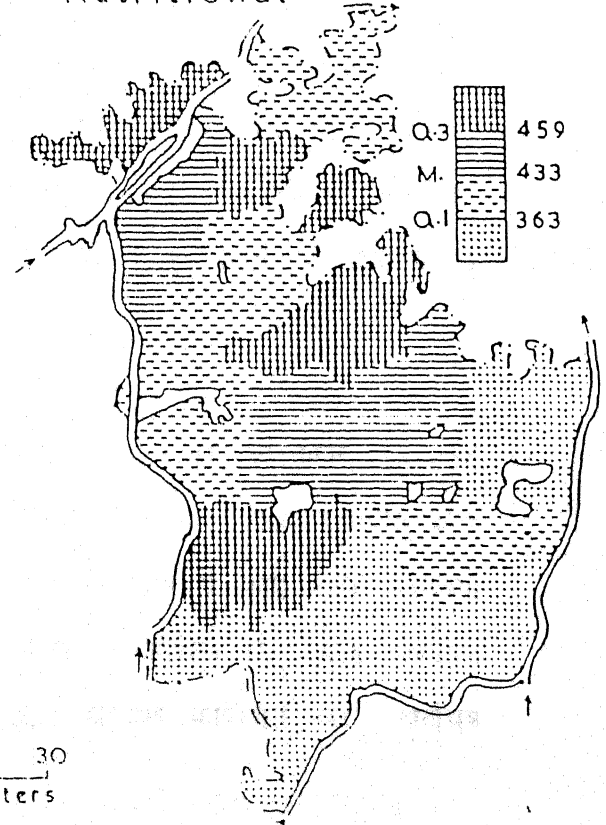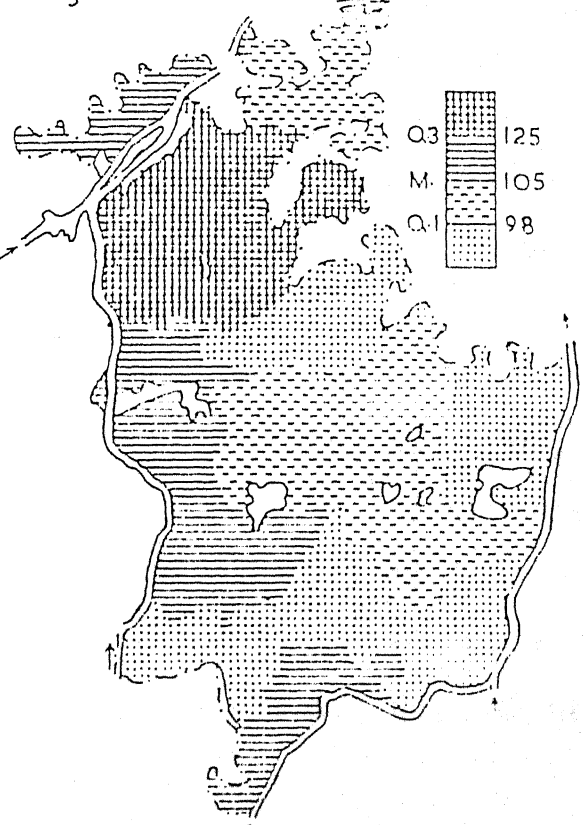
Fig 2.14

क्रियाशीलता पर उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधनों आदि की तीव्रता पाई जाती है वहाँ जनसंख्या सघन, जबकि न्यून सिंचाई के साधनों वाले भागों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य भौगोलिक कारकों का प्रभाव भी जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करता है।

5) लिंगानुपात साक्षरता एवं व्यवसायिक संगठन :

(SEX RATIO, LITERACY AND OCCUPATIONAL ORGANISATION)

अध्ययन क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति दशक घट रहा है। जो वर्ष 1971 में 871 है। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात में अधिक अन्तर नहीं पाया जाता। सर्वाधिक स्त्रियाँ समर्रा तथा बल्देवगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डलों में जबकि, सबसे कम दिगौड़ा तथा औरछा राजस्व निरीक्षक मण्डलों में पाई जाती है। (मानचित्र 2.)

1901 की जनगणनानुसार जिला टीकमगढ़ में 24.06 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे। इनमें 15.20 प्रतिशत पुरुष और लगभग 4% महिलायें साक्षर थीं। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक साक्षरता पाई जाती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में कुल साक्षरता 13.51% जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह अनुपात अपेक्षाकृत वृद्धिकर गया है। सर्वाधिक साक्षरता 32.69% और सबसे कम 12.46% टीकमगढ़ व कुडीला में पाई जाती है। (मानचित्र क्रमांक 2.) 15

1991 की जनगणनानुसार जिला टीकमगढ़ में 72.94% काश्तकार, 13.46% कृषि मजदूर, 2.88% पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या और 10.73% जनसंख्या अन्य कार्यों में संलग्न पाई जाती है। कुल जनसंख्या का अध्ययन क्षेत्र में कार्य शील जनसंख्या 35.08%, 7.32% सीमान्त कार्यकर्ता और 57.59% व्यक्ति अकार्यशील थे। कुल कार्यशील जनसंख्या (35.08%) में 81.78% पुरुष और 18.22% महिलायें कार्यशील थीं। मानचित्र

Literacy & Sex Ratio
% of Literates Persons To Total Population
12-16
16-20
20-24
24-28
28-32
% of Sex Ratio
Below 868
868-878
879-888
889-898
Over 899
N
0
30
KM
% of Male Literates To Total Population
20-24
24-28
28-32
32-36
36-40
Over 40
Forests
% of Female Literates To Total Population
Below 5
5 - 7
7 - 9
9 - 12
Over 12

Fig 2.15

Occupatinal Structure of Population
A
B
C
D
N
Location Queotient
For
Rural Population
Below-0.86
0.87-1.0
Over-1.1
Forests
Location Queotient
For
Urban Population
Below-2.0
2.0 - 4.0
Over-4.0
0
30
KM.
Location Queotien
t For Cultivators
Below-0.91
0.91-0.96
0.97-1.02
1.03-1.08
Over-1.08
Location Queotient
For Agricultral
Labourers
Below
0.70
0.70-0.80
0.81-0.90
0.91-1.00
1.01-1.20
Over-1.20
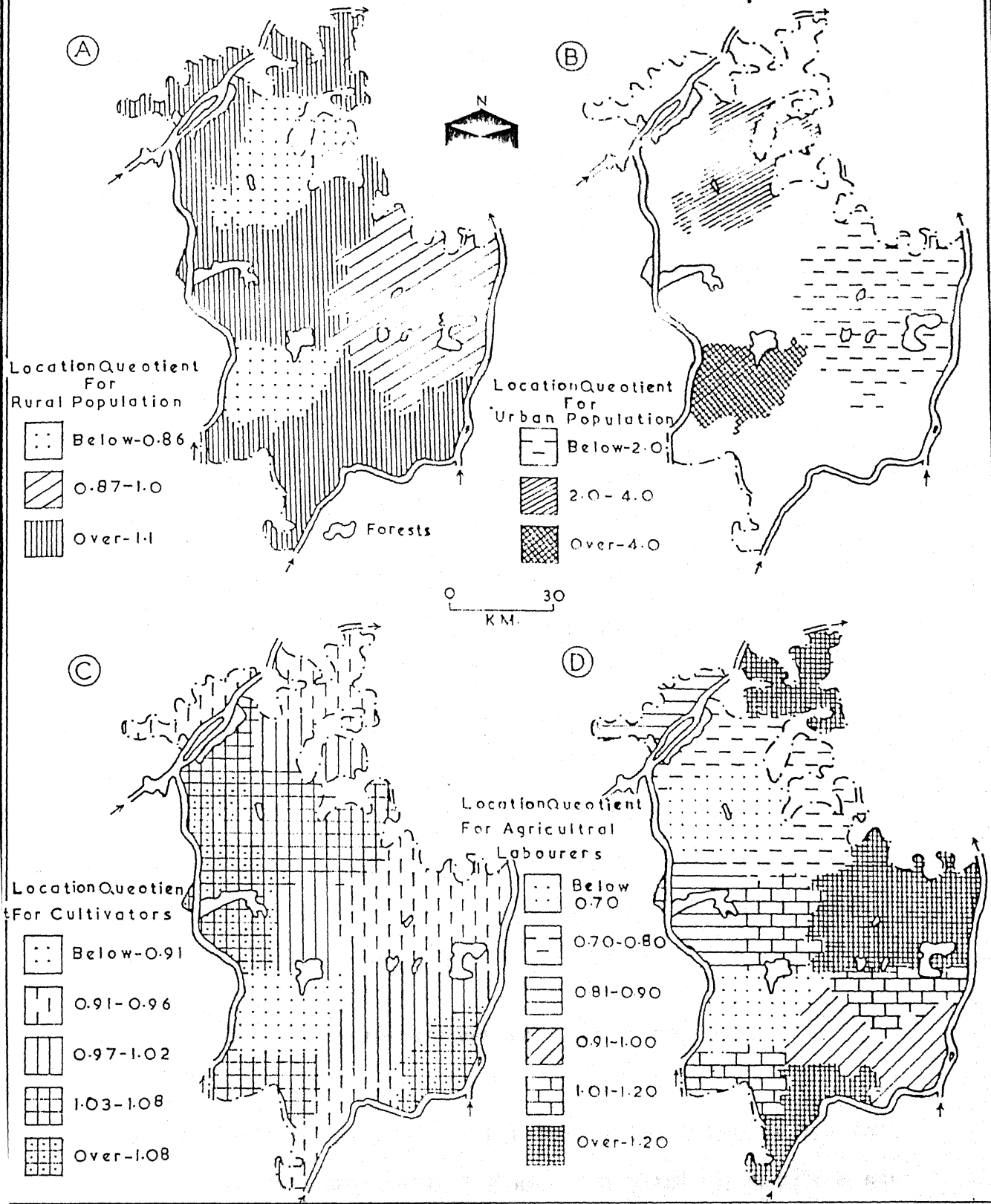
Fig 2.16

2. में इसे दर्शाया गया है। जिला टीकमगढ़ में कृषि पर निर्भरता आज भी (1991) बनी हुई है, क्योंकि यहाँ कृषि पर 80% से भी अधिक जनसंख्या निर्भर है। इसका तात्पर्य यह है कि जिला टीकमगढ़ एक उद्योगों से पिछड़ा जिला है। अध्ययन क्षेत्र में नैगुंवा, सिमरा, पृथ्वीपुर, समर्रा और कुडीला शत प्रतिशत कृषि पर निर्भर कृषि मजदूर पाये जाते है। जिले के संर्वागीण विकास के लिये आज आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक विषमता को समाप्त किये बगैर ग्रामीण विकास को प्राप्त करना आज भी एक पहेली है।[48] मानचित 2.14 इसे दर्शाया गया है ।

6) अधिवास : (SETTLEMENTS)

अधिवास भू-सतह पर मानव वसाव की व्यवस्था को दर्शाते हैं ये अधिवास मानव को एक या अधिक घट एवं भवनों के पाये जाने की कहते हैं।[49] अधिवास भूगोल के अन्तर्गत अधिवास मानव निवास के लिये ही नहीं, बल्कि मानव के कार्यस्थल भण्डार, व्यापार एवं वाणिज्य इत्यादि से सम्बन्धित होता है। किसी क्षेत्र के अधिवासों का निर्माण स्थानीय भौतिक वातावरण के तत्व की प्राप्ति और वहाँ की मानव क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिवासों का आकार, घनत्व व दूरियाँ सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के द्वारा निर्धारित हाती हैं।[50] इस प्रकार अधिवास सांस्कृतिक वातावरण की विभिन्न क्रियाओं जैसे भूमि उपयोग ओर जनसंख्या में निकंटतम सम्बन्ध को स्थापित करता है, किसी क्षेत्र के अधिवासों के निर्धारण में स्थानिक क्रियायें आधारभूत तत्व होती हैं। मानव की गति और पदार्थ अधिवास की क्षेत्रीयता को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यात्मक विश्लेषण में अधिवासों को सदैव ही स्थान दिया जाता है

11. संचार सेवायें : (COMMUNICATIONAL SERVICES)

किसी भी देश, प्रदेश व क्षेत्र के विकास में डाक व्यवस्था का बहुत महत्व है।[56] अध्ययन क्षेत्र (जिला टीकमगढ़) में डाक व तार सुविधायें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय

से प्राप्त हैं। वर्तमान में एक मुख्य डाकघर, 19 उपडाकघर एवं 158 शाखा डाकघर सेवारत हैं। जिले में 31 वस्तियों में टेलीफोन की सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 ग्रामों में व 6 नगरीय बस्तियों में टेलीफोन सुविधा प्राप्त है।

उप डाकघरः

अध्ययन क्षेत्र जिला टीकमगढ़ में उपडाकघर 158 हैं, जिनमें 155 उप डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत हैं। अध्ययन क्षेत्र में 1000 से कम आवादी वाली बस्तियों में इनकी कोई शाखा नहीं है, 1000 से 1999 तक आवादी वाली बस्तियों में 3 उप डाकघर सेवारत हैं। 2000 से 4999 तक आबादी वाली बस्तियों में इनकी संख्या 7 है एवं 5000 से अधिक आवादी वाले ग्रामों में इनकी केवल 1 संख्या है। नगरीय क्षेत्रों में 8 उप डाकघर सेवारत हैं। मुख्य डाकघर केवल जिला मुख्यालय पर कार्यरत है। राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर सबसे अधिक उप डाकघर टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में इनकी संख्या 4 है। नैगुंवा, समर्रा व कुड़ीला राजस्व निरीक्षक मण्डलों में एक भी उप डाकघर नहीं है। निवाड़ी व तरीचरकलाॅं राजस्व निरीक्षक मण्डल में दो-दो उप डाकघर हैं। सिमरा, पृथ्वीपुर, मोहनगढ़, लिधौरा, दिगौड़ा, जतारा, पलेरा, बड़ागाँव, बल्देवगढ़ एवं खारगापुर राजस्व निरीक्षक मण्डलों में एक-एक उप डाकघर सेवारत है।

शाखा डाकघर :

शाखा डाकधरों का सम्बन्ध उप डाकघरों से होता है, जिले में कुल 158 शाखा डाकघर हैं। जिनमें 155 शाखा डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में व 3 शाखा डाकघर नगरीय क्षेत्रों में सेवारत हैं। शाखा डाकघर के वितरण की दृष्टि से इनकी संख्या 200 से कम आवादी वाले ग्रामों में नहीं है 200 से 499 तक आवादी वाले 5 ग्रामों में शाखा डाकघर हैं, 500 से 999 तक आवादी वाले 27 ग्रामों में इनकी सेवायें उपलब्ध हैं, 1000 से 1999 तक

आवादी वाले 86 ग्रामों में शाखा डाकघर हैं। 2000-4999 तक आवादी वाले 35 ग्रामों में शाखा डाकघर है एवं 5000 से अधिक आबादी वाले 2 ग्रामों में शाखा डाकघर हैं। नगरीय क्षेत्रों में 3 नगरों में इनकी सेवायेंय उपलब्ध हैं। राजस्व निरीक्षक मण्डल में वितरण के आंकलन की दृष्टि से सबसे अधिक शाखा डाकघर जतारा राजस्व निरीक्षक मण्डल में इनकी संख्या 16 है। सबसे कम शाखा डाकघर सिमरा राजस्व निरीक्षक मण्डल में 4 है। इसी प्रकार खरगापुर में 13, लिधौरा में 12, तरीचरकालँ, पृथ्वीपुर, मोहनगढ़, पलेरा, समर्रा में 11-11, बड़ागाँव में 10, निवाड़ी में 8-8, नैगुँवा, दिगौड़ा कुडीला में 6-6, तथा ओरछा राजस्व निरीक्षक मण्डल में 5 शाखा डाकघर है।

टेलीफोन की सुविधा प्राप्त बस्तियाँ :

अध्ययनक्षेत्र 51 बस्तियों में टेलीफोन की सुविधा प्राप्त है, ग्रामीण क्षेत्रों में 39 बस्तियों में व 12 नगरीय क्षेत्रों में टेलीफोन की सेवायें उपलब्ध हैं। अध्ययन क्षेत्र में टेलीफोन सुविधा प्राप्त बस्तियों के वितरण के आंकलन से 200 से कम आबादी वाले ग्रामों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 200 से 499 तक आबादी वाले दो ग्रामों में यह सुविधा है। इसी प्रकार 500 से 999 तक आबादी बसितयों में तीन ग्रामों में टेलीफोन सुविधा है। इसी प्रकार 1000-1999 तक आबादी वाले 20 ग्रामों में यह सुविधा उपलब्ध है। 2000 से 4999 तक आबादी वाली बस्तियों में 18 ग्रामों में यह सुविधा है। 5000 से अधिक आबादी वाले 2 नगारों में टेलीफोन है। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर टेलीफ़ोन युक्त बस्तियों की संख्या की दृष्टि से नैगुँवा व समर्रा राजस्व निरीक्षक मण्डल में टेलीफोन की सुविधा नहीं हैं।

टेलीविजन केन्द्र :

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1987 में संचार माध्यमों को जन-जन तक पहुँचाने के

लिए दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना की गई। यह रिले केन्द्र अत्यंत सूक्ष्म उच्च आवृति का है। तथा इसकी सीमा 5 किलोमीटर हवाई मार्ग तक है। टीकमगढ़ नगर और उसके आस पास के 10 किलोमीटर क्षेत्र के लोग आसानी से इस दूर संचार का उपयोग करते हैं।

तार-वेतार :

जिला मुख्यालय पर तार बे-तार के लिये एक सूक्ष्य तरंग टावर, पुलिस लाईन, टीकमगढ़ में स्थापित है, जिसका सम्पर्क राज्य की राजधानी भोपाल एवं जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों, थानों एवं पुलिस चौकियों से है। सुरक्षा की दृष्टि से सम्पर्क स्थापित करने के लिए यह एक अत्यंत उपयोगी महत्वपूर्ण संचार का माध्यम है जो प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखता है। ये केन्द्र निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा एवं बल्देवगढ़, तहसील मुख्यालयों पर भी हैं।

कम्प्यूटर संचार :

जिला मुख्यालय टीकमगढ़ में योजना आयोग द्वारा सन् 1988 में उपग्रह के माध्यम से कम्प्यूटर संचार प्रणाली प्रारम्भ की गई, जिसका सम्पर्क, चौबीसों घण्टे सुपर कम्प्यूटर दिल्ली से बना रहता है। योजना आयोग अति आवश्यक एवं गोपनीय जानकारी कम्प्यूटर द्वारा तत्काल प्रांतीय राजधानी एवं दिल्ली को भेजी जाती है। 1991 की जनगणना के आंकडे इसी के माध्यम से सूपर कम्प्यूअर को भेजे गये थे।

एस.टी.डी. सेवायें :

1991 में सर्वप्रथम टीकमगढ़ नगर की सेटलाइट टेलीविजन डिपार्डमेन्ट की ओर से एस.टी.डी. सुविधा के लिये नूतन बिहार कालौनी ढौंगा में एक माइक्रोवेव टावर की निर्माण

किया गया। वर्तमान समय में टीकमगढ़ नगर में 24 एस.टी.डी. केन्द्र (पी.सी.ओ.) संचालित है। जिला प्रशासन को फैक्स सेवायें भी प्राप्त हैं।

12. बैंक सेवायें : (BANKING SERVICES)

अध्ययन क्षेत्र में बैंकों की शाखायें सर्वत्र एक समान नहीं हैं। कुल जनसंख्या का 77.87 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में रहती है जबकि बैंकों की कुल शाखाओं के 71.79 प्रतिशत बैंक शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यहीं नहीं, ये ग्रामीण बैंक व शाखायें भी समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में समान नहीं हैं। जिले में कुल 78 बैंक शाखायें कार्य कर रही हैं जो इस प्रकार हैं :-

भारतीय स्टेट बैंक :

भारतीय स्टेट बैंक अपने अग्रणी कार्यालय के साथ 9 शाखाओं के माध्यम से सेवारत हैं। इस बैंक की शाखायें 2000 से कम आबादी वाले सेवाकेन्द्रों में नहीं हैं। 2000 से 4999 तक आबादी वाले सेवाकेन्द्रों में इस बैंक की 3 शाखायें हैं एवं 5000 से अधिक आबादीय बस्तियों में एक शाखा कार्यरत हैं। नगरीय क्षेत्रों में इस बैंक की 5 शाखायें हैं। भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर एक शाखा निवाड़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल में, एक पृथ्वीपुर राजस्व निरीक्षक मण्डल में, एक लिधौरा राजस्व निरीक्षक मण्डल में, एक दिगोड़ा राजस्व निरीक्षक मण्डल में, एक जतारा राजस्व निरीक्षक मण्डल में, एक पलेरा राजस्व निरीक्षक मण्डल में, एक टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में, एक बड़ागाँव राजस्व निरीक्षक मण्डल में व एक बल्देवगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में इनकी शाखा है।

भारतीय स्टेट बैंक की इन शाखाओं के माध्यम से लोगों को दीर्घ कालीन व अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं जो उद्योगों, कृषि एवं अन्य सेवाओं हेतु प्रदान करते हैं।

स्टेट बैंक की शाखाओं पर 81887 जनसंख्या दबाव है।

इलाहाबाद बैंक :

अध्ययन क्षेत्र में इलाहाबाद बैंक की केवल एक शाखा है जो जिला मुख्यालय पर कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बैंक की कोई शाखा नहीं है। इस बैंक पर जनसंख्या दबाव 736981 है। इलाहाबाद बैंक द्वारा वित्त पोषण का कार्य किया जाता है। जिला शाखा योजना, 88-90 एवं वार्षिक कार्य योजना, 1988 हेतु कुल लक्ष्य का लगभग 2 प्रतिशत कार्य अपने नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर की ओर से स्थानीय शाखा प्रबंधक द्वारा स्वीकार किया गया जो कृषि वृत, उद्योग वृत एवं सेवा वृत आदि के लिये था

सेन्ट्रल बैंक :

जिले में सेन्ट्रल बैंक की केवल एक शाखा जिला मुख्यालय पर है। इस बैंक के द्वारा भी ऋण व पोषण का कार्य किया जाता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्रीण ग्रामीण बैंक :

अध्ययन क्षेत्र में इस बैंक की कुल 43 शाखायें कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बैंक की 39 शाखायें हैं व नगरीय क्षेत्र में 8 शाखायें कार्यरत हैं। 500 से कम आबादी वाले ग्रामों में इनकी शाखायें नहीं है। 500 से 999 तक की आबादी वाले ग्रामों में 4 शाखायें 1000 से 1999 की आबादी वाले ग्रामों में 12 शाखायें, 2000 से 4999 तक आबादी वाले ग्रामों में 21 शाखायें और 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में 2 शाखायें हैं। राजस्व निरीक्षक मण्डल आधार पर इस बैंक की सबसे अधिक शाखायें पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डलों में चार-चार शाखायें हैं। निवाड़ी, तरीचरकलॉं दिगौड़ा, पलेरा, कुड़ीला

एवं खरगापुर राजस्व निरीक्षक मण्डलों में तीन-तीन शाखायें कार्यरत है। ओरछा नैगुंवॉ, सिमरा, मोहनगढ़, लिधौरा, बड़ागाँव राजस्व निरीक्षक मण्डलों में दो-दो शाखायें हैं। समर्रा राजस्व निरीक्षक मण्डल में केवल एक शाखा है। एवं बल्देवगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में इस बैंक की शाखा नहीं हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इन शाखाओं पर जनसंख्या का दबाव 17139 व्यक्ति प्रति शाखा है।

REFERENCES

1. District Gazetteer Tikamgarh District, Madhya Pradesh, Bhopal (M.P.0 1995.

2. Census of India, Tikamgarh District Primary Census Abstract (Computer Sheet) 1991. Madhya Pradesh Bhopal.

3. टीकमगढ़ दर्शन - मंगल प्रभात, ग्वालियर.

4. Tikamgarh District Gazettear, Madhya Pradesh, Bhopal, M.P. 1995.

5. अवस्थी एन.एम. (1986) : " सिंचित कृषि का ग्रामीण विकास पर प्रभाव ", अप्रकाशित शोध प्रबंध, अ.प्र. सिंह विश्व विद्यालय, रीवा (म.प्र.) पृष्ठ क्रमांक 10.

6. अवस्थी, एन.एम.(1986) : " सिंचित कृषि का ग्रामीण विकास पर प्रभाव " अप्रकाशित शोध प्रबंध, अ.प्र. सिंह, विश्व विद्यालय, रीवा (म.प्र.) पृष्ठ क्रमांक 19.

7. Saxena, J.P. (1969): Agricultural Geography of Bundelkhand (Unpublished Ph.D. thesis) Dr. H.S.Gour Vishwavidyalaya, Sagar, P: 87.

8. Harpsteed, M.I. ad P.D. Hole (1988): Soil Science Simplified Scientific Publishers, Jodhpur PP : 8-14.

9. अवस्थी, एन.एम. (1986) : वही पृष्ठ 163.

10. तिवारी, आर.पी. एवं आर.एस. त्रिपाठी (1993) : भूमि उपयोग क्षमता, कृषि उत्पादकता एवं कृषि विकास स्तर - कृषि भूगोल (सम्पा. भीकमसिंह) , जयपुर पृ. 100-119.

11. Buck, J.L. (1937) : Land utilization in china, Univiersity of Nonking, Shanghai Commercial Press PP : VII-XX.

12. Jonnason, C. (1925) : Agricultural Regions of Europe, Economic Geography, I, PP : 227-314.

13. Singh Jasbir (1972) : A New Techniques of Measuring Agricultural Efficiency in Haryana ' The Geogrpher Vol. XIX PP : 15-33.

14. Singh, B.P. (1970): Economic Survey of Barut Block (Unpublished Ph.D. Thesis) Dept. of Geography, Banaras Hindu University, Varanasi P : 89.

15. जोशी वाई.जी. (1972) : नर्मदा बेसिन का कृषि भूगोल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ. क्र. 110-118.

16. Bhatia, S.G. (1965): Pattern of Crop concentration and Diversification in India, Economic Geography Vol. 41, No.1, PP: 39-56.

17. James, P.E. and F.J. Jones (1954): American Geography, Inventry and Prospects, P: 259.

18. Singh, H.P. (1965) : Crop Combination Regions in the cropping Tract of Punjab, Deccan Geographers Vol.3, No.1, P : 78.

19. Backer, O.E. (1926): Agricultural Regions in North America, Economic Geography Vol.2, PP: 459-93.

20. Jonnason, O. (1926) : Agricultural Regions of Europe Economic Geog. Vol. I (1925) and Vol.II (1926): PP: 19-48.

21. Weaver, J.C. (1954) : Crop combination of Regions in the Middle West of Republic of Germany Vol. 44, Annals PP: 175-200.

22. Coppock, J.T. (1964): Agricultural Atlas of England and Wales, London, Paper-I, Edition P.211.

23. Johnson, R.R. (1958) : Crop Combination of West Pakistan Pak Geographical Review P : 43.

24. Peter Scott (1975): Agricultural Regions of Tasmania A statistical Depretion, Economic Geography Vol.33, P: 109.

25. Powell, S.M. (1969): Crop Combination of Western Victoria (1961-91) Australian Geography, 11, PP : 157-69.

26. Benergee, B. (1964): Changing Crop Land of West Bengal Geographical Review of India No.1 PP : 64-69.

27. Singh, H.P. (1965): Op.Cit. P: 84.

28. Aiyar, N.P. (1969) : Crop Combination Regions of Madhya Pradesh, A study of Methodology, Geographical Review of India, Vol.31 No.1, P : 17.

29. पाण्डे, जे.एन. (1969) पूर्वी उत्तर-प्रदेश के शस्य संयोजन प्रदेश,' उत्तर भारत भूगोल पत्रिका ' अंक-5, पृ. : 1 - 14.

30. Raffiullah, S.M. (1965): A new Approach to Functional classification of Towns, The Geographer No. 12 , P: 46.

31. Doi, K. (1959): The Industrial Structure of Japanese Protecture Proceedings of I.G.D. (1957) PP : 310-16.

32. Tiwari, R.P. and R.S. Tripathi (1993): Land use Efficiency, Crop Productivity and Agicultural Development, A case study, Jaipur, PP: 100-119.

33. Kendal, M.G. (1939) : The Geographical Distribution of Crop Productivity in England, The Journal of Royal Statistical Society Vol. 162. PP : 21-62.

34. Buck, J.L. (1937) : Land Utilization in China, University of Nonking, Shanghai, Commercial Press, PP : VII-XX.

35. Stamp, L.D. (1963) : Applied Geography, Penguin Books Harmond and North, PP: 108-09.

36. Shafi, M. (1960): Measurement of Crop Efficiency in Uttar Pradesh, Economic Geography Vol. 43, No. 4, PP : 295-306.

37. Bhatia, S.S. (1968): A new Measures of Crop Efficiency in Uttar Pradesh, Economic Geography, Vol. 43, No.3, PP: 244 -260.

38. Hussain, M. (1979) : Agricultural Geography, Inter India Publications, New Delhi, P: 136.

39. Sapre, S.G. and Deshpande, V.D. (1964): Inter District Variations in Agricultural Efficiency in Maharastra State, Indian Journal of Economics; PP : 242-53.

40. Enyedi, G.Y. (1964): Geographical Types of Agriculture, Applied Geography, Hungery, Budapest Akademiad Kiado.

41. Shafi, M. (1972): Measurement of Agricultural Productivity of the Great Indian Plains Economic Geographers Vol.72, No.1.

42. Shinde, S.D. (1978): Agricultural productivity in Maharastra: A Geographical Analysis, National Geographer, Vol. 13, No.1, PP : 35 -41.

43. Vidyanath, V. (1985): Crop Productivity in Relation to Crop, Land in Andhra Pradesh. A Spatial Analysis, Transactions, I.I.G. No.1, Vol. 7, PP.: 49-55.

44. Tiwari, R.P. and R.S. Tripathi (1993): Op.Cit. PP : 110-119.

45. Tripathi, K.P. (1983): Location and Distribution of large Scale Industries in Orissa, Uttar Bharat Bhoogol Parishad, Gorakhpur.

46. Tiwari, R.P. (1979): Population Geography of Bundelkhand Unpublished Ph.D. Thesis Vikram University, Ujjain, PP: 129.

47. Zomali, F.Z. (1996): Population Geography of Nimar, Uttar Bharat Bhoogol Parished, Gorakhpur, P : 89.

48. Tripathi R.S. and R.P. Tiwari (1996): Population Growth and Development in India, Ashish Publishing House, New Delhi.

49. Nath, M.L. (1989): The Upper Chambal Basin, A Geographical Study in Rural Settlements, Northern book Centre, New Delhi, Chapter 3, PP : 35-52.

50. Nath, M.L. (1989): Op.cit. P : 59.

----0----

अध्याय तीन

अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का अभिज्ञान

सेवा केन्द्रों का अभिज्ञान : (IDENTIFICATION OF SERVICE CENTRES)

1. सेवा केन्द्र से आशय :

सेवा केन्द्र के निर्धारण में " केन्द्रस्थल " शब्द का वास्तविक और स्पष्ट तात्पर्य समझना आवश्यक है। " केन्द्रस्थल " शब्द अब एक विशेष तकनिकी अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। इस के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्दों में 'सेवाक्रन्द्र' तथा 'बाजार केन्द्र' अधिक प्रचलित हैं दूसरे शब्दों में समीपवर्ती स्थित चारों ओर के क्षेत्रों के लिये उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं, सेवाओं तथा वस्तुओं के विनिमय की भिन्न-भिन्न क्रियाओं के केन्द्र को सेवा केन्द्र कहते हैं।[1] प्राय: सभी नगर चाहे वे छोटे हों या बड़े, केन्द्रस्थलों के रुप में कार्य करते हैं। ग्रामीण अथवा अर्द्धनगरीय बस्तियाँ या स्थान जो बाजारों के रुप में विनिमय कार्य सम्पादित करते हैं सेवाकेन्द्र होते हैं।[2] प्रत्येक सेवाकेन्द्र एक स्थाई मानव निर्माण या बस्ती होता है, जिसका कुछ न कुछ प्रभाव क्षेत्र अवश्य होता हे ओर अपने क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं, सेवाओं एवं बस्तुओं का विनिमय उसी केन्द्र पर या उसके द्वारा संचालित होता है। ऐसे केन्द्र की सबसे बड़ी पहचान यही है कि समीपवर्ती क्षेत्र सेवाकेन्द्र में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं पर निर्भर अवश्य हो, सेवाकेन्द्र केवल अपने ही निवासियों की आवश्यकता पूर्ति नहीं करता हो बल्कि सेवा स्थल होने के लिए दूसरी प्रमुख पहचान यह है कि उस स्थल पर विनिमय सम्बन्धी क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं सम्बन्धित आर्थिक कियाओं की राजधानी के रुप में अवश्यक कार्य करता हो।[3] वह किसी राजनैतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक क्रियाकलापों विशेष का केन्द्रस्थल नहीं हो।[4] चूँकि वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय मानव की एक प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिये प्रत्येक क्षेत्र या प्रदेश में सेवा केन्द्रों की उपस्थिति भी अनिवार्य है। अतएव बिना सेवाकेन्द्रों के कोई भी आर्थिक प्रदेश या इकाई पूर्ण नहीं कहा जा सकती है।[5] किसी ऐसे प्रदेश की वास्तविक राजधानी उस प्रदेश पर अधिकांश अनियंत्रण रखने वाला सेवा केन्द्र ही हो सकता है, क्योंकि उस प्रदेश का

बहुगम्य और बहुसुलभ स्थान उसकी आर्थिक क्रियाओं की भी राजधानी या केन्द्र यही स्थल या सेवाकेन्द्र होगा ।[6]

नगरों का जन्म तथा विकास भी मानव समाज की इसी विनिमय - सम्बन्धी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए होता है। अतः उनका आधारभूत कार्य अपने क्षेत्र के लिए सेवास्थल या सेवाकेन्द्र के रुप में कार्य करना है, लेकिन कुछ नगर ऐसे भी होते है, जिनमें केन्द्रीय कार्यों का अभाव हो। अर्थात जो केवल अपनी स्थानीय जनसंख्या की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो और इसलिए उनका अपना प्रभाव क्षेत्र या प्रदेश न हो, उदाहरण के लिये खानों की बस्तियाँ, शौक्षणिक एवं औद्योगिक निर्माण, सैनिक आवास, हवाई पट्टी के निकट की बस्तियाँ, बन्दरगाह इत्यादि ये सभी तरह के नगर केन्द्रीय कार्यो का सम्पादन करें ही ऐसा अनिवार्य नहीं है और न तो " नगर " शब्द की परिभाषा से ही ऐसी बात निकलती है। अतः ऐसे विशेष या शुद्ध नगरों का होना जो केन्द्र स्थल का कार्य न करते हों सैद्धान्तिक रुप से ओर व्यावहारिक रुप से भी असमान नहीं है, क्योंकि किसी भी ऐसे स्थाई मानव निवासों के सघन समूह को नगर की संज्ञा दी जा सकती है। जहाँ अप्राथमिक व्यवसायों एवं भूमि उपयोगों की अत्यंत प्रधानता हो, और यदि कोई स्थान ऐसा हो तो हमें आवश्यक रुप से उसे अपनी इस परिभाषा के अनुसार नगर मानना पड़ेगा, चाहे उसका कोई प्रभाव क्षेत्र हो या न हो। यह बात दूसरी है कि ऐसे शुद्ध या विशेष किस्म के नगरों में केन्द्रीय कार्यो का विकास कुछ न कुछ और किसी न किसी अवस्था में प्रायः हो ही जाता है।[7] इसलिए ये सेवाकेन्द्र हो जाते हैं। सेवाकेन्द्र स्थल कहे जाने के लिए किसी स्थान में निम्नलिखित आवश्यकताओं का होना अनिवार्य है -

1) यह एक स्थाई मानव बस्ती का निर्माण होता है।

2) अपनी आंतरिक जनसंख्या की किसी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त उसमें प्रत्यक्ष रुप से समीप स्थित क्षेत्रों की सेवापूर्ति का कोई कार्य भी होता है, अर्थात् तृतीयक आर्थिक कार्यो अथवा सेवाओं का सम्पादन यहाँ अथवा उसके द्वारा होता है।

3) मानव-समाज की आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय (वाणिज्य एवं व्यापार) का कार्य समीपवर्ती क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है। और

4) प्रत्येक केन्द्रस्थल " प्रादेशिक राजधानी " के रुप में कार्य करता है और इसलिए प्रत्येक केन्द्रस्थल का अपना प्रभाव क्षेत्र आवश्यक होता है।[8]

ऐसा भी कोई सेवाकेन्द्र नहीं हो सकता, जिसमें वाणिज्य का प्रभाव न हो या जो प्रादेशिक राजधानी के रुप में कार्य न करता हो, लेकिन शेष अन्य दशायें विद्यमान हों, जैसे शुद्ध राजनैतिक या प्रशासकीय केन्द्र, वस्तु निर्माण उपयोग केन्द्र या कारखाना, मनोरंजन केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, चिकित्सा केन्द्र या स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष केन्द्र स्थान आदि।[9] ऐसे स्थानों को भी सेवाकेन्द्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेवाकेन्द्र मूलतः एक भू-आर्थिक केन्द्र या राजधानी होता है। अतएव समीपवर्ती प्रदेश की आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र होना अनिवार्य है। तीसरी दशा पूरी होने पर दूसरी दशा स्वमेव पूरी हो जाती है। ऐसे स्थान जो केवल दूर के क्षेत्रों पर प्रभाव डालते है अथवा जो अस्थाई किस्म के होते है, केन्द्र स्थल नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ निवाड़ी की रेलवे बस्ती का अभ्युदय प्रारंभ में एक शुद्ध रेलवे स्टेशन के रुप में हुआ, सेवाकेन्द्र के रुप में नहीं, लेकिन अब वहाँ केन्द्रीय कार्यो का विकास हो जाने के कारण सेवा केन्द्र भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ की अधिकांश नगरीय जनसंख्या निर्माण कार्यों में लगी हुई है जो एक माध्यमिक कार्य है, और समीपवर्ती क्षेत्रों के लिये सेवापूर्ति का तृतीयक कार्य वहाँ नगण्य है। रेखाचित्र 3.1 में अधिवासों में आधारभूत कार्यो का संचयी आवृत्ति वक्र निर्मित किया गया है। जो सेवाकेन्द्रों की सघनता का द्योतक है।

2. सेवाकेन्द्रों का चयन और निर्धारण :

सेवाकेन्द्र शब्द का अर्थ जान लेने के बाद भी एक व्यवहारिक समस्या यहाँ बनी रह जाती है कि किसी क्षेत्र विशेष में कैसे अर्थात किन आधारों पर केन्द्र स्थलों का

Tikamgarh District
Cumulative Frequency Curves of All The Settlements (As) & The Settlement Having Function (Sf)
(A) Education
(B) Health
(C) Communication
(D) Credit
AS
PCS
PSG
Primary School
Junior High School
High School
Intermediate (10+2)
Collage & Others
Hospital
Dispensary
Primary Health Centre
Family Planning Centre
Subsidised Medical Practioner
Primary Health Sub-Centre
MCW CWC & Others
Sub Post Office
Branch Post Office
Telephone
Bus Stop
Railway
Co-Operative Society
Co-Operative Bank
Land Dev. Bank
Bundal Khand Rural Dev. Bank
Nitionalized Bank
A-Below 200-Persons
B-200 - 499 "
C-500 - 999 "
D-1000 - 1999 "
F-5000- Above "
G-Urban Area "
PSG- Size of Group of Population
PCS- Percent Inhabited Settlement

Fig 3.1

निर्धारण या चयन किया जाये, क्योंकि किसी बृहदाकार प्रदेश में बस्तियों, स्थानों और केन्द्र स्थलों की संख्या बहुत अधिक होती है और विस्तृत, असीमित और सतत जनसंख्या के केन्द्र स्थलों का अध्ययन व्यवहारिक रुप में सम्भव नहीं है। केन्द्रस्थलों का निर्धारण किन्हीं निश्चित मापदण्डों के आधार पर ही किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र जितना ही बृहत होता है उतनी ही सीमित ओर सामान्यीकृत भी होता है और इसके विपरीत लघु आकार के प्रदेशों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संभव होता है। छोटे क्षेत्रों के सभी केन्द्र स्थलों का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन बड़े प्रदेशों में उनकी संख्या सीमित या कम करने की आवश्यकता भी पड़ती है। ऐसा करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि अधिक महत्वपूर्ण केन्द्रस्थल छूट न जाए। केन्द्रस्थलों के निर्धारण में दूसरा प्रश्न इच्छित आंकड़ों एवं तथ्यों की उपलब्धि का है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में केन्द्रस्थलों के निश्चित या परिणामात्मक मापदण्डों का उपयोग नहीं किया जा सकता। हमें प्रायः सभी अध्ययनों में अपने विश्लेषण की आधार मुख्य रुप से जनगणना एवं अन्य सहकारी सूचनाओं एवं अन्य तरह के आंकड़ों का संग्रह अपेक्षाकृत एक दुष्कर कार्य है और आंकड़ों की शुद्धता भी संदिग्ध होती है चूँकि हमारा अध्ययन व्यवहारिक रुप से प्रायः ऐसे ही सरकारी एवं अर्ध-सहकारी आंकड़ों पर आधारित होता है, इसलिए प्रदेशों, नगरीय क्षेत्रों एवं प्रशासकीय सीमाओं के अनेक निर्धारणों और परिसीमाओं को उसी रुप में स्वीकार करना पड़ता है, भले ही वे वास्तविक भौगोलिक व्यवस्थाओं से न मिलता हों।

सेवा केन्द्रों के चयन के लिए कई प्रकार के आधारों एवं पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सेवाकेन्द्र के निर्धारण में उसकी परिभाषा की सबसे अधिक सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे केन्द्र स्थलों का निर्धारण या चयन, केन्द्रीयता ज्ञात करना और प्रभाव क्षेत्रों की सीमांकन ये तीनों समस्यायें एक दूसरे से निकटतम सम्बन्धित अथवा अन्योन्याश्रित होती हैं और केन्द्रीयता को ज्ञात करने के उपरान्त प्रभावकारी क्षेत्रों का सीमांकन असानी से किया जा सकता है। सेवाकेन्द्र के निर्धारण में क्षेत्रीय विशालता और आंकड़ों की उपलब्धि पर आधारित होती है। इस हेतु अलग-अलग मापदण्डों का सहारा लिया जाना अनिवार्य हो सकता है। हमारा आधार जितने अधिक परिमाणात्मक या संख्यात्मक होगें सेवाओं के विश्लेषण में

उतनी ही सुविधा होगी। छोटे क्षेत्रों की विशेषताओं के आधार पर सभी सेवा केन्द्रों को अध्ययन के लिये चुना जा सकता है, क्योंकि तभी हमारा अध्ययन पूर्ण एवं यथार्थ होगा। केन्द्रस्थलों के चयन के समय बहुत से परस्पर सम्बन्धित प्रश्न स्वतः सामने आते हैं -

1) क्या कोई स्थान या केन्द्र पास के क्षेत्रों की सेवापूर्ति करता है या नहीं और यदि करता है तो कौन-कौन सी आवश्यकताओं की । इन बातों का निश्चित और तथ्यात्मक प्रत्योत्तर होना चाहिये।

2) क्या किसी स्थान या बस्ती में केन्द्रीय या स्थानीय जनसंख्या के अतिरिक्त और भी क्षेत्र सम्मलित हैं।

3) केन्द्रस्थलों के भिन्न-भिन्न और जटिल ढंगों के कार्यो और सेवाओं में से किन-किन पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाय।

4) किसी क्षेत्रं की असंख्य बस्तियों और स्थानों में से किन-किन की परीक्षा मापदण्डों से की जाये इत्यादि प्रश्न एक दूसरे से सम्बन्धित होकर सेवा केन्द्र की महत्ता को और अधिक स्पष्ट करते है।

सेवाकेन्द्रों के चयन में सबसे अधिक स्पष्ट और उत्तम मापदण्ड केन्द्रीय सेवाओं और सस्थानों का है। इन कार्यात्मक संस्थानों या इकाईयों में जो अधिक भौतिक या महत्वपूर्ण हैं उनके आधार पर हम उन स्थानों को चुन सकते हैं। जिनमें वे विद्यमान हों, जैसे-प्रतिदिन का क्रय-विक्रय, कपड़ा की दुकानों, चिकित्सालय या दवाईयों की दुकानों, हाईस्कूल इत्यादि। इसी प्रकार बस सेवाओं के आधार पर भी भूगोलविद सेवाकेन्द्रों की केन्द्रीयता का चयन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे केन्द्रस्थल जो सेवापूर्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बस सेवाओं की अनुपस्थिति के कारण छूट सकते हैं। केन्द्रस्थलों के चयन में केन्द्र ओर उसके क्षेत्र के बीच की अन्य सेवाओं या क्रियाओं की सहायता भी ली जा सकती है। माडल 3.2 में केन्द्रीय स्थानों का विघटन एवं प्रसरण दर्शाया गया है।

Model For

Central Place Diffusion

(A) Christaller Landscape K=3

(B) Christaller Landscape With Undivided Settlements
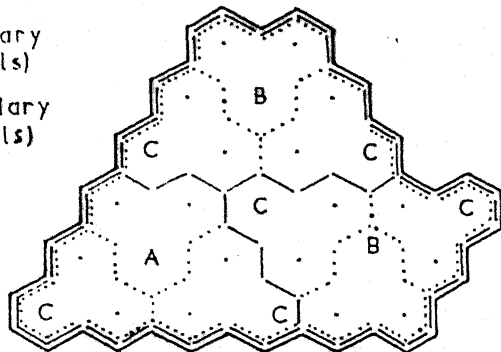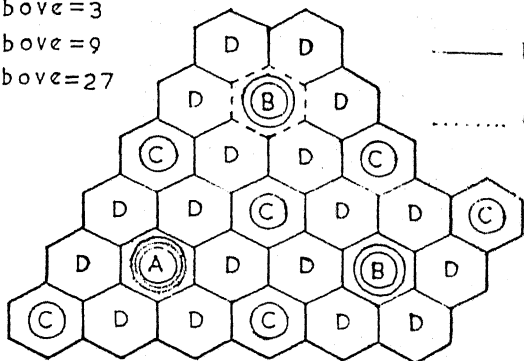
(C) Purely Hierarchic Diffusion Process From "A" [Numbers Indicate Time Period Of Innovaton

(D) Purely Neighbourhood Effect From "A"
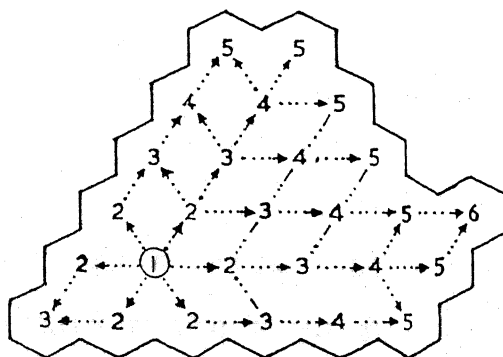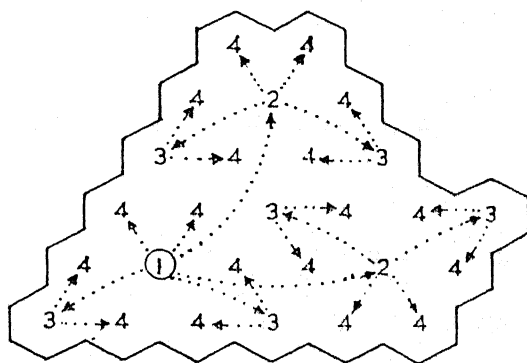
(E) Combined Hierarchic And Neighbourhood Processes
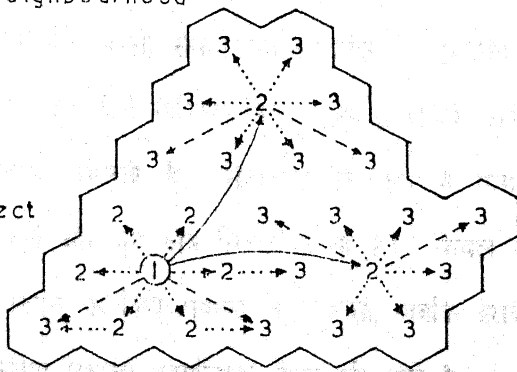
Source : Haggett, Cliff, Frey : Locational Models, P. 241.

Fig 3.2

सेवाकेन्द्रों के निर्धारण की एक व्यवहारिक विधि व्यक्तिगत सर्वेक्षण या क्षेत्र अध्ययन के आधार पर हो सकती है। इसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कौन-कौन से स्थानों में बाह्य सेवा पूर्ति की विशेषतायें और नियंत्रित प्रभाव क्षेत्र मिलते हैं प्रश्नावली की सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन-कौन संस्थान या बस्ती किन सेवा केन्द्रों पर निर्भर है लेकिन यह विधि अधिक कष्टसाध्य होने के साथ-साथ छोटे क्षेत्रों के लिए ही अधिक उपयोगी है। केन्द्रस्थलों की दूसरी निर्धारण विधि जनसंख्यात्मक हो सकती है। चूँकि वाणिज्य का कार्य केन्द्रस्थलों का सर्वाधिक मूलभूत और व्यापक कार्य हैं, इसलिये केन्द्रों की पूरी जनसंख्या में वाणिज्य कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के प्रतिशत मूल्य की कोई आधार संख्या ली जा सकती है और यह प्रतिशत संख्या प्रादेशिक मध्य मान से कम नहीं होनी चाहिये।[10] केन्द्रीय जनसंख्या की आन्तरिक संरचना, आकार और घनत्व के आधार पर भी केन्द्रस्थलों का चयन किया जा सकता है, कयोंकि जनसंख्या की विशेषतायें भिन्न-भिन्न केन्द्रों का सपेक्षिक महत्व भी प्रायः दर्शाती है, ऐसा करते समय सेवापूर्ति के लिये आधारभूत कार्य में लगी जनसंख्या पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा, विशेषतः वाणिज्य के आर्थिक कार्य में लगी जनसंख्या पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा ।

3. वर्तमान सेवाकेन्द्र ओर उसका नियोजन :

केन्द्रीय स्थान और सेवाकेन्द्र शब्दों का उपयोग एक दूसरे के पर्याचवाची के रुप में किया जाता है, जो अपनी बस्तियों के अन्तर्गत की कृषिगत क्रियाओं को प्रदेश के अंदर ही पूर्ण करते हैं।[11] कोई एक केन्द्र जिसमें कुछ निश्चित महत्व के कार्य जो वहाँ की जनसंख्या ओर चारों ओर के क्षेत्र को अपनी सेवाऐं प्रदान करते हैं, प्रादेशिक नाभिक बिन्दु कहलाते है। ये समस्त विभिन्न स्तरों वाले नाभिक बिन्दु जहाँ सामाजिक आर्थिक क्रियायें और सामूहिक स्थान सम्मिलित है, परस्पर मिलती है, सेवाकेन्द्र के रुप में कहलाती है। एक केन्द्र के साथ इस परिवर्तन में चारों और का क्षेत्र निर्भर करता है। केवल केन्द्रीय अवस्थिति एक स्थान के नाम जैसे-केन्द्रीय स्थान के लिये पर्याप्त नहीं होती, जबकि इसके अन्दर केन्द्रीय कार्यों और सेवाओं से सम्बन्धित न्याय प्रभुत्व कार्यात्मक केन्द्र भी आते है। इस प्रकार केन्द्रीय

स्थान स्थित अपने पड़ौसी क्षेत्रों को सेवायें प्रदान करती हैं और इस प्रकार की सेवाओं को सेवाकेन्द्रों के अन्दर सम्मिलित किया जाता है। एक सेवाकेन्द्र के किसी निर्धारित स्थान के विशष्ट केन्द्रीय कार्यों के आधार पर परिभाषित किया जाता है जो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। और दूसरे क्षेत्रों की आवश्यकतओं की भी अपनी सेवायें प्रस्तुत करता है। किसी सेवाकेन्द्र की प्राथमिक विशेषताओं के अन्तर्गत वस्तुओं के आदान-प्रदान ओर क्षेत्र के लिये सेवाओं की अपनी क्षमता द्वारा प्रस्तुत करना है। ये केन्द्र आय और व्यय केन्द्रों के समान कार्य करते हैं, इसलिये प्रादेशिक आर्थिकी को अग्रसर करते हैं। जिससे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक स्तर ऊँचा उठता है। इसी प्रकार सेवाकेन्द्रों का विश्लेषण जैसे कि केन्द्रीय स्थान है। क्रिस्टालर[12] ने इसे दृष्टिगत किया है । भारत में सेवाकेन्द्रों का अस्तित्व ओर उनका सांस्कृतिक स्वरुप केवल उच्च वर्ग के सेवाकेन्द्र जेसे नगरीय केन्द्र प्रादेशिक संतुलित ओर समाकलित विकास के लिये (विशिष्टतया कृषि) निम्न और उच्च वर्ग के सेवा केन्द्रों के समुचित विकास की शीघ्र आवश्यकता दृष्टिगत होती है। क्षेत्रीय योजना की रुपरेखा में ये सेवाकेन्द्र केन्द्रीय विस्तार और परस्पर कार्यात्मक तीव्रता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेवाकेन्द्रों के लिये कुछ आधारभूत मान्यतायें प्रादेशिक स्तर पर पायीं जाती है जो प्रादेशिक निर्माण में मानवीय क्षेत्रीय विशेषताओं को प्रस्तुत करती है। सामान्यत: निम्नलिखित चार मान्यतायें अध्ययन के अन्तर्गत होनी चाहिए।

1) एक सेवा केन्द्र मनुष्य की स्थायी बस्ती होती है।

2) वस्तुओं का आदान प्रदान सेवाकेन्द्र और उसके चारों ओर के क्षेत्र के मध्य आवश्यकताओं की पूत्रि परस्पर निर्धारित होनी चाहिए। इस प्रकार कुछ निश्चित वाणिज्यिक और अन्य सेवाओं का निर्वाह सेवाकेन्द्रों में हो सकता है।

3) कार्यत्मक स्तर का विभाजन चारों ओर की बस्तियों पर निर्भर होगा, जो कि सामाजिक आर्थिक ओर प्रशासनिक स्तर की आवश्यकतओं की पूर्ति करती है।

4) निम्न वर्ग के केन्द्रों को आत्म निर्भरता प्रदान की जाये और इनकी निर्भरता उच्चवर्गीय केन्द्रों से भी होनी चाहिए। सेवाकेन्द्रों और कार्यो को कमी के

आधार पर रोका जा सके।

किसी क्षेत्र के सन्तुलित विकास के लिये, सामाजिक और आर्थिक कार्यों के लिए दूसरे समीपवर्ती क्षेत्रों से सहायता लेनी पड़ती है। केन्द्रीय बिन्दु के कार्यात्मक सम्बन्ध का निर्धारण गाँव के समूहों के साथ वास्तविक योजना इकाई के लिये किया जा सकता है। क्योंकि केन्द्रीय बस्ती अपने समीपवर्ती बस्तियों को विभिन्न सुविधायें वितरित करते हैं। क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की विकास की संकल्पना का आधार विकास केन्द्र (उत्पत्ति केन्द्र) सम्पूर्ण तथ्यों को एक नया मार्ग प्रस्तुत करता है। विकास के सभी तत्वों, वास्तविक योजना केन्द्रों और सेवा प्रदत्त केन्द्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के रहन सहन स्तर को ऊँचा रखना होता है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के उपरान्त यह पाया गया है कि समीपवर्ती ग्रामों के ग्रामीण लोग अपने पास की विकास खण्ड क्रियाओं की और, ग्रामों की दूरियों की जानकारी रखते है, उन्हीं जानकारियों एवं संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण किया गया है, वास्तव में अध्ययन क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक एवं आर्थिक स्थानान्तरण केन्द्रीय प्रभावशाली साधनों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मानव के सम्पूर्ण कार्यो का प्रारम्भ एवं संचालन स्थानिक आकार द्वारा निर्मित होता है। यहाँ सभी बस्तियों में सभी संसाधन उपलब्ध नहीं है और न ही उनका वितरण एक समान है जिससे कि प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक कार्य के लिये अपने ऊपर आश्रित हों। प्रादेशिक योजनाविदों के लिये ग्राम ओर नगरीय स्तर पर क्षेत्रीय स्वरुप निर्मित करते समय भौगोलिक बिन्दुओं के निर्धारण की प्रमुख समस्या है। यह समस्या निर्धारित स्थान पर क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर अधिक आती है। वृद्धि जनक पद्धति के ढांचे में संवाकेन्द्र पद्धति को वास्तव में उक्त विश्लेषण में प्रस्तुत किया गया।[13] वृद्धिजनक पद्धति आधारभूत गतिक संकल्पना को वृद्धि ध्रुव सिंद्धांत (Growth Pole Theory) और स्थिर केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त (Central Place Theory) में आवश्यक परिवर्तनों के आधार पर आर्थिक वृद्धि उत्पन्न होती है और प्रादेशिक जनसंख्या को सेवाऐं प्रदान कर आत्म निर्भर क्षेत्र को बनाया जा सकता है। सारणी 3.1 में सेवा केन्द्रों के निर्धारण हेतु विभिन्न कार्यों को दर्शाया गया है।

सारणी 3.1 : जिला टीकमगढ़ में विभिन्न कार्यों के आधार पर प्रवेश बिंदु एवं जनसंख्या सीमांकन

क्रमांक	कार्य	प्रवेश बिंदु	प्रवेश बिंदु के ऊपर के सेवाकेन्द्रों की संख्या	कार्य रखने वाले सेवा केन्द्रों की संख्या	जनसंख्या सीमांकन	जनसंख्या सीमांकन सूचकांक
1.	फुटकर दुकानें	178	742	850	867	100
2.	दूरभाष केन्द्र	214	713	31	23773	2742
3.	औद्योगिक क्षेत्र	237	697	1	736981	85003
4.	आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र	394	546	26	28345	3269
5.	नाई गिरी	448	500	811	909	105
6.	चाय की दुकान	484	476	481	1532	177
7.	चिकित्सा सुविधायें	502	455	458	1609	185
8.	भेड़ प्रजनन केन्द्र	549	418	1	736981	85003
9.	साईकिल मरम्मत का कार्य	585	399	781	944	109
10.	दर्जी	658	353	742	993	114
11.	धोबी-गिरी	682	341	480	1535	177
12.	हस्त करधा/पावरलूम	758	300	54	13648	1574
13.	आटा-चक्की	773	293	635	1161	134
14.	बढ़ाई-गिरी	795	280	727	1014	117
15.	कृषि यंत्र मरम्मत एवं निर्माण	827	266	611	1206	139
16.	प्राईमरी स्कूल	828	264	683	1079	124
17.	हैयर कटिंग सैलून	828	264	70	10528	1214
18.	औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र	852	256	507	1454	168
19.	मत्स्य संवर्धन केन्द्र	877	243	1	736981	85003

सारणी 3.1

क्रमांक	कार्य	प्रवेश बिंदु	प्रवेश बिंदु के ऊपर के सेवाकेन्द्रों की संख्या	कार्य रखने वाले सेवा केन्द्रों की संख्या	जनसंख्या सीमांकन	जनसंख्या सीमांकन सूचकांक
20.	जूता मरम्मत एवं निर्माण	890	238	521	1414	163
21.	मिष्ठान भण्डार	928	220	208	3543	4009
22.	व्यक्तिगत खाद्य विक्रेता	966	217	52	14173	1635
23.	लकड़ी/बाँस उद्योग	999	208	324	2275	262
24.	जनरल स्टोर	1068	182	31	23773	2742
25.	फुटकर सिले कपड़े की दुकान	1090	177	34	21676	2500
26.	स्वर्ण आभूषण निर्माण	1096	173	103	7155	825
27.	पुस्तक एवं स्टेशनरी की दुकान	1175	159	54	13648	1574
28.	विद्युत सामान की दुकान	1265	141	74	9959	1149
29.	रेडियो एवं घड़ी मरम्मत	1335	131	38	19394	2237
30.	सहकारी उचित मूल्य की दुकान	1422	120	360	2047	236
31.	गोबर गैस संयत्र	1449	113	29	25413	2931
32.	बुनियादी प्रशिक्षण संस्था	1551	97	1	736981	85003
33.	ऋतु विज्ञान उपकेन्द्र	1551	97	1	736981	85003
34.	आटो मोबाइल्स सुधार केन्द्र	1557	91	19	38788	4474
35.	चाइल्ड वैल-फेयर केन्द्र	1639	86	1	736981	85003
36.	कृत्रिम गर्वाधान उपकेन्द्र	1685	80	36	20472	2361
37.	धार्मिक स्थल	1709	77	6	122830	14167
38.	शाखा डाकघर	1765	71	158	4664	538
39.	मिडिल स्कूल	1801	68	153	3817	555
40.	दर्शनीय स्थल	1929	59	9	81887	9445

सारणी 3.1

क्रमांक	कार्य	प्रवेश बिंदु	प्रवेश बिंदु के ऊपर के सेवाकेन्द्रों की संख्या	कार्य रखने वाले सेवा केन्द्रों की संख्या	जनसंख्या सीमांकन	जनसंख्या सीमांकन सूचकांक
41.	दर्शनीय स्थल	1929	59	9	81887	9445
42.	बस स्टॉप	1936	59	165	4466	515
43.	साप्ताहिक बाजार	2058	48	157	4694	541
44.	फल एवं सब्जी की दुकान	2058	48	25	29479	3400
45.	लोहे की दुकान	2244	45	10	73698	8500
46.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2350	44	17	43352	85008
47.	शराब की दुकान	2490	34	135	5459	630
48.	नर्सरी (वन विभाग)	2492	34	9	81887	9445
49.	सब रेंज (वन विभाग)	2526	33	19	38788	4474
50.	मेडीकल स्टोर	2628	30	13	56691	6539
51.	हाईस्कूल	2686	30	64	11515	1328
52.	पशु औषधालय	2765	29	46	16021	1848
53.	सहकारी साक्ष्य नीति	2817	29	87	8471	977
54.	पिक्चर फ्रेमिंग	3046	26	6	122830	14167
55.	भोजनालय	3053	26	20	36489	4250
56.	फोटोग्राफर की दुकान	3233	26	19	38788	4474
57.	धर्मशाला	3432	21	30	24566	2833
58.	शीत गृह	3487	21	1	736981	58003
59.	शामयाना हाऊस	3654	18	11	66998	7727
60.	मोटर पार्टस एवं बैटरी	3933	15	5	147396	17001
61.	इन्टर मीडियेट (10+2)	3946	15	36	20472	2361

सारणी 3.1

क्रमांक	कार्य	प्रवेश बिंदु	प्रवेश बिंदु के ऊपर के सेवाकेन्द्रों की संख्या	कार्य रखने वाले सेवा केन्द्रों की संख्या	जनसंख्या सीमांकन	जनसंख्या सीमांकन सूचकांक
62.	मुद्राणालय	4007	15	6	122830	14167
63.	बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4056	15	43	17139	1677
64.	फोटो स्टेट की दुकान	4455	10	7	105283	12143
65.	साईकिल विक्रेता	4657	10	4	184245	21251
66.	ट्रांसपोर्ट	4657	10	4	184245	21251
67.	बस आपरेटर	4796	10	3	245660	28334
68.	टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र	4796	10	3	245660	28334
69.	कूलर, बक्से एवं अलमारी निर्माण	4998	9	3	245660	28334
70.	ब्रेड एवं डबल रोटी निर्माण	5231	9	1	736981	85003
71.	रेल्वे स्टेशन	5412	8	3	245660	28334
72.	बर्फ फैक्टरी	5668	7	5	147396	17001
73.	लॉंज	6050	7	1	736981	85003
74.	उप डाकघर	6684	7	17	42352	5000
75.	प्रतिदिन उपभोग की वस्तुओं का बाजार	6844	6	22	33499	3864
76.	आटा मशीन	7046	5	10	73698	8500
77.	ट्रेक्टर विक्रेता	7059	5	1	736981	85003
78.	राजस्व निरीक्षक मण्डल मुख्यालय	7413	5	17	42352	5000
79.	सहकारी बैंक	7529	5	17	42352	5000
80.	आटोमोबाइल्स विक्री केंन्द्र	8471	4	1	736981	85003
81.	पुलिस स्टेशन	9047	4	12	61415	7084

सारणी 3.1

क्रमांक	कार्य	प्रवेश बिंदु	प्रवेश बिंदु के ऊपर के सेवाकेन्द्रों की संख्या	कार्य रखने वाले सेवा केन्द्रों की संख्या	जनसंख्या सीमांकन	जनसंख्या सीमांकन सूचकांक
82.	राष्ट्रीय बैंक	9195	54	9	81887	9445
83.	पशु बाजार	9333	4	11	66998	7727
84.	कार्या.म.प्र. टैक्स्टाइल कार्पोरेशन	10462	2	1	736981	85003
85.	बीड़ी बनाने के कारखाने	10588	2	1	736981	85003
86.	पेट्रोल एवं डीजल वितरण	10645	2	4	184245	21251
87.	कृषि उपज मण्डी	10877	2	6	122830	14167
88.	पशु चिकित्सालय	11256	2	9	81887	9495
89.	विश्राम गृह	12690	1	6	122830	14167
90.	सब्जी मण्डी	12690	1	6	122830	14167
91.	सिलाई एवं बुनाई प्रशिक्षण केंद्र	13204	1	2	368490	42502
92.	रहट एवं थ्रेसर निर्माण	13204	1	2	368490	42502
93.	भूमि विकास बैंक	13343	1	7	105283	12143
94.	एलोपैथिक उपचार	13336	1	7	105283	12143
95.	महाविद्यालय	13742	1	5	147396	17001
96.	नर्सिंग होम	14118	1	1	736981	85003
97.	समाचार पत्र प्रकाशन केन्द्र	14118	1	1	736981	85003
98.	नगरपालिका मुख्यालय	14902	1	6	122830	14167
99.	विकासखण्ड मुख्यालय	14902	1	6	122830	14167
100.	तहसील मुख्यालय	15734	1	5	147396	17001
101.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	15942	1	4	184245	21251
102.	होम्योपैथिक उपचार	16388	1	3	245660	28334

सारणी 3.1

क्रमांक	कार्य	प्रवेश बिंदु	प्रवेश बिंदु के ऊपर के सेवाकेन्द्रों की संख्या	कार्य रखाने वाले सेवा केन्द्रों की संख्या	जनसंख्या सीमांकन	जनसंख्या सीमांकन सूचकांक
103.	मत्स प्रशिक्षण केन्द्र	17051	1	4	184245	21251
104.	वन परिक्षेत्र (वन विभाग)	17572	1	4	184245	21251
105.	पत्थर हस्तकला निर्माण केन्द्र	19414	1	3	245660	28334
106.	सिनेमा घर	21177	1	1	736981	85003
107.	कार्या. उप. मुख्य अभियंता विद्युत	27258	1	2	368490	42502
108.	कार्यालय सूचना एवं प्रकाशन	42354	00	1	736981	85003
109.	कार्या. वन मण्डलाधिकारी	42354	00	1	736981	85003
110.	कार्या. दि मध्य प्रदेश स्टेट मइनिंग कार्पोरेशन	42354	00	1	736981	85003
111.	कार्या. जिला उद्योग केन्द्र	42354	00	1	736981	85003
112.	कार्या. महिला बाल विकास विभाग	42354	00	1	736981	85003
113.	कार्या. जिला पुलिस अधीक्षक	42354	00	1	736981	85003
114.	कार्या. उप संचालक पशु चिकित्सा	42354	00	1	736981	85003
115.	कार्या. उप संचालक कृषि	42354	00	1	736981	85003
116.	कार्या. सिंचाई विभाग	42354	00	1	736981	85003
117.	कार्या. जन्म एवं मृत्यु पंजी.	42354	00	1	736981	85003
118.	भारतीय जीवन बीमा निगम	42354	00	1	736981	85003
119.	कार्या. लोक निर्माण विभाग	42354	00	1	736981	85003
120.	कार्या. ग्रामीण विकास अभि.	42354	00	1	736981	85003
121.	कार्या. जिला आपूर्ति एवं विपणन संघ	42354	00	1	736981	85003

सारणी 3.1

क्रमांक	कार्य	प्रवेश बिंदु	प्रवेश बिंदु के ऊपर के सेवाकेन्द्रों की संख्या	कार्य रखने वाले सेवा केन्द्रों की संख्या	जनसंख्या सीमांकन	जनसंख्या सीमांकन सूचकांक
122.	सघन श्वेच्छेदन केन्द्र	42354	00	1	736981	85003
123.	दूरदर्शन प्रसारण क्रन्द्र	42354	00	1	736981	85000
124.	कार्या. जिला अग्रणी बैंक	42354	00	1	736981	85003
125.	राज्य परिवहन सब डिपो	42354	00	1	736981	85003
126.	मुख्य डाकघर	42354	00	1	736981	85003
127.	जिला न्यायालय	42354	00	1	736981	85003
128.	टेलीफोन एक्संचेंज	42354	00	1	736981	85003
129.	कुकिंग गैस वितरण	42354	00	1	736981	85003
130.	जवाहर कृषि अनुसंधन केंन्द्र	42354	00	1	736981	85003
131.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था	42354	00	1	736981	85003
132.	शोध केन्द्र	42354	00	1	736981	85003
133.	जिला जेल	42354	00	1	736981	85003
134.	रोजगार कार्यालय	42354	00	1	736981	85003
135.	कार्या. उप संचालक शिक्षा	42354	00	1	736981	85003
136.	कार्या. अधीक्षक भू-अभिलेख	42354	00	1	736981	85003
137.	कार्या. जिला साख्यिकी	42354	00	1	736981	85003
138.	जिला मुख्यालय	42354	00	1	736981	85003
139.	राजीव गाँधी शिक्षा मिशन	42354	00	1	736981	85003
140.	जिला खनिज उत्खनन केन्द्र	42354	00	1	736981	85003

4. **सेवाकेन्द्रों के पदानुक्रम की संकल्पना :**

सेवाकेन्द्र वह अवस्थिति होती है जो अपने चारों ओर की बस्तियों को वस्तुऐं अथवा सेवाऐं प्रदान करती है। उस स्थान की केन्द्रीयता उसके किन्हीं आन्तरिक गुणों के कारण नहीं होती वरन् उस स्थान पर कुछ कार्यों स्थित हो जाने के कारण होती है। केन्द्रीय स्थान सिद्धांत की संकल्पना सर्वप्रथम दो शोधकर्ताओं क्रिस्टलर[14] और लॉश[15] अर्थशास्त्री ने की थी, इसके पूर्व लियोन लेनिनी ने इसके उद्भव के विचार प्रस्तुत किये थे। क्रिस्टालर का सिद्धांत मुख्यतः समकोण वितरण पर आधारित है, जबकि लॉश ने ऑंकड़ों के आधार मानकार अवस्थिति अर्थशास्त्र और प्रादेशिक वितरण को पुर्नस्थापित किया। दोनों शोधकर्ताओं के सिद्धांत तीन क्रियाओं पर आधारित थे ।[16] ये तीन कारण निम्नलिखित हैं -

1) क्षेत्रीय उपयोगी क्रियाओं का अस्तित्व एवं उनका वितरण ।
2) परिवहन मूल्य एवं उसकी तीव्रता ।
3) मापन का अर्थशास्त्र विनियोग एवं मानवीय पहूँच ।

क्रिस्टालर के अनुसार एक नगरीय केन्द्र को उत्पादक भूमि का एक निश्चित क्षेत्रफल आधारित रहता है, उस केन्द्र की सत्ता इसलिए बनी रहती है कि वह अपने चारों ओर के क्षेत्र की अनिवार्य सेवाऐं करता है।[17] कालान्तर में सेवाकेन्द्रों का अध्ययन इजाई[18], हैगरस्टेन्ड[19], बेरी एवं गैरीसन[20] और सेन[21] ने भी किया है।

प्रस्तुत सेवाकेन्द्र के पदानुक्रम की संकल्पना उक्त सिद्धातों का निष्कर्ष है तथा क्षेत्रीय वृद्धि ओर निर्माण आर्थिक विकास ध्रुव ब्रूस तथा ब्रेसी[22] तथा आर्थिक वृद्धि का प्रसार भौगोलिक घटनाओं पर निर्भर हैं। थाम्पसन[23] और हर्षमान [24] ने विभिन्न श्रेणी की वस्तुएं और सेवाएं, जनसंख्या का सीमांकन और उनके संसाधन केन्द्रों को विभिन्न वर्गो में विभाजित किये हैं, निम्नवर्ग के केन्द्र आधारभूत स्तरीय वस्तुओं ओर सेवाओं को न्यून दूरी तक ओर उच्च वर्ग के केन्द्र उच्च वर्गीय वस्तुओं और सेवाओं को बड़ी जनसंख्या वाले बृहत दूरी के क्षेत्रों तक पहूँचाते हैं, उच्च वर्ग के केन्द्र छोटे वर्ग के केन्द्रों को सुविधायें पहुँचाते हैं जबकि

निम्न वर्गीय केन्द्र निम्नतम केन्द्रों को सेवायें देते हैं, इस प्रकार क्षेत्र में सेवा केन्द्रों की एक श्रेणी निर्मित हो जाती है।

स्माल[25], ब्रूस[26], कार्टर[27], कैरोल[28] डिकिन्सन[29], ने सेवाकेन्द्रों ओर उनके पदानुक्रम के निर्धारण के लिये विभिन्न उपादानों का प्रयोग किया है। सेवाकेन्द्रों के परिचय के लिये विभिन्न परिचायात्मक तत्वों जैसे क्रेताओं के प्रति दुकानदारों का विक्रय व्यवहार, बैरी[30] द्वारा फुटकर व्यापार में रोजगार प्राप्त व्यक्ति गोडुलुण्ड[31] द्वारा, वाणिज्यिक जनसंख्या सिंह[32] और सिंह[33] ओर सिंह [33] द्वारा संयुक्त श्रेणी विधि, भाट[34] द्वारा उक्त आशय के लिये विभिन्न विधियों का उपयोग किया गया। टीकमगढ़ जिला का सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश लगभग ग्रामीण हैं, जहाँ वाणिज्यिक जनसंख्या केन्द्रीय स्थानों के परिचय के लिये अप्राप्त है, इस कारण दो विधियाँ वर्तमान अध्ययन में प्रयोग के तौर पर विश्लेषित की गयी है। व्यक्तिगत चुनाव ओर बाह्य तथा आन्तरिक सेवा क्षमताएं आदि, जिसमें प्रथम विधि को जनसंख्या सीमांकन विधि जो समुचित एवं यथेष्ठ परिणाम प्रस्तुत नहीं करती, जबकि दूसरी विधि में आंकड़ों द्वारा क्षेत्र में निश्चय आकलन प्राप्त किया गया है, समस्त क्षेत्र के प्रत्येक आवास क्षेत्र का सर्वेक्षण करना अत्यंत कठिन है। संसाधनों की अपर्याप्तता, संसाधनों के समय और परिवहन के साधनों की कमी के कारण चयनित व्यक्तियों, द्वारा प्राप्त सचनाओं के आधार पर सर्वेक्षण कार्य सम्भव हुआ है, इस कार्य के लिये इस कार्य को 150 प्रश्नों की तैयार किया गया था। वे कार्य जो पूर्व में ही क्षेत्र में प्राप्त थे, उन्हें विश्लेषण में सम्मिलित किया गया है। सामान्यतः यह देखा गया है कि यहाँ के केन्द्र कुछ विशिष्ट सेवाएं और कार्य कुछ दूरी तक प्रदान करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों की प्राप्त तीव्रता जितनी अधिक बढ़ेगी, वर्गों का महत्व उतना ही कम होगा, वास्तव में सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम इसी आधार पर निर्धारित होता है। नगरीय सेवाकेन्द्रों के पदानुक्रम को निर्धारित करने की अनेक विधियाँ है, किन्तु ग्रामीण सेवाकेन्द्रों के निर्धारण के लिये अभी तक एक विधि समग्र रुप से सेवाकेन्द्रों का निर्धारण नहीं करती। भारत में अनेकों प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताऐं हैं, जो ऐकिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं और ग्रामीण सेवाकेन्द्र पदानुक्रम घटते चले जाते हैं। उपरोक्त विद्धानों ने ग्रामीण सेवाकेन्द्रों के निर्धारण में पर्याप्त कार्य किया है।

REFERENCE

1. Tiwri, P.C., Rawat, J.S. and Pandey, D.C. (1983): Centrality and Ranking of Settlements : A Comparative study of Hills of Tarai Bhabar Region, District Nainital, D.P. Himalaya, The Deccan Geographers Vol.21, PP: 391-401.
2. Wamali, S. (1972) : Central Place and Their Tributary Population: Some observations, Behavioural scence and Community Development, NICD, HYderabad, 6 PP : 1-10.
3. Singh, J. (1979) : Central Place Hierarchy in a Backward Economy: Gorakhpur Region, Tijdschrift voor Economische in Sociale Geographic, 70, PP :300-6.
4. Decay, M.F. (1962): Analysis of Central Places and Point Patterns by a Nearest Neighbour Method, Land Studies in Geography, Series B, Human Geography, 24, PP : 55-75.
5. Christaller, W. (1966): Central Places in Sourthern Germany (Translated by C. Baskin), England cliffs, New Jursey.
6. Carol, H. (1960) : The Hierarchy of Central Places Functions with the city, A.A.A.G. 50 PP: 419-38.
7. Johnson, R.J. (1966): Central Place and the Settlement Pattern A.A.A.G. 56, PP : 541-49.

8. Mandal, R.B. (1975) : Central Place Hierarchy in Bihar Plain (N.G.J.I.) 21, PP : 120-26.

9. Marshal, J.V. (1964) : Model and Realities in Central Place Studies, Prof. Geographers, VOL. 16, PP : 5-8.

10. Wanmali, S. (1972) : Op cit P: 35.

11. Mishra, G.K. (1972) : A service Classification of Rural Settlements in Miryalguda Taluka of Andhra Pradesh, Behaivioural Sciences and Community Development, NICD, Hyderbad-6, PP : 64-75.

12. Christaller, W. (1966) : Die Seutrale Ortiem Suddentschi and Jena. G. Fisher (1933) Translated by C.W. Baskin, Englewood Cliffs, New Jursey, P-560.

13. Sen, L.K. *et. al.* (1975) : Growth Centres in Raichur: An Integrated Area Development Plan for a district of Karnataka, NICD, Hyderbad-6.

14. Christaller, W. (1966) : Opcit P: 593.

15. Losch, A. (1954) : The Economics of Location, Yale Universtiy Press, New Heaven.

16. Hersemansen, T. (1972): Development of Poles and Development Centres in National and Regional Dev., Elements of Theortical Frame works in A. Kuklinski(Ed.) Growth Poles & Growth Centres in Regional Planning, Monton Press.

17. Christaller, W. (1966) : Op. cit P: 595.

18. Isard, W. (1960) : Methods of Regional Analysis, MIT Press, Cambridge, Messachussettes.

19. Hagerstrand, T., (1967) : Innovation Duffision a spatial Process,, University of Chikago.

20. Barry, B.J.L. and and Garrison, W.L. (1958) : Recent Development of Central Place Theory, Papers and Proceedings of the Regional Science Association -4, PP : 107-20.

21. Sen, L.K. <u>et</u>. <u>al</u>. (1975) : Growth Centres in Raichur, An Integrated Area Development Planning for district in Karnataka, N.I.C.D. Hyderabad, P : 74.

22. Brush, J.E. and bracy, H.E., (1967) : Rural Service Centres in South Wiscensim and Southern England, Urban Geography (eds H.M. Mayer and C.F. Cohin) Allahabad, P : 213.

23. Thompson, I.B. (1966) : Some Problem of Regional Planning in Predominantly Rural Environment, The French Experience , in Crosea, Scottish Geographer Magezine, VOL. 85, P : 239.

24. Hershnian, A.O. (1958): The Strategy of Economic Development, New Heaven. P : 210.

25. Smiles, A.E. (1947): The analysis and Distribution of Urban Fields, Geography 32, PP: 151-61.

26. Brush, J.E. (1956) : The Hierarchy of Central Places in South Western Wisconsin, Geographical Review, 43, (1953), PP: 390-401 and Brush, J.F. and Howard, E.B., Rural Service Centres in South West Wisconsin and South England, Geographical Review 45, PP:413-17.

27. Carter, H.C. (1955): Urban Grades and Spheres of Influence in South West Wales, Scottish Geographical Magezine, 7, PP: 43.58.

28. Carol, H. (1960) : The Hierarchy of Central Places Functions within the city, A.A.A.G., 50, PP : 419-38.

29. Dikinson, R.E. (1932) : The Distribution and Functions of the Smaller Settlements of East Angila Geography, 17, PP : 19-31.

30. Berry, B.J.L. (1967) : Geography of Market Centres and Retail Distribution, Prinfice Hall, Englewood Cliffs, London Rep. 12, PP: 10-23.

31. Godlund, S. (1956) : The Functions and Growth of Bus Traffic within the sphere of Urban Influence, Land Studies in Geography Series, B. 18, PP : 13-20.

32. Singh, K.N. (1961) : Rural Markets and Urban Centres in Eastern U.P., A Geographical

Analysis, Ph.D. Thesis, banaras Hindu University, Varanasi, (U.P.).

33. Singh, O.P. (1971) : A study of Central Places in U.P. Towards Determining Hierarchy of Service Centres, N.G.J. 1, Varanasi, Vol. XVII, Pt. 4, PP : 171 - 72.

34. Bhat, L.S. et. al. (1976) : Micro Level Planning- A case study of Karnal Area, Haryana, K.B. Publication, New Delhi, PP : 65-105.

35. Sen, L.K. et. al. (1971): Planning of Rural Growth Centres for Integrated Area Development, A case study of Miryalguda Taluka, N.I.C.D., Hydrabad, P : 79.

-----0----

अध्याय चार

सेवा केन्द्रों का उद्भव एवं विकास

- प्राचीन काल
- मध्य काल
- आधुनिक काल
- पूर्व स्वतंत्रता काल
- स्वतंत्रता के पश्चात् का समय
- संदर्भित ग्रन्थों की सूची

टीकमगढ़ जिला के व्यक्तियों की व्यवसायिक और समूह प्राविधि के अनुसार सेवाकेन्द्रों के उद्भव को भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारकों के साथ विश्लेषित करता है। भूमि अधिग्रहण और आवासीय प्रतिरुप विभिन्न कालों में ग्रामीण भू-दृश्य को नया स्वरुप देते हैं इससे भारतीय इतिहास निम्नानुसार विकसित हुआ है और अध्ययन क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है।

सेवा केन्द्रों का उद्भव एवं विकास :

प्राचीन काल :

1. पूर्व आर्य काल (1750 से 500 ईसा पूर्व)
2. बुद्ध काल (500 से 325 ईसा पूर्व)
3. मौर्य और कुषाण काल (325 ईसापूर्व से 320 ईसवीं तक)
4. हिन्दू काल (320 ईसवी से 1200 ईसवीं तक)

मध्य काल :

5. पूर्व मध्य काल (1200 से 1526 ईसवी तक)
6. मुगल काल (1526 से 1764 ईसवीं)

आधुनिक काल :

7. ब्रिटिश काल (1764 से 1947 ईसवीं)
8. स्वतंत्र काल (1947 के उपरान्त)

पूर्व आर्य काल :

टीकमगढ़ जिले का प्राचीन इतिहास क्षेत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है विभिन्न समयों में इसे चेदी देश, चेदि राष्ट्र अथवा चेदि जनपद तदुपरान्त जयजकभुक्ति, और बाद में बुन्देलखण्ड के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में इस क्षेत्र में भील, कोल, सहारिया, गौड़, भार, बॉंगड़ और खॅंगार निवास करते थे जो आज भी जिले में न्यून संख्या में पाये जाते हैं।[1] अन्वेषण में कुछ प्राचीन औजार प्राप्त हुये जो उस समय की हाथ कुल्हाड़ी

संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। ये हाथ के बने औजार सैंडस्टोन के बने हैं और इन्हें बड़ी चतुराई के साथ बनाया गया हैं।[2]

आर्य यमुना और विन्ध्याचल [3] के बीच घिरी हुई चेदि देश की भूमि पर निवास करते थे इनका राजा कशुचेद्य था।(महाभारत) इस राजा ने अपनी स्वतंत्रता के लिये दान स्तुति की (ऋग्वेद आठ, 8,5,37 से 39)[4] किन्तु चेदि ऋग्वैदिक काल में चेदि प्रगट नहीं हुई[5] पौराणिक परम्परा के अनुसार मनु का पौत्र पूरावशऐला (जो इलाहाबाद के निकट हैं; में राज्य करता था) ने गंगा के द्वारा मालवा के पठार और पूर्वी राजस्थान [6] को जीतने के बाद झाँसी तथा टीकमगढ़ के इस क्षेत्र को अपने आधिपत्य में लिया इसके उपरान्त यदु ने चम्बल, बेतवा और केन नदियों द्वारा जलापूर्ति क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। [7] कुछ समय बाद हैहय वशियों और यादवों के बीच सीमा रेखा निर्मित हुई [8] और यादवों के राजा विदर्भ ने चेदि देश निर्मित किया ।[9] जो आधुनिक बुन्देलखण्ड के नाम से जाना जाता है।[10] महाभारत में वर्णित है कि कुरन और पांचाल एक दूसरे को सम्बन्धी मानते थे और मतस्यास से भी इनके सम्बन्ध बनते थे। चेदि राज्य उस समय के दशार्ण देश का एक प्रमुख जनपद था।[11] जिसका विस्तार मध्य देश तक था।[12] तथा चिवालरस क्षत्रियों के प्रमुख सहयोगी कृष्ण के द्वारा शासित था।[13]

बुद्ध काल :

वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से लेकर इस क्षेत्र में ग्राम समूहों का विकास नहीं हुआ था बल्कि इस वनाच्छादित भू-भाग पर यत्र-तत्र ऋषि मुनियों के आश्रम विद्यमान थे। इन ऋषि मुनियों के ज्ञान से आलोकित होकर यहाँ की जनजातियाँ विकास के प्रथम चरण को लाँघ कर द्वितीय सोपान में प्रविष्ट हुई और छठवीं शताब्दी से ग्राम समूहों का प्रार्दुभाव हुआ। परन्तु कृषि और उद्योग से शून्य इस पिछड़े भू-भाग पर वन सम्पदा एवं चरागाह ही आय के प्रमुख साधन थे ।

ईसा से 400 वर्ष पूर्व तक महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद मगध के नंद

साम्राज्य का विकास हुआ परन्तु हैहय वंशियों ने इन्हें शीध्र ही समाप्त कर दिया ये चेदि वंशियों को पसन्द करते थे जो यदुवंशियों के ही वंशज थे। और जो इस काल में मध्य भारत पर शासन कर रहे थे।[14] इसके उपरान्त इस क्षेत्र में शासक राजाओं का इतिहास 16 प्राथमिक राज्यों (महाजनपदों) में समाहित हो गया तथा वित्तिछोत्र ने चेदि के इस जनपद पर जिसे वर्तमान बुन्देलखण्ड कहते है उस पर राज्य किया तथा इसमें ओरछा स्टेट भी शामिल था। छठी ईसा पूर्व के मध्य में प्रदोत्य राजा ने वितिहोत्र को अवन्ती में समाप्त किया। चौथी ईसा पूर्व में नद राजा ने वितिहोत्र की सीमाओं को और आगे बढ़ाया लगभग 250 ईसा पूर्व यह राज्य मौर्य शासकों के हाथ में चला गया जिसकी राजधानी उज्जैन थी इसी समय कुमार अथवा आर्यपुत्र एवं राजकुमार कहने की परम्परा आरम्भ हुई।[15]

मौर्य और कुषाण काल :

शुंगों ने मौर्यों पर विजय प्राप्त की और बुन्देलखण्ड अथवा मालवा क्षेत्रों को मौर्यो के शासन से मुक्त किया और अग्निमित्र को यहाँ का राजा बनाया गया जिसकी राजधानी ✓ विदिशा थी शुंगो की विदिशा शाखा को जारी रखते हुये बन्देलखण्ड के इस क्षेत्र को अर्द्धमुक्त करते हुये मनुवो की राजधानी बनाया गया इस क्षेत्र का व्यापार एवं मार्ग मगध की ओर जाता था। शुंगों का शासन दकन के सात वाहनों द्वारा समाप्त किया गया और पहली शताब्दी तक यह प्रदेश कनिष्क द्वारा शासित कुषाण की राजधानी बना और वसुदेव के समय तक उसके अधीन रहा।[16] एलमी ने अपने भौगोलिक वर्णन में लिखा है कि यमुना नदी के दक्षिण में प्रसीक राजा की राजधानी कालिन्जर थी।[17] कुषाणों के आक्रमण के उपरान्त सालवाहन समाप्त हुये और पूरा क्षेत्र स्वतंत्र हुआ और इस पर अहीरों का शासन हुआ जो विदिशा और झाँसी मार्ग पर रहते थे तथा इस क्षेत्र को अहिखारा [18] कहा गया प्राप्त शिलालेखों में वंशी अहीर [19] का उल्लेख मिलता हैं। ईसवी शाताब्दी में विन्ध्य शक्ति नामक शासक ने सालवाहनों को समाप्त किया और नये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग पर शासन किया। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस राजा के सीधे शासन का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु विन्ध्य शक्ति के द्वितीय पुत्र गंधर्वसेन प्रथम ने बुन्देलखण्ड की सीमाओं को हैदराबाद राज्य तक बढ़ाया और

गौतमीपुत्री (भाराशिवा राज्य के भावनागा राजा की पुत्री) से विवाह कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया।[20] तीसरी शताब्दी में सालवाहनों के पतन का लाभ लेकर विन्ध्य शक्ति ने अपनी शक्ति को बढ़ाया इसी समय अनार्य नागों के के रुप में कुषाणों के पतन के बाद सामने आये और नागाओं ने तीसरी तथा चौथी शताब्दी में मध्य भारत के इस भाग पर राज्य किया। इनकी राजधानी नरवर थी पुराणों के अनुसार नागों के 9 सफल राजा हुये। और बहुतो ने अपने सिक्के चलाये।[21] इनमें भाव नागा, गणपति नागा प्रमुख है। गणपति नागा एक शक्तिशाली राजा था और गुप्त शासक समुद्र गुप्त से चौथी शताब्दी के मध्य में इसका युद्ध हुआ।[22]

हिन्दु काल :

चौथी शताब्दी के मध्य में यह क्षेत्र गुप्त शासकों के हाथ में चला गया और छठवीं शताब्दी तक इन्हीं के आधिपत्य में रहा इस समय तत्कालीन राज्य 'भुक्ति' जिसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड का बहुत सा क्षेत्र आता था चेदि भुक्ति के नाम से जाना गया और बाद में जयजकभुक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ।[23] गुप्त काल में जिला टीकमगढ़ में पर्याप्त प्रगति हुई गढ़-कुड़ार, अछरुमाता, इसी समय प्रकाश में आये। गुप्त काल में इस क्षेत्र में अनेक मंदिर, बावरिया और किले निर्मित किये गये। देवगढ़ का किला और विष्णु भगवान का मंदिर इसके उदाहरण है। इन मंदिरों के शिलालेखों और वास्तुशिल्प से गुप्तकाल के राजाओं की कला के प्रति गहरी रुचि दिखाई देती है। गुप्त राजाओं ने इस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों पर गाँव बसाये।[24] गुप्त शासन के पतन के अंतिम शासकों ने बुद्धगुप्त (477 से 500 ए.डी.) ने बुन्देलखण्ड के पारिवृजक महाराजा से संधि की कुछ वर्षो बाद बुद्धगुप्त के भाई नरसिंहगुप्त वालादित्य ने हूणों के राजा तोरामन से संधि की और ऐरन को अपनी राजधानी बनाया। छठी शताब्दी में पारिवृजक महाराजा के पुत्र समकशोमा जो गुप्तों के उत्तराधिकारी थे अर्द्ध स्वतंत्र होकर इस क्षेत्र में सातवीं शताब्दी के मध्य तक राज्य किया इसी समय ह्वेन्सांग यहाँ आया ह्वेन्सांग ने 641-42 में चीचीतो नामक पुस्तक में लिखा है कि यह क्षेत्र उत्पादकता के लिये प्रसिद्ध है और ब्राह्मण इस पर राज्य करते हैं। इसी समय जिझोती (जयजकभुक्ति) नाम इस क्षेत्र को दिया गया। यह भी सम्भव है कि यहाँ का राजा हर्ष (606 से 647) अपनी विस्तारवादी

नीति को संकुचित रखता हो। सातवीं शताब्दी के मध्य के बाद उत्तर भारत का इतिहास बेहद संयुक्त हो गया है। इसी समय पृथ्वीराज इस क्षेत्र में आया और गौड़ों के राजा के साथ मिलकर टीकमगढ़ के दक्षिण में एक नये राज्य की स्थापना की। विन्ध्याचल की पहाड़ियों के बीच गौड़ों का राज्य लम्बे समय तक फलता फूलता रहा इन राजाओं ने बहुत से पत्थरों के मंदिर बनवाये और इसी समय जैन मंदिरों का निर्माण भी गौड़ राजाओं ने नदियों को छोटे-छोटे बाँधों के द्वारा जलाशयों में बदला और कृषि के लिये सिंचाई का साधन अपनाया। यह उनके सभ्य समाज को दर्शाता है।[26] आठवीं शताब्दी में प्रतिहार राजपूतों ने इस क्षेत्र में गौड़ों के आधिपत्य को समाप्त किया और नोंवी शताब्दी में चंदेल राजा यहाँ आये आठवीं शताब्दी के पहले अर्द्ध में कन्नौज के राजा यशोवर्धन इस क्षेत्र में आये और आठवीं शताब्दी के अन्त में यह क्षेत्र प्रतिहारों के हाथ में चला गया। प्रतिहारो ने इस क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे गाँव बसाये और आवासों की प्राथमिक संरचना को जन्म दिया।[27]

चंदेलों का विश्वास था कि इस क्षेत्र में गौड़ तथा खँगार पुनः सत्ता में आ सकते हैं। अतः इन्होंने इस क्षेत्र से गौड़ों को दक्षिण पूर्व की ओर खदेड़ दिया।[28] चंदेलों के प्रमुख ने इस क्षेत्र को जयशक्ति, जिजाका, अथवा जीजा तथा बाद में प्राचीन शब्द भुक्ति को इससे जोड़ देने से जयजकभुक्ति का नाम दिया। हर्ष चंदेल का पुत्र रोहला बाद में गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद कन्नौज के महीपाल प्रथम कन्नौज छोड़कर राष्ट्रकूट को अपनी राजधानी बनाया हर्ष के पुत्र यशोवर्द्धन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अपने राज्य की सीमाओं को और अधिक बढ़ाया। कालान्तर में इस क्षेत्र यशोवर्द्धन से संग राजाओं के हाथ में चला गया तथा झाँसी के निकट इनकी राजधानी थी। 30 वर्ष बाद अरब यात्री अलबरुनी ने लिखा है कि यह एक बड़ा नगर था और ग्यारवीं शताब्दी का महत्वपूर्ण राज्य बन गया था। इसी समय इस क्षेत्र पर महमूद गजनबी ने अपना आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1022 में बड़ी सेना लेकर कालिन्जर में पुनः युद्ध किया तथा चंदेलों से हार गया। तत्कालीन शासक विद्याधर के पुत्र विजयपाल 1030 से 1050 और चंदेलों के पतन के बाद देववर्मन 1050 से 1060 तक इस गद्दी पर बैठा 1060 से 1100 ईसवीं तक देववर्मन [29] का पुत्र कीर्तिवर्मन

गद्दी पर बैठा और उसने कलचुरी के राजा कर्णदिव को कई बार हराया। 1100 से 1115 तक कीर्तिवर्मन के पुत्र लक्षवर्मन ने चेंदेल राज्य को और अधिक बढ़ाया। लक्षवर्मन के बाद जयवर्मन इसके बाद पृथ्वीवर्मन, मदनवर्मन और बाद में यशोवर्मन गद्दी पर बैठा। इसी समय छोटे-छोटे पर्गनों में राज्य को विभक्त किया गया।[30] और चंदेलों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी कराया। चंदेलों के इस शासन काल में इस क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास हुआ, जनसंख्या में समरुपता बढ़ी, अनेकों तालाब, मंदिर और बावरियाँ बनवायी गयी तथा छोटे छोटे बाँध बनाये गये। लिधौरा, पाली, वासी, दौलतपुर, मड़खेरा, सिरोन आदि पर्गना इसी समय निर्मित किये गये इसमें कोई सन्देह नहीं है कि चंदेल राजाओं ने इस क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या को बहुत हद तक हल किया है। बहुत से गाँवों में जहाँ गन्ना बोया जाता था प्राचीन शक्कर मिलों की स्थापना की जो पत्थरों द्वारा बनायी जाती थी।[29] गंगा, यमुना के द्वार से दकन तक इस क्षेत्र से होकर व्यापारी गुजरते थे। इसी समय सेवाद, वैष्णववाद, जैनवाद तथा हिन्दू वाद के साथ साथ बौद्धवाद निर्मित हुये। देहली के सुलतान के आगमन के बाद इस क्षेत्र में चंदेलों का शासन समाप्त हुआ तथा मुहम्मद गौरी ने कई बार इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। तुर्की शासक कुतुबुद्धीन ऐबक ने कालिन्जर के किले पर हसन अरनाल[31] की कमान के साथ चंदेलों पर चढ़ाई की।

पूर्व मध्य काल :

चंदेलों के पतन के बाद यह क्षेत्र 1232 ईसवीं में इल्तुतमश के कब्जे में आया। 1235 में कालिन्जर ने एक सुबेदार छोटी सी सेना के साथ छोड़ दिया गया। इस क्षेत्र के राजा को राज्य का पाँचवा हिस्सा सुबेदार को सौपना पड़ता था। 1251 में बलवन ने इस क्षेत्र पर चढ़ायी की और त्रिलोक्यवर्मन को समाप्त किया। त्रिलोक्यवर्मन के बाद वीरवर्मन ने इस क्षेत्र पर राज्य किया। यही समय बुन्देल शासक सोहनपाल का समय था, जिसने खँगार क्षत्रियों को मार भगाया। 1257 में ही बेतवा नदी के किनारे गढ़कुडार में सोहनपाल मारा गया। 1291-92 में आलाउद्दीन खिलजी इस जिले से होकर गुजरा और चंदेरी पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक तमार को इस क्षेत्र की सूबेदारी सौंपी। इसके बाद

आले सुलतान कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक खुसरो खॉन को इस क्षेत्र का राज्य सौंपा। 1325 से 1351 यह क्षेत्र मुहम्मद बिन तुग्लक के राज्य में रहा और इस क्षेत्र का शासन चंदेरी मुख्यालय द्वारा होता था। इबनेबटूटा ने इस क्षेत्र में शान्त परिस्थितियाँ देखी है। इसके बाद यह क्षेत्र कालपी के राजा नसरुद्दीन के हाथ में चला गया और बाद में अनेक मुस्लिम शासकों ने यहाँ राज्य किया। इनमें मलिक जफर, नसीर खॉन, जलाल खॉन, मुबारक खॉन आदि प्रमुख थे। इसके बाद इब्राहीम शाह शारकी ने ऐरच और ओरछा पर फतह की 1434-35 में रामदुगर ने ऐरच पर चढ़ायी की और जतारा के निकट स्माईल खॉन को परास्त किया तथा स्माईल खॉन की पुत्री को उठाकर ले गया। जिससे बाद में विवाह कर लिया। अगले 30 साल का इतिहास इस क्षेत्र में बुन्देल राजपूतों के जन्म का इतिहास है। गढ़कुडार के बुन्देलों ने सर्वप्रथम अपने राज्य की सीमाओं की फैलाना प्रारम्भ किया और दक्षिण में चंदेरी से उत्तर में कालपी तक ले गये। गढ़कुडार के राजा मलखान सिंह का युद्ध बहारुल लोदी से हुआ। बाद में लोधी के सत्ता को स्वीकार किया जिसमें 1468 से 1501 ईसवीं तक अपने पुत्र रुद्र प्रताप ने सर्व प्रथम ओरछा का राजधानी बनया। 1509 में चंदेरी के राजा ने उत्तरी राज्य को महमूंद खॉन लोदी को सौंप दिया। 1517 के बाद राजपूतों ने पुनः इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जिन्हें कालान्तर में इब्राहीम लोदी ने हराया।

मुगल काल :

बावर के आगमन के बाद आलम खॉन ने इस क्षेत्र को 25 लाख तनखो में खरीद लिया। बावर ने जलाल खॉन को 1527 में गिरफ्तार कर लिया। इसी समय बावर का युद्ध इब्राहीम लोदी से हुआ और मुगल शासन प्रारम्भ हुआ। इनका यह शासन कालिन्जर से कालपी तक फैला हुआ था। बावर ने ज्यों ही चंदेरी कालपी को हाथ में लिया त्यों ही रुद्रप्रताप ने मुगलों के आक्रमण से आशंकित होक कुड़ार को सैनिक केन्द्र बनाया। जिसका प्राचीन नाम ओरछा था। ओरछा दुर्ग बेतवा के चट्टानी सुड़ा पर ओर से छोर तक अथवा आरपार बना है। ओरछोर से ओड़छा तथा अग्रेजी भाषा के प्रभाव से ओरछा हो गया। इसका प्राचीन नाम गंगापुरी था जो प्रतिहारों की राजधानी थी। महाराजा रुद्रप्रताप ने कुड़ार को खाली

करने की दिशा में सर्वप्रथम ओरछा को सैनिक छावनी का स्तर दिया और 1531 में ओरछा दुर्ग का शिलान्यास कर नगर की स्थापना की वे भी कुड़ार में रहते थे तो कभी ओरछा में। रुद्रप्रताप के 12 वे पुत्र भारतीचन्द्र और ग्यारवे पुत्र मधुकर शाह ओरछा के राजा रहे। तथा उदयादित्य को नुनामहेवा 32 (लिधौरा की जागीर ली गई) भारतीचन्द्र ने नगर की सुरक्षा हेतु बेतवा के वामपाशर्त में 12 मील लम्बा विशाल नगर कोट का निर्माण कराया। शेरशाह की मृत्यू के पश्चात उसके पुत्र स्लामशाह सूर ने पूर्वी बुन्देलखण्ड को अपने अधिकार में लेकर जतारा को सिलामावाद नाम से अपना मुख्यालय बना लिया था। परन्तु महाराजा भारती चन्द्र ने उसे बुन्देलखण्ड से खादेड कर पुनः जतारा नाम दिया। जतारा क्षेत्र उपजाऊ और सम्पन्न क्षेत्र रहा है इसीलिये मुगलों ने इसे लेने की बार बार चेष्टा की। जतारा के बारे में प्रसिद्ध है नौ सो वेर नवासी कुँआ छप्पन ताल जतारा हुआ। अकबर के समय बुन्देलखण्ड के ऐरच, कालपी, भाडेक, विजपुर और जतारा महल सुवा आकरा से नियमित होते थे। 1785 में अकबर ने मधुकर शाह को दक्षिण में चढ़ाई करने के लिये निर्देश दिया किन्तु इनके द्वारा अवहेलना करने पर 1587 में शाही सेना ने चढ़ाई कर दी रामसहाय की गद्दी पर बैठते ही ओरछा राज्य के 22 टुकड़े हो गये। 1599 में वीरसिंह का युद्ध सलीम से हुआ। सन् 1602 में वीरसिंह ने अबुल फजल को मार डाला। ओरछा दरबार रिकार्ड रजिस्टर 83 में उल्लेख हे कि वीरसिंह ने मुगल सेना को तंग कर समाप्त करने के लिये क्षेत्र के कुँओ को विषाक्त करा दिया था।

वीरसिंह देव प्रथम ने अपनी 52 वी वर्षगाँठ पर सन 1618 ईसवी में 52 स्थापत्यों की शिला रखी ये स्थापत्य उनकी बुन्देलां स्थापत्य शैली के प्रतीक है। परसी ब्राऊन ने उन्हें बुन्देला स्थापत्य शैली का जनक कहा है। उन्होंने सात किले बनवाये, जो झाँसी, छामोनी, दिनारा, करेला, कुड़ला, गटमऊ और दतिया में खड़े है। उसी समय ओरछा में जहांगीर महल, चित्रकूट ओरछा, नौवत खाना ओरछा, शहरपनाहा ओरछा और शिकारगाह ओरछा है। उन्होंने चार तालाब बनवाये जो वीरसागर वीरगढ़ (पृथ्वीपुर के पास) सिंह सागर कुड़ार, देव सागर दिनारा और समुद्र सागर, नदनवारा है। जो सरोवर स्थापत्य के प्रतीक है। उन्होंने यात्रियों की सुविधा हेतु सात बावरियों का निर्माण भी कराया। ओरछा में इसके अतिरिक्त चार

बगीचों का निर्माण, नौ चौक महल, 12 मंदिर वीरसिंह ने बनवाये थे। सन् 1627 से 34 तक जुझारसिंह ओरछा का राजा रहे। सन् 1641 से 53 तक टहरी के जागीरदार ओरछा की राजगद्दी मिली। सन् 1664 में सम्राट औरगजेब ने मजाराजा जससिंह के साथ युद्ध करने के लिये सुजानसिंह को पुरन्दर दुर्ग भेजा। महाराजा सुजानसिंह ने अरजाड़ ग्राम में विशाल सुजान सागर तालाब बनवाया। सुजानसिंह की माता हीरादेवी ने हीरा नगर (बावरी) कस्बा और उनकी रानी बृजकुमारी ने रानीपुर ग्राम बसाया था रानी ने अड़जार तालाब के पीछे 10 कि.मी. क्षेत्र में सुन्दर बगीचा लगवाया था। इसके उपरान्त 1675 से 84 में यशवंत सिंह गद्दी पर बैठे। 1684 से 79 तक यशवंत सिंह के पुत्र भगवंत सिंह और बड़ागाँव कुटुम्ब से उध्योदत्य सिंह 1679 से 1736 तक गद्दी पर बेठे उध्योदत्य सिंह मुगल सम्राट बहादुर शाह, जहाँदार शाह, फख्क शियर ओर मुहम्मद शाह के समकालीन थे। उध्योदता सिंह के समय आंतरिक जागीरदार भी उपद्रव करने लगे थे। उध्योदत्य सिंह ने बरुआ सागर में उध्योदत्य सागर, ओरछा में उध्योदत्य निवास, उध्योदत्य मुहल्ला तथा उध्योदत्य मंदिर बनवाया था। उनके अधीन 17 परगना, 1926 ग्राम, 2533207 रु. वार्षिक आय के थे। उध्योदत्य सिंह के समय मोहनगर में मणिमाला चित्रकारी की गई जो अपनी में निराली है। पृथ्वीसिंह 1736 से 53 तक ओरछा राज्य बुन्देलखण्ड की एकता और स्थायित्व को मराठी ने हिलाना तथा बलात भूमि हड़प कर राज्य स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। पृथ्वीपुर दुर्ग इन्हीं ने बनवाया था। इसके बाद पृथ्वीसिंह गद्दी पर बैठे। मुस्लिम बादशाहों ने इस क्षेत्र पर कई आक्रमण किये। 1764 ईसवी में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना ने मुगल सत्ता को धक्का देकर अपने प्रसार और राज्य सत्ता का मार्ग निष्कंटक बना लिया था। इसके बाद मराठों ने ओरछा की घेराबन्दी की ओर निवाड़ी के दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। सावन सिंह के समय बड़ागाँव जागीर के आठ हिस्से होकर अष्टगद्दी नाम से प्रसिद्ध हो गये थे।

ब्रिटिश काल :

1765 से 75 ईसवी के दस वर्ष के अन्तराल में ओरछा गद्दी पर 4 अस्थिर राजा आसीन हुये जो मराठों के आक्रमण को सामना करने में असमर्थ थे। राज्य की सीमा

संकुचित होने लगी। इस समय टहरौली, सिमरा, जिरौन, पलेरा, देवराहा और मोहनगढ़ के जागीरदान अराजकता मचाये थे। ये सोर्ट एकाउन्ट औफ बुन्देला राजपुत चीफशिप इन सेन्ट्रल इण्डिया पृष्ठ 15 पर उल्लेख है कि झाँसी के नगरों के दमन अराजकता और लूट के कारण महाराजा विक्रमादित्य सिंह ने सन् 1700 ईसवीं में ओरछा के स्थान पर टहरी को राजधानी बनाया। ये भगवान कृष्ण के परम भक्त थे जिस कारण सन् 1787 में टीकमजी कृष्ण के नाम पर टहरी का नाम टीकमगढ़ रखा गया। विक्रमादित्य सिंह ने 1812 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सुरक्षात्मक संधि कर ली। महाराज विक्रमादित्य सिंह ने मराठा पिडारियों की लूट से सुरक्षा हेतु, अस्तौन, बड़ागाँव, बल्देवगढ़, चन्दपुर, मजना, पुरुषोत्तमपुर, बम्होरी, रामगढ़ में दुर्गों का निर्माण कर किलेदार रखे थे। जिनके अधीन सुसज्जित सेना भी रहती थी। टीकमगढ़ का तोप खाना, बग्गी खाना, गाड़ीखाना, जानकी बाग, नजरबाग ओर जुगल निवास उनके ही स्थापत्य है। इसके बाद 1817 से 1834 तक धर्मपाल गद्दी पर बैठा। धर्मपाल के राज्य में नट जाति की अराजकता बढ़ी तो उन्होंने नटों को बावरी में बसाकर जनता को चोरों से भय मुक्त किया था। 1854 से 74 ईसवीं में हमीरसिंह गद्दी पर बैठा जो लड़ई रानी ने बड़ागाँव वंशज के पट्टीदार दिगौड़ा के जागीरदार के पुत्र को गोद लिया। 1862 में ओरछा राजा को स्थाई गोद प्रदान किया गया। और 1866 में टीकमगढ़ में सवाई महेन्द्र हाई स्कूल की सन् 1868 में स्थापना की गई। प्रतापसिंह ने 1877, 1881, 1982 ईसवीं में राज्य में भूमि प्रबंध कराकर किसानों के हितों का संरक्षण किया था 1891 में टीकमगढ़ नगर पालिका की स्थापना की गई 1894 में झाँसी, मानिकपुर रेल्वे लाईन को भूमि दी थी। सन् 1902 में भारत का लार्ड कर्जन ओरछा आया। महाराजा प्रताप सिंह ने राज्य में 217 ग्राम और 210 खिरक बसाये थे। 7086 कुँए और 73 तालाब बनवाये थे जिससे लोगों के जीवन निस्तार और कृषि में सुविधायें प्राप्त हुयी थी। प्रतापसिंह को इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था उनके स्थापत्यों में प्रतापगट (वर्तमान न्यायालय(तालकोठी (महाविद्यालय(, जुबली हॉल, नई रार। कुण्डेश्वर कोठी, अब्दावीर, सेन्ट्रल जेल, सवाई महेन्द्र स्कूल, महेन्द्र कूट, छेलधोड़ा बावरी, महेन्द्रबाग, सर्किट हाऊस, पनमारा कोठी, चन्दपुरा कोठी, पुलिस लाइन, लड़वारी के तालाब, गौशाला, ढ़ोगा का सवारी मैदान, महेन्द्र सागर टीकमगढ़, महेन्द्र सागर पर प्रतापखेर शिव मंदिर

Tikamgarh District
DEVELOPMENT OF ROADS
(A) Medival Period
(1200-1800 A D.)
Prithvipur
Jatara
Tehri
N
(B) British Period
(1800 1900 A D.)
Niwari
Prithvipur
Lidhora
Jatara
Kharagapur
Tikamgarh
Baldeogarh
(C) British Period in The Phase of Trasport Revolution
(1900 1947)
Forest
0 20
KMS.
(D) Post Independence Phase
(1947 Present Time)
===== Kachcha Road or Sadak
Pacca Road
---- Cart Tracks
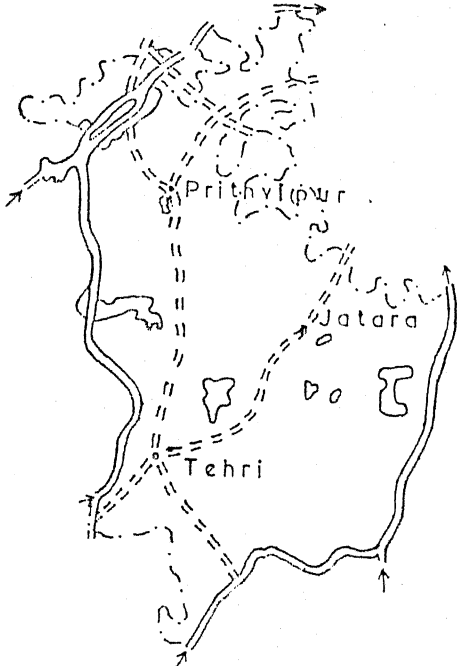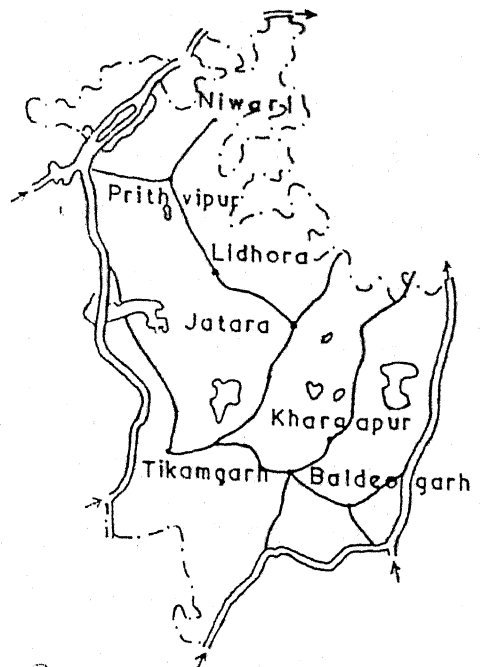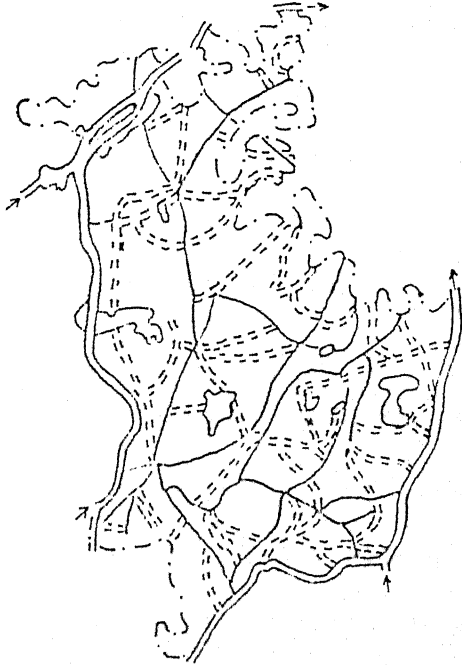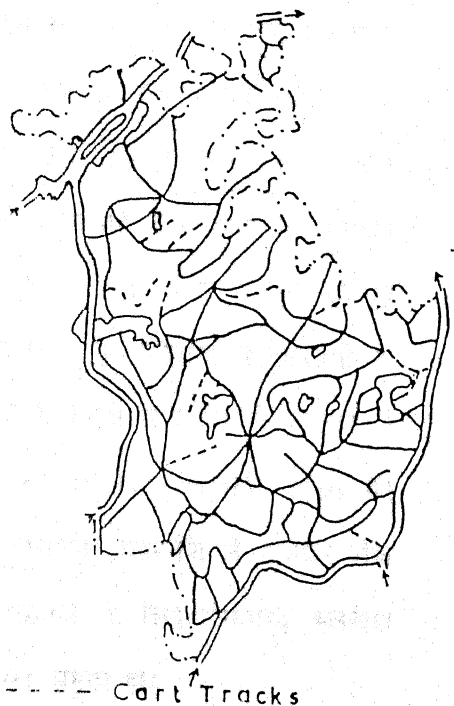
Fig 4.1

एवं नजरबाग स्थित शिव मूर्ति प्रसिद्ध है। 3 मार्च 1930 को प्रतापसिंह का स्वर्गवास हो गया और वीरसिंह द्वितीय गद्दी पर बैठे। वीरसिंह द्वितीय को कर्नल आरजे हील ने मुकुट बाँध कर गद्दी पर बैठाया। इस अवसर पर उन्होंने 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। इसी वर्ष उन्होंने भगवंत क्लब की स्थापना की जिसके खिलाडियों ने सम्पूर्ण भारत एवं औलिम्कि प्रतियोगिताओं में अपनी उत्तम प्रतिभा प्रदर्शित की थी। सन् 1930 में ही बघेल खण्ड शाखा के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड में जन जागरण आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। सन् 1942 में टीकमगढ़ में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई लेकिन महाराजा साहब ने कोंग्रेस के सेवा संघ दल गठित कर राज्य में राष्ट्रीय भावना के अनुरुप कार्य करने की अनुमति दी। ओरछा सेवा संघ के तत्वावधान में टीकमगढ़ अनुगणना में बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण का शुभारम्भ किया गया। इसी वर्ष ओरछा हरिजन सेवा संघ का सम्बन्ध मध्य सेवा हरिजन संघ से हो गया और 1943 में खादी भण्डार का जलसा मनाया गया। 1945 में सरदार सिंह ने ओरछा विद्यार्थी संघ की स्थापना की इसी समय ओरछा सेवा संघ द्वारा टीकमगढ़ में पुनः बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण ओर पुनः एकीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी समय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने कुण्डेश्वर से मधुकर का बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण विशेषांक निकाला था। इस अधिवेशन में महाराजा साह ने उत्तरदायी सरकार बना देने का आश्वासन भी दिया। वर्ष 1946 के प्रारम्भ में ओरछा राज्य सेवा संघ का संबंध मध्य भारत लोक देशी राज्य से किया गया। मई में निवाड़ी राज्य में बेगार प्रथा समाप्त करने, कर्ज वसूली हितेशी कानूनों को जनहितेशी बनाने बुन्देलखण्ड प्रान्त में आवागमन के साधनों का विकास करने तथा कर्मचारियों का वेतन बनाने के प्रस्ताव पारित किये गये। सन् 1947 में एक राजपूत सेवा दल का गठन किया गया जो राष्ट्रीय सेवा के विचार धारा के गतिशील कार्यकर्ताओं के दमन के लिए समानान्तर पहली संस्था थी। दिसम्बर 1947 में समूचे बुन्देलखण्डी रजवाड़े में सर्वप्रथम राज्य सरकार की बागडोर जनता के हाथ सौंप कर लोकप्रिय उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। उत्तरदायी शासन के पश्चात लालाराम बाजपेयी प्रधानमंत्री ने राजपूत सेवा संघ के कार्य कर्ताओं को नारायण दास खरे के कत्ल के पूछताछ के लिये टीकमगढ़ बुलवाया जिनमें खरगापुर जागीर के जागीरदार तथा हीरापुर के हरबलसिंह प्रमुख थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय :

12 मार्च 1948 को बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड राज्यों को मिलाकर विन्ध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। इसमें राजाओं में राज्यों पर से अपने पुरातन स्वत्य और वैद्यता देवों का परित्याग अपने राज्यों को विन्ध्य प्रदेश में विलीन करने की स्वीकृति प्रदान की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिला टीकमगढ़ को, निवाड़ी, जतारा और टीकमगढ़ तीन तहसीलों में विभक्त किया गया। सन् 1885 में दो अन्य तहसीलें पृथ्वीपुर और बल्देवगढ़ बनायी गई वर्तमान समय में जिला टीकमगढ़ में 997 ग्राम है। जिनमें 875 ग्राम आवासीय तथा 122 ग्राम आवासहीन है।

प्राचीन सेवा केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति एवं बनावट एवं भूमिका :

ओरछा राज्य का भू-भाग जो अग्रेजी शासन काल में सन् 1812 में मराठों की लूट, दबाव दमन की नीति के कारण नवोदित अग्रेजी सरकार से सुरक्षा संधी कर उनके अधीन हो गया था। यह ओरछा राज्य 24.26^0 और 25.40^0 उत्त्तरी अक्षांश तथा 78.26^0 और 70.26^0 पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित था जिसकी प्राकृतिक सीमायें पश्चिम में बेतवा, जमड़ार नदियाँ पूर्व में धसान नदी उत्तर में सुखनई और दक्षिण में जमड़ार और उसकी सहायक नदियाँ रही हैं। इस राज्य का भू-भाग प्राचीन काल से पहाड़ी पथरीला ही रहा है। वनाच्छादित प्रदेश होने के कारण यहाँ वनवासी जातियाँ अधिक रहती थी भूमि पथरीली टोरियाँ रही है। जिसके कारण कृषि का समुचित विकास नहीं हो सका था परिणाम स्वरुप ग्रामों की बसाहट भी विलम्ब से ही हुई। राज्य में यत्र तत्र विशेषकर मध्य पश्चिमोत्तर भू-भाग की भूमि मोटी (काली काँवर) हैं जहाँ कृषि होती रही है परन्तु सिंचाई सुविधाओं के अविकसित होने के कारण कृषि वर्षा ऋतु और भाग्य के भरोसे पर ही होती रही हैं। ग्राम एवं शहरों का उद्भव और विकास उद्योग घन्धे, कृषि, उपज और आवागमन के सुगम तीर्थ स्थानों की प्रसिद्धि के कारण ही सम्भव होता है, परन्तु वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से लेकर रामायण और महाभारत काल में इस क्षेत्र में ग्राम समूहों का विकास शून्य ही था। इस वनाच्छादित भू-भाग

में यत्र-तत्र ऋषि-मुनियों और तपस्वियों के आश्रम विद्यमान थे, जिनमें चित्रकूट, कालीन्जर, वाल्मीकी आश्रम, सनकुआ में सनकनदन का आश्रम, ब्रह्म आश्रम, नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध थे। इन ऋषि-मुनियों के ज्ञान से आलोकित होकर यहाँ जनजातियाँ विकास के प्रथम चरण को लाँघकर द्वितीय सोपान में प्रविष्ट हुई और छठवीं शताब्दी से ग्राम समूहों का प्रार्दुभाव हुआ परन्तु कृषि उद्योग अविकसित और पिछड़े ही रहे कृषि जो वर्षा का निर्भर थी उसमें खरीब के बीज जो एक प्रकार से जंगल की घास के बीज ही रहे हैं जो वर्षा होने पर स्वतः उत्पन्न होते थे, जिनमें कोदों, धान, समा के (चावल) रठारा आदि प्रमुख थे। इन्हीं को लोग खाया करते थे । कन्द मूल और फल भी जंगलों में खूब प्राप्त होते थे। इनके अतिरिक्त लोगों का जीवन पशुओं पर विशेष रुप से निर्भर था जिनको मांस ओर दूध की प्राप्ति होती थी जो लोगों की दिनचर्या का अभिन्न अंग था। पशु पालन व्यवसाय कृषि से पूर्ति का सहज और सामान्य आधार था।

छठवीं शताब्दी के पश्चात् इस भू-भाग में ग्रामों के विकास का पता शैव और वैष्णव मतावलम्बियों द्वारा निर्मित विशाल प्रस्तर मठों से होता है। क्षेत्र में वैष्णव मत से पूर्व शैव मत का प्रचलन था इसकी पुष्टि प्रत्येक ग्राम नदी, नालों, कुँओं के समीप स्थित शिवालयों शिव पिण्डयो, शिव लिंगों से होता है। शिव क्षेत्र में सर्वाधिक मान्य सर्वाधिक सरल देव रहे हैं। पश्चातवर्ती काल में वैष्णव धर्म का प्रार्दुभाव भी यहाँ हुआ जो सूर्य, विष्णु, मंदिरों की स्थापना के रुप में हुआ ऐसे ग्राम स्थलों का वर्णन अधोलिखित हैं -

प्राचीन सेवा केन्द्रों का वितरण :

1) मड़खेरा :

मड़खेरा ग्राम गकाटक छठवीं, सातवीं शताब्दी का विकसित ग्राम था। मड़खेरा ग्राम टीकमगढ़ - मोहनगढ़ मार्ग पर ग्राम शिवराजपुर से 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लिये पहुँच मार्ग है। जिसका स्पष्ट प्रमाण यहाँ का वाकाटक युगीन सूर्य मंदिर है। वाकाटर ब्राह्मण राजा थे जो शैव मतावलम्बी थे। उनके नागों से वैवाहिक सम्बंध थे। परन्तु जब उनके वैवाहिक और राजनयिक सम्बंध गुप्त राजाओं से हुये तो वह वैष्णव धर्म के

मतावलम्बी हो गये थे। उन्होंने ही मड़खेरा में ही भगवान भास्कर विशाल प्रस्तर मठ बनवाया था। मंदिर के गर्भ गृह में सूर्य भगवान की प्रतिमा आज भी दर्शनीय है। लम्बी युग यात्राएं देखता सुनता यह मंदिर आज भी दर्शनीय है। मन्दिर की भव्यता से आभास होता है कि प्राचीन काल में मड़खेरा के भव्य सम्पन्न ग्राम रहा होगा। ग्राम नगर के वासी वैभव धन सम्पति और व्यवसाय से सम्पन्न होगे तभी तो यह नगर शैली की शिल्प कला यहाँ मुखरित हो सकी।

ऊमरी ग्राम :

ऊमरी ग्राम टीकमगढ़ जिले के दक्षिण पूर्व में बड़ागाँव, ककरवाहा, बसमार्ग से 2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। जमड़ार नदी के पार्श्व पर स्थित है। छठवीं शताब्दी में यह ग्राम वैभवशाली एवं धनधान्य से परिपूर्ण था जिसे उम्मरगढ़ कहा जाता था यहाँ पर वर्तमान ग्राम के पश्चिमी भाग में विशाल सूर्य मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर अमरावती शैली कला के लिये प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों ओर नदी के किनारे तक प्राचीन भवनों के खण्डहरों के बुनियादी चिन्ह आज भी देखे जा सकते है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग किन्हीं कारण वश भाग कर महाराष्ट्र के अमरावती जा बसे थे। जिन्होंने स्थापत्य और मूर्ति कला के क्षेत्र में अमरावती शैली का विकास किया था। कालान्तर में ऊमरी ग्राम नष्ट हो गया और वर्तमान में अपने मूल स्थान से हटकर पूर्वी हिस्से की ओर एक छोटे से ग्राम के रुप में रह गया है।

मामौन :

टीकमगढ़ से पूर्व में 3 कि.मी. की दूरी पर मामौन ग्राम एक पहाड़ी पर स्थित था जोकि दसवीं शताब्दी तक यह ग्राम कृषि ओर पशुपालन के क्षेत्र में विकसित था। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या ब्राह्मणों की थी। यहाँ के प्राचीन मंदिर पहाड़ी पुर ध्वस्त हवेलियाँ वर्तमान में भी दृष्टव्य है। यह ग्राम भी पहाड़ी से हटकर मैदानी भाग में एक छोटे पुरवा के रुप में अवशिष्ट है।

मोहनगढ़ :

टीकमगढ़ के पश्चिमी भाग में और ओरछा के पूर्व में मोहनगढ़ स्थित है। प्राचीन काल में केवल इसका नाम गढ़ था। यहाँ के गुप्तेश्वर शिव मंदिर मिट्टी में दबे हुए गुप्त कालीन मंदिर यहाँ के शेषशाही विष्णु की मूर्ति दुर्ग के अन्दर विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियाँ देखाने से ऐसा आभास होता है कि छठवीं शताब्दी से यह ग्राम कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकसित रहा होगा। शिव पार्वती की मूर्तियाँ भी इस ग्राम परिक्षेत्र में बहुतायत में दृष्टव्य है।

कुढ़ार :

कुढ़ार ग्राम ओरछा के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। कुढ़ार ग्राम चन्देल शासकों के पहले भी वैभव सम्पन्न ग्राम था। इसी कारण चन्देल शासकों ने इसे अपने सैनिक मुख्यालय बनाया। पहाड़ी पर किले का निर्माण कराया और अपना एक किलेदार भी नियत किया। कुढ़ार ग्राम कालांतर में विकसित होकर पूर्ण वैभव प्राप्त करने में सफल हुआ। बारवीं से चौदवीं शताब्दी तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र की राजधानी के रुप में प्रसिद्ध रहा। कालचक्र के प्रभाव से कुढ़ार का प्राचीन वैभव विलोपित हो गया और आज एक छोटे के ग्राम के रुप में विद्यमान है।

पम्पापुरी :

पम्पापुरी की वर्तमान में पपावनी कहते है। जो टीकमगढ़ बल्देवगढ़ बस मार्ग पर स्थित है। यहाँ की पहाड़ी पर घ्वस्त मकानों के अवशेष आज भी देखे जा सकते है। ग्राम परिक्षेत्र की बावरियाँ मूर्तियाँ विजय स्तम्भ (जैत स्तम्भ) के अवलोकन के पश्चात यह निश्चित धारणा बनती है कि प्राचीन काल पम्पापुरी उर्फ पपाऊनी ग्राम वैभवशाली और सम्पन्न रहा होगा।

महेवा :

महेवा ग्राम ओरछा के उत्तरपूर्वी और लिधोरा के उत्तर में सुखनयी नदी के

किनारे पहाड़ीयों के मध्य की पहाड़ी पर रानी सागर ताल के किनारे स्थित रहा है। यह ग्राम प्राचीन काल में वैभव सम्पन्न रहा होगा। जिसकी पुष्टि ग्राम की चारों ओर पहाड़ियों के मध्य पाँच तालाब करते है। पहाड़ियों पर भ्रमण करने एवं चारों ओर विशाल नगर कोट और उसके अन्दर पहाड़ियों पर आवासीय खण्डहर गाँव की विशालता, भव्यता और वैभव सम्पन्नता का अवबोध कराते है। यह महेवा ग्राम अपने मूल अस्तित्व के रुप नष्ट होकर सुखनयी के किनारे स्थापित हुआ। मध्य काल में सुखनयी नदी के किनारे से दाँये भाग से अनेक टोलों में बिखर गया जिसे महेबा चक्रों के नाम से जाना है। प्राचीन महेवा ग्राम के उत्तर में विशाल नगर प्रवेशद्वार कुँआ, बावडीयाँ ओर सुखनयी नदी के तट पर कपिलनाथ का मंदिर यहाँ के कलात्मक वैभव को प्रदर्शित करते हैं।

नारायणपुर :

नारायणपुर ग्राम टीकमगढ़ के पूर्व में और अहार क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। प्राचीन काल में यह ग्राम कृषि और उद्योग के क्षेत्र में विकसित था यहाँ की पहाड़ियाँ में चाँदी प्राप्त होती रही है। यह ग्राम विलासपुर अहार से नावागढ़, मदनपुर चन्देरी मार्ग पर स्थित होने से प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था यहाँ के प्राचीन मठ मंदिर यत्र-तत्र बिखरी मूर्तियाँ ग्राम के प्राचीन वैभव की याद दिलाती है।

अहार :

अहार सिद्ध तीर्थ स्थल है। प्राचीन काल में इसका नाम मुदनेश पुरी भी था, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मदनकुमार जी जैन सिद्ध निवास करते थे ऐसी भी किवदन्ती है कि अहार ग्राम नारायणपुर ग्राम का अग्रद्वार था जो कलान्तर में अहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ यहाँ की पहाड़ी पर सिद्ध मुनियों के चरण चिन्ह प्राप्त है। समीपस्थ एक बड़ा नाला है जिससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में इस नाले के किनारे लडीयाँ (भूपत्थर की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार) रहा करते थे। यहाँ के जैन संग्रहालय में छठवीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ अवलोकनीय है। इससे स्पष्ट होता है कि अहार ग्राम परिक्षेत्र छठवीं शताब्दी से ही

विकसित और सम्पन्न रहा है। कलान्तर में चन्देल राजा मदनवर्मा ने यहाँ मदन सागर तालाब के किनारे पहाड़ी पर मदनमहल और मदनेश्वर का मठ एवं बावरी निर्मित करायी थी। चन्देला युग में ही बुन्देलखण्ड के महान वास्तुकार पापट द्वारा निर्मित भगवान शान्तीनाथ की 21 फुट ऊँची प्रतिमा की स्थापना कराई गई थी। यह ग्राम अपने प्राचीन स्वरुप से नष्ट होकर एक छोटे सिद्ध जैन तीर्थ के रुप में प्रसिद्ध है।

बल्देवगढ़ :

बल्देवगढ़ वर्तमान में एक कस्बा के रुप में टीकमगढ़ - गुलागंज मार्ग पर स्थित है। प्राचीन काल में इसका नाम बाधा था कालान्तर में ओरछा के महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने ग्वाल सागर तालाब का निर्माण कराया और उसकी पहाड़ी पर किला बनवाकर किले के मध्य तालाब बाँधा पर बलदाऊ जी का मन्दिर बनवाया। उन्हीं के नाम पर दुर्ग और बाँधा ग्राम का नाम बल्देवगढ़ रखा था। बल्देवगढ़ ग्राम प्राचीन काल से उद्योग धन्धों और कृषि के क्षेत्र में विकसित ग्राम था। ऐसा माना जाता है कि यह बाधा ग्राम प्राचीन काल में जतारा परगने के 149 ग्रामों का टप्पा था। यहाँ सवा लाख रुपया मालगुजारी, वसूल की जाती थी।

टीकमगढ़ :

टीकमगढ़ प्राचीन ओरछा राज्य और वर्तमान जिला टीकमगढ़ का मुख्य नगर रहा है। प्राचीन काल में टीकमगढ़, टेहरी नाम से प्रसिद्ध था। टेहरी आज भी पुरानी टेहरी नाम से एक मुहल्ला के रुप में स्थित हैं। इसके पूर्व टेहरी नगर के मध्य की पहाड़ी के पूर्वी भाग में मादेले लोधीर्यो की बस्ती थी जो कृषि और पशुपालन किया करते थे। भोदिलों के पश्चात् पुरानी टेहरी में तिवारी ब्राह्मणों का प्रभाव बड़ा। तत्पश्चात् टेहरी पहाड़सिंह की जागीर के रुप में विख्यात रहा उनके बंशज शंकरसिंह ने नगर के उत्तरी तट पर पहाड़ी पर शंकरगढ़ को अपना आवास बनाया। अन्त में झाँसी के मराठा सुवेदारी से झाँसी के मराठों की लूट और अराजकता से त्रस्त होकर सन 1783 में ओरछा के महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने टेहरी को अपनी राजधानी बनाया तथा पहाड़ी पर वर्तमान दुर्ग की आधार शिला रखी।

महाराजा विक्रमाजीत सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे जिस कारण उन्होंने **भगवान टीकमजी** (कृष्ण) के नाम पर दुर्ग और नगर का नाम टीकमगढ़ रखा था। इसी समय से टीकमगढ़ वर्तमान नगर किले के पृष्ठ भाग में (पश्चिमी भाग में) एक नई बस्ती के रुप में विकसित हुआ। महाराजा ने सुरक्षा की दृष्टि से नये विकसित टीकमगढ़ नगर का नगरकोट बनवाकर लुटेरे पिण्डारियों से लोगों की सुरक्षा की थी।

टेहरका :

ओरछा राज्य के अंतर्गत टेहरका ग्राम झाँसी-मानिकपुर रेल्वे लाइन पर स्थित है। यह ग्राम सिद्ध बावा की जागीर था। प्राचीन काल में इस ग्राम की कुण्डलपुर के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ की भूमि काली मोटी है। प्राचीन काल में यहाँ पर गन्ने की खूब खेती होती थी जिसका प्रमाण यहाँ पर प्राप्त पत्थर के कोल्हू है। ओरा राज्य शासन के सर्वे (भू-मापन) में टेहरका की डोरी माप काफी प्रचलित थी। यह ग्राम प्राचीन काल से ही धन सम्पन्न और खुशहाल रहा है।

पृथ्वीपुर :

पृवीपुर ग्राम टीकमगढ़ निवाड़ी मार्ग पर स्थित है। यहाँ के लोग प्राचीन काल से कृषि पशु पालन और उद्योग धन्धे से जुड़े रहे है। जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही है। पृथ्वीपुर के पास की पहाडीयों में लोहा अधिक संख्या में पाया जाता है। 15 फुट नीचे भूमि में लोहा का अयस्क प्राप्त है। पत्थर कोयले का अंश भी प्राप्त होता है। धोकन ओर मजयारे की टोरीयाँ में लोहा उद्योग खूब चलता था। परन्तु कालान्तर में ओरछा राज्य के राजाओं की उपेक्षा के कारण लोह उद्योग विकसित न हो सका।

जतारा :

टीकमगढ़-मऊरानीपुर मार्ग पर जतारा तहसील कस्बा स्थित है। प्राचीन काल में इसका नाम बतवाँरा था। जतारा ग्राम की भूमि उपजाऊ रही है। जिस कारण यहाँ के लोग

प्रारम्भ से ही वैभवशाली और सम्पन्न रहे है। चन्देला युग में जतारा मदनवर्मा फदेली का प्रिय स्थल रहा है जिसने मदन सागर तालाब और मदनमहल जैसे बेजोड़ स्थापत्य प्रतीक निर्मित कराये थे। मुगल सम्राटों का भी यह प्रिय स्थल रहा हैं। इस्लाम शाह सूर के अधिकार में भी यह स्थल रहा हैं। उसने तो जतारा का नाम इस्लामाबाद रखा था। जतारा का स्थापत्य वैभव ही यहाँ की सम्पन्नता का अवबोधक है। यहाँ के प्राचीन जैन मंदिर सनत अवदर पीर की दरगाँह, बाजने का मठ, 12 दरवाजे शाहजहाँ के शासन काल को महत्वपूर्ण इमारतें रही है। ग्राम के उत्तरी दरवाजे के बाहर भारतीय और ईरानी (इण्डोई रानी) शैली की बावरियाँ भी दर्शनीय है। जिनमें लौह लंगर की बावरी प्रसिद्ध है। यहाँ का स्थापत्य और पुरातात्विक सामग्री देखने पर आभास होता है कि प्राचीन काल में यह ग्राम परिक्षेत्र धन वैभव सम्पन्न था।

लिधौरा :

जतारा के पशिचम में और टीकमगढ़ के उत्तर में लिधौरा ग्राम स्थित है। यहाँ की भूमि उपजाऊ और काँवर मोटी है। यह ग्राम प्राचीन काल से सम्पन्न रहा। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा। ओरछा के राजा हरीसिंह, (मानसिंह के समसने) लिधौरा दुर्ग का निर्माण हुआ। तत्पश्चात उन्होंने इसे कुछ समय तक अपनी राजधानी भी बनाया। यहाँ का बड़ामन्दिर प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ कृषि के साथ साथ प्राचीन काल से ही चमड़ा उद्योग विकसित रहा है।

मबई :

टीकमगढ़ से 12 कि.मी. की दूरी पर टीकमगढ़ मऊ रोड़पर मबई ग्राम स्थित है। प्राचीन काल में यह महादेले लोधीयों की बस्ती रहा है। जो पगारा के नाम से प्रसिद्ध थी। पगारा बस्ती के ध्वस्त अवशेष वर्तमान मबई ग्राम के उत्तर पूर्व में पगारा हार है। प्राचीन काल में यह पगारा इतनी बड़ी बस्ती था कि उर नदी पर एक घाट पगारा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। कहते है कि पगारा नगर की रानी नित्य नया घाघरा पहना करती थी तथा एक हीपा (दर्जी) नित्य रानी को नया घाघरा तैयार कर देता था इस प्रकार पगारा में

365 धर हीपो के थे। पगारा का वैभव वर्तमान में कालकवलित हो गया। वर्तमान में वहाँ के लोग हीपोन खेरा में और मवई में बस गये। मवई की पहाड़ी के गुहा शिव दर्शनीय है। जो स्वयम्भू हैं।

भेलसी :

भेलसी ग्राम बल्देवगढ़-खरगापुर के मध्य बस मार्ग पर स्थित है यह ग्राम अति प्राचीन है। जहाँ के लोग कृषि और पशु पालन का धन्धा करते थे इस ग्राम की समृद्धि वहाँ के प्राचीन पाँच शिव मठों एवं एक बाराह की अनुपम मूर्ति से होता है। यहाँ के पुरातात्विक सामग्री इस बात का प्रतीक है कि यह ग्राम धन सम्पन्न होने के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी पूर्ण विकासित था।

निवाड़ी :

निवाड़ी कस्वाँ भी प्राचीन सम्पन्न नगर रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसकी सम्पन्नता देखकर मराठे ईर्ष्यालू हो उठे थे। इसी कारण उन्होंने निवाड़ी के पहाड़ी पर बने हुए किले को ध्वस्त कर दिया था। तथा ग्राम की लूट लिया था।

नदनवारा :

नदनवारा ग्राम टीकमगढ़ के उत्तर-पश्चिम में 40 कि.मी. की दूरी पर है। यहाँ का तालाब प्रसिद्ध है जिससे खेती की सिंचाई की सुविधा पूर्णरुपेण है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस ग्राम को क्षत्रियों ने बसाया था जो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे।

ओरछा :

ओरछा मध्यकाल का प्रसिद्ध नगर रहा जिसे कुराढ के राजा रुद्र प्रताप ने 1531 ईसवीं में बसाया था। बेतवा की दो धाराओं के मध्य के टापू पर ओर से छोर तक

दुर्ग और सैनिक परकोटा निर्मित कराया था। टापू के ओर से छोर तक दुर्ग बन वाने के कारण इसे ओरछा नाम दिया गया था। तत्पश्चात् भारतीय चन्द ने 15 कि.मी. दुर्ग के पश्चिमी भाग में बेतवा के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक 15 कि.मी. अर्द्धव्यास में विशाल पत्थर पर नगर का बनवाकर ओरछा नगर स्थापित कराया था।

पचेर :

टीकमगढ़ के पूर्वेत्तर भाग में धसान नदी के किनारे पचेर ग्राम स्थित है। प्राचीन काल में इसका नाम पुरुषोत्तमगढ़ था। प्राचीन काल में यह ग्राम परिहारों के अधीन था। यहाँ कृषि व्यवसाय सम्पन्न रहा हैं। कालान्तर में यहाँ के परिहारों को आलीपुर की ओर जाना पड़ा और यह ग्राम ओरछा राज्य के अन्तर्गत था।

देरी :

देरी ग्राम टीकमगढ़ के पूर्वोत्तर किनारे सीमा का प्रमुख ग्राम है। जो तालाब के बँधान और पहाड़ी पर स्थित है। यह ग्राम कृषि ओर पशुपालन पर निर्भर रहा है। ग्राम के मध्य की पहाड़ी पर चन्देला युगीन कला का उत्कृष्ट प्रतीय शिव मठ बना हुआ है। पहाड़ी की चोटी पर कलाका देवी का गुहा मंदिर प्रसिद्ध है। जहाँ परिक्षेत्र के लोग दर्शनों के लिये आया करते है।

दुबदेई :

दुबदेई मध्य काल का धार्मिक आधार पर विकसित ग्राम है। यह छोटी सी बस्ती है। पहाड़ी पर दूवदेई देवी की प्राकृतिक प्रतिमा है। जिसके कारण ही यहाँ दर्शनार्थियों का आना जाना होता है। इसी आधार पर कुछ लोगों ने यहाँ पर बसना आरम्भ कर दिया और कृषि व्यवसाय से जुड़ गये।

REFERENCES

1. Beams, John (Ed.) : Memairs on the History Folk-lare, and Distribution of the Races of the North-Western Provinces of India, VOL.I, PP. 33, 95, 96, 153, 347, : Davidson, Cal, J : Report on the Settlement of Lullutpare (1871) PP : 14-15; Crooke, W. : The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh, Vol. II, PP : 1-11, 47-54, 430-438; Vol. III, PP : 228-238, Vol. IV, PP : 252-255, Russell, R.V. : Tribes and Castes of the Central Provinces of India, Vol. IV, PP : 440-443, Atkinson, E.T.: Statistical, Descriptive and Historical Account of the North-Western Provinces of India, Vol. I, Bundelkhand PP : 1., 19, 58, 267, 269, 331, 351 Drake - Brockman, D.L. : Jhansi: A Gazetteer, P : 245..
2. Sankalia, H.D. : Pre-history and Prato-history in India and Pakistan, (Bombay, 1962), P : 58 Indian Archeology 1956-57, A Review P:79.
3. The History and culture of the Indian People Vol.I The Vedic Age PP: 248,250, Raychaudhari, H.C.: Political History of Ancient India,

(Sixth Ed., P : 129 foot note).

4. Ibid, P: 130, The Vedic Age Op. Cit. P: 248; The Cambridge History of India, Vol. I, P:75.

5. Ibid, The Vedic Age, Op. Cit. P: 248.

6. Ibid, PP : 272-273.

7. Ibid, P : 274.

8. Ibid, P : 278.

9. Ibid, P : 248.

10. Ibid, B. N. 23; Dey, N.L. : Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, P: 48.

11. Mahabharata, BhishmaParva Ch. 9, V.40.

12. The Cambridge; History of India, Vol. I. P : 245.

13. Mahabharata Udyoga-Parva, Ch. 28, V.XI, XIV; Ibid. P:325; Raychaudhuri, Op. Cit. PP: 233-134. The Cambridge History of India VOl. I, PP : 281-282.

15. Ibid, P : 153, The History and Culture of the Indian People Vol. II- The Age of Imperial Unity, P : 1.

16. Ibid, P : 473; the age of Imperial Unitoy Op. Cit. PP : 141-142.

17. Atkinson, Op. Cit. P : 2.

18. Raychaudhuri, Op. Cit. P: 545; The History and culture of the Indian Peopole Vol. II. P : 221; Vol. III, P : 9. A tributary of

the Betwa Passing through the district near Talbehat is also called the Ahirwara Nala (cb Atkinson Op. Cit. P : 591).

19. Drake - Brockman Op. Cit., PP : 234-235.

20. Ibid, P: 541; The Age of Imperial Unity Op. Cit. P : 220.

21. त्रिपाठी, के.पी. (1988) : बुन्देलखण्ड का इतिहास; अनुराधा प्रकाशन, इलाहाबाद - पृष्ठ : 221-230.

22. त्रिपाठी, के.पी. (1988) : वही पृष्ठ : 302

23. मिश्रा विष्णु (1989) : मध्यकालीन बुन्देलखण्ड का इतिहास, अप्रकाशित शोध प्रबंध अवधेश प्रताप सिंह विश्व विद्यालय, रीवा म.प्र.

24. अवस्थी, एन.एम. (1986) : सिंचित कृषि का ग्रामीण विास पर प्रभाव, (अप्रकाशित) शोध प्रबंध) अ.प्र. सिंह, विश्व विद्यालय, रीवा (म.प्र.).

25. त्रिपाठी, के.पी. (1988) : वही पृष्ठ सं. 132.

26. टीकमगढ़ दर्शन (1965) : ग्वालियर पृ.क्र. 50.

27. District Gazetteer, Tikamgarh Dist: Bhopal P:201.

28. District Gazetter, Jhansi District, Lucknow.

29. Tiwari, R.P. (1979) : Population Geography of Bundelkhand (Un published Ph.D. Thesis) Vikram University, Ujjain, (M.P.).

30. त्रिपाठी, के.पी. (1988) : वही पृ. सं. 143 - 151.

31. त्रिपाठी, के.पी. (1988) : वही पृ. संख्या 153.

32. त्रिपाठी, के.पी. (1988) : वही पृष्ठ संख्या 243.

----0----

अध्याय पाँच

सेवाकेन्द्रों का वर्गीकरण

- वर्गीकरण के आधार
- आकारिकी पर आधारित वर्गीकरण
- सेवा स्तर एवं उनका नियोजन
- सन्दर्भित ग्रन्थों की सूची
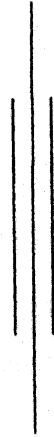
सेवा केन्द्रों का वर्गीकरण : (CLASSIFICATION OF SERVICE CENTRES):

वर्तमान समय में सेवाकेन्द्रों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु ही नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण हेतु भी प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः स्थानीय सेवा केन्द्रों द्वारा उन सीमित संसाधनों की खोज करके उच्च तकनीकी एवं प्रशिक्षण द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। ममफोर्ड[1] ने अपनी पुस्तक में सेवाकेन्द्रों के नियोजन में मानव को ही सर्वोपरि बताया है। जिसके अन्तर्गत विश्लेषण किया जाता है कि एक सेवा स्थान दूसरे सेवास्थान से किस तरह प्रभावित है। सेवाकेन्द्रों के विकास की प्रमुख आवश्यकता किसी प्रदेश के निवासियों को समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विकास के लिये कार्य करना है।[2] अध्ययन क्षेत्र टीकमगढ़ जिला में सेवाकेन्द्रों के वर्गीकरण की आवश्यकता के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :

कृषि एवं सम्बन्धित वस्तुओं का विकास; जैसे -

1) भूमि सुधार, मिट्टी संरक्षण, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि उर्वरकों के प्रयोग का महत्व, पशुपालन, मुर्गी पालन एवं क्षेत्रीय वनों का विकास आदि।

2) क्षेत्रीय कच्चे माल की प्राप्ति के अनुसार लघु एवं कुटीर अथवा बृहत उद्योगों की स्थापना, यातायात एवं संचार के साधनों की आवश्यकता।

3) मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विकास जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक हितों के लिये विभिन्न प्रस्तावों एवं योजनाओं की आवश्यकता एवं विकेन्द्रीकरण।

4) ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों एवं उपकार्यों को आवश्यकतानुसार हितग्राहियों (व्यक्तियों या परिवारों) तक पहुँचाकर उनके आर्थिक विकास की आवश्यकता।

5) क्षेत्रीय समग्र विकास के लिये विभिन्न उद्देश्यों एवं कार्यों को अपनाकर

स्थानिक बातावरण के विकास की आवश्यकता।

क) सेवा केन्द्रों का आकारानुसार वर्गीकरण :

सेवास्थलों का वर्गीकरण के अन्तर्गत आवास और उनमें आवासित क्षेत्र का विश्लेषण हैं। यहाँ बहुत से कारक हैं जो सेवाकेन्द्रों के वर्गीकरण द्वारा आकार को प्रभावित करते हैं। इनमें जनसंख्या, क्षेत्र, आवासीय मकान एवं परिवारों का आकार प्रमुख है।

प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मण्डल की जनसंख्या के इकाई क्षेत्रफल में वितरण के आधार पर जनसंख्या का आधार निरुपित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में औसतन 839 व्यक्ति प्रति सेवाकेन्द्र में आवासित हैं। इनमें सर्वाधिक 1354 टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में है क्योंकि टीकमगढ़ नगर होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या आकार अधिक है, जबकि नैगुंवा राजस्व निरीक्षक मण्डल में 503 व्यक्ति प्रति ग्राम वितरित हैं। इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटे-छोटे ग्राम अधिक हैं। अतः जनसंख्या का आकार न्यून है। मांचनित्र 5.1 में जनसंख्या का आकार दर्शाया गया है। 1991 की जनगणनानुसार अध्ययन क्षेत्र में 17.03 प्रतिशत अति न्यून जनसंख्या अर्थात् 200 से कम अधिवास, 30.96 प्रतिशत न्यून 200 से 499 एवं 500 से 999 जनसंख्या अर्थात् मध्यम आकार में, 28.77 प्रतिशत, वृहत आकार के अन्तर्गत (1000 से 1999), 17.72 प्रतिशत सेवा स्थल और वृहत्तम ग्रामीण जनसंख्या आकार के अन्तर्गत 5.52 प्रतिशत सेवाकेन्द्र आते हैं। इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या आकारों के अन्तर्गत न्यून जनसंख्या आकार वाले 10000 से कम 50 प्रतिशत नगर, मध्यम जनसंख्या वाले (10000 से 20000) में 33 प्रतिशत अध्ययन क्षेत्र में वृहद् जनसंख्या आकार के अन्तर्गत एक भी नगर नहीं, जबकि वृहत्तम जनसंख्या का आकार 500000 से अधिक एक मात्र नगर टीकमगढ़ पाया जाता है। लोरंज वक्र में अध्यन क्षेत्र के ग्रामीण एवं नगरीय सेवास्थलों को दर्शाया गया हैं। इसी प्रकार सचयी ग्राफ के अन्तर्गत गणितीय आधार पर सेवाकेन्द्रों के आकार का आकलन किया गया है। सारणी 5.1 में सेवाकेन्द्रों का आकार को दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक 5.1 : सेवाकेन्द्रों का आकार, घनत्व एवं विस्तार 1991.

क्रमांक	राजस्व निरीक्षक मण्डल	क्षेत्रीय आकार	जनसंख्या आकार	आवासीय आकार	परिवार का आकार	घनत्व	विस्तार
1.	ओरछा	3.59	589	79	90	2.03	2.14
2.	निवाड़ी	4.95	1058	142	143	3.39	2.51
3.	तरीचर कलॉं	5.22	903	129	130	2.45	2.58
4.	नैगुँवा	3.32	503	66	72	1.96	2.06
5.	सिमरा	4.14	863	131	137	2.19	2.30
6.	पृथ्वीपुर	5.24	924	142	143	2.46	2.58
7.	मोहनगढ़	4.54	633	91	94	2.29	2.40
8.	लिधोरा	6.21	942	131	132	2.68	2.81
9.	दिगोड़ा	6.85	1026	130	135	2.81	2.95
10.	जतारा	6.03	969	130	144	2.64	2.77
11.	पलेरा	5.97	798	114	115	2.62	2.76
12.	टीकमगढ़	5.44	1354	195	198	2.50	2.63
13.	समर्रा	5.14	634	92	93	2.44	2.56
14.	बड़ागाँव	5.96	726	124	125	2.62	2.75
15.	बल्देवगढ़	4.72	753	120	120	2.33	2.45
16.	कुडीला	5.53	639	106	106	2.53	2.65
17.	खरगापुर	6.78	951	151	152	2.80	2.94
	जिला टीकमगढ़	**5.27**	**839**	**122**	**125**	**2.48**	**2.60**

स्रोत : प्राथमिक जनगणना सार एवं ग्राम व नगर निर्देशनी, जिला टीकमगढ़ 1991.
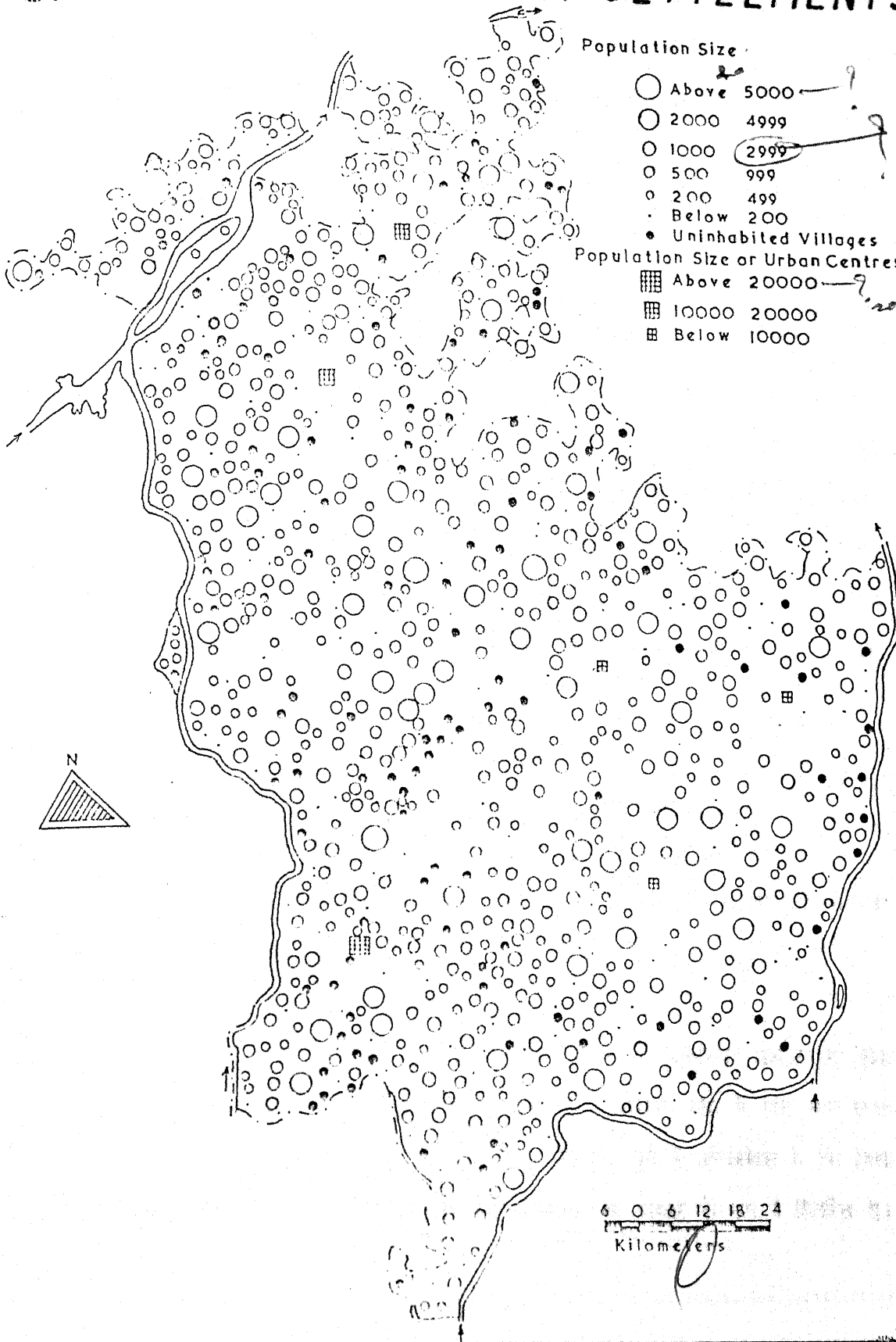
जनसंख्या आकार के अनुसार बहुत छोटे और बहुत बड़े ग्रामीण एवं नगरीय सेवाकेन्द्र अध्ययन क्षेत्र में सभी जगह बिखरे हुए हैं। उत्तरी भाग में इनकी सघनता एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग में विरलता दृष्टिगोचार होती है। टीकमगढ़ जिला के मध्य-पूर्व में सर्वाधिक जनसंख्या आकारयुक्त सेवाकेन्द्र विन्यासित पाये जाते है।

2. सेवाकेन्द्रों की क्षेत्रीय आकार :

अध्ययन क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल को आवासित ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या से विभाजित करने पर सेवाकेन्द्रों का क्षेत्रीय आकार प्राप्त होता है। अध्ययन क्षेत्र के वे राजस्व निरीक्षक मण्डल जहाँ कृषि कार्य कम है, सिंचाई के साधनों का विकास कम हुआ है। न्यून क्षेत्रीय आकार में पाये जाते हैं। इसके अन्तर्गत नैंगुंवा राजस्व निरीक्षक मण्डल 3.32 ओरछा 3.59 सिमरा 4.14 उल्लेखनीय हैं। अध्ययन क्षेत्र का उत्तरी पश्चिमी भाग में सेवाकेन्द्रों का क्षेत्रीय आकार न्यून हैं। जबकि दिगौड़ा 6.85 खरगापुर 6.78 लिधौरा 6.21 ओर जतारा 6.03 वृहत क्षेत्रीय आकार के अधिवास हैं। अर्थात् अध्ययन क्षेत्र के मध्य मात्र वृहत आकार सेवाकेन्द्र कृषिगत विस्तार के कारण पाये जाते हैं।

3. सेवाकेन्द्रों का गृहीय आकार :

जनसंख्या का आकार एवं सेवास्थलीय गृहों के आकार में घनात्मक सह-सम्बन्ध (+0.95) पाया जाता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय व जनसंख्या आकार में वृद्धि सेवास्थलीय गृहों के आकार में भी अभि-वृद्धि करती है। अध्ययन क्षेत्र में प्रति सेवा स्थल 122 गृह सेवित गृहीय के आकार में पये जाते हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि जिला टीकमगढ़ का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र न्यून क्षेत्र एवं जनसंख्या का आकार के रुप में वितरित है।

TIKAMGARH DISTRICT
SIZES OF SERVICES CENTRES
A
Areal Size
Q.3
M.
Q.1
6.03
5.24
4.72
Forest
B
Population Size
Q.3
M.
Q.1
969
852
639
N
C
Residential House Size
Q.3
M.
Q.1
142
129
106
D
Household Size
Q.3
M.
Q.1
143
130
106
0
30
KMS
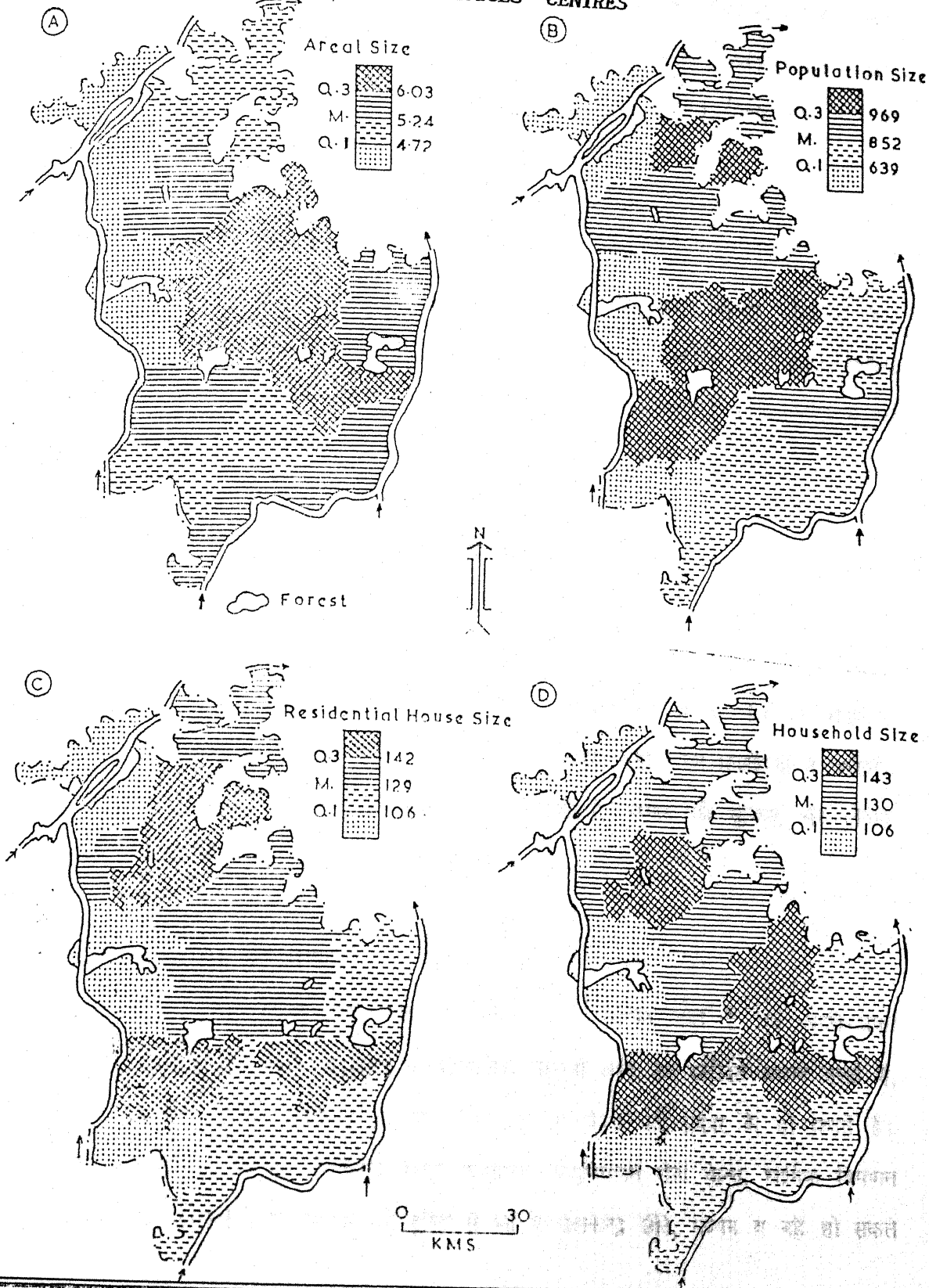
Fig 5.2

अतः इसी क्षेत्र में नैगुंवा (66), ओरछा (79) मोहनगढ़ (91) में न्यून सेवाकेन्द्रीय गृह आकार पाये जाते हैं जबकि मध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी अथवा नगरीय जनसंख्या वाले राजस्व निरीक्षक मण्डलों जैसे-टीकमगढ़ (195), खारगापुर (151), जतारा (139), निवाड़ी तथा पृथ्वीपुर (142) गृहीय आकार पाया जाता है।

4. सेवा केन्द्रों का परिवारीय आकार :

अध्ययन क्षेत्र में उक्त तीनों आकारों की भाँति नैगुंवा, औरछा, मोहनगढ़ तथा समर्रा में परिवारों का आकार न्यून और टीकमगढ़, खारगापुर, जतारा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी राजस्व निरीक्षक मण्डलों में वृहत परिवार आकार दृष्टिोचर होता है। मानचित 5.2 एवं 3 में इन आकारों वितरण दर्शाया गया है।

ख) सेवाओं पर आधारित सेवा केन्द्रों का वर्गीकरण :

1. आधार-भूत सुविधायुक्त लघु स्तरतीय सेवाकेन्द्र :

इस प्रकार के सेवा केन्द्रों की संख्या अध्ययन क्षेत्र में 32 है। ये सेवाकेन्द्र ग्रामीण नगरीय सुविधा समुदाय के रुप में भविष्य में विकसित होंगे, इन सेवाकेन्द्रों में प्राथमिक पाठशालायें, डाकघर, माध्यमिक विद्यालय, सहकारी समितियों, बाजार की सुविधा, बैंक सेवायें, कृषि विस्तार केन्द्र, आटा मिल आदि पाये जाते हैं।

2. विपणन सेवा हेतु बाजार :

यह स्थान जहाँ क्रेता व विक्रेता दोनों एकत्रित होते हैं एवं अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्राकृतिक व अप्राकृतिक वस्तुओं आदि को खरीदते अथवा बेचते हैं, बाजार अथवा विपणन सेवाकेन्द्र कहलाते हैं। यह सेवाकेन्द्र कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे- साप्ताहिक विपणन सेवाकेन्द्र, स्थाई सेवाकेन्द्र, पशुविपणन सेवा केन्द्र, धार्मिक विपणन सेवा केन्द्र, (मेला) आदि आकार की दृष्टि से भी ये सेवाकेन्द्र छोटे, मध्यम व बड़े हो सकते

हैं। परन्तु इन सभी सेवाकेन्द्रों की उपयोगिता अपनी-अपनी जगह महत्वपूर्ण होते है। अध्ययन क्षेत्र में विपणन सुविधाओं का आकलन जनसंख्या एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर दोनों प्रकार से किया गया है।

इस तरह के सेवाकेन्द्रों की संख्या 12 है जिनमें ओरछा, निवाड़ी, टेहरका, पृथ्वीपुर, लिधौरा, दिगौड़ा, जतारा, पलेरा, टीकमगढ़, खरगापुर, बड़ागाँव हैं। इन सेवाकेन्द्रों में पुलिस स्टेशन, कृषि विस्तार सेवाकेन्द्र, बैंक, शाखा डाकघर, बाजार, इन्टरमीडिएट कालेज, खाद्य एवं बीज वितरण केन्द्र, ट्रेक्टर, पम्प तथा अन्य वाहनों आदि की मरम्मत के केन्द्र स्थापित होंगे। ये सेवाकेन्द्र अपने चारों ओर की कम से कम 50-50 बस्तियों को सेवायें प्रदान करते हैं।

3. प्रशासनिक सेवायुक्त केन्द्र स्थल :

अध्ययन क्षेत्र में पाँचवें स्तर के सेवाकेन्द्रों की संख्या 9 है, जिनमें ओरछा निवाड़ी, टेहकरा, पृथ्वीपुर, लिधोरा, जतारा, पलेरा, टीकमगढ़ एवं बल्देवगढ़ हैं। इन वृद्धिजनक सेवाकेन्द्रों पर तहसील मुख्यालय, विकासखण्ड मुख्यालय महाविद्यालय, कृषि, उपज मण्डी, मेडीकल स्टोर, फोटोस्टेट की दुकान, सिलाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र रहट एवं थ्रेसर निर्माण आदि सेवायें प्रदान की जाती है ये सेवाकेन्द्र अपने आस-पास के कम से कम 100-100 ग्रामों को सेवायें प्रदान करते हैं।

4. उच्च सुविधा सम्पन्न सेवा स्थल :

अध्ययन क्षेत्र में दो प्रादेशिक नगर हैं जिनमें टीकमगढ़ एवं निवाड़ी सेवाकेन्द्र हैं। इन सेवाकेन्द्रों में नर्सिंग होम, हौम्योपैथिक उपचार, एलोपैथिक उपचार, समाचार पत्र प्रकाशन केन्द्र, सिनेमा घर, पत्थर हस्त कला केन्द्र, डबलरोटी एवं ब्रेड निर्माण, दूरदर्शन, कुकिंग गैस वितरण केन्द्र, विज्ञान गृह, आटो मोबाइल्स आदि सेवायें प्रदान की जाती हैं। इन सेवाकेन्द्रों के मध्य से सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र को सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

सेवाकेन्द्रों के कार्यात्मक वर्गीकरण की विधियाँ :

1) अतिरिक्त कार्य सूचकांक विधि :

इस विधि द्वारा बाजार सेवाकेन्द्रों के अतिरिक्त कार्य सूचकांक का आँकलन किया जाता है। इस विधि को ज्ञात करने के लिये दीक्षित[3] ने ज्ञात किया, केवल राजनैतिक कार्य इसके अन्तर्गत लिये जाते हैं जो शासकीय नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं, राजनैतिक कार्यों की आशा में अराजनैतिक कार्य पिछड़ जाता है इस दृष्टि कोण के आधार पर ही इस विधि को अपनाया गया है, यह सूचकांक एक अतिरिक्त समग्र कार्यतम संमीपता की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो अपने चारों और के क्षेत्र को कितना उपयोगी सहारा प्रदान करता है, यह निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है-

सूत्र $Ca = Cax + Cay + Caz - Can$

जहाँ Ca = स्थान की सकेन्द्रीयता

Cax = × कार्य के सम्बन्ध में × स्थान की केन्द्रीयता

सूत्र $Cax = (xa - xe)\ KFm$

जहाँ Xa=a केन्द्र पर कार्यों को कार्यात्मक इकाई की वास्तविक संख्या

Xe = कार्यो की कार्यात्मक इकाई की अनुमानित संख्या

सूत्र $KFm = \frac{P}{x}$

जहाँ KFm = कार्यत्मक रखरखाव का स्थायित्व

उक्त सूत्र द्वारा समझने के लिये अतिरिक्त कार्य जैसे -साप्ताहिक विपणन जो एक वेवाकेन्द्र के रुप में माने जाते हैं में 1000 जलनसंख्या पायी जाती है इसलिए सूत्रानुसार कार्यात्मक रख रखाव का आंकलन होगा -

$$KFm = \frac{97880}{31} = 3157.42$$

$$Xe = \frac{XP}{Pr} = \frac{31 \times 1000}{97880} = 0.32$$

$$CAX = (Xa - Xe)\ KFm$$
$$= 0.68 \times 3157.42$$
$$= 2147.00$$ (सूचकांक)

अर्थात अध्ययन क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या वाले सेवाकेन्द्र का अतिरिक्त कार्य सूचांकाक औसत रुप से 2147 है।

2) **व्यापार - वाणिज्य एवं सेवा सूचकांक विधि :**

इस प्रकार का सूचकांक ज्ञात करने के लिये व्यापार वाणिज्य एवं अन्य सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में से स्थानीय सेवा केन्द्र की कुल जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है।[4]

सूत्र $Ci = \frac{Tc}{Pc}$

जहाँ Ci = किसी केन्द्र का केन्द्रीयता सूचकांक ।

Tc = किसी केन्द्र में व्यापार-वाणिज्य एवं अन्य सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या

Pc = उक्त केन्द्र की कुल संख्या ।

इस सूत्र द्वारा एक संयुक्त सूचकांक निर्मित किया गया जो व्यापार वाणिज्य एवं सेवा सूचकांक को दर्शाता है। उक्त अध्ययन से यह देखा गया है कि टीकमगढ़ नगर में सर्वाधिक उक्त सूचकांक पाया जाता है, तदानुसार इसी क्रम में द्वितीय स्तर पर जतारा, पृथ्वीपुर, ओरछा, टेहरका, मवई, कारी और इसके बाद तृतीय स्तर पर बल्देवगढ़ पलेरा एवं लिधौरा है। अध्ययन क्षेत्र में यह सूचकांक सबसे कम उन 25 ग्रामों में हे जो पूर्ण रुप से आश्रित हैं।

3. सेवाकेन्द्रों के वर्गीकरन की गुणात्मक विधि :

निकटतम पडौसी विधि द्वारा विश्लेषण करने पर टीकमगढ़ जिला में कुछ बड़े आकार के सेवाकेन्द्रों का विकास गुणात्मक दृष्टि से पाया जाता है। टीकमगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा, बल्देवगढ़, खारगापुर, औरछा, दिगौड़ा, मोहनगढ़, सिमरा, जैरोन, चंदेरा, तरीचरकलॉ, नैगुंवा, औरछा, कारी, मवई, बड़ागाँव, कुडीला आदि ऐसे सेवाकेन्द्र हैं, जिनमें शौक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी बैंक, दूरसंचार सेवाएं, कृषि विस्तार एवं खाद्य बीज वितरण क्रन्द्र पाये जाते हैं। कृषि पर अधिकांश उद्यम निर्भर करने के लिए कारण नवीन विकास की छुरी औद्योगिक विकास के रुप में अछूती रह गई है, यद्यपि इस क्षेत्र में जनसंख्या प्रवाह के एक सेवा केन्द्र से दूसरे सेवाकेन्द्र की और आधारभूत सुविधाओं का पूर्ति हेतु होता है, केन्द्रीय बस्ती से वृद्धि बिन्दु से वृद्धि केन्द्र की और आधारभूत सुविधायें जैसे- उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें एवं कृषि यंत्रों के लिये जनसंख्या प्रवाह होता है। अध्ययन क्षेत्र में यह ाीा देखा गया है कि बृहत सेवाकेन्द्र जैसे- टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा, पृथ्वीपुर, पलेरा, बल्देवगढ़ एवं खारगापुर नगरों में बाजार एवं परिवहन की सुविधाओं के साथ-साथ यहाँ सामाजिक आदान प्रदान भी होता है। केन्द्रीय बत्तियों तथा बाजार केन्द्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग इन केन्द्रों पर अपनी सामाजिक समस्याओं का निराकरण करते हैं, साथ ही साथ विवाह एवं अन्य संस्कारों से संबंधित आदान-प्रदान भी करते हैं।

गिनी[5] तत्सम्बन्ध गुणांक द्वारा तथा अक्षों पर समान वितरण की देखा द्वारा उक्त विश्लेषण और अधिक सरलतापूर्वक समझा जा सकता है-

सूत्र

$$G = \frac{1}{1000x1000} \left(\sum_{i=1}^{n} = (xouo \quad 1) - Y1x1x1+1 \right)$$

गिनी[5] के सह-संबंध गुणांक का ऑकलन बहुत छोटे आश्रित ग्रामों और बड़े बाजार केन्द्रों का 0.350 एवं 0.432 है, उक्त आंकलन यह तथ्य प्रस्तुत करता हे कि आश्रित

ग्राम ओर आरित ग्राम, बाजार एवं वृद्वि बिन्दुओं से जयादा मिलते हुए हैं।

4. सेवाकेन्द्रों के वर्गीकरण की मात्रात्मक विधि :

टीकमगढ़ जिले में सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम ज्ञात किया गया है और यह पाया गया हे कि क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का वितरण असमान है और टीकमगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा एवं खरगापुर, पलेरा नगरों के अतिरिक्त यहाँ अन्य सेवाकेन्द्रों का विकास ग्रमीण परिवेशं में हुआ है। जिनका संकेन्द्रण दक्षिण-पश्चिम की ओर है, उत्तरी पूर्वी ओर में सेवाकेन्द्र केन्द्रीय ग्रामों के रूप में विकसित हैं तथा मध्य-पूर्व भाग में पराश्रित ग्रामों की संख्या भी अधिक पायी जाती है, सेवा केन्द्रों के मात्रात्मक विशलेषण में ग्रामीण जनसंख्या को उनके सेवाविस्तार से गुणाकर अधिभार से भाग देने पर प्रतिशत सेवासार ज्ञात किया गया है जिसका सूत्र निम्नानुसार है।[6]

$$\text{सूत्र} \quad SL = \frac{WS}{RP \times S} \times 100$$

जहाँ **SL** = सेवास्तर सूचकांक

WS = राजस्व निरीक्षक मण्डल का कुल अधिभार।

RP = कुल जंनसंख्या

S = राजस्व निरीक्षक मण्डल में सेवाकेन्द्रों का विस्तार।

सारणी 5.2 में टीकमगढ़ जिला का सेवास्तर दर्शाया गया है, इस सारणी के अनुसार निवाड़ी, ओरछा, टीकमगढ़, पृथ्वीपुर एवं तरीचरकलाँ राजस्व निरीक्षक मण्डलों में सेवास्तर अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत नैगुंवा, खरगापुर, कुड़ीला एवं समर्रा राजस्व निरीक्षक मण्डलों में बहुत कम पाया जाता है। यद्यपि इस विश्लेषण से समुचित विश्लेषण नहीं हो पाता है, क्योंकि सेवाकेन्द्रों का विकास अधिक होते हुए भी यहाँ ग्रामीण जनसंख्या के

अधिक होने से सेवास्तर में अपेक्षाकृत कमी पाई है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी सेवाकेन्द्र से दूरी बढ़ती है तो उसके पड़ौसी बस्ती की उपयोगिता घटती है, इसलिए सेवाकेन्द्रों के विस्तार के साथ लिया जाना चाहिए इसके लिए टीकमगढ़ नगर का उदाहरण दिया जा सकता है। वृद्धि केन्द्र के रुप में विकसित होने के बाद भी अपेक्षित सेवास्तर जनसंख्या एवं क्षेत्रीय विस्तार की अधिकता होने के कारण कम पाया जाता है।

सेवाकेन्द्रों का सेवास्तर :

उपरोक्त सूत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों के सेवा स्तर का निर्धारण किया गया है। सारणी के अनुसार जिला टीकमगढ़ में निम्नलिखित सेवास्तरों का निर्धारण किया गया है।

1. निम्न सेवा स्तर :

अध्ययन क्षेत्र में दक्षिणी-पूर्वी भाग में सेवाकेन्द्रों का सेवास्तर निम्न पाया जाता है। समर्रा, बड़ागाँव, खरगापुर, नैगुंवा एवं कुड़ीला राजस्व निरीक्षक मण्डलों में सेवास्तर 0.37 से 0.47 तक पाया जाता है, जिसका कारण बाजार केन्द्रों का कमी है।

2. मध्यम सेवास्तर :

अध्ययन क्षेत्र में मध्यम सेवासतर के अन्तर्गत क्षेत्र का मध्यपूर्वी भाग आता है। जिसमें सिमरा, दिगौड़ा, लिधौरा, एवं पलेरा राजस्व निरीक्षक मण्डल आते हैं। इनका सेवा स्तर 0.48 से 0.55 तक है।

3. उच्च सेवास्तर :

उच्च सेवास्तर के अन्तर्गत जिला टीकमगढ़ में तरीचरकलाँ, पृथ्वीपुर, मोहनगढ़ एवं जतारा राजस्व निरीक्षक मण्डल आते हैं, जिनका सेवास्तर 0.63 से लेकर 0.75 तक है।

सारणी 5.2 : सेवा केन्द्रों का सेवा स्तर

क्रम सं.	राजस्व निरीक्षक मण्डल	जनसंख्या	सेवाकेन्द्र दूरी	अधिभार	सेवास्तर
1.	ओरछा	23559	3.84	812.68	0.90
2.	निवाड़ी	42311	4.88	2035.16	0.98
3.	तरीचरकलाँ	47887	5.37	1879.93	0.73
4.	नैगूंवा	22136	5.37	444.67	0.37
5.	सिमरा	25893	6.32	909.72	0.55
6.	पृथ्वीपुर	49875	5.37	2001.37	0.75
7.	मोहनगढ़	48090	6.32	1903.43	0.63
8.	लिधौरा	52748	6.32	1613.35	0.48
9.	दिगौड़ा	45129	6.32	1395.37	0.49
10.	जतारा	64916	6.32	2910.15	0.71
11.	पलेरा	46293	7.67	1724.31	0.48
12.	टीकमगढ़	81214	6.32	4037.38	0.79
13.	समर्रा	31695	6.32	937.81	0.47
14.	बड़ागाँव	35574	6.32	1009.12	0.45
15.	बल्देवगढ़	41417	6.32	1618.56	0.42
16.	कुडीला	32608	7.67	1175.34	0.47
17.	खरगापुर	45666	7.67	1468.39	0.42

स्रोत : प्राथमिक जनगणनासार, जिला टीकमगढ़ 1991.

Tikamgarh District
CENTRILITY INDEX & LEVEL OF CENTRILITY IN R.I. CIRCLE
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tikamgarh
Jatara
Niwari
Lidhora
Tarichar Kalan
Prithvipur
Khargupur
Mohangarh
Digoda
Palera
Badagaon
Kudila
Baldeogarh
Samarra
Simra
Orchha
Neguwan
R.I. Circles
Distribution of Service Levels
Index
S.L. Category
Very high
High
Medium
Low
5 0 5 10 15 20
KMS.
N
Population Size & Service Centres
> 1000 Persons
1001 – 2000 "
2001 – 4000 "
4001 – 8000 Persons
8001 – 16000 "
< 16000 "

Fig 5.3

4. अति उच्च सेवास्तर :

जिला टीकमगढ़ में इसके अन्तर्गत ओरछा, निवाड़ी एवं तरीचरकलाँ राजस्व निरीक्षक मण्डल आते हैं, इनका सेवास्तर 0.79 से लेकर 0.98 तक पाया जाता है। अति उच्च सेवास्तर पाये जाने का कारण इन क्षेत्रों में बाजार केन्द्रों की निकटता का पाया जाना है।

ख) सेवाओं पर आधारित प्रादेशिक नियोजन :

आर्थिकी के अंतर्गत जीवन के सभी आर्थक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रतिरुपों को सम्मिलित किया जाता है। और आज क्षेत्रीय आर्थिकी तन्त्र के विकास के लिये प्रादेशिक नियोजन को एक तकनीकी के रुप में प्रयोग में लाये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्षेत्रीय आर्थिक तंत्र के विकास के लिये बनाये गये कार्यक्रमों को नियोजन की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः नियोजन का मूलभूत तात्पर्य मानव समाज को संगठित कर प्रगति प्रदान करना है। बदलते हुए सामाजिक तकनीकी परिवेश में विभिन्न समाज अपना समायोजन कर सकें तथा इस वातावारण अधिकतम् लाभ भी अपने सदस्यों के लिए प्राप्त कर सकें। मेरियम[7] ने नियोजन के लिए कहा कि नियोजन सामूहिक बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता का प्रयोग है जो मानव वातावरण एवं उसके सामान्य हितों के सम्बन्धित सार्वजनिक क्रियाओं को दिशा, क्रम, शान्ति एवं प्रगति प्रदान करता है।

उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखकर सेवाकेन्द्रों का सेवाओं पर आधारित वर्गीकरण की आवश्यकता अनुभव की गयी। इस प्रकार वर्गीकरण में किसी प्रदेश के निवासियों के आर्थिक समाजिक एवं सांस्कृतिक विकास से सम्बन्धित हो गया जो प्रायः प्रादेशिक नियोजन को संकल्पना पर आधारित है और वर्तमान आर्थिक तंत्र के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपयुक्त संकल्पना किसी प्रदेश के सम्पूर्ण विकास को अपने अन्दर समाहित किये हुए है। प्रादेशिक नियोजन की आधारभूत आवश्यकता निम्न है।

1. प्रादेशिक नियोजन, सेवाकेन्द्र संकल्पना का भी प्रयोग स्थानिक संगठन एवं विकास के लिये करता है।

2. प्रदेशों एवं समस्याओं का पदानुक्रम भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित है, अर्थात् यह नियोजन प्रदेश को विभिन्न पदानुक्रमों में विभक्त करता है और उसके बाद उस प्रदेश की समस्याओं का क्रम निर्धारण करता है। इस प्रकार एक के बाद एक समस्या के हल ढूंढने की आज महती आवश्यकता है।

3. प्रादेशिक नियोजन राष्ट्रीय आर्थिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उपराष्ट्रीय क्षेत्रों की समस्याओं की परखता है ओर राष्ट्रीय हितों के अनुसार उसे विकसित करता है।

4. संतुलित प्रादेशिक विकास एवं आर्थिक क्रियाओं के प्रसार हेतु प्रादेशिक नियोजन में विशेष ध्यान देने का आवश्यकता है।

5. प्रादेशिक नियोजन के अन्तर्गत नियोजन इकाईयों के विभाजन के समान इकाइयों का निर्धारण में प्रशासनिक सीमाओं को विशेष महत्व दिये जाने की आवश्यकता है।

6. प्रादेशिक नियोजन के दानों मण्डलों (एलोकेटिव तथा नवीनीकरण इन्नोकेटिव) दोनों ही समान रुप से महत्वपूर्ण हैं। एलोकेटिव पर पूर्ण ध्यान देने से तकनीकी एवं प्रबन्ध संबंधी दोष नहीं आ पाते। अतः प्रत्येक समय दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है।

7. नियोजन में दोनों क्रियाकलापों (विकास एवं वातावरण सुधार) हेतु कार्य करने की अध्ययन क्षेत्र में तत्काल आवश्यकतां है, क्योंकि दोनों क्रियाएं विपरीत दिशा में क्रियाशील होती है। जैसे, उद्योगों एंव कृषि में लगातार प्रगति से अन्य क्रियाएं धीमी पड़ जाती है। अतः प्रादेशिक नियोजन के लिये वातावरण सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा जैविक संसाधन नष्ट हो जायेंगे। पर्यावरण एवं प्रदूषण पर रोक एवं नियंत्रण इसी का अंग है।

8. प्रादेशिक नियोजन के सार्वभौमिक तथ्य विशिष्ट कारकों का अन्तर तथा विभाजन स्पष्ट होना चाहिए।

9. प्रादेशिक नियोजन विषद होना चाहिए साथ ही साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा विकास प्रक्रिया में उत्पन्न विभिन्न प्रतिरुपों एवं समस्याओं से

सम्बन्धित होना चाहिए। क्योंकि प्रादेशिक नियोजन पूर्णरुपेण तभी सफल होगा, जब इसे राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गति से जोड़ा जाए और इसमें प्रादेशिक मानवीय और प्राकृतिक सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाये।

नियोजन की आवश्यकता :

प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्रादेशिक नियोजन की सहायता से संसाधनों के नियोजन हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। इसके द्वारा भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना का प्रयोग स्थानीय प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय किसी भी स्तर पर नियोजन हेतु किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी प्रदेश की समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। प्रादेशिक नियोजन की सहायता से कृषि प्रदेश एवं औद्योगिक प्रदेश नियोजन हेतु सुझाव अग्रसरित किये जाते हैं। पदानुक्रम के अनुसार विभिन्न पदानुक्रम स्तरों पर भी नियोजन संभव है। वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्रीय नियोजन नगरीय एवं महानगरीय नियोजन, समुदाय एवं मानव संसाधन नियोजन, वातावरण नियोजन, प्राकृतिक संसाधन नियोजन, आर्थिक विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन किया जाता हैं।[8]

नियोजन प्रदेश उपराष्ट्रीय क्षेत्र होते हैं अतः नियोजन प्रदेश का प्रयोग राष्ट्रीय नियोजन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्रादेशिक कार्यक्रम तथा निर्णय में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अतः नियोजन प्रदेश को अपने आप में पर्याप्त एवं पूर्ण होना चाहये जो नियोजन उद्देश्यों की विशेषताओं, सामाजिक न्याय, अर्थिक विकास तथा वातावरण के गुण को स्थानिक स्तर पर प्राप्ति कर सकें।[9] इनकी उपलब्धि हेतु नियोजन करते समय क्षेत्र के प्रादेशिक संसाधन उपयोगों वर्तमान आर्थिक स्तर, सामाजिक एवं भौतिक विकास तथा भावी विकास की सम्भाव्यता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में नियोजन प्रदेश ऐसे होने चाहिए। जो प्रदेश के अंदर या बाहर उपलब्ध संसाधनों के आधार आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करने में पूर्णतया सक्षम हो।[10]

नियोजन प्रदेश को जीवन उपयोगी एवं आर्थिक अस्तित्व वाला होना चाहिए तथा प्रदेश उपलब्ध तथा सम्भाव्य संसाधनों के आधार वांछित विकास स्तर प्रदान करने में स्वमेव सक्षम हो। अर्थात् नियोजन प्रदेश इस क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने एवं रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इसके अतिरिक्त संसाधन एवं संसाधनों के उपयोग में प्राकृतिक संतुलन अथवा पारिस्थितिकीय संतुलन प्राप्त करना भी नियोजन प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिये। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिक असन्तुलन के कारण विभिन्न रोग, सूखा, बाढ़ इत्यादि दैवीय प्रकोप प्रारम्भ हो जाते हैं। नियोजन प्रदेश के सीमांकन के आधारभूत कारक नियोजन के स्तर क्षेत्र के विशेषता एवं विविधता तथा भावी विकास की सम्याव्यता पर निर्भर करते हैं। ऐसे प्रदेशों को विषय क्षेत्र तथा उपायों की दृष्टि से कार्यात्मक होना चाहिए। जिससे सम्भाव्य एवं परिवर्तन में ग्रहणशील बन सके। एम. चार्ल्स ब्रून्ज ने नियोजन प्रदेशों के सीमांकन हेतु निम्नलिखित चार आधार बताये हैं।

1) किसी प्रदेश के सीमांकन के समय उस प्रदेश की जलवायु, भूगर्भिक बनावट, प्राकृतिक उत्पादों, प्रजातियों, रीति-रिवाजों, इतिहास एवं भाषा की एकरुपता पर विचार करना चाहिए।

2) उस प्रदेश की विशेषताओं का पूरा समाकलन होना चहिए, किन्तु विद्यमान विशेषताओं पर भी बल दिया जाना चाहिए।

3) क्षेत्रीय आर्थिक प्रतिरुपों खासकर मानवीय आर्थिक क्रिया कलापों एवं व्यापारिक संबंधों पर विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए।

4) नियोजन प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायः समान होने चाहिये।

नियोजन प्रदेश चूँकि विकास कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में स्थानिक इकाई के रुप कार्य करते हैं। अतः प्रादेशिक उद्देश्यों, प्रशासनिक दृष्टिकोणों के साथ साथ विभिन्न नियोजनों के अनुसार इनकी सीमायें लचीली भी होनी चाहिये।

REFERENCES

1. Mumford, L. (1961) : The city in History London P : 51.
2. Singh, K.N. (1966) : Spatial Patterns of Central Place Systems in Middle Ganga Valley National Geographical Journal of India, 12 P : 151.
3. Diddee, J.N. and Dikshit, K.R. (1979) : A note on Measuring Centrality of Small and Medium Size Central Places, Transactions, Institute of Indian Geographers, 1 PP : 70-79.
4. Dikshit, K.R. and Sawant, S.B. (1969): Hinterland as Region, Its Types Hierarch, Demarcation and Characteristics, Illustrated in the case of the Hinterland of Poona, N.G.J.I. 14, PP : 1-22.
5. Nath, M.L. (1989) : The upper Chambal Basisn, A Geographical study of Rural Settlement; Northern Book Centre, New Delhi, P : 64.
6. Nath, M.L. (1989) : Op. cit, P: 80.
7. Singh, K.N. et. al. (1985) : Service centres and Development strategy in Vindhyachal -

Baghelkhand Region : A spatial and Functional Approach. The National Geographical Journal of India, Vol. XXXI Pt. 2, P : 78.

8. Tiwari, P.C., J.W. Rawat and D.C. Pandey (1983) : Centrality and Ranking of settlements : A comparative Study of Hills and Tarai of Bhabar Region, District Nainital, U.P. Himalayas, The Deccan Geographers, VOL. XXI, No.3, P : 391.

9. Bronger, D. (1978) : Central Place System, Regional Planning and Development in Developing Countries - Case of India in R.L. Singh et. al. Ed. Transportation of Rural Habitat in Indian perspective - A Geographical Dimensions : NGSI, India Varanasi.

10. Singh, J. (1979) : Central Places and spatial Organisation in a Backward Economic : Gorakhpur Region, - A study in Integrated Regional Development : Uttar Bharat Bhoogol Parishad, Gorakhpur PP : 5 - 11.

11. Mishra, R.P. (1976) : Regional Development and Planning in India, A New Strategy, Vikas Publiching House, New-Delhi, P : 110.

----0----

अध्याय छह

सेवाकेन्द्रों के कार्य और कार्यात्मक पदानुक्रम

- अधिवास पदानुक्रम का सैद्धान्तिक उपागम
- केन्द्रीयता सूचकांक पर आधारित पदानुक्रम
- केन्द्रीयता मापन की विधियाँ
- पदानुक्रम वर्ग
- कार्यात्मक सूचकांक पर आधारित पदानुक्रम
- कार्यात्मक सूचकांक का निर्धारण
- पदानुक्रम स्तर
- सन्दर्भित ग्रन्थों की सूची

सेवाकेन्द्रों के कार्य तथा कार्यात्मक पदानुक्रम : (FUNCTIONS AND FUNCTIONAL HIERARCHY OF SERVICE CENTRES:

केन्द्रीय स्थानों के क्षेत्रीय समाकन ओर कार्यात्मक सहसम्बन्ध प्रादेशिक योजनाओं के आधारभूत लक्ष्य होते हैं। किसी क्षेत्र की मानवीय क्रियायें और क्षेत्रीय कार्य वहाँ की स्थिति के अन्तर्सम्बन्धित होती है। वास्तव में क्षेत्रीय संसाधनों की अपक्रिया और उनका कार्यात्मक विश्लेषण स्थानीय की संरचनात्मक विशेषताओं ओर मानवीय क्रियाओं द्वारा परस्पर सहसम्बधित होते हैं।[1] कार्यों की केन्द्रीयता, उनका विकेन्द्रीकरण या नाभिक परम्परा भू-सतह पर क्षेत्रीय निर्माण कार्य एवं मानवीय व्यवहार के मूलभूत उपागम है। क्षेत्रीय निर्माण की बाह्य संरचनायें जैसे स्थान, माँग अर्थिकी के विकास को दर्शाता है और परिवहन मूल्य सीधे सम्बन्धित होते हैं। कार्यात्मक ओर अन्तर्क्षेत्रीय मानवीय क्रियाऐं समस्त समूह के अधिवासों में क्षेत्रीय संरचनाओं का निर्माण करती है। अतः किसी क्षेत्र के केन्द्रीय कार्य जो बस्तियों द्वारा निर्मित किये जाते हैं। उनको समझने तथा उनकी केन्द्रीयता को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। किन्तु केन्द्रीयता, केन्द्रीय स्थानों के विकास में राजनैतिक व्यवस्था भी प्रस्तुत करती है।[2]

अधिवासों के पदानुक्रम के सैद्धान्तिक उपागम :

अधिवासों को उनकी परम्परागत विशेषताओं और केन्द्रीय कार्यों के अनुसार आकारिकी में पृथक किया जाता है। केन्द्रीय कार्य वे है जो कुछ स्थानों पर निर्मित होते हैं, किन्तु बहुत से अन्य स्थानों के लिये उपयोगी होते हैं कार्यों की श्रेणियों बस्तियों के आकार एवं प्रतिरुप पर निर्भर होती हैं। सामान्यतः जनसंख्या आकार के आधार पर बस्तियों के आकारों को समझा जा सकता है जो कि प्रमुख क्रियाशील कारक हैं। जनसंख्या के उपरांत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारक जो विशेषकर, सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक विभिन्न

प्रकार(कार्यों को प्रतिपादित करते हैं, इसके अन्तर्गत आते हैं।[3] जिला टीकमगढ़ में अध्ययन के लिये चुने गये कार्यों की यद्यपि समुचित स्थिति प्राप्त नहीं है, किन्तु स्थानिक प्रशासनिक स्थिति के कारण जिला मुख्यालय टीकमगढ़ तहसील मुख्यालयों, विकासखण्ड मुख्यालयों, राजस्व निरीक्षक मण्डलों एवं नगरीय केन्द्रों में कार्यों का तुलनात्मक क्षेत्र अधिक पाया जाता है, नगर एवं कस्बों के स्थान उन ग्रामीण क्षेत्रों का जो सड़क, दूरसंचार एवं अन्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। अधिक कार्यों की श्रेणियाँ रखते हैं क्योंकि सड़क के किनारे स्थित होने एवं सहकारी समितियों के पाये जाने से केन्द्रीय स्थानों की महत्ता बढ़ जाती है। अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण से यह पता लगा की कार्यों की संख्या और बस्तियों की संख्या के बीच ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अर्थात् कार्यों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जाती है ग्रामीण बस्तियों की संख्या भी उसी अनुपात में घटती जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय कार्यों के वितरण के केन्द्रीय स्थानों का प्रादुर्भाव होता है। और यह परम्परा कार्यात्मक पदानुक्रम की पद्धति में समूहों को जन्म देती है। मानचित्र 6.1 में अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत कार्यों का वितरण दर्शाया गया है।

केन्द्रीय सूचकांक पर आधारित पदानुक्रम :

जनसंख्या सीमाकन विधि :

विधि द्वारा कार्यों के सापेक्ष विश्लेषण को निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या सीमांकन के लिये न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता कार्यों के लिये बल प्रदान करने के लिये हेती है। इसके लिये निम्न लिखित आधार होते हैं।

1. प्रवेश बिन्दु :

प्रवेश बिन्दु के अन्तर्गत जनसंख्या के वे कार्य, जिसमें विशेष कार्य सभी के लिए नहीं होते जैसे जिला टीकमगढ़ में 200 से कम जनसंख्या वाली बस्तियों में प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है। अर्थात 200 व्यक्ति से कम जनसंख्या वाली बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश बिन्दु होगा।

Tikamgarh District
Facilities
A Education
P – Primary Schools
M – Middle Schools
H – High Schools
I – Intermediate (10+2)
DC – Degree College
B Health
H-Hospital
D-Dispensary
PHC-Primary Health Centre
FPC-Family Planning Centre
PHS-Primary Health Sub Centre
CWC-Child Welfare Centre
MCW-Maternity & Child Welfare
SMP-Subsidised Medical Practioner
O-Others
C Drinking Water
W- Wells
HD-Hand Pump
TW-Tape Water
D Credit & Communication
SP-Sub Post Office
BP-Branch Post Office
BS-Bus Stop
RS-Railway Station
NB-Nationalized Bank
BKB-Bundal Khand Rural Dev. Bank
LDB-Land Development Bank
CBS-Co operative Bank & Society
N
0 30
KM.
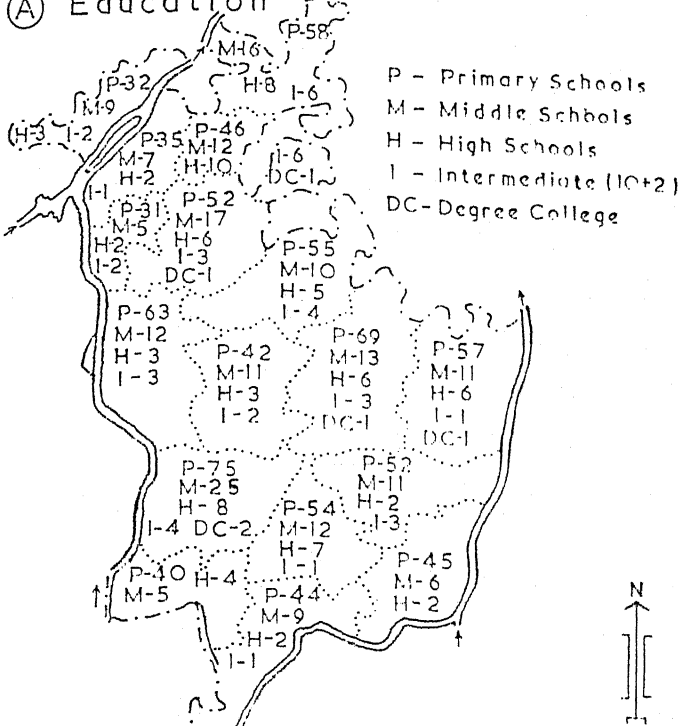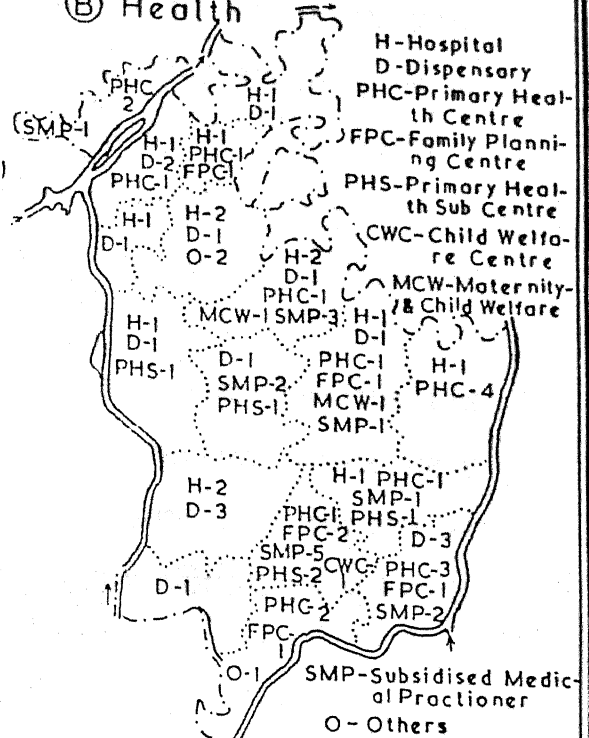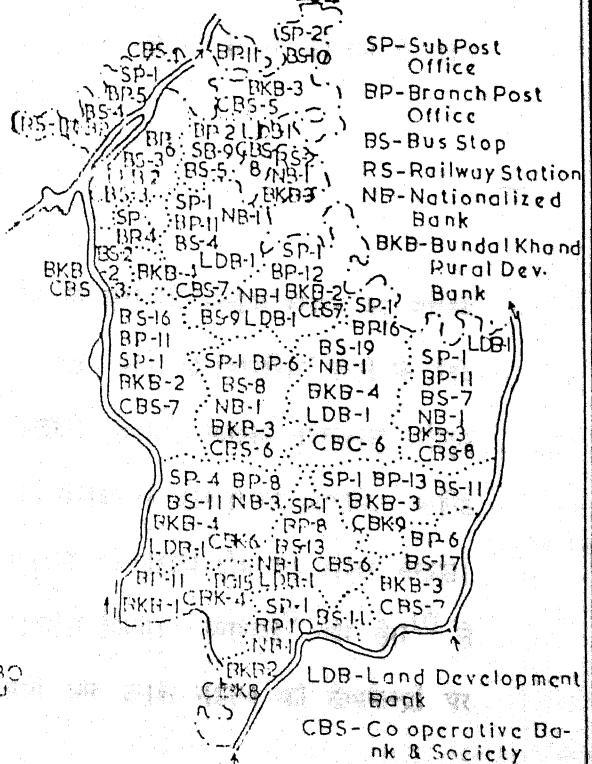
Fig 6.1

2. परिपूर्णतः बिन्दु :

इसमें जनसंख्या का वह आधार जिसमें बस्तियों में सभी कार्यों को होना चाहिये। जिला टीकमगढ़ में कुछ कार्यों के लिए चयनित केन्द्र में प्रसार सेवायें वितरित की गई, और इन, प्रसार सेवाओं के वितरण में कोई निश्चित जनसंख्या आकार नहीं है। 100 जनसंख्या से अधिक वाली लगभग सभी बस्तियों में इस प्रकार की सेवायें पाई जाती है।

3. प्रवेश मण्डल :

प्रवेश बिन्दु एवं परिपूर्णतः बिन्दु के संयुक्त आधार को प्रवेश मण्डल कहते हैं। कार्यों की प्रकृति का वितरण अनिश्चित होने से एवं प्रवेश मण्डल निर्धारित होने से प्रत्येक कार्यों के लिये जनसंख्या सीमांकन किया जाता है। सरणी 6.1 में प्रवेश बिन्दु ओर उनका अधिभार दिया गया है। इन अधिभारों के मध्य जनसंख्या सीमांकन किया जाता है।

4. प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन :

प्रभाव क्षेत्र से तात्पर्य उस प्रक्षेत्र से है, जिसमें समान सेवाओं के लिये जनसंख्या एक केन्द्रीय बस्ती पर निर्भर करती है, केन्द्रीय स्थान और उस पर निर्भर बस्तियों के बीच आकर्षण कार्यों और सेवाओं की प्रकृति का निर्धारण करती हैं।

पदानुक्रम स्तरों का निर्धारण :

आर्थिक ओर सामाजिक विकास प्रतिनिधि के रुप में केन्द्रीय स्थान का महत्व विकास कार्यों में सहायक क्षेत्र के रुप में होता है। प्रभाव क्षेत्र को विभाजित करने के लिये अनेकों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें रिलीज नियम[3], कनवर्स संकल्पना, यीट्स मॉडल[4] आदि प्रमुख है। गोडलुण्ड[5] और ग्रीन[6] ने बस सेवाओं के आंकड़ों पर आधारित, जबकि क्रिस्टालर[7] ने सम्बन्धित केन्द्रों के केन्द्रीयता और पदानुक्रम को प्रभाव क्षेत्र का आधार बनाया। ब्रेसी[8] ने ग्रामीण समुदायों की केन्द्रीयता का नवीन उपयोग किया। वनमाली[9] ओर सेन[10] ने नवीन पहूँच मार्ग निर्मित की जो विशिष्ट आवश्यकताओं ओर उनके महत्व को सेवाकेन्द्रों पर

आधारित थीं। वर्तमान अध्ययन में प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन को **गुणात्मक ओर मात्रात्मक दोनों** विधियों का उपयोग किया गया है।

पदानमुक्रम निर्धारण की गुणात्मक विधि :

इस विधि का प्रयोग आवश्यकतानुसार स्थानीय कार्यों और क्षेत्रीय विशिष्टताओं पर आधारित होता है। केन्द्रों के चयन-जैसे, क्षेत्रीय प्रमुखता के आधार पर स्वच्छ समीकरण जो किसी केन्द्र के प्रभाव क्षेत्र को दर्शातें हैं विधि का उपयोग दो सफलतम अवस्थाओं में किया गया। सबसे पहले कार्यात्मक पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर केन्द्र को मानचित्र पर अंकित किया जाता है। दूसरे प्रत्येक केन्द्र के प्रभाव क्षेत्र की क्षेत्रीय कटिबद्धता को सम्मिलित किया गया है, जिनको दूसरे, तीसरे ओर चौथे स्तर पर विभाजित किया गया है। प्रत्येक केन्द्र की विभिन्न कार्यात्मक पदानुक्रम स्तर को बहुत से सेवित क्षेत्रों और वहाँ की जनसंख्या को सर्वेक्षित कर सारणी बद्ध किया जाता है।[12]

पदानुक्रम निर्धारण की मात्रात्मक विधि :

प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन के लिये बहुत से शोधकर्ताओं ने फुटकर गुरत्वाकर्षण पर आधारित 'रिलीस नियम' का प्रयोग किया है।[12] रिलीस के अनुसार तथा गाँव, कस्बों के बीच व्यापारिक क्षेत्र का सीमांकन से निश्चित दूरी में निम्नलिखित जनसंख्या ओर केन्द्रीय कार्यों के संख्या के अनुसार निश्चित की जा सकती है। जनसंख्या और केन्द्रीय कार्यो की संख्या आकार के सूचकांक के रुप में निम्न सूत्र द्वारा आकलित किया जाता है।

$$\text{सूचकांक} = \frac{A \text{ तथा } B \text{ के बीच की दूरी (कि.मी. में)}}{1 + \sqrt{A \text{ का आकार} / B \text{ का आकार}}}$$

वर्तमान अध्ययन में उक्त सूत्र को थोड़ा परिवर्तन किया गया है जो निम्नानुसार है।[13]

सूत्र : $$LS = \frac{D}{1+\sqrt{\frac{1}{AC / BC}}}$$

जहाँ

D = केन्द्रों के बीच की दूरी

AC = केन्द्र A का केन्द्रीयता अंक

BC = केन्द्र B का केन्द्रीयता अंक

LS = A से B स्थानों के सेवा क्षेत्र की सीमा

उक्त सूत्र के द्वारा प्रत्येक का प्रभाव क्षेत्र कार्यात्मक स्तर के अनुसार सीमाबद्ध किया गया है इस मॉडल को बस्ती के मानचित्र में अध्यारोपित करने पर सारांश इस प्रकार मिलता है।

1. मॉडल की सीधी रेखायें बस्तियों की वास्तविक सीमाओं को प्रस्तुत नहीं करती हैं।

2. प्राकृतिक अवरोध जो अध्ययन क्षेत्र में जहाँ जहाँ फैले हैं। मानव क्रियाओं को एकल्पता प्रदान करने में बाधक है।

3. क्षेत्रीयता के सम्बन्ध में वास्तविक मानव व्यवहार प्रतिरुप ज्यामितीय स्वरुप के साथ मॉडल के अन्तर्गत समाहित नहीं होता।

उक्त अवगुणों के आधार पर पूर्व में प्रस्तुत सैद्धांतिक विधि के विश्लेषण को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार दिशा निर्देशों के लिये प्रयोग सिद्ध विधि अपनायी गयी है।

योजना इकाइयों के निर्धारण में केन्द्रीय स्थानों के प्रभाव क्षेत्र मानचित्र में

विभिन्न वर्गीय पदानुक्रम रखते हैं जो दोनों विधियों द्वारा अध्यारोपित हैं। सामंजस्य हीनता की स्थिति में क्षेत्रीय एकरुपता को आंकड़ों के आधार माना गया है। योजना इकाईयों को अंतिम सीमा निर्धारण प्रशासनिक सीमाओं के साथ समायोजित है। सूक्ष्य स्तरीय नियोजन इकाईयों केन्द्रीय ग्रामों, उनके प्रभाव क्षेत्र के अनुसार निर्मित बाजार वाले गाँव और स्थानिक क्रियाओं वाले गाँव की विशेषतायें बृहत प्रभावी होकर अधिक केन्द्रीय होती है।[14] इस प्रकार तीन विभिन्न मापकों की इकाईयों अध्यवसायी प्रकृति को इंगति करती हैं। आश्रित बस्तियों जो केन्द्रीय बस्ती से स्वतः जुड़ी होती हैं, नये सेवा केन्द्रों का नियोजित स्वरुप अपनाते हुये नियोजन किया जाना आवश्यक है। जिससे वे क्षेत्रीय बाह्य कटिबद्धता में और अधिक शक्तिशाली हो सके। इसी प्रकार समाजिक सुविधाओं और कृषिगत अद्यःसंरचना को निम्नवर्गीय योजनाओं, इकाईयों जो समूहों के रुप में जोड़ा जाना चाहिए। जहाँ आधार भूत संरचनायें अनुपस्थित हैं। सामान्यतः योजनओं के लिये प्रादेशिक कस्बों पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य होना चाहिये। साप्ताहिक बाजार युक्त गाँव और उसके प्रभाव क्षेत्रों को ओर अधिक विकसित किया जाना चाहिये जिससे वर्तमान नियोजन प्रक्रिया विभिन्न वर्गों की चयनित वर्गों और व्यय पर आधारित हो सके।[15]

पदानुक्रम स्तरों का स्थानिक वितरण :

क्षेत्र के संतुलित विकास के लिये किसी केन्द्र पर जनसंख्या के दबाव को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है इस जनसंख्या दबाव को जाने बिना वहाँ के आर्थिक स्तर का समुचित अध्ययन कर पाना असम्भव होता है। इकाईयों के प्रभाव क्षेत्र को सीमांकित करने के लिये विभिन्न शोधार्थियों ने केन्द्र की ओर फुटकर आकर्षण शक्ति की वास्तविकता का नियम स्वीकार किया है।[16]

अध्ययन क्षेत्र की नियोजन इकाईयों के प्रभाव क्षेत्र को सीमांकित करने के लिये सड़क, यातायात, बैलगाड़ी, रास्ता और नदियाँ अवरोधकों को नहीं लिया गया है, बल्कि वहाँ के लोगों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चुनी गई इकाईयों के प्रभावक्षेत्र (पहूँच) द्वारा नियोजन इकाईयों के प्रभावित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। नियोजन इकाईयों को चार पदानुक्रम

स्तरों में बाँटा गया है। जो निम्नलिखित है-

तृतीय स्तर के सेवा केन्द्र :

तीसरे इकाई के अन्तर्गत 150 सेवा केन्द्र आते हैं जो 875 बस्तियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन केन्द्रों पर जनसंख्या दबाव 736981 है। जो सारणी 6.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.1 : जिला टीकमगढ़ में तृतीय स्तर के सेवाकेन्द्र एवं उनकी सेवित जनसंख्या.

क्रमांक	सेवाकेन्द्र	सेवित ग्रामोंकी संख्या	सेवित जनसंख्या
1.	हीरानगर	3	2697
2.	कारी-खास	7	8335
3.	अनन्तपुरा	7	2540
4.	नयाखेरा	7	3288
5.	गनेशगंज	2	960
6.	जमड़ार (शिवपुरी)	1	1551
7.	टीकमगढ़	9	44900
8.	धजरई	5	2544
9.	मवई-खास	3	2899
10.	मजना-खास	9	3014
11.	माडूमर	11	5664
12.	मिनौरा-खास	14	4402
13.	अस्तौन-खास	7	5673
14.	पठा-खास	7	5631
15.	गुदनवारा-खास	7	2899
16.	समर्रा	3	3143
17.	अजनौर-खास	8	5542
18.	लार-खास	2	2360
19.	बड़माड़ई	3	1896
20.	नन्हीं टेहरी-खास	3	2925

सारणी 6.1

क्रमांक	सेवाकेन्द्र	सेवित ग्रामों की संख्या	सेवित जनसंख्या
21.	बुड़ेरा	8	8118
22.	दरगुंवा	6	3655
23.	बड़ागाँव	12	9498
24.	डूँडा	7	4806
25.	ककरवाहा खास	8	4316
26.	झिनगुंवा	12	7746
27.	लड़वारी खास (अहार)	3	3031
28.	अहार	8	4402
29.	चंदूली	7	3707
30.	गुखरई-खास	6	3717
31.	बल्देवगढ़	6	6971
32.	देवरदा	5	3589
33.	भेलसी	6	6166
34.	सुजानपुरा-खास	2	2088
35.	सरकपुर-खास	3	2652
36.	गोरा	2	2609
37.	गुना	4	4735
38.	खरगापुर	10	13291
39.	चन्दपुरा	2	874
40.	फुटेर चक्र-1	4	3744
41.	मातोली-खास	6	4546
42.	देरी	12	9547
43.	कुड़ीला	12	11247

सारणी 6.1

क्रमांक	सेवाकेन्द्र	सेवित ग्रामों की संख्या	सेवित जनसंख्या
44.	दूबदेई	7	1181
45.	हीरापुर-खास	8	4521
46.	पटौरी जागीर	8	4223
47.	मलगुँवा	7	6014
48.	सूरजपुर-खास	3	2103
49.	हटा	11	8047
50.	नंदनवारा-खास	9	5396
51.	बम्हौरी-बराना	8	7282
52.	कुम्हैड़ी-खास	7	3581
53.	अचरा-खास	5	3616
54.	मोहनगढ़-खास	9	7395
55.	मालपीथा	4	1706
56.	दरगांय-खुर्द	6	2212
57.	गोर	7	3964
58.	बिजरावन	6	4083
59.	खैरा	5	4291
60.	मड़खेरा	10	4564
61.	मनयारा-खेरा	4	2947
62.	वर्मा-ताल	2	1586
63.	वर्माडाँग-खास	12	7771
64.	मऊ बुजुर्ग	3	3382
65.	धामना	5	4917
66.	दिगौड़ा	7	7294
67.	बछौड़ा	4	4932
68.	मुहारा	1	4310
69.	सतगुँवा	1	4235
70.	ईसोन	3	1004
71.	वीरऊ	5	3645
72.	लिधौरा-खास	15	16054
73.	चंदेरा-खास	9	11423

सारणी 6.1

क्रमांक	सेवाकेन्द्र	सेवित ग्रामोंकी संख्या	सेवित जनसंख्या
74.	खरों	5	4153
75.	जेवर	7	7814
76.	मैदवारा	5	4023
77.	नुना	6	4742
78.	पहाड़ी बुजुर्ग	3	3168
79.	सगरवारा	4	3053
80.	उदयपुर	11	6663
81.	बम्होरी कलाँ	11	8532
82.	बराना	7	5162
83.	सिमरा खुर्द	5	5403
84.	जतारा	6	15836
85.	वाजीत पुरा	4	3727
86.	बैरवारा	6	5109
87.	पिपरट	5	4338
88.	करमौरा	5	4929
89.	धूरा-खास	9	6620
90.	बूदौर	9	5504
91.	मवई (पलेरा)	2	2117
92.	गोवा	8	5031
93.	पलेरा-खास	10	12244
94.	लारौन	2	2816
95.	टौरिया-खास	6	5115
96.	आलमपुरा-खास	9	5974
97.	रामनगर-बुजुर्ग	9	5653
98.	सुनौरा खिरिया पश्चिमी	5	4058
99.	सुनौरा खिरिया-खास	5	2581
100.	ढिल्ला	3	1604
101.	नैगुवाँ	11	5203
102.	दरेठा	8	4112
103.	उरोदौरा	10	4932
104.	जेरोंन खालसा	20	14288

सारणी 6.1

क्रमांक	सेवाकेन्द्र	सेवित ग्रामों की संख्या	सेवित जनसंख्या
105.	सिमरा-खास	5	6454
106.	जेरा-खास	3	3163
107.	भोपाल पुरा	4	2664
108.	पृथ्वीपुर	3	12687
109.	मड़िया	3	3048
110.	अछरुमाता	2	656
111.	लुहरगुँवा	6	5074
112.	ककावनी खास	4	3083
113.	ज्योरा मौरा	4	4273
114.	बिरोरा खेत	2	2048
115.	बिरोरा पहाड़ खास	7	5121
116.	दुमदुमा	9	5273
117.	चौमौ	9	4689
118.	सकेरा भड़ारन खास	5	3923
119.	पुंछी करगुवां	12	11905
120.	असाटी-खास	10	7968
121.	सेंदरी	8	7390
122.	कुड़ार	8	4086
123.	उबौरा	5	3057
124.	तरीचरकलाँ	4	6001
125.	पठाराम	1	1572
126.	चचावली	1	1087
127.	धमना	2	2422

सारणी 6.1

क्रमांक	सेवा केन्द्र	सेवित ग्रमों की संख्या	सेवित जनसंख्या
128.	थोना	2	3369
129.	जमुनियाँ-खास	6	3414
130.	महराजपुरा	5	2551
131.	चंदावनी-खास	2	4078
132.	चकरपुरा	2	1411
133.	लठेसरा	2	1143
134.	मड़ोर पूर्वी	3	1888
135.	राधापुर	3	1016
136.	ओरछा	4	3002
137.	कुम्हर्रा-खास	2	1355
138.	प्रतापपुरा	6	1211
139.	सीतापुर	7	4541
140.	लड़वारी कछयाऊ	5	3523
141.	राजपुर	6	2753
142	कुलुवा-खास	4	2737
143.	पोहा-खास.	3	2694
144.	निवाड़ी	4	14471
145.	निमचौनी	3	1398
146.	बहेरा	3	1722
147.	दबरी नायक	2	501
148.	अस्तारी	1	1331
149.	टेहरका-खास	3	6123
150.	घुघसी-खास	44	3004

चौथे स्तर के सेवा केन्द्र :

अध्ययन क्षेत्र में चौथे स्तर के 14 सेवाकेन्द है तथा एक बाहय् केन्द्र झाँसी महानगर का प्रभाव भी इस के साथ सम्मिलित होता है। कुल सेवा ग्रामों की संख्या 260 (अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत) तथा 15 बाहय् क्षेत्र द्वारा सेवित है। सरणी 6.2 में इन केन्द्रों को दर्शाया गया है।

सारणी 6.2 : चौथे स्तर के केन्द्र, जनसंख्या दबाव और सेवित बस्तियों की संख्या

क्रमसंख्या	सेवाकेन्द्रों के नाम	सेवित ग्रामों की संख्या	सेवित जनसंख्या
1.	टीकमगढ़	110	112909
2.	बड़ागाँव	49	35574
3.	बल्देवगढ़	55	41417
4.	खारगापुर	99	78274
5.	मोहनगढ़	76	48090
6.	दिगौड़ा	44	45129
7.	लिधौरा	22	19830
8.	चँदेरा	34	32918
9.	जतारा	67	64916
10.	पलेरा	58	46293
11.	पृथ्वीपुर	107	86905
12.	तरीचर कलाँ	42	39287
13.	निवाड़ी	80	59165
14.	टेहरका	17	14820
		860	725527
अध्ययन क्षेत्र से बाहर का केन्द्र (झाँसी)		15	11454
	जिला टीकमगढ़	**875**	**736981**

पाँचवे स्तर के केन्द्र :

अध्ययन क्षेत्र में इस स्तर के केन्द्रों की संख्या 4 है, जिनमें टीकमगढ़, जतारा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी हैं। ये केन्द्र 835 बस्तियों की 734422 जनसंख्या को सेवायें प्रदान कर रहे हैं। एक केन्द्र (झाँसी) जो अध्ययन क्षेत्र से बाहर का है, 40 बस्तियों की 23559 जनसंख्या को सेवित करता है। इस प्रकार पाँचवे स्तर के केन्द्रों की संख्या 5 है जो सारणी 6.3 में दर्शायी गयी हैं।

सारणी 6.3 : पाँचवे स्तर के केन्द्र, जनसंख्या दबाव और सेवित बस्तियों की संख्या

क्रम संख्या	केन्द्रों के नाम	सेवित केन्द्रों की संख्या	सेवित जनसंख्या
अ)	अध्ययन क्षेत्र के अन्दर के केन्द्र :		
1.	टीकमगढ़	433	361393
2.	जतारा	181	163957
3.	पृथ्वीपुर	128	97904
4.	निवाड़ी	93	90168
ब)	बध्ययन क्षेत्र से बाहर के केन्द्र :		
5.	झाँसी	40	23559
	जिला टीकमगढ़	**875**	**736981**

स्रोत : प्राथमिक जनगणनासार, जिला टीकमगढ़ ।

छठे स्तर के केन्द्र :

छठे स्तर के केन्द्रों में अध्ययन क्षेत्र के अन्दर एक ही केन्द्र, जिला मुख्यालय टीकमगढ़ में हैं जो 698 बस्तियों की 601118 जनसंख्या को सेवित कर रहा है। इसी तरह अध्ययन क्षेत्र के बाहर का एक केन्द्र (झाँसी) 177 बस्तियों की 135863 जनसंख्या को सेवायें प्रदान कर रहा है, इस केन्द्र का प्रभाव अध्ययन क्षेत्र के ओरछा, तरीचरकलां एवं निवाड़ी

Tikamgarh District
People Choice of Centres For
(A)
Third Level Functions
Puchhik-arguwan
Pratappura
Tarichar Kalan
Orchha
Niwari
Tehar Ka
Nagwan
Prithvipur
Sakera Bhadoran
Jeraun Kha-
Chandra
Bamhori Kalan
Lidhora
Mohangarh
Bamhori
Jatara
Palera
Digoda
Karmora
Ramnagar-Buzurg
Kari
Mabai
Khargapur
Tikamgarh
Kudila
Shivpuri
Baldeogarh
Samarra
Hata
Badagaon
(B)
Fourth Level Functions
Orchha
Niwari
Tehar Ka
Prithvipur
Lidhora
Palera
Digoda
Jatara
Khargapur
Tikamgarh
Baldeogarh
Badagaon
N
(C)
Fifth Level Functions
Orchha
Niwari
Tehar Ka
Prithvipur
Lidhora
Jatara
Palera
Tikamgarh
Baldeogarh
(D)
Sixth Level Functions
Niwari
Tikamgarh
5 0 5 10 15 20
Kilometers

Fig 6.2

राजस्व निरीक्षक मण्डलों के बस्तियों पर है। छठे स्तर के केन्द्रों को सारणी 6.4 तथ मानचित्र 6.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.4 : छठे स्तर के केन्द्र, जनसंख्या दबाव एवं सेवित बस्तियों की संख्या.

क्रम संख्या	केन्द्रों के नाम	सेवित बस्तियों की संख्या	सेवित जनसंख्या
अध्ययन क्षेत्र के अन्दर के केन्द्र :			
1.	टीकमगढ़	698	601118
अध्ययन क्षेत्र से बाहर के केन्द्र:			
2.	झाँसी	177	135863
	योग जिला टीकमगढ़	**875**	**736981**

स्रोत : प्राथमिक जनगणनासार, जिला टीकमगढ़.

ख) कार्यात्मक सूचकांक पर आधारित पदानुक्रम :

केन्द्रीय स्थानों के निर्धारण के लिये कुछ तत्वों को चुना जाता है, इनसे कार्यात्मक पदानुक्रम की सेवा सम्बन्धीं महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है।[17] जिला टीकमगढ़ में व्यक्तिगत सर्वेक्षण द्वारा यह पाया गया कि कार्यों के वितरण में समरुपता नहीं है और न ही एक जैसे कार्य सभी स्थानों पर पाये जाते हैं यह अंतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्यात्मक पदानुक्रम स्तर को एक निश्चित स्वरुप प्रदान करते हैं। एक ही प्रकार के कार्य समूहों को उनके स्तरों के समान सम्बन्धित महत्व प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिये प्राथमिक पाठशाला, पूर्व माध्यमिक शाला, माध्यमिक शाला, उच्चतर माध्यमिक शाला (विद्यालय) ओर महाविद्यालय समान कार्य समूहों के आते हैं इस प्रकार इन सेवाकेन्द्रों को एक समूह में रख कर महत्वपूर्ण सम्बन्ध स्तर को निकाला जाता है। कार्यात्मक पदानुक्रम में कार्यों के सभी वर्गों को शिक्षा स्वास्थ्य, बस सेवायें, संचार, व्यवस्था वित्तीय सुविधायें, बाजार, फुटकर सेवायें, किराना, टेलरिंग, चाय, हार्डवेयर, कैमिस्ट एवं ड्रगिस्ट सम्मिलित है। प्रत्येक कार्यों के उपकार्यों

को भी उनके स्तरों के अनुसार रखा जाता है ऐसे कार्य जो अधिक महत्व के नहीं हैं अन्य कार्यों के अन्तर्गत रखे जाते है। उपकार्यों के स्तर को जो प्रत्येक वर्ग का पदानुक्रम निर्धारित करते हैं अलग कार्यों के अन्तर्गत रखे जाते है। अध्ययन क्षेत्र की कच्ची व पक्की सड़कों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। क्षेत्रीय रेल सुविधायें, रेल्वे स्टेशनों, बस स्टॉप, प्रार्थना बसस्टाप एवं प्राईवेट बस सेवा को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता हैं।

कार्यात्मक पदानुक्रम की संरचना सेवास्थलों में कार्यों की वैद्यता की जटिलता होती है। बड़े केन्द्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य अधिक जटिल और छोटे केन्द्रों में कम जटिल होते हैं। प्रत्येक केन्द्र का कार्य स्तर पदानुक्रम वर्ग के अनुसार ऊँचा होता है। कार्यों का निर्धारण जनसंख्या के आकार के अनुसार किया जाता है। यद्यपि यह सही है कि कुछ कार्यों के लिये जनसंख्या की आवश्यकता कम होती है, जिसे जनसंख्या प्रवेश द्वार कहते हैं। हैगिट[18] तथा हैगरस्ट्रेन्ड[19] ने इन कार्यों की विलोमता समाप्त करने के लिए एक कार्य के प्रवेश मण्डल ओर प्रवेश क्षेत्र के मध्य बिन्दु के कार्यों का निर्धारण किया। रीडमुंच[20] ने ग्राफ के अन्तर्गत जनसंख्या प्रवेश मार्ग के मध्य प्रस्तुत किया, अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या प्रवेश बिन्दु में चुने गये कार्यों के लिये किया गया विश्लेषण वांछित परिणाम नहीं देता, क्योंकि कुछ कार्यों में बहुत कम और कुछ में बहुत ऊँचा जनसंख्या स्तर पाया जाता है।

कार्यात्मक पदानुक्रम का स्तर :

केन्द्रीय स्थान और उनके पदानुक्रम को समीकृत करने के लिये ज़नसंख्या सीमांकन विधि की सहायता ली गयी है। प्रत्येक कार्य के लिये मानचित्र 6.2 में बस्तियों के कार्य दर्शाये गये हैं। प्रत्येक कार्य के लिये सारणी एवं मानचित्र द्वारा बस्तियों के कार्यों की तीव्रता का आंकलन किया गया है। विभिन्न जनसंख्या स्तरों का वितरण अध्ययन क्षेत्र में विखंडित पाया जाता है। सरणी 6.5 अध्ययन क्षेत्र का कार्यात्मक पदानुक्रम स्तर दर्शाया गया है।

सारणी 6.5 : कार्यों का पदानुक्रम स्तर.

कार्य स्तर	जनसंख्या स्तर	कार्यों की संख्या	सेवाकेन्द्रों की संख्या
अतिनिम्न	867 - 11515	27	699
निम्न	13648 - 43352	24	113
मध्यस्त	56691 - 122830	21	20
उच्च - मध्यस्त	147396 - 184245	10	3
उच्च	245660 - 368490	9	7
उच्चतम	368491 - 736981	47	7
6		**138**	**849**

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत अति निम्न में 27, निम्न में 24, मध्यम में 21, उच्च मध्यम 10, उच्च में 9 और उच्चतम में 47 कार्यस्तर पाये जाते हैं। इनमें क्रमशः 700, 113, 20, 3, 7 तथा 7 के केन्द्रस्थान है। स्थानीय प्राथमिकता विशिष्ट कार्यों के लिये व्यक्तियों द्वारा बस्तियों तथा केन्द्रीय स्थानों के चुनावों की प्राथमिकता है। अर्थात वहाँ के निवासियों द्वारा चयनित केन्द्रीय स्थान हैं।

सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम स्तर :

अध्ययन क्षेत्र में केन्द्रीय स्थानों का पदानुक्रम निर्धारित करने एवं उनके विश्लेषण तथा मध्ययन क्षेत्र की बस्तियों की क्रियाशीलता एवं वस्तुस्थिति के आधार पर निम्न तथ्यों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें -

1. पदानुक्रम का दृष्टिकोण स्पष्ट करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में सेवाओं का आंकलन एवं क्षेत्रीय विकास के लिए सूक्ष्य स्तरीय सुझाव प्रस्तुत करना है।

उपरोक्त तथ्यों की सहायता से बस्तियों के कार्यात्मक पदानुक्रम को निर्धारित करने के लिये छठें स्तर के केन्द्र, पांचवे स्तर के केन्द्र, चतुर्थ स्तर के केन्द्र, तृतीय स्तर के केन्द्र द्वितीय स्तर के केन्द्र एवं प्रथम स्तर के केन्द्र चुने गये हैं।

छठें स्तर के केन्द्र :

कार्यात्मक वस्तुस्थिति के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में इन केन्द्रों के निर्धारण के लिए सारणी 6.5 में दर्शाया गया है। इस प्रकार के केन्द्रों में अध्ययन क्षेत्र 7 बस्तियाँ आती हैं, जिनमें टीकमगढ़, प्रतापपुरा, मिनौरा, धजरई, कुण्डेश्वर, सुजानपुरा एवं निवाड़ी केन्द्र सम्मिलित हैं, क्योंकि ये अपनी विशिष्ट सेवायें अध्ययन क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को प्रदान कर रहे हैं।

पाँचवे स्तर के केन्द्र :

पाँचवे स्तर के केन्द्र धनात्मक वस्तुस्थिति द्वारा निर्धारित है, इन केन्द्रों के निर्धारण में वस्तुस्थिति की कार्यात्मकता को महत्व दिया गया है। अध्ययन क्षेत्र में 7 बस्तियाँ इस प्रकार के केन्द्र, जतारा, पृथ्वीपुर, ओरछा, टेहरका, मवई, भेलसी एवं कारी है। इनमें स्वास्थ्य सेवायें, वित्तीय संस्थायें, परिवहन सुविधायें, विस्तार सेवायें, बाजार सेवायें एवं संचार सेवाओं का विस्तार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन केन्द्रों में वह सेवायें भी प्रप्त हैं जो अध्ययन क्षेत्र में केवल इन्हीं केन्द्रों पर उपलब्ध है।

चतुर्थ स्तर के केन्द्र :

इन केन्द्रों के निर्धारण में अन्तर्आश्रितता को लिया गया है, उन बस्तियों को चतुर्थ स्तर के केन्द्रों में सम्मिलित किया गया है, जिनमें कार्यात्मक आश्रितता 2500 से 2400 के मध्य पायी जाती है इनमें बल्देवगढ़, पलेरा एवं लिधौरा बस्तियाँ आती है।

तृतीय स्तर के केन्द्र :

तृतीय स्तर के ऐसे केन्द्रों में उन बस्तियों को रखते हैं जो कार्य केवल उन्हीं बस्तियों में होते हैं। जैसे- पशु बाजार, धार्मिक स्थल, दर्शनीय स्थल एवं नर्सरी (वन) आदि हैं। तृतीय स्तर के केन्द्रों में अध्ययन क्षेत्र की 20 बस्तियों आती हैं इस प्रकार के केन्द्र जिले के दक्षिण-पश्चिम में स्थित हैं।
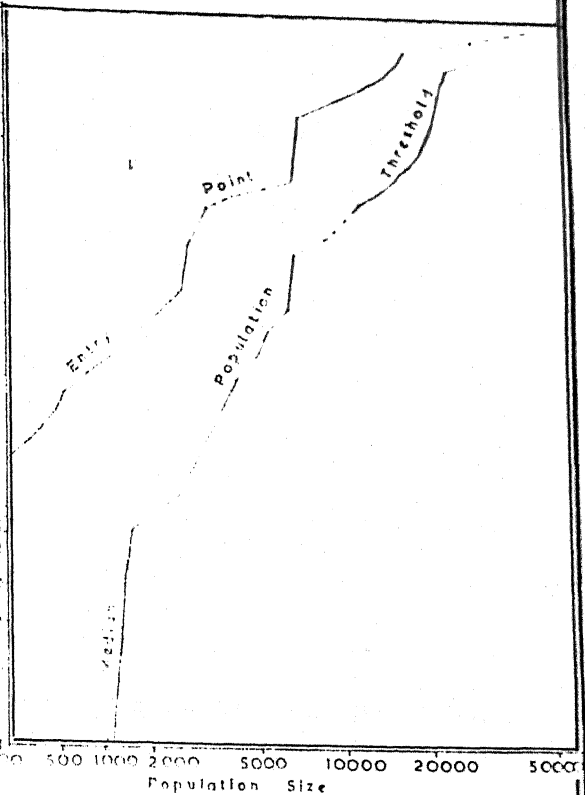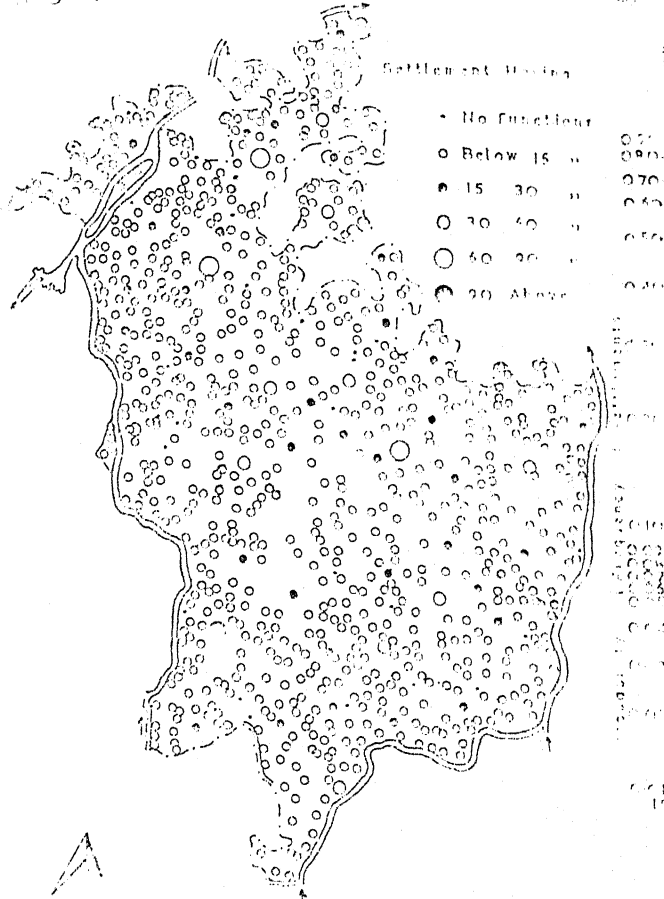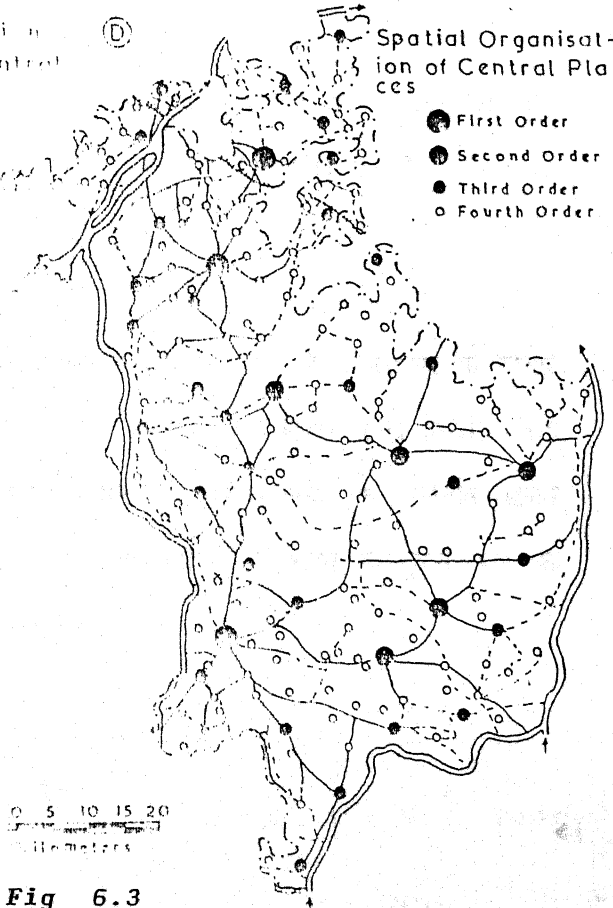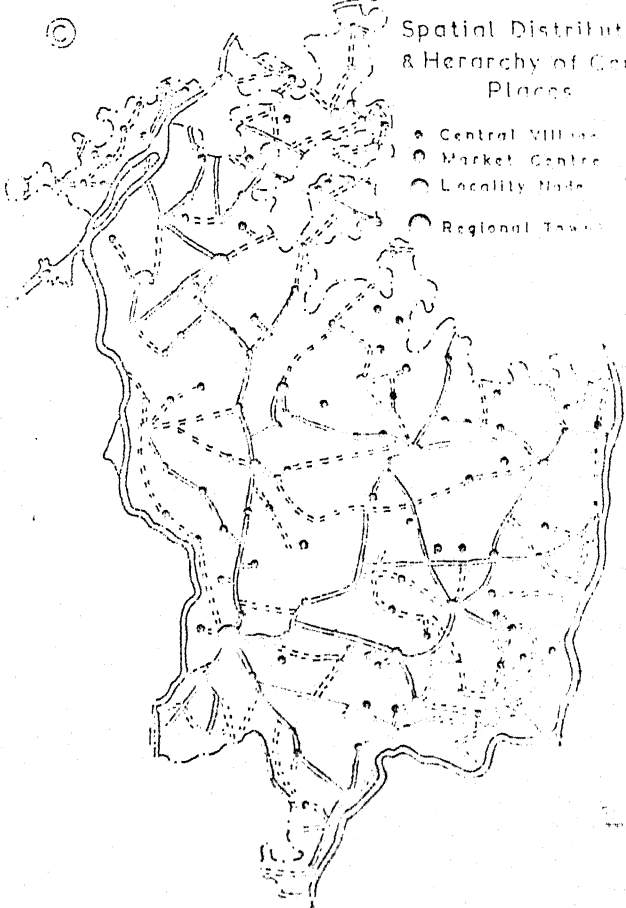
द्वितीय स्तर के केन्द्र :

इस प्रकार के केन्द्रों में माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल, दर्जी, नाई, पोस्ट आफिस, बाजार, बस सुविधायें, किराना की दुकानें, चाय की दुकानें आदि सेवाओं के रुप में पायी जाती हैं इस प्रकार के केन्द्र पाँचवें एवं चतुर्थ केन्द्रों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या अध्ययन क्षेत्र में 113 हैं।

उपाश्रित केन्द्र अथवा प्रथम स्तर के केन्द्र :

अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या 699 बस्तियाँ है जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पातीं, इस प्रकार के केन्द्र तृतीय और द्वितीय केन्द्रों पर आश्रित रहते हैं। इन केन्द्रों में प्राथमिक विद्यालय, औपचारिकेत्तर शिक्षा, आटाचक्की, साईकिल मरम्मत, लुहार, बढई, दर्जी, नाई, जूता मरम्मत आदि सेवायें उपलब्ध कराते हैं।

पूर्ण आश्रित बस्तियाँ :

अध्ययन क्षेत्र में 25 बस्तियाँ ऐसी भी है जहाँ एक भी सेवा नहीं हैं जो पूरी तरह इन छठों केन्द्रों पर आश्रित हैं जैसा कि सारणी क्रमांक 6.1 में दर्शाया गया है।

निरीक्षण :

अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम छह संख्या में है, क्रिस्टालर के बाजार सिद्धांत का विकास संख्या 6 है, अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टालर का बाजार केन्द्र सिद्धांत जिला टीकमगढ़ के अन्य केन्द्रों की तुलना में अधिक निकट है अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत बाजार केन्द्रों के सिद्धांत का प्रदर्शन अनुकूल है। तथा बस्तियों के विभिन्न पदानुक्रम वर्गो का समीकरण प्रस्तुत करने का विधि अधिक अनुकूल है।

-*-

REFERENCES

1. Singh, O.P. (1971): Towards Determining Hierarchy of service Centres : A Methodology for Central Place Studies, National Geographical Journal of India, P: 17.

2. Berry, B.J.L. and Garrison, W.J. (1968): The Functional Basis of the Central Place Hierarchy, Economic Geography, 34, PP: 145-54.

3. Reilly, W.J. (1929): Methods of the study of Retail Relationship Res: Monograph, No.4. Neareau of Rusiness Research, University of Texas Bulletin, U.S.A. PP: 198-211.

4. Yeats, N. (1963) : Hinterland Determination, A Distance minorizing Approach; Professional Geographers, Vol. 15, P : 371.

5. Godlund, S. (1956) : The functions and Growth of Bus Traffic within the sphere of Urban Influence, Land Studies in Geography Series, No. 18, P: 249.

6. Green, F.H.W. (1948): Motor Bus Services in West England Transactions, Institute of British Geographers 19 , P: 45-57.

7. Christaller, W. (1966) : Die Zentrale Ortiem Suddentch P and Jeha G. Fisher (1933) Translated by Basking Englewood cliffs New Jursey

United States of America.

8. Wanmali (1972): (a) Central Places and their Tributary Population : Some Observations, Behavioural Science and Community Development, NICD, Hyderabad, 6 PP: 11-39. (b) Zones of Influence of Central Villages in Miryalguda Taluka : A Theoritical Approach Behavioural and Community Development, NICD, Hyderabad, 6, PP : 1-10.

9. Sen, L.K. et. al. (1975) : Growth Centres in Raichur : An Integrated Arera Development Plan for a District in Karnataka, NICD Hyderabad, 6 PP : 121-140.

10. Scott, P (1964) : The Hierarchy of Central Places in Tasmania, The Australian Geographer Vol. 9, P : 170

11. Reilly, W.J. (1929): Op.cit. P-280

12. Reilly, W.J. (1929): Op.cit. P-281

13. Singh, O.P. (1971) : Towards Determining Hierarchy of Service Centres, A Methodology for Central Place Studies, National Geographical Journal of India, P : 17.

14. Singh, O.P. and D.C. Pandey (1986): Development Planning : Theory and Practice, Gyanodaya Publications, PP: 144 - 159.

15. Tiwari, R.C. and Tripati, S. (1985) : Integrated Rural Development and Central Place Theory Govind Vallabh Pant Social Science Institute, Allahabad, Paper presented in National Conference, Allahabad.

16. Tiwari, P.C., J.S. Rawat and D.C. Pandey (1983): Centrality and Ranking of Settlements : A Comparative Study of Hills and Tarai Bhaban Region, District Nainital, U.P., Himalaya, The Deccan Geographers Vol. 21, PP : 391 - 401.

17. Haggett, P. (1966) : Locatioal Analysis in Geography, Edward Arnold, London.

18.Hegerstrand, T. (1967) : Innovation of Diffusion as Spatial Process, Translated by Allen Pred. Chikago University Press, U.S.A.

19. Saxena, N.P. and Tyagi, R.P. (1975) : Criteria for Determining Centrality in Micro Regions. The Geographical Observer, 2. P: 61.

-0-

अध्याय सात

स्थानिक वितरण तथा श्रेणी आकार सम्बद्धता

- सेवा केन्द्रों का स्थानिक वितरण
- आकार एवं प्रकीर्णन
- वितरण की पद्धतियाँ
- सेवा केन्द्रों की श्रेणी आकार सम्बद्धता
- वर्तमान उपागम
- अतिक्रम पद्धतियाँ
- सन्दर्भित ग्रन्थों की सूची

सेवा केन्द्रों का स्थानिक वितरण एवं श्रेणी आकार सम्बद्धता : (Spatial Distribution and Rank Size Relationship of Service Centres.)

सेवाकेन्द्रों के वितरण प्रतिरुप को जलवायु, धरातल, जलापूर्ति, अपवाह तंत्र तथा सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। अध्ययन क्षेत्र का विस्तार अधिक न होने के कारण तापक्रम व प्रकाश का प्रभाव सम्पूर्ण जिले में लगभग एक समान है। धरातलीय बनावट को दृष्टि से सघन एवं विरल दोनो प्रकार के सेवाकेन्द्रों के वितरण प्रतिरुप निर्मित होते हैं। जलापूर्ति और अपवाह तंत्र द्वारा सेवाकेन्द्रों की सघनता होती है। सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव भी किसी सीमा तक विभिन्नताओं को प्रदर्शित करता है, इसमें भाषा, धर्म और जाति सेवाकेन्द्रों के वितरण प्रतिरुप को निर्मित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नगरीय सेवाकेन्द्रों को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रशासनिक केन्द्र, यातायात के साधन, बाजार की सुविधा, सुरक्षा आदि तत्व प्रभावित करते हैं।

1. सेवा केन्द्रों का आकार एवं विस्तार :

सेवास्थलों का मूल स्वरुप घर होता है, उनकी प्रकृति, निर्माण की प्रक्रिया जाति, वर्ग और धर्म के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती है।[1] ग्रामीण सेवा स्थल वातावरण के कारकों के साथ निर्धारित होता है। इनमें सेवा के निर्माण का पदार्थ स्थानीय सामग्री द्वारा निर्धारित होता है। मकानों के प्रकार बदल रहे हैं, क्योंकि भवन निर्माण में नवीन तकनीकी प्रवेश कर चुकी है। इसलिये व्यक्तित्व की सांस्कृतिक विरासत में परिवर्तन आया है, इससे अध्ययन क्षेत्र अछूता नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में भवन निर्माण का पदार्थ भौतिक पर्यावरण से निर्मित है। अध्ययन क्षेत्र में मिट्टी के ईट, गारा, खपरैल अदि तैयार होते हैं। यद्यपि पक्के मकानों का प्रचलन शुरु हुआ है, किन्तु पक्के मकानों को यहाँ के लोग पहले ईट, गारा से तैयार करते हैं और उसकी छाप सीमेन्ट अथवा चूने द्वारा निर्मित करवाते हैं। छतों के निर्माण में भौतिक पर्यावरण प्रभावी है इसमें कंकरीट रेत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई

है। अध्ययन क्षेत्र में कंकरी व रेत अल्प मात्रा में उपलब्ध हाने से भवनों का निर्माण मिट्टी के द्वारा निर्मित ' पक्की ईट ' (जिसे स्थानीय भाषा में 'गुम्मा' कहते हैं) के द्वारा निर्मित होती है।

ग्रामीण सेवा स्थल के निर्माण में स्थिति और स्थल योजना सांस्कृतिक कारकों जैंसे - व्यवसायिक, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों द्वारा प्रभावी होते हैं। एक किसान की व्यवसायिक आवश्यकता छोटे व्यवसायी और गृह योजना से पूरी तरह भिन्न होती है। उसी प्रकार वाणिज्यिक भवनों, शिक्षण संस्थाओं, औद्योगिक इकाईयों की योजनायें भी एक-दूसरे से भिन्न होती हैं और आवश्यक-आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन होते हैं। वस्तुतः गृह योजना किसी क्षेत्र की अधिकाधिक जनसंख्या के धार्मिक पक्ष पर निर्भर करती है।[2]

1) सेवा स्थलों का स्थानिक वितरण प्रतिरुप :

सेवास्थलों का वितरण जनसंख्या एवं अधिवासों से निकटतम सम्बन्ध रहता है। जिला टीकमगढ़ में 27 भवन प्रति वर्ग कि.मी. में वितरित हैं। मकानों का सर्वाधिक घनत्व टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में 41 भवन प्रति वर्ग कि.मी. हैं। इस राजस्व निरीक्षक मण्डल में अधिक भवनों के घनत्व का कारण टीकमगढ़ नगर (अध्ययन क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर) का पाया जाना है। कम घनत्व पलेरा, कुड़ीला तथा समर्रा में 21 भवन प्रति वर्ग कि.मी. वितरित हैं। इन राजस्व निरीक्षक मण्डलों में कम घनत्व का कारण समतल भूमि का अभाव, कृषि भूमि का अपेक्षाकृति अभाव एवं सिंचाई के साधनों की कमी है, सेवा स्थल के प्रतिरुप की वृद्धि परम्परागत जनसंख्या के समान है। अतः यह कहा जा सकता है कि सेवा केन्द्र जनसंख्या वृद्धि से सीधे सम्बन्धित हैं। सरणी 7.1 में अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों का आकार एवं घनत्व को दर्शाया गया है।

सारणी 7.1 : सेवाकेन्द्रों का आकार एवं घनत्व

राजस्व निरीक्षक	मकानों की संख्या	प्रतिशत	परिवारों की संख्या	प्रतिशत	मकानों का घनत्व	परिवारों घनत्व
ओरछा	3576	2.91	4057	3.24	25	28
निवाड़ी	6950	5.67	7003	5.59	35	35
तरीचरकलाँ	7624	6.22	7678	6.13	28	28
नैगुँवा	3483	2.84	3840	3.06	24	26
सिमरा	4190	3.42	4397	3.51	34	35
पृथ्वीपुर	8659	7.06	8724	6.96	31	31
मोहनगढ़	8310	6.77	8592	6.86	24	25
लिधौरा	8674	7.07	8731	6.97	25	25
दिगौड़ा	7284	5.94	7562	6.04	24	25
जतारा	10182	8.30	10497	8.30	25	26
पलेरा	7394	6.03	7483	5.97	21	22
टीकमगढ़	13462	10.97	13682	10.92	41	42
समर्रा	5442	4.44	5466	4.36	21	21
बड़ागाँव	6723	5.48	6764	5.40	23	23
बल्देवगढ़	7061	5.76	7100	5.67	27	27
कुड़ीला	5951	4.85	5959	4.76	21	21
खरगापुर	7695	6.27	7738	6.18	25	24
कुल जिला में	**122660**	**100.00**	**125273**	**100.00**	**27**	**27**

स्रोत : प्राथमिक जनगणनासार, ग्राम व नगर निदर्शनी, जिला टीकमगढ़ 1991.

सारणी 7.1 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में मकानों की कुल संख्या 122660 है जो टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में (10.97%) सर्वाधिक तथा वन क्षेत्र के अधिक विकसित होने के कारण नैगुँवा रा.नि.म. में सबसे कम है। परिवारों के आकार में भी यही स्थिति परिलक्षित होती है। टीकमगढ़ में मकानों का घनत्व 41 सर्वाधिक है जबकि न्यूनतम 21 कुड़ीला, समर्रा, पलेरा, रा.नि.म. में दिखाई देता है।

अध्ययन क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रकार के आवासीय स्थल पाये जाते है। यह केवल अधिवासों में ही नहीं, बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी परिवर्तित हैं जो उस क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार उस क्षेत्र में पाये जाने वाले सेवा केन्द्रों का स्वरुप निर्धारित करते हैं।

ख) श्रेणी आकार सम्बर्धता :

जितने अधिक सेवास्थल बढ़ते हैं, उतना ही अधिक सेवाकेन्द्रों का आकार बढ़ता है।[3] अध्ययन क्षेत्र में आवास और उनके आकार में स्वस्थ सम्बर्धता पायी जाती है। यह सम्बंर्धता प्रत्येक रा. नि. म. में कम या अधिक पाई गई है। जिला टीकमगढ़ के सेवास्थलों के आकारों को श्रेणीबद्ध वर्गों में बाँटा गया है। सभी वर्ग एक ही परम्परा के अनुसार बहुत कम अन्तर को प्रगट करते हैं। बड़ागाँव की संख्या क्षेत्रीय आकार के अन्तर्गत 4 से 6 वर्ग कि.मी. जनसंख्या का आकार 600 से 800 सेवा केन्द्रीय गृह आकार 100 से 150 ओर परिवार आकार 90 से 140 के मध्यं है। सरणी 7.2 में इसे दर्शाया गया है।

ग) सेवा केन्द्रों का घनत्व :

सेवाकेन्द्रों के क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण सेवाकेन्द्रों के घनत्व द्वारा आंकलित है। प्रत्येक रा. नि. म. का कुल क्षेत्रफल, सेवास्थान / ग्रामों की संख्यां द्वारा विभाजित है जिसे सेवाकेन्द्रों का क्षेत्रीय आकार प्राप्त हुआ। सांख्यिकी में उच्च भागफल इकाई क्षेत्रफल में ग्रामीण सेवास्थलों को कम करेगा। उदाहरण के लिय नैगुँवा रा. नि. म. में न्यूनतम 3.3 और दिगौड़ा में 6.85 सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है।

Classical Models Of Central Place Theory
A Marketing Principle
Arrangement
Nesting
Routes
B Transport Principle
Arrangement
Nesting
Routes
C Administrative Principle
Arrangement
Nesting
Routes
After Christaller, 1950
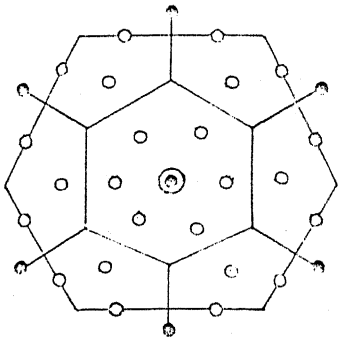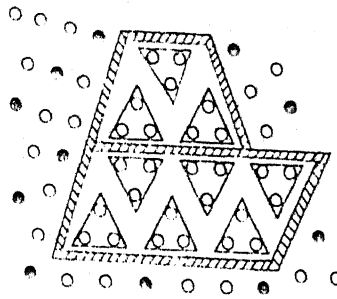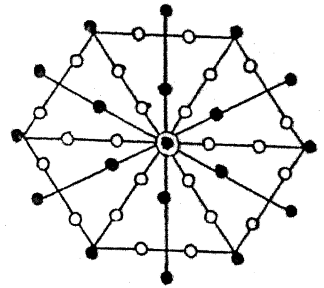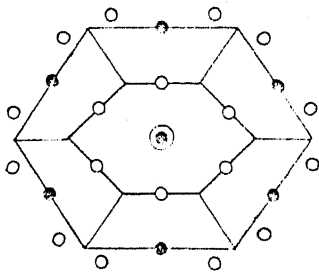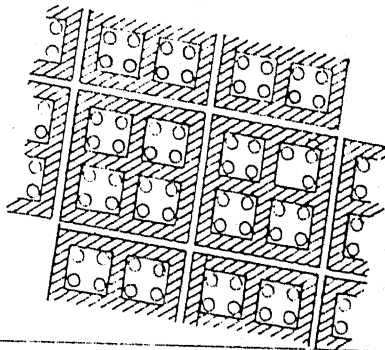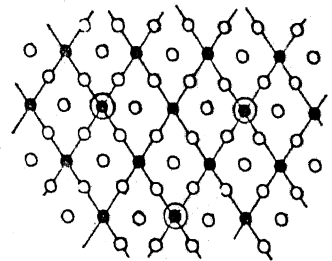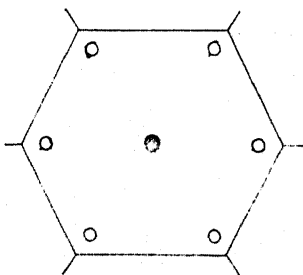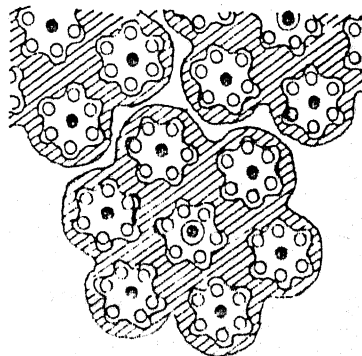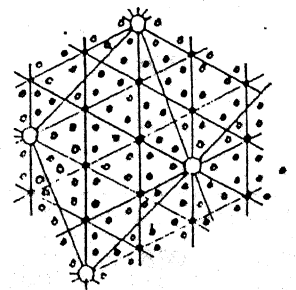
Fig 7.1

सारणी 7.2 : जिला टीकमगढ़ सेवाकेन्द्र घनत्व प्रति सेवाकेन्द्र औसत क्षेत्रफल एवं औसत जनसंख्या.

राजस्व निरीक्षक मण्डल	प्रति 100 वर्ग कि.मी. सेवा घनत्व	प्रति सेवाकेन्द्र औसत क्षेत्रफल (वर्ग मि.मी.)	प्रति सेवाकेन्द्र औसत जनसंख्या
ओरछा	27.86	3.59	589
निवाड़ी	20.21	4.95	1058
तरीचरकलाँ	19.16	5.22	903
नैगुँवा	30.08	3.32	503
सिमरा	24.13	4.14	863
पृथ्वीपुर	19.89	5.24	924
मोहनगढ़	22.02	4.54	633
लिधौरा	16.09	6.21	942
दिगौड़ा	14.59	6.85	1025
जतारा	16.57	6.03	969
पलेरा	15.60	5.97	798
टीकमगढ़	18.39	5.44	1353
समर्रा	19.44	5.14	634
बड़ागाँव	16.77	5.96	726
बल्देवगढ़	21.19	4.72	753
कुड़ीला	18.87	6.78	639
खरगापुर	14.75	5.53	951
जिला टीकमगढ़	**19.65**	**5.27**	**839**

घ) सेवास्थलों का अन्तराल :

भूगोल में क्षेत्रीय विश्लेषण के लिये दूरी एक प्रमुख कारक है। **सेवा स्थलों** के आपसी बीच की दूरी को सेवास्थलों का अन्तराल कहते हैं। सिंह[4] ने **सेवास्थलों की** अवस्थिति व्यवस्था को सेवाकेन्द्रों का अन्तराल कहा है, उनके अनेक शोधकर्ताओं ने सेवाकेन्द्रों का अन्तराल करने के लिये अनेक सांख्यिकी तकनीकी को सुझाया है जिनमें वेकली[5], विनिंग[6], भाट[7], वनमाली[8], रफी उल्लाह[9], रील[10], वेरी[11], और मुकर्जी[12] प्रमुख हैं। माथ्यर[13] ने निम्न लिखित सूत्र का प्रयोग किया जिसे समीपवर्ती पड़ोसी विधि के रुप में जाना जाता है।

सूत्र $$D = 1.0746 \sqrt{\frac{A}{N}}$$

जहाँ

D = एक सेवा केन्द्र से दूसरे सेवाकेन्द्र के बीज की दूरी.

A = कुल क्षेत्रफल.

N = सेवाकेन्द्रों की कुल संख्या.

अतः उक्त सूत्र के अनुसार सेवाकेन्द्रों के चारों ओर एक षटकोण निर्मित होता है। जो अन्तर सेवाकेन्द्र दूरी को प्रदर्शित करता है। मुकर्जी[14] ने वृत्ताकार सेवाकेन्द्र के चारों ओर अन्तर सेवास्थलों के मध्य की दूरी को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया।

$$S = 1.1284 \sqrt{\frac{A}{N}}$$

उक्त दोनों सूत्रों का उपयोग न कर अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मण्डल का आंकलन किया गया है। सारणी 7.3 में सेवाकेन्द्रों के अन्तराल को दर्शाया गया है, जिसमें एक से दूसरे सेवाकन्द्र की दूरी एवं षटकोणीय सेवा केन्द्र दूरी दी गई है।

मैथनी[15] द्वारा मुकर्जी के उक्त सूत्र की आलोचना करते हुए कहा कि सेवाकेन्द्रों का अन्तराल वृत्तों में न होकर रिक्त स्थानों में होना चाहिए। इस प्रकार एक सेवाकेन्द्र से दूसरे सेवाकेन्द्र के बीच और उनके चारों ओर से वृत्त निर्मित होता है वह सैद्धांतिक अधिक किन्तु प्रायोगिक कम।

सेवाकेन्द्रों के विभिन्न समूहों को वर्गीकृत कर जिला टीकमगढ़ में सेवाकेन्द्रों की विस्तार की प्रकृति का आधार बनाया गया। सेवाकेन्द्रों के विस्तार का प्रवृति एक बस्ती से दूसरी बस्ती की दूरी से निकटतम सम्बन्ध है। स्माइल्स[16] तथा डिमांजया[17] ने निम्नलिखित सूत्र दिया -

$$K = E \times \frac{N}{T}$$

जहाँ

K = आवश्यक विखराब गुणांक

E = प्रमुख नाभिक बस्ती की जनसंख्या.

N = कुल बस्तियाँ.

T = जनसंख्या।

हयूस्टन[18] ने अलग-अलग सेवाकेन्द्रों की दूरी को आंकलित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया -

$$K = S \times \frac{N}{T - N}$$

जहाँ

K = विकीर्ण सूचकांक.

S = क्षेत्रफल.

N = कुल बस्तियाँ.

T = कुल जनसंख्या.

E = प्रमुख स्थान से जनसंख्या का आहरण.

सिंह एवं पाण्डे[19] ने हयूस्टन के उक्त सूत्र के परिवर्तन किया और निम्न सूत्र द्वारा सेवाकेन्द्रों के विखाराव की प्रकृति को ज्ञात किया है।

$$D = \frac{Tc \times N}{Tr}$$

जहाँ

D = बिखारव सूचकांक.

Tc = एक समूह की जनसंख्या.

N = एक समूह में बस्तियों की संख्या.

Tr = प्रदेश की कुल जनसंख्या.

क्लार्क और ईवांस [20] ने निकटतम् पड़ोसी विधि प्रस्तुत की। इस विधि द्वारा एक नियमित एवं सामूहिक प्रतिरुप का आंकलन आकर्षित वास्तविक बिन्दु प्रतिरुप के विपरीत निकटतम अन्तर सेवाकेन्द्र दूरी के मध्य किया जाता है।

इसे निम्न लिखित सूत्र की सहायता से आंकलित किया गया है।

$$Rn = \frac{ro}{re}$$

जहाँ

Rn = निकटतम अधिवास दूरी.

ro = निकटतम सेवाकेन्द्र सीधी रेखा में दूरी.

re = वितरण की अपेक्षित दूरी.

आकर्षित सूचकांक विस्तार में आगे परिवर्तन करते हुए क्लार्क एवं ईवांस ने मूल्य एवं प्रतिशत के बीच अनुपातिक सम्बन्ध प्रस्तुत किया। इस सूत्र में 100 से गुणा कर प्रतिशत मूल्य ज्ञात किया जाता है जिसे निम्न सूत्र द्वारा -

$$Di = \frac{ro}{re} \times 100$$

सारणी 7.3 : जिला टीकमगढ़ में सेवाकेन्द्रों का बिखराव एवं **प्रकीर्णन सूचकांक**

राजस्व निरीक्षक	बिखराव सूचकांक	आवश्यक गुणांक	प्रकीर्णन सूचकांक
ओरछा	1.28	6.03	0.25
निवाड़ी	2.30	9.89	0.20
तरीचरकलाँ	3.44	3.69	0.31
नैगुँवा	1.32	3.12	0.29
सिमरा	1.05	4.23	0.14
पृथ्वीपुर	3.65	12.17	0.32
मोहनगढ़	4.96	5.30	0.55
लिधौरा	4.01	7.50	0.39
दिगौड़ा	2.69	4.21	0.30
जतारा	5.90	9.84	0.44
पलेरा	3.64	9.94	0.44
टीकमगढ़	6.61	31.29	0.27
समर्रा	2.15	4.30	0.41
बड़ागाँव	2.36	4.72	0.41
बल्देवगढ़	3.09	5.64	0.36
कुड़ीला	2.26	4.02	0.45
खरगापुर	2.97	7.31	0.35
औसत जिला	**3.16**	**7.89**	**0.34**

स्रोत : प्राथमिक जनगणनासार जिला टीकमगढ़ 1991.

आंकलित किया है। इस प्रकार के आंकलन से जिला टीकमगढ़ में प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मण्डलानुसार अन्तर सेवाकेन्द्र विस्तार प्रतिरुप से पाँच वर्ग प्राप्त होते हैं सारणी 7.2 में अध्ययन क्षेत्र के उक्त सूत्रों के अनुसार सेवाकेन्द्रों का विखराव उनका प्रकीर्णन आदि को दर्शाया गया है।

1. आकस्मिक विस्तार :

जिला टीकमगढ़ में आकस्तिक विस्तार नगरीय सेवाकेन्द्रों जैसे - टीकमगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा और पलेरा में पाया गया है। इन नगरों में निकटवर्ती ग्रामों के सम्मिलित हो जाने के परिणामस्वरुप आकस्मिक विस्तार अधिक है। 1991 की जनगणनानुसार जिला टीकमगढ़ के अन्य नगरीय भागों में भी आकस्मिक विस्तार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

2. निम्न विस्तार के सेवाकेन्द्र :

अध्ययन क्षेत्र में औसतन 1.38 जिसमें मूल्य 64 प्रतिशत तक है। निम्न विस्तार के सेवाकेन्द्र नैगुँवा, समर्रा, ओरछा, बल्देवगढ़ रा. नि. म. में पाया जाता है।

3. मध्य विस्तार के सेवाकेन्द्र :

इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र का औसत विस्तार 1.35 मूल्य पाया जाता और मूल्य 62 प्रतिशत है। मध्य विस्तार क्रमशः पलेरा, जतारा, मोहनगढ़, पृथ्वीपुर, ओरछा, बड़ागाँव, कुड़ीला रा. नि. म. में पाया जाता है।

4. उच्च विस्तार के सेवाकेन्द्र :

1.38 से अधिकमूल्य वाले तथा 65 प्रतिशत से अधिक मूल्य के सेवाकेन्द्र को इस वर्ग में रखा गया है इसके अन्तर्गत खरगापुर, तरीचरकलां, निवाड़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल प्रमुख है।

बाजार सेवाकेन्द्रों का वितरण :

1) स्थाई विपणन सेवा केन्द्र :

इस प्रकार के सेवाकेन्द्रों में उन वस्तुओं का आंकलन किया गया है। जहाँ एक निश्चित् स्थान पर स्थाई दुकाने बनी हों, जिनसे दैनिक एवं अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं को खरीद या बेच जा सकें, स्थाई विपणन सेवाकेन्द्र की संज्ञा दी गई है।[2] इस प्रकार के स्थाई विपणन सेवाकेन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों 1000 से कम आवादी वाले ग्रामों में नहीं है। 1000 से 1999 तक आबादी वाले चार ग्रामों में 2000 से 4999 तक आबादी वाले 10 ग्रामों में और 50000 से अधिक आबादी वाले 2 ग्रामों में स्थाई बाजार हैं। नगरीय क्षेत्रों में सभी 12 नगरों में (1991 की जनगणनानुसार) स्थाई बाजार हैं।

2) पशु विपणन सेवाकेन्द्र :

अध्ययन क्षेत्र में पशु बाजारों की संख्या अत्यंत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु बाजार साप्ताहिक न होकर वार्षिक पशु बाजार या वार्षिक मेला के रुप में लगते हैं। 200 से 499 तक की आबादी वाले एक ग्राम में, 1000 से 1999 तक आबादी वाले दो ग्रामों में एवं 2000 से 4999 तक आबादी वाले दो ग्रामों में पशु बाजार लगते हैं। नगरीय क्षेत्रों में पशु बाजारों की संख्या 6 है जो सारणी 7.4 से स्पष्ट है।

साप्ताहिक विपणन सेवाकेन्द्र :

साप्ताहिक विपणन सेवाकेन्द्रों की ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उपयोगिता है; क्योंकि साप्ताहिक बाजार से ग्रामीण व्यक्तियों की बहुत सी आवश्यकताओं की खरीददारी का केन्द्र होते हैं। 200 से कम आवादी वाले 2 ग्रामों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, 500 से 999 आवादी वाले 23 ग्रामों में 23 बाजार लगते हैं। 1000 से 2999 तक आवादी वाले 81 ग्रामों

सारणी 7.4 : जिला टीकमगढ़ में विपणन सेवाकेन्द्र 1992.

बस्ती का आकार	बस्तियों की संख्या	स्थाई विपणन सेवा केन्द्र	पशु विपणन सेवा केन्द्र	साप्ताहिक विपणन सेवा केन्द्र
200 से कम	148	-	-	-
200 - 499	269	-	1 (1)	2 (2)
500 - 999	250	-	-	23(23)
1000 - 1999	154	4 (4)	2 (2)	84(81)
2000 - 4999	54	10(10)	2 (2)	53(42)
5000 से अधिक	3	2 (2)	-	6 (3)
योग ग्रामीण	869	16(16)	5 (5)	168(151)
योग नगरीय	6	6 (6)	6 (6)	12(6)
कुल योग	875	22(22)	11(11)	180(157)

में 84 साप्ताहिक विपणन केन्द्र हैं, 2000 से 4999 तक आवादी वाले 42 ग्रामों में 53 साप्ताहिक विपणन केन्द्र और 5000 से अधिक आवादी वाले 3 ग्रामों में 6 साप्ताहिक विपणन सेवाकेन्द्र हैं। नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार 12 नगरों में 12 विपणन केन्द्र हैं। इस प्रकार कुल 157 बस्तियों में 180 साप्ताहिक विपणन केन्द्र की सुविधा है जो सारणी 6.5 से स्पष्ट है। रा. नि. म. स्तर पर साप्ताहिक बाजारों का वितरण की दृष्टि से सबसे अधिक साप्ताहिक विपणन केन्द्र तरीचरकलाॅ रा. नि. म. में 18 साप्ताहिक विपणन केन्द्र बाजार की 14 बस्तियों में सुविधा है; जबकि सब से कम ओरछा व नैगुंवा रा. नि. म. में क्रमशः एक-एक ग्रामों में साप्ताहिक बाजारों की सुविधा है। इसी प्रकार निवाड़ी, सिमरा, पृथ्वीपुर, मोहनगढ़, लिधौरा, दिगौड़ा, जतारा, पलेरा, टीकमगढ़, समर्रा, बड़ागाँव, बल्देवगढ़, कुड़ीला व खरगापुर रा. नि. म. में क्रमशः 8 बाजार 9 बस्ती में, 5 बाजार 4 बस्ती में, 13 बाजार 5

सारणी 7.5 : जिला टीकमगढ़ में राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर साप्ताहिक विपणन सेवा केन्द्र

राजस्व निरीक्षक	ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र	सम्पूर्ण रा.नि.मण्डल
ओरछा	1 (1)	-	1 (1)
निवाड़ी	8 (7)	1 (1)	9 (8)
तरीचरकलाँ	18 (14)	-	18 (14)
नैगुँवा	1 (1)	-	1 (1)
सिमरा	5 (4)	-	5 (4)
पृथ्वीपुर	12 (12)	1 (1)	13 (13)
मोहनगढ़	16 (14)	-	16 (14)
लिधौरा	7 (7)	-	7 (7)
दिगौड़ा	14 (11)	-	14 (11)
जतारा	13 (13)	1 (1)	14 (14)
पलेरा	13 (13)	1 (1)	14 (14)
टीकमगढ़	6 (4)	7 (7)	13 (5)
समर्रा	6 (6)	-	6 (6)
बड़ागाँव	11 (10)	-	11 (10)
बल्देवगढ़	10 (10)	-	10 (10)
कुड़ीला	15 (11)	-	15 (11)
खरगापुर	12 (11)	1 (1)	13 (12)
योग जिला	**168 (151)**	**12 (6)**	**180 (157)**

बस्ती में, 6 विपणन केन्द्र 6 बस्ती में, 11 बजार 10 बस्ती में, 10 बजार 10 बस्ती में, 15 विपणन केन्द्र 14 बस्तियों में और 13 बाजार 12 बस्तियों में साप्ताहिक विपणन केन्द्र सुविधा उपलब्ध हैं। जो सारणी 7.5 में स्पष्ट है।

साप्ताहिक विपणन सेवाकेन्द्रों का विश्लेषण :

अध्ययन क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार 200 से कम आबादी वाले 148 ग्रामों में इन बाजारों की सुविधा नहीं जो पास के साप्ताहिक बाजारों पर निर्भर रहते हैं। 200 से 499 तक आबादी वाले 269 ग्रामों में से 2 ग्रामों में सप्ताह में एक दिन बाजार लगते हैं, 500 से 999 तक आबादी वाले 250 ग्रामों में से 25 ग्रामों में सप्ताह में एक दिन बाजार की सुविधा है। 1000 से 1999 तक आबादी वाले 154 ग्रामों में से 78 ग्रामों में सप्ताह में एक दिन व 3 ग्रामों में सप्ताह में 2 दिन इस बाजारों की सुधिा है, 2000 से 4999 तक आवादी वाले 45 ग्रामों में से 31 ग्रामों में एक दिन एवं 11 ग्रामों में सप्ताह में दो दिन यह सुविधा प्राप्त है।

सारणी क्रमांक 7.6 : जिला टीकमगढ़ में साप्ताहिक विपणन सेवा केन्द्र 1992

बस्ती का आकार	बस्ती की संख्या	सप्ताह में एक दिन लगने वाले	सप्ताह में दो दिन लगने वाले	सप्ताह में तीन या अधिक दिन लगने वाले
200 से कम	148	-	-	-
200 - 499	269	2 (2)	-	-
500 - 999	250	23(23)	-	-
1000 - 1999	154	78(78)	6 (3)	-
2000 - 4999	55	31(-3)	22(11)	-
5000 से अधिक	3	1 (1)	2 (1)	3 (1)
योग ग्रमीण	**869**	**135(135)**	**30(15)**	**3 (1)**
योग नगरीय	**6**	**5 (5)**	**-**	**7 (1)**
कुल योग	**875**	**140(140)**	**30(15)**	**10(2)**

स्रोत (1) प्राथमिक जनगणनासार एवं नगर व ग्राम निदर्शनी, जिला टीकमगढ़.
(2) स्वयं द्वारा सर्वेक्षित.

एवं 5000 से अधिक आवादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 3 ग्रामों में से एक ग्राम में सप्ताह में एक दिन, एक ग्राम में दो दिन तथा एक ग्राम में सप्ताह में तीन दिवस बाजार की सुविधा है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार एक दिन वाले 135 ग्राम दो दिन वाले 15 ग्राम व तीन दिन वाला एक ग्राम हैं। जैसे कि सारणी 7.6 से स्पष्ट होता है नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार कुल 12 नगरों में से 2 नगरों में सप्ताह में दो दिन व शेष नगरों में सप्ताह में सातों दिन बाजार की सुविधा उपलब्ध है। साप्ताहिक बाजारों की प्रमुख विशेषता यह है कि इन बाजारों में शब्जियाँ, फल और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मिश्रित बाजार होते हैं। इन बाजारों में जाने वाले विक्रेता शाम को अपनी दुकानें समेट कर घर चले जाते हैं।

विपणन सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम स्तर :

किसी तत्व के क्रम या स्तरों के निर्धारण को पदानुक्रम कहते हैं। जिला टीकमगढ़ में बाजारों के पदानुक्रम को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या एवं कार्यों के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण किया गया है। इन कार्यों में कृषिगत बाजार, पशुमेला या बाजार, वस्त्र, परचून, बर्तन आदि सम्मिलित हैं। बाजार में प्राप्त कार्य के स्तर निर्धारित किया गया है। सारणी 7.7 में जिला टीकमगढ़ के सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम स्तर दर्शाया गया है।

सारणी 7.7 में प्रथम स्तर के पदानुक्रम अन्तर्गत जिला मुख्यालय टीकमगढ़ को प्रमुख बाजार है। इस बाजार में सर्वाधिक बस्तुएं विक्रय की जाती है, यही कारण है कि सेवित क्षेत्र का प्रतिशत भी अधिक है ओर कुल सेवित जनसंख्या पर प्रतिशत भी अधिक है। मानचित्र 7.1 में बाजारों के इस क्रम को पूर्णतः सैवित क्षेत्र के रुप में दर्शाया गया है।

द्वितीय स्तर के पदानुक्रम के अन्तर्गत निवाड़ी, जतारा और पृथ्वीपुर तहसील के बाजार आते हैं जो क्षेत्र के उत्तरी एवं मध्य भाग में अपनी सेवायें प्रदान करते हैं। ये बाजार

सारणी 7.7 : सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम स्तर

क्रम सं.	पदानुक्रम स्तर	सेवा केन्द्रों के नाम	सेवित जन संख्या का प्रतिशत	सेवित क्षेत्रफल का प्रतिशत
1.	प्रथमस्तर	टीकमगढ़ (1)	30	34
2.	द्धितीय स्तर	निवाड़ी, जतारा, पृथ्वीपुर (3)	21	18
3.	तृतीय स्तर	टेहरका, बल्देवगढ़, पलेरा, लिधोरा, दिगोड़ा, बड़ागाँव, खारगापुर, चंदेरा मोहनगढ़, तरीचरकलाँ (10)	19	13
4.	चतुर्थ स्तर	प्रतापपुर, मिनौरा, कुण्डेश्वर, ओरछा, मवई-खास, भेलसी, कारी, कुड़ीला, अछरुमाता, सिमराखास, जेराखास , सिमराखुर्द, अस्तौनखास, जुहरगुंवाँ, ज्योरामोरा, मड़िया, मजना, बिरोरा, चौमो, लड़वारी, कछयाऊखारों, नैगुंवाँ, समर्राखास, पूर्वी सुनौनिया, तुना, दुमदुमा, गनैशगंज, जैरोन, अहार, बम्हौरी बराना, मुहारा, बम्हौरीकलाँ (32)	17	15
5.	पाँचवां स्तर	(106)	13	20
		151	100 %	100 %

स्रोत : प्राथमिक जनगणनासार, जिला टीकमगढ़ म.प्र. 1991.

21 प्रतिशत जनसंख्या तथा 18 प्रतिशत क्षेत्रफल को अपनी सवायें प्रदान करती हैं पृथ्वीपुर व निवाड़ी के दोनों बाजारों के अधिक निकट होने के कारण मानचित्र क्रमांक 7.1 में समुचित सेवित क्षेत्र के साथ साथ अतिव्यापक क्षेत्र के रुप में ही इस अध्ययन क्षेत्र के उत्तरवर्ती भाग

Tikamgarh District
Market Facilities
Nature of Markets
A
B
PCS
PSG
AS
Daily Market
Cattle Market
Weekly Market
Weekly
Twice in a week
Trice in a week
A - BELOW 200 PERSONS
B - 200 - 499 "
C - 500 - 999 "
D - 1000 - 1999 "
E - 2000 4999 PERSONS
F - 5000 ABOVE "
G - URBAN AREA "
PSG Size Group Of Population
PSC Percent Inhabited Settlement
C
Distribusion of Market Centres
D
Market Centres & Their Service Areas
Settlement
Weekly
Twice in a Week
Trice in a week
Daily
CM Cattle Market
Overlapped Areas
Well Served Areas
Unserved Areas
Market Centre
Existing
Proposed
Kilometers
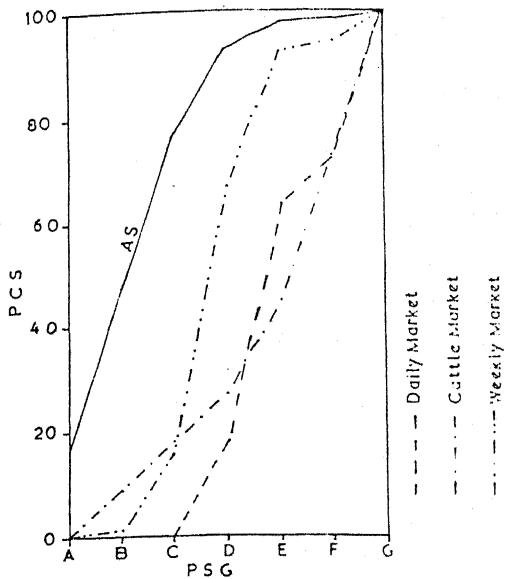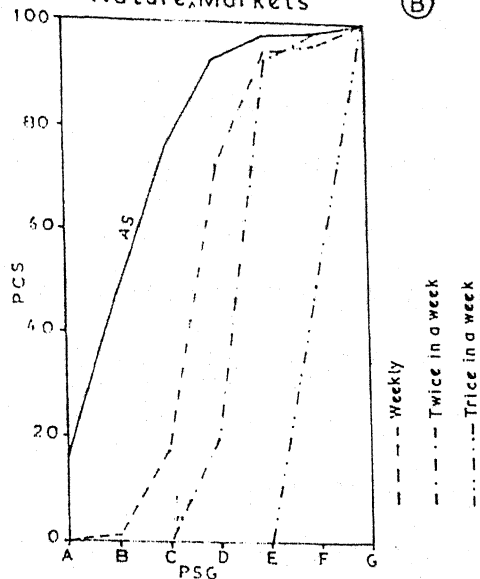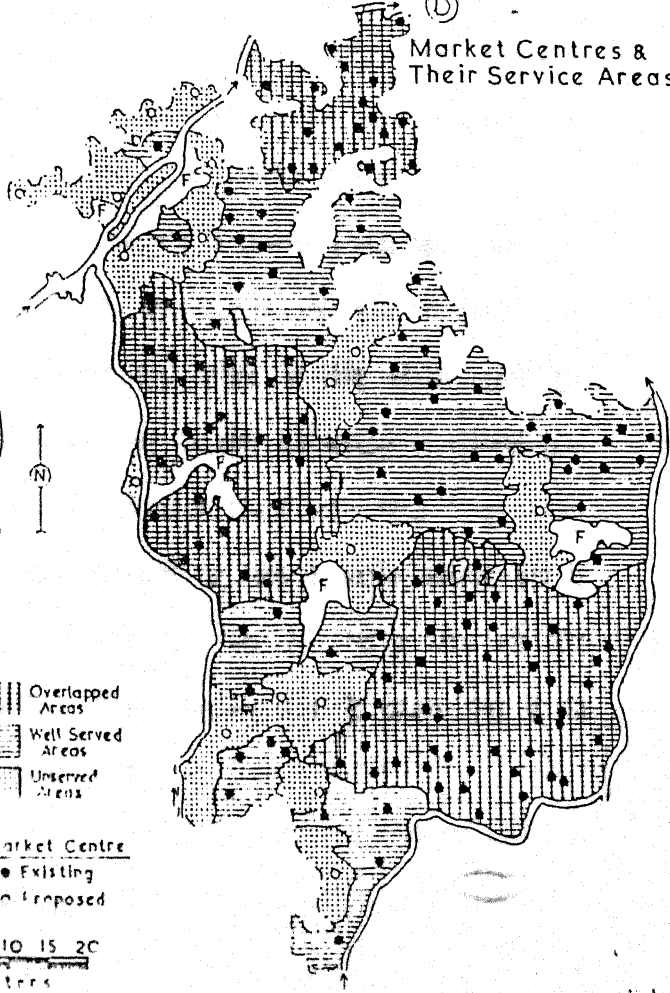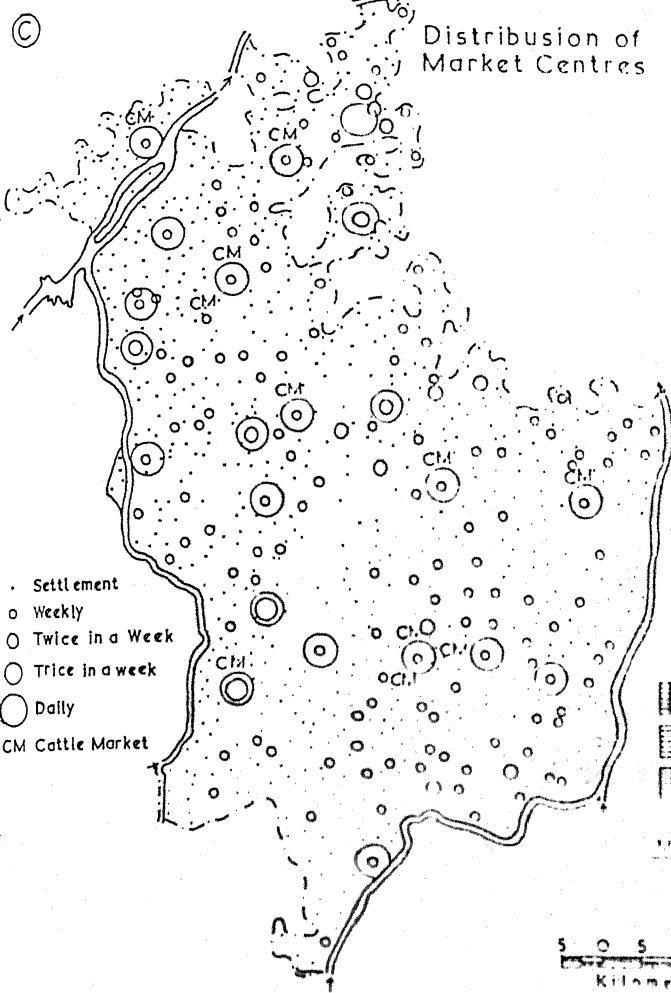
Fig 7.2

को रखा गया है। इस पदानुक्रम में कृषि उत्पाद, लघु एवं कुटीर उद्योग के उत्पाद तथा घरेलू हस्तशिल्प की वस्तुयें, विक्रय की जाती हैं।

तृतीय पदानुक्रम के स्तर में अध्ययन क्षेत्र के टेहरका, पलेरा, बल्देवगढ़, लिधौरा, दिगौडा, बड़ागाँव, खरगापुर, चंदेरा, मोहनगढ़ और तरीचर कलां सम्मिलित हैं। इन बाजारों द्वारा अध्ययन क्षेत्र की 19 प्रतिशत जनसंख्या एवं 13 प्रतिशत क्षेत्र की सेवायें की जाती हैं। इन बाजारों में कृषि उत्पाद, पशु उत्पाद, के साथ-साथ सौंदर्य के अलावा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार होता है। इन बाजारों का महत्व 1991 की जनगणना में नगरीय क्षेत्र के रुप में सम्मिलित किये जाने के कारण स्थानीय महत्व और बढ़ गया है।

चतुर्थ स्तर के पदानुक्रम के अन्तर्गत 32 केन्द्र ग्रामीण एवं कस्बा के रुप में अध्ययन क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये 17 प्रतिशत जनसंख्या को अपनी सेवायें प्रदान करते हैं। कृषि एवं घरेलू उत्पादों का व्यापार इन बाजारों में क्रय-विक्रय होता है। स्थानीय जनजाति, पिछड़ा एवं हरिजन वर्ग के लोग इन बाजारों का भरपूर उपयोग करते हैं। मछली, मिट्टी के बर्तन, सब्जियाँ, महुआ इन बाजारों में बड़ी मात्रा में बेची जाती हैं। स्थानीय कस्बों से मिट्टी का तेल, नमक, सिले बस्त्र तथा अन्य सूती कपड़े, सौदर्य प्रसाधन सामग्री आदि इन बाजारों में बेचे जाते हैं। बाजारों की व्यवस्था सरपंच या नगरपालिका के अन्तर्गत होती है।

अध्ययन क्षेत्र में अत्यंत्र छोटे बाजारों के रुप में सप्ताह में एक बार लगने वाले पाँचवे स्तर के 106 बाजार है, जिनमें कृषि एवं घरेलू उत्पाद बड़ी मात्रा मे विक्रय हेतु पहुँचते हैं। स्थानीय मजदूर, हरिजन, एवं आदिवासी एक सप्ताह के लिये भोजन सामग्री इन बाजारों से क्रय करते हैं। बड़े कृषक या सामान्य वर्ग के लोग इन बाजारों से सब्जियाँ क्रय करते हैं। ये बाजार अपने चारों और के ग्रामों को ही अपना सेवायें प्रदान करते हैं दूर-दराज में लगने के कारण सभी क्षेत्र को अपनी सेवायें प्रदान नहीं कर पाते हैं यद्यपि अध्ययन क्षेत्र वे सभी बाजारों को विद्युत एवं सड़क परिवहन से जोड़ दिया गया है, किन्तु आज भी और अधिक बाजारों की खुलने की आवश्यकता है। जिस्से मानचित्र 7.1 में दर्शाया गया है जो रिक्त क्षेत्र उचित सेवा के रुप में परिवर्तित हो सकते हैं।

-0-

REFERENCES

1. Asthana, V.K. (1975) : Study of Rural Settlements in Almora and its Environs : Paper presented at I.G.U. Symposium on Rural Settlements, Banaras Hindu University, Varanasi 1 - 6 Dec.

2. Alber, R., Adams,J.S. and Gould, P. (1971) : Spatial Organisation; The Geographers view of the World, Printice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jursey, USA, P: 180.

3. Bhat, L.S. and Sharma, A.N. (1974) : Functional Spatial Organisation of Human Settlement for Integrated Area Study, 13th Indian Economic Conference, Ahamdabad.

4. Singh, R.L. (1975) : Meaning, objectives and scope of Settlement Geography, in R.L. Singh and K.N. Singh (Eds.) Readings in Rural Settlement Geography, National Geographicl society of Inidia, Research Publications, No.14, Varanasi, PP:201-24.

5. Wakely, R.E. (1961): Types of Rural and Urban Community Centres in U.P. State, Newyork, I. Ithaca, Mioneograph Bulletin, No. 59, PP : 159-171.

6. Vining, R. (1955) : A Description of certain spatial Aspects of an Economic System, Economic Development and Cultural Change, 3, PP : 104-120.

7. Bhat, L.S. (1981) : Conceptual and Analytical Frame work for Rural Development in India Paper Presented to the National Symposium on Regional Planning and Rural Development G.B. Pant, Social Science Institute, Allahabad, U.P, P : 74.

8. Wanmali, S. (1972):(b) Zones of Influence of Central Villages in Miryalgnda Taluk: A Theortical Approach, Behavioral and Community Development, NICD, Hyderabad, 6. PP:1-10.

9. Raffiullah, S.M. (1965): A new Approach to Functional Classification of Towns, The Geographers No. 12, P : 132.

10. Reilly, W.J. (1929) : Methods of the study of Retail Relationship Res: Monograph No.4, Reaurau of Business Reserch Universtiy of Texas, USA, P:141.

11. Berry, B.J.L. (1967): Geography of Market Centres and Retail Distibution, Printice Hall, England, London, P: 301.

12. Mukerjee, A.B. (1969):Spacing of Rural Settlements

in Andhra Pradesh; A spatial Interpretation, Geographical outlook, 6, and spacing of Rural Settlement in Rajasthan (1970): Geographical View point I, P:104.

13. Mather, R.C. (1944) : A Linear Distance of Farm Population in the United States, AAAG, Vol. 34, P : 372.

14. Mukerjee, B. (1966) : The Community Development in India, Orient Longman, Calcutta, (W.B.) P : 402.

15. Maithini, B.P. (1986): Spatial Analysis in Micro-Level Planning, Omsons Publications, Gauhati, PP:231 - 260.

16. Smailes, A.E. (1944) : The Urban Hierarchy in England and Wales, Geography, 29 PP:41-51.

17. Demongeon, A. (1983) : Une carta de l' Habitat Annals de Geographic, 42 PP:225-32.

18. Houston, J.M. (1961) : A Social Geography of Europe, London PP: 301-10.

19. Singh, O.P. and Pandey D.C. (1986) : Development Planning: Theory and Practice Gyanodaya Publications, Nainital P : 171.

20. Clark P.J. and F.C. Evans (1954) : Distance to

Nearest Neighbour. As a measure of Spatial Relationships in Population, Ecology, 35 - PP : 445 - 453.

21. Dixit, R.S. (1983) : Role of Markets in Regional Development and their Spatial Planning in the Metropolition Region of Kanpur, (U.P.) P : 172.

----0----

अध्याय आठ

सेवाकेन्द्रों की आकारिकी

- प्रतिचयन
- कार्यात्मक आकारिकी का उद्‌भव
- आन्तरिक संरचना
- मार्ग प्रतिरुप
- कार्यात्मक सीमायें
- आकार विश्लेषण
- वर्गीय स्थानिक मॉडल
- मॉडलों की प्रयोजनीयता
- सन्दर्भित ग्रन्थों की सूची

सेवा केन्द्रों की आकारिकी : (MORPHOLOGY OF SERVICE CENTRES):

भूगोल में केन्द्रीयता का विशेष महत्व है। किसी केन्द्र में वितरित कार्य अपने चारों ओर कितनी सेवाओं को प्रस्तुत करते हैं तथा सेवाओं के प्रस्तुतीकरण में उनकी केन्द्रीयता कितनी सार्थक है, इस बात का अध्ययन किया जाता है।[1] केन्द्रीय स्थानों के स्थानिक विश्लेषण में केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति, विस्तार व सीमायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस आधार पर सेवाकेन्द्रों का वितरण प्रतिरुप एवं केन्द्रों की वर्तमान उपलब्धता और उनका वितरण प्रतिरुप तथा आपसी सहसम्बन्ध कैसा है, इसे प्रस्तुत करता है।[2]

सेवा केन्द्रों का उद्‌भव एवं आकारिकी :

अधिवास भू-सतह पर मानव बसाव की व्यवस्था को दर्शाते हैं, ये मानव बसाव एक या अधिक घरों एवं भवनों के पाये जाने का कहते हैं।[3] अधिवास भूगोल के अन्तर्गत अधिवास मानव निवास के लिये ही नहीं, बल्कि मानव के कार्यस्थल, भण्डार, व्यापार एवं वाणिज्य इत्यादि से सम्बन्धित होता है। किसी क्षेत्र के अधिवासों का निर्माण स्थानीय भौतिक वातावरण के तत्व की प्राप्ति और वहाँ की मानव क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। सेवित क्षेत्रों का आकार, घनत्व व दूरियाँ सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के द्वारा निर्धारित होती है।[4] इस प्रकार सेवाकेन्द्र सांस्कृतिक वातावरण की विभिन्न क्रियाओं जैसे भूमि उपयोग और जनसंख्या में निकटतक सम्बन्ध को स्थापित करता है, किसी क्षेत्र के सेवाकेन्द्र के निर्धारण में स्थानिक क्रियाऐं आधार भूत तत्व होती है।[5] मानव की गति और पदार्थ अधिवास की क्षेत्रीयता को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यात्मक विश्लेषण में सेवाकेन्द्रों को सदैव ही स्थान दिया जाता है।

सेवाकेन्द्रों का उद्‌भव एवं वृद्धि :

मनुष्य एक गतिशील भौगोलिक कारक है जो प्राकृतिक भूदृश्य को परिवर्तित करने के प्रमुख साधन है। सांस्कृतिक भूदृष्य मानवीय क्रियाओं और तत्वों, वर्तमान और सांस्कृतिक क्रियाकलापों जिनमें अधिवास और उनके अन्तर्गत की जा रही विभिन्न मानवीय क्रीयाऐं मुख्य रुप से भोजन एवं सैन्य के साथ जिला टीकमगढ़ में पशु आवास भी सम्मिलित हैं। अध्ययन क्षेत्र में सेवा क्षेत्रों की उद्‌भव की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है, वैदिककाल में चैदिदेश के अन्तर्गत वनों से घिरे हुऐ मानव के पूर्वज निवास किया करते थे, इसी प्रकार दशांर्ण देश के अन्तर्गत ग्रामों का क्रम एवं सेवाकेन्द्र का समूल विकसित होकर पाया जाता था। ईसा पूर्वकाल में सेवित क्षेत्र का वितरण विरल होते हुए भी ओरछा राज्य के अन्तर्गत स्थित पाया जाता था, इन सेवा स्थलों पर जो तत्कालीन सेवा प्रक्रिया को दर्शाते हैं। मुस्लिम एवं ब्रिटिशकाल में सेवा स्थलों में आवश्यक परिवर्तित हुऐ, किन्तु यह परिवर्तन तत्कालीन सेवाओं के विकास की प्रक्रिया को समग्र रुप से प्रस्तुत करता, हैं।

सेवाकेन्द्रों का स्थानिक वितरण :

अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का वितरण मानचित्र 8.1 स्थल प्रतिरुप के रुप में दर्शाया गया है, यह जानने के लिए कि यह वितरण समान है अथवा नहीं कई वर्ग वितरण परीक्षण के निम्नलिखित सूत्र के उपयोग करने पर ज्ञात किया जा सकता हैं।[6]

$$x^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

सारणी 8.1 : जिला टीकमगढ़ में सेवाकेन्द्रों की काई वर्ग वितरण परीक्षण

राजस्व निरीक्षक मण्डल	O_i	E_i	O-E	$(O-E)^2$	$\frac{(O-E)^2}{E}$
ओरछा	40	44	- 4	16	0.36
निवाड़ी	40	42	- 2	4	0.10
तरीचरकलाँ	53	57	- 4	16	0.28
नैगुँवा	44	49	- 5	25	0.51
सिमरा	30	24	+ 6	36	1.50
पृथ्वीपुर	54	58	- 4	16	0.28
मोहनगढ़	76	59	+17	289	4.90
लिधौरा	56	67	+11	121	1.81
दिगौड़ा	44	52	- 8	64	1.23
जतारा	67	70	- 3	9	0.13
पलेरा	58	65	- 7	49	0.75
टीकमगढ़	60	39	+21	441	11.31
समर्रा	50	53	- 3	9	0.17
बड़ागाँव	49	53	- 4	16	0.30
बल्देवगढ़	55	57	- 2	4	0.07
कुड़ीला	48	50	- 2	4	0.08
खरगापुर	51	36	+15	225	6.25
	875	**875**	**-**	**1344**	**= 30.03**

स्रोत : प्राथमिक जनगणना सार एवं ग्राम व नगर दि निदर्शनी जिला टीकमगढ़ 1991

जहाँ = आंकलित मूल्य/सेवितक्षेत्रों की संख्या.

= अनुमानित मूल्य, सेवितक्षेत्रों की संख्या.

वितरण परीक्षण में प्रत्येक रा. नि. मं. के सेवाकेन्द्रों का किया गया जिसे सारणी 8.1 में दर्शाया गया है। 'नल' अवधारणा के अन्तर्गत सेवा केन्द्रों की संख्या प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मण्डल में अपने क्षेत्रफल के अनुपात में समान रुप से वितरित है, स्वतंत्रता का वर्ग (+1) वर्तमान अध्ययन में 6-1= 5 है। संयुक्त मूल्य 30.03 है जो सारणी कृत मूल्य से अधिक है इसलिए ये निश्चित है कि अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का वितरण एक समान नहीं है।

सेवाकेन्द्रों के वितरण को अनेक प्राकृतिक व मानवीय कारक प्रभावित करते हैं। इनमें भौतिक कारकों के अन्तर्गत धरातल, अपवाह तंत्र, कुल क्षेत्रफल आदि प्रमुख हैं, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि एवं आधुनिक अद्य:संरचनात्मक संगठन सेवाओं के वितरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।[7]

ख) सेवाकेन्द्रों की आंतरिक संरचना :

अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्र ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के हैं, यहाँ 369 ग्रामीण एवं 12 नगरीय सेवाकेन्द्र पाये जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि अध्ययन क्षेत्र का वातावरण पूरी तरह ग्रामीण है। अत: अध्ययन में ग्रामीण सेवाकेन्द्रों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।

सेवाकेन्द्रों के विश्लेषण में वहाँ के भौतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वातावरणों के व्यवसायिक संगठन को जो विशिष्टता प्रदान करते हैं, परिचय आवश्यक है। अधिवास का प्रकार एक सीमा में गृह के विस्तार पर निर्भर है। इसी विस्तार और प्रकार के आधार पर प्रदेश को भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों द्वारा आकार तथा स्वरुप के रुप में विभक्त किया जाता है। अर्न्तक्षेत्रीयता के द्वारा सेवाकेन्द्रों के प्रमुख प्रकारों को जाना जाता है।

सघन सेवा केन्द्र :

अध्ययन क्षेत्र में सघन सेवा स्थल सिमरा, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, बल्देवगढ़ एवं

लिधोरा राजस्व निरीक्षक मण्डलों में अधिक सकेन्द्रित पाये जाते हैं। इन रा. नि. म. में सघन सेवा स्थल होने के प्रमुख कारण-सघन कृषि, सिंचाई के साधनों की पर्याप्तता, समतल भूमि, संयुक्त परिवार पद्धति आदि का विकासित होना है। प्राचीन भारतीय परम्परायें और रीतियाँ सेवाकेन्द्रों की सघनता के लिये भी उत्तरदायी हैं।[8] प्रारम्भ काल से भी अधिक उपजाऊ भू-भागों पर प्राचीन आकार और स्वरुप के सघन सेवाकेन्द्र पाये जाते हैं।[7] और जहाँ पर कृषि व्यवसायिक फसल के रुप में होती है वहाँ आर्थिक समुन्नति अधिक होने के वे क्षेत्र धीरे-धीरे नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र सामाजिक संगठन, अधिक उत्पादन, सुरक्षा इत्यादि सघन सेवाकेन्द्र को निर्मित करने के प्रमुख कारक हैं। ग्रामीण अथवा नगरीय सेवाकेन्द्र पूर्णतः इन्हीं के चारों ओर सम्पूर्ण भारत की तरह अध्ययन क्षेत्र में भी विकसित हुए हैं।

उप सघन सेवा केन्द्र :

उप सघन सेवाकेन्द्र का विकास एक सांस्कृतिक केन्द्रीयता के अधिक निकट हुआ है जहाँ नाभिक अवस्था के चारों ओर झुग्गी-झोपड़ियाँ, नवीन निर्मित कार्य क्षेत्र जैसे सड़क अथवा धार्मिक केन्द्र पाये जाते हैं। ये झोपड़ियाँ गाँव की जनसंख्या को कार्यस्थल विकसित हो जाने के कारण आकर्षित करती है। इसी प्रकार के सेवाकेन्द्र अध्ययन क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी भाग के तरीचरकलां, निवाड़ी, पलेरा रा. नि. म. में पाये जाते हैं। इनमें सर्वाधिक सड़कों के किनारे हैं और ये झोपड़ियाँ मुख्यतः गरीब व्यक्तियों और उनके परिवारों की होती है, जिनके पास कृषि के लिये या तो भूमि नहीं है अथवा बहुत कम है। इनका प्रमुख उद्यम इन सड़कों के किनारे छोटी-छोटी दुकानें हैं। साथ ही कृषि मजदूर, मजदूरी का काम भी इन उप सघन सेवाकेन्द्रों में करते हैं।

आश्रित ग्राम या सेवाहीन स्थल :

अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास नदी, नालों के किनारों पर अधिक पाये जाते हैं। धसान, बेतवा और जामनी नदी के किनारे पर 500 से कम जनसंख्या वाले लगभग

सभी सेवाहीन क्षेत्र इसके अन्दर सम्मिलित हैं। इस प्रकार के आश्रित क्षेत्र ओरछा, नैगुंवा, सिमरा, मोहनगढ़, टीकमगढ़ बड़ागाँव, बल्देवगढ़, खरगापुर, पलेरा और कुड़ीला रा. नि. मण्डलों में अधिकांश छोटे या गाँव या पुरवा दिखाई देते हैं। इन सेवाकेन्द्रों में सर्वप्रथम असमतल भूमि के कारण सिंचाई के साधनों का विकास कम से कम हुआ है। अतः कृषि की प्राचीन पद्धति विकसित पायी जाती है। आर्थिक विकास नगण्य होने के कारण यहाँ के निवासियों को प्रमुख कार्य पशु-पालन और निकटवर्ती गाँव में जाकर मजदूरी करना होता है। परिवहन के साधनों की कमी छोटे गाँवों को या विरल सेवाओं को निर्मित करते हैं। आय के स्रोतों के अभाव के कारण गाँव में वनों से प्राप्त लकड़ी द्वारा झुग्गी-झोपड़ियाँ पायी जाती हैं।

सेवाकेन्द्रों का वितरण प्रतिरुप :

किसी सेवाकेन्द्र का विस्तार या प्रसार वहाँ के निवास स्थान और आधारभूत संरचना से होता है। स्थान की प्रकृति, किसी बस्ती को विशेष दशा में आकर्षण और अनाकर्षण बलों के द्वारा विकसित करने को प्रस्तुत करती है। वास्तव में सेवाकेन्द्र का बाह्य क्षेत्र सड़क, रास्ता तथा निवास स्थान की प्रकृति पर निर्भर करता हैं।[9] सघन और उप सघन प्रकार के सेवाकेन्द्रों में इस प्रकार के प्रतिरुप देखे जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में रेखाकार, आयताकार, वृत्ताकार, एल और टी आकृति में अधिकांश पाये जाते हैं। सिंह[10] ने अपने वर्गीकरण में विभिन्न सेवा स्थलों के प्रतिरुपों की विभिन्न क्रियाओं को विश्लेषित किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ के सेवाकेन्द्रों प्रतिरुपों के विवरण को उच्चावच, जलआपूर्ति, अपवाह तंत्र, मिट्टी की उर्वरता ने क्षेत्रीय वितरण का प्रभावित किया है। परिवहन तथा दूर संचार सुविधाओं, भूमि उपयोग, जनसंख्या का व्यवसायिक प्रतिरुप, सिंचाई की पद्धति आदि कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कारक जो सेवाकेन्द्रों के वितरण और घनत्व को निर्मित करने के लिये प्रभावशाली हैं। मानचित्र 8.1 में अध्ययन क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण सड़क सेवाकेन्द्र प्रतिरुप दर्शाये गये हैं।

आयताकार प्रतिरुप :

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश गाँवों में आयताकार स्वरुप विकसित हुए हैं। वीघा पद्धति के अनुसार सभी गाँव आयताकार स्वरुप में पाये जाते हैं। खेत की इकाईयों की गणना एवं विभाजन द्वारा सेवाकेन्द्रों का नया स्वरुप प्राप्त हुआ है। इसकी तुलना जापान की जौरी, चीन की हानदेन तथा इटली की जुगेरियन पद्धति से की जा सकती हैं। जीरोन, तरीचरकलाँ, मुहारा, ज्योरामौरा, मवई, बाघाट, धामना, पुरैनिया, बघौड़ा, अन्तोरा, टेहरका आदि गाँवों में इस प्रकार के प्रतिरुप देखे जा सकते हैं। मानचित्र 8.1 से स्पष्ट है कि ये सभी गाँव ग्रामीण तालाबों एवं मंदिर के चारों ओर विकसित हैं।

रेखीय प्रतिरुप :

सीधी रेखा में ग्रामीण सेवाकेन्द्रों का विकास रेखीय प्रतिरुप के अन्तर्गत आता है। इन प्रतिरुपों के विकास में स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये प्रतिरुप परिवहन मार्गों या नदी के किनारों पर विकसित होते हैं। रेखीय गाँव ओरछा, कुण्डेश्वर, राजापुर, लड़वारी, टीकमगढ़-झाँसी, मार्ग पर बल्देवगढ़, पठा, समर्रा, लिधौरा, नाका खिरिया आदि गाँव प्रतिरुप में पाये जाते हैं।

दुहरे सेवा क्षेत्र :

दो गाँव का एक समूह इस प्रतिरुप के अन्तर्गत आता है, जिसमें दो अलग-अलग कार्य क्षेत्रों पर सेवाक्षेत्रों का विकास विकसित होता गया हैं। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार के कई गाँव हैं जो संयुक्त अवस्था में पाये जाते हैं, इसके अन्तर्गत एक ही गाँव का वह भाग भी सम्मिलित है जो अलग नाम से जाना जाता है, किन्तु इसकी गणना एक ही गाँव मं होती है।

जैसे- हीरानगर-बावरी, बड़ागाँव खुर्द, फुटेरी, माडूमर-पपौरा, जमड़ार-शिवपुरी आदि है। ये इस प्रकार के सेवाक्षेत्र जो कि निकटतम गाँव के निवासी सड़क के दूसरी ओर, नदी या नहर के उस पार जाकर बस गये हैं, इनके विकास का प्रमुख कारण बाजार के क्षेत्रों का आकर्षण भी हैं।

एल-आकृति प्रतिरुप :

एल आकृति के सेवाक्षेत्र जिन्हें दो आयताकार अथवा वर्गाकार प्रतिरुप आपस में संयुक्त हुए हैं। इस प्रकार अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार की संरचना ग्रामीण सड़कों के किनारों अन्य किसी कार्य की प्रधानता के कारण ग्रामीण सेवित क्षेत्र उस ओर निर्मित होने लगते हैं तो इस प्रकार की एल आकृति उभरकर आती है। जैसे-सुन्दपुर, नंदनवारा, मालपीथा, संगरवारा, खरगापुरा, विजरोन, सोरका, पोहा खास आदि हैं।

टी आकृति के प्रतिरुप :

टी आकृति के सेवा स्थलों का निर्माण भी एल आकृति के सेवाकेन्द्रों के समान होता हैं। जब ग्रामीण सेवाकेन्द्र बैलगाड़ी के मार्ग में विकसित होकर प्रमुख सड़क से जुड़ जाता है तो सड़क के दोनों ओर शीघ्रता से सेवित क्षेत्र टी आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। इन प्रतिरुपों के कार्य मुख्य सड़क पर प्राप्त आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार प्रतिरुप ग्रामीण क्षेत्रों में चंदेरा, लिधोरा, गोर, अस्तौन, बुड़ेरा, सतगुँवा, नैगुंवा सेंदरी, कुलुवा खास आदि तथा नगरीय सेवाकेन्द्रों में पृथ्वीपुर, पलेरा एवं खरगापुर हैं।

वृत्ताकार प्रतिरुप :

किसी बाजार केन्द्र, धर्मिक स्थल, सामाजिक संस्था चौपाल आदि के चारों ओर वृत्ताकार प्रतिरुप का जन्म होता है। प्राचीन सेवाकेन्द्रों में इस प्रकार के प्रतिरुप पाये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण सेवाकेन्द्रों में हीरानगर, अचर्रा, वैरवारा, अछरुमाता, चचावली, निमचोनी, अस्तारी आदि ग्रामों में एवं नगरीय सेवाकेन्द्र में टीकमगढ़ जतारा और निवाड़ी नगरों में इस प्रकार के प्रतिरुप पाये जाते हैं।

SITES OF SERVICE CENTRES
N
Chandra
Kachora
Machi
Marhia
Barana
Dulupra
Baragaon
Jatara
Tikamgarh
Ghura
Radha-pura
Mazra Khairar
Kundusawar
Dargan Bhata
Dargan Kala
Dargain Khurd
Narayanpur
Khushipura
Khargapur
Gallwara
Jolondar
Bachhora
Matol
Settlements
Contours
Tanks
Streams
Metalled Road
Unmetalled
Cart Track
1000 500 0 1
Metres
Kilometres
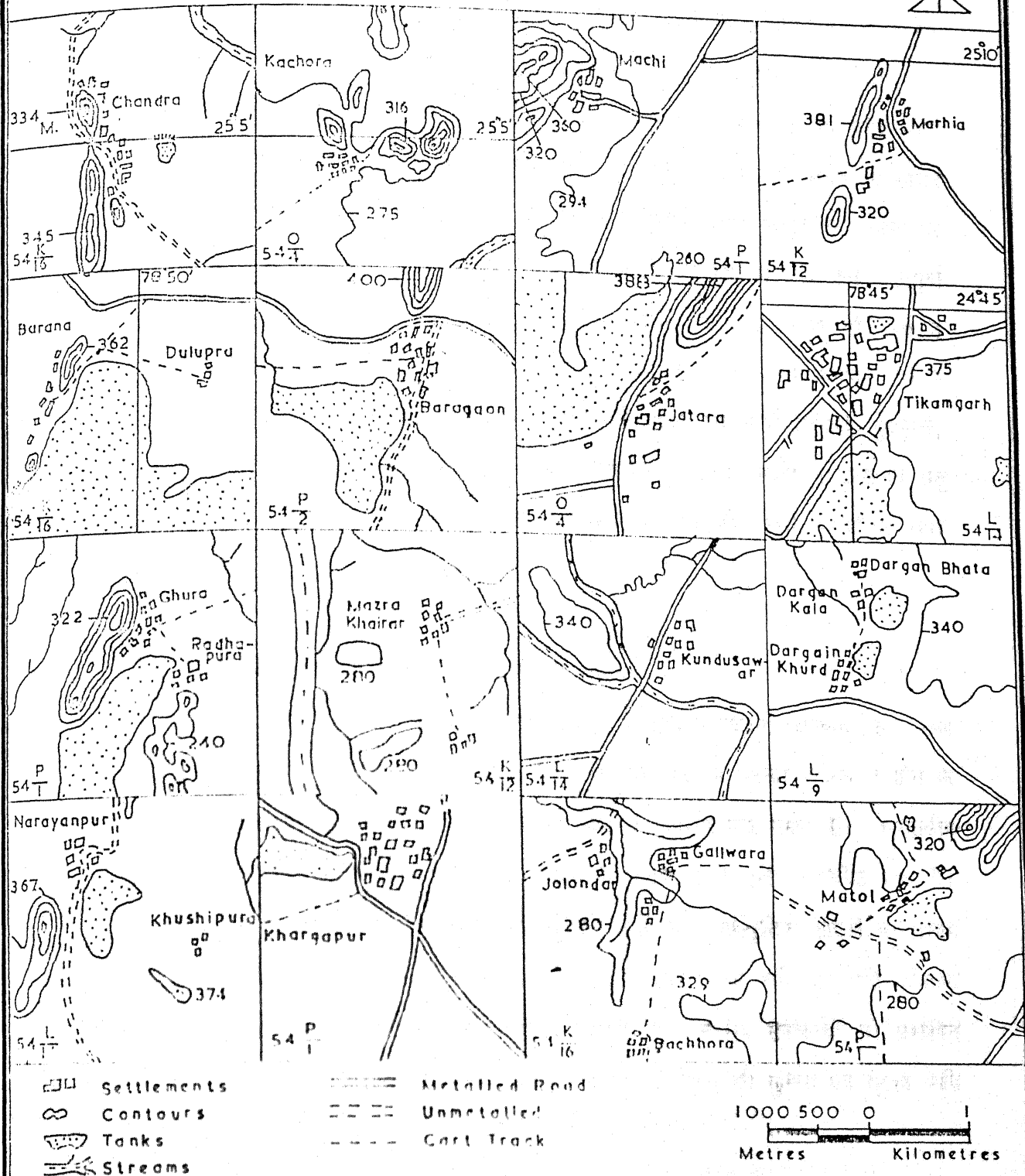
Fig 8.1

सेवाहीन बिखरी झोपड़ियाँ :

अध्ययन क्षेत्र में कृषि की सुरक्षा, आवश्यक सामग्री के उपयोग एवं रख-रखाव की दृष्टि से प्रत्येक ग्रामों के खेतों मे बिखरी हुई झोपड़ियाँ पायीं जाती हैं। यद्यपि सेवा केन्द्रों के अन्तर्गत इसे सम्मिलित नहीं किया गया है, किन्तु मानव बसाव यहाँ पर रबी/खरीफ अथवा जायद फसल के समय अवश्य ही होता है। विगत एक दशक से सिंचाई के साधन (कुंओं द्वारा) विकसित होने के कारण यहाँ गाँव के बाहर कृषक, कृषि मजदूर, तथा खानों पर काम करने वाले मजदूर यहाँ निवास करते हैं। कृषि में क्रियाशीलता बढ़ने के कारण सम्पूर्ण परिवार यहाँ आ कर निवास करने लगता है। और मिश्रित ग्राम का विकास हो जाता है धीरे-धीरे कृषि मजदूर भी आकर बस जाते हैं। इस तरह के मानव बसाव अध्ययन क्षेत्र में बिंधिया, कारी (बजरुवा), ईसोन, पनयारा खेरा, आदि कृषि कार्य हेतु, कारी (जंगल), गुड़ापाली,, खेरा, मड़खेरा, राजापुर, लंड़वारी, प्रतापपुरा, लिधोरा, जिजौरा, कुम्हार्रा, बसोवा में उत्खनन हेतु अधिवास पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश ग्रामों के चारों ओर बिखरे 'पुरवा' या 'खेरा' भी पाये जाते हैं।

सेवा केन्द्रों की आकारिकी को प्रभावित करने वाले कारक :

सेवाकेन्द्रों के प्रतिरुप को जलवायु, धरातल, जलपूर्ति, अपवाह तंत्र तथा सांस्कृतिक कारक पूरी तरह प्रभावित करते हैं। अध्ययन क्षेत्र का विस्तार अधिक न होने के कारण तापक्रम व सूर्य प्रकश का प्रभाव संपूर्ण जिले में लगभग एक समान हैं। धरातलीय बनावट की दृष्टि से सघन एवं विरल दो प्रकार के सेवाकेन्द्रों के प्रतिरुप निर्मित होते हैं। जलापूर्ति और अपवाह तंत्र द्वारा सेवाकेन्द्रों की सघनता होती हैं। सांस्कुतिक कारकों का प्रभाव भी किसी सीमा तक विभिन्नताओं को प्रदर्शित करता हैं, इसमें भाषा, धर्म और जाति अधिवास के प्रतिरुप को निर्मित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नगरीय सेवाकेन्द्रों को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रशासनिक केन्द्र, यातायात के साधन, बाजार की सुविधा एवं सुरक्षा आदि तत्व प्रभावित करते हैं।

1. आवास :

अधिवासों का मूल स्वरुप आवास होता है, उनकी प्रकृति, निर्माण की प्रक्रिया, जाति वर्ग और धर्म के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती हैं।[8] ग्रामीण आवास स्थल वातावरण के कारकों के साथ निर्धारित होता है। इनमें आवास के निर्माण का पदार्थ स्थानीय सामग्री द्वारा निर्धारित होता है। मकानों के प्रकार बदल रहे हैं, क्योंकि भवन निर्माण में नवीन तकनीकी प्रवेश कर चुकी है। इसलिये व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत में परिवर्तन आया है, जिससे अध्ययन क्षेत्र अछूता नहीं हैं।[10]

2. निर्माण सामग्री :

अध्ययन क्षेत्र में भवन निर्माण का पदार्थ भौतिक पर्यावरण से निर्मित होता है। अध्ययन क्षेत्र में मिट्टी के द्वारा ईट, गारा, खपरैल आदि तैयार होते हैं। यद्यपि पक्के मकानों का प्रचलन शुरु हुआ है, किन्तु पक्के मकानों को यहाँ के लोग पहले ईटं, गारा से तैयार कराते हैं अर उसकी छाप सीमेंट अथवा चूने द्वारा निर्मित करवाते हैं। छतों के निर्माण में भौतिक पर्यावरण प्रभावी है इसमें कंकरीट रेत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अध्ययन क्षेत्र में कंकरीट व रेत अल्प मात्रा में उपलब्ध होने से भवनों का निर्माण मिट्टी के द्वारा निर्मित 'पक्की ईट' (जिसे स्थानीय भाषा में ' गुम्मा ' कहते हैं) के द्वारा निर्मित होती है।

3. सांस्कृतिक पर्यावरण :

ग्रामीण आवास स्थल के निर्माण में स्थिति और स्थल योजना सांस्कृतिक कारकों जैसे- व्यवसायिक, सामाजिक और धार्मिक रीत-रिवाजों द्वारा प्रभावी होते हैं। एक क्षेत्र में एक ही समाज, धर्म या जाति के लोगों द्वारा एक जैसी सांस्कृतिक अवस्था होने के कारण एक समान आवासीय क्षेत्र का विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का परिवेश प्रायः अध्ययन क्षेत्र में दिखाई देता है। नगरीय सेवाकेन्द्रों के प्रशासनिक, औद्योगिक, बाजार तथा सेवा सुविधाओं द्वारा सांस्कृतिक पर्यावरण सेवाकेन्द्रों को मिश्रित स्वरुप प्रदान करते हैं।

4. सेवाकेन्द्रों की आंतरिक संरचना :

नगरों का विकास शनैं-शनैं ग्रामीण क्षेत्रों पर होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में विकसित करने के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य नगरीय क्रियाओं को स्थानीयकरण है अर्थात् ग्रामीण भू-भाग पर कहाँ एवं कैसे सड़कों और गलियों का प्रतिरुप स्कूल, व्यापारिक प्रतिष्ठान आवासीय क्षेत्र (अच्छे और मध्यम लोगों के लिए) औद्योगिक क्षेत्र मनोरंजन के साधन गाड़ियों के खड़ा करने का स्थान तथा सीवेलाइन का विस्तार किया जाये उदाहरण स्वरुप यदि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है तो सैंकड़ों एकड़ भूमि का विकास करना होगा जहाँ रेल्वे और सड़कों की सुविधा हो, तथा कारखानों के धुओं से नगर प्रदूषण न हो सके। ऐसी स्थिति का चुनाव किया जाता है सामान्यतः नियोजकों के अनुसार न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि मनोरंजन साधनों (पार्क, चिड़िया घर, गोल्फ) के अन्तर्गत रखना चाहिये।[11] अध्ययन क्षेत्र के नगरों में भी व नवीन क्षेत्रों का विकास हो रहा है जिसमें टीकमगढ़, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, जतारा आदि प्रमुख हैं।

4. नियोजन प्रणाली :

नियोजकों को नगरों में पूर्व निर्मित क्षेत्रों एवं वहाँ की समस्याओं पर गम्भीरता से दृष्टिपात करना पड़ता है। क्योंकि अधिकांश नगर बिना किसी योजना के नैसर्गिक विकास के कारण अति जनसंख्या, गन्दे तथा अस्वास्थ्यकर हो जाते हैं। नगर का पुराना भाग शैंनः शैंनः अति सघन हो जाता है जैसे कि टीकमगढ़ नगर के पुरानी टेहरी, नरइया मुहल्ले की संकीर्ण गलियों के मकान शुद्ध वायु, धूप एवं प्रकाश से वंचित हो गये हैं इसलिये नगर के प्राचीनतम भाग का नियोजन किया जाता है। नगरीय संरक्षण के अन्तर्गत भूमि उपयोग में किया किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता हे क्षेत्र की सफाई अभियान स्वस्थ्य संबंधी सेवा के प्रसार हेतु नियम बनाकर आवासों भण्डार गृहों एवं अन्य भवनों के उचित रख रखाव पर ध्यान दिया जाता है जिससे सार्वजनिक सुविधाओं का संरक्षण किया जा सके। नगरीय

पुर्नविकास के अन्तर्गत भूमि उपयोग में पूर्ण परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। पुराने ढांचों को गिराकर उनकी जनसंख्या एवं आवश्यक सुविधाओं की दृष्टि से डिज़ाइन बनाकर नव निर्माण किया जाता हैं।[12]

नगरीय नवीनीकरण की आवश्यकता उन भागों में होती है, जिनकी स्थिति अपेक्षाकृत दयनीय है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी भूमि उपयोग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जाता है। परन्तु कुछ पुराने जर्जर भवनों को जिनके द्वारा जन-धन की क्षति की आशंका हो, गिराकर बनाया जाता है। उसमें गन्दी बस्तियों को हटाकर उसी स्थान पर नये भवन निर्माण भी सम्मिलित है। जैसे- टीकमगढ़ नगर की कई बस्तियों को फिर से नया रुप दिया गया है।

नगरीय भूमि उपयोग एवं सेवायें :

पहले नगरों के विकास की गति अत्यंत मंद थी तथा उनका आकार भी छोटा था। परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के बाद नगरों के आकार में तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है तथा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगरीय विस्तार तेजी से हो रहा है। परिणामस्वरुप नगरीय भूमि उपयोग की वर्तमान समस्या सबसे विकट हो गयी है। नगरीय भूमि से तात्पर्य नगर की उस भूमि से है जिस पर आवास उद्योग वाणिज्य, फुटकर एवं थोक व्यापार, संस्थाएं, मनोरंजन के साधन तथा अन्य कई प्रकार की सार्वजनिक सेवायें और सुविधायें फैली होती हैं।

नगरीय भूमि उपयोग की सैद्धांतिक और क्रमबद्ध व्याख्या बर्गीस, हायट, मैकेंजी, हैरिस, उलमैन तथा फिरेयु के शोध पत्रों से स्पष्ट हो जाती है। वर्गीस ने नगरीय भूमि का सकेन्द्रीय कटिबंध के रुप में हायट ने सेक्टर के रुप में, तथा हेरिस और उलमैन ने बहुकेन्द्र के रुप में देता है। फिरेय ने नगरीय भूमि व्यवस्था को नगर में रहने वाले लोगों की रुढ़ियों एवं प्रवृत्तियों के रुप में निम्नानुसार वर्णन किया है।

Model For
Spatial Planning
Man
Social Demands
Economic Demands
Plans
Resources
Potentility
Technology
Transport System
Infrastructural co-ordinates
Primary
Secondary
Tertiary
Social Values And Institutions
Spatial Functional Organisations
Settlement System
Functional System
Esoteric Box
Modified After R. L. Singh Or, Al 1978
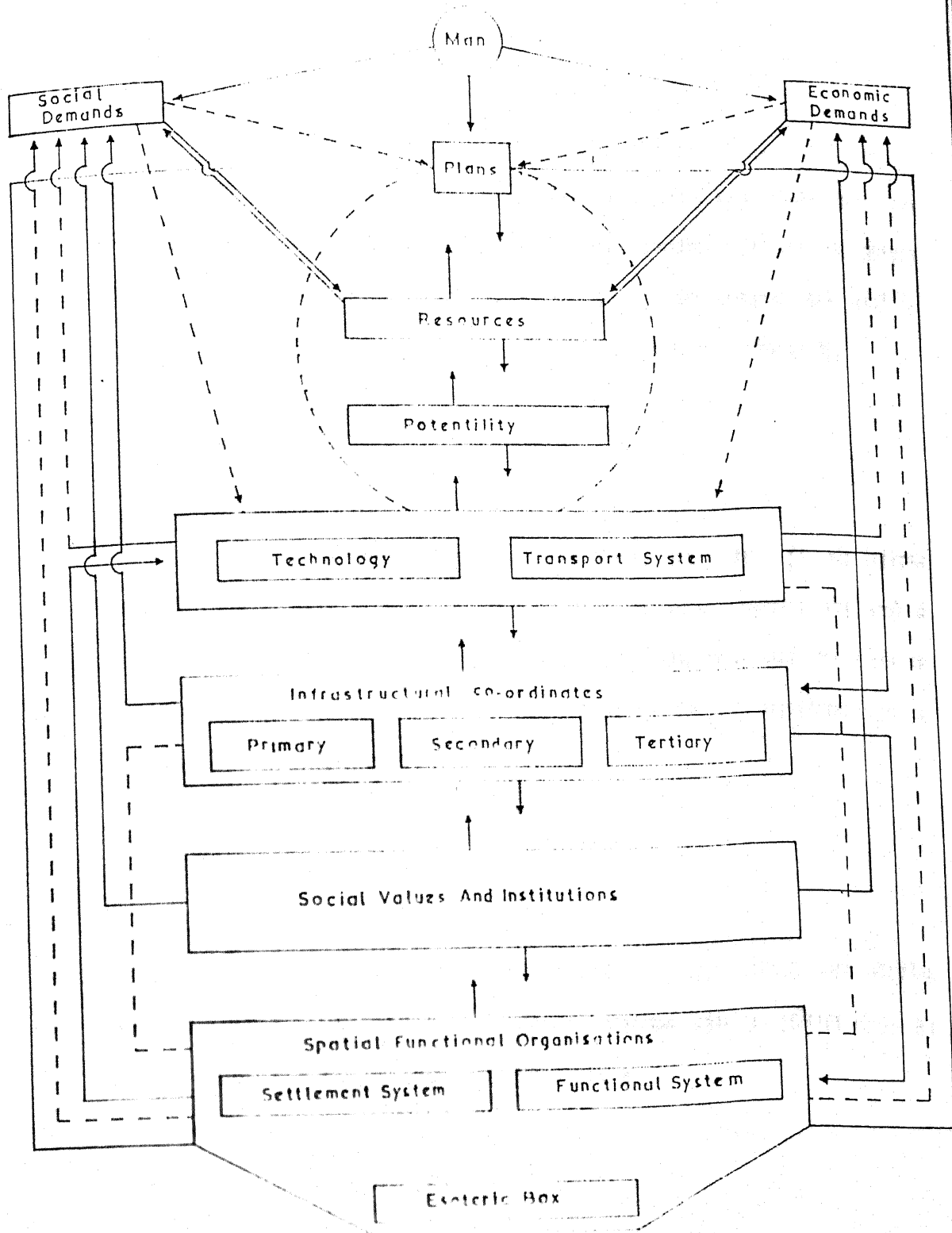
Fig 8.2

1. आवासीय भूमि :

प्रायः नगरों में औसत 47 प्रतिशत आवासी भूमि मिलती है जो नगरीय भूमि का सबसे बड़ा उपयोग है। नगरों में 38 से 57 प्रतिशत तक आवासीय भूमि उपयोग पाया जाता है। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में प्रायः विकसित भूमि का 38 प्रतिशत आवासों के अन्तर्गत पड़ता है यह प्रतिशत 20 हजार से 50 हजार जनसंख्या वाले नगरों के लिये 49 प्रतिशत तथा 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों के लिये 5 प्रतिशत हैं।

2. वाणिज्यिक भूमि :

सम्पूर्ण 12 नगरों का औसत 3.08 प्रतिशत है। यह भूमि भी विभिन्न आकार के नगरों में अलग-अलग मिलती है। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 4.4 प्रतिशत अन्य नगरों में यह 2.5 से 3.5 प्रतिशत के बीच पाया जाता है। क्षेत्र के अन्य नगरों में इसका प्रतिशत अधिक है। अतः जिला टीकमगढ़ में वाणिज्यिक भूमि के नियोजन की नितान्त आवश्यकता है।

3. औद्योगिक भूमि :

अध्ययन क्षेत्र के नगरों में विकसित भूमि का 5.72 प्रतिशत भाग औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत है, छोटे नगरों में प्रायः अधिकतम औद्योगिक भूमि का प्रतिशत 6.95 है। इसके बाद मध्यम नगरों में 6.34 प्रतिशत औद्योगिक भूमि है।

4. सड़क एवं गलियों के अन्तर्गत भूमि :

राजमार्ग, सड़कें एवं गलियाँ नगरीय भूमि के दूसरे सबसे बड़े भूमि उपयोग हैं। 12 नगरों की लगभग 12.75 प्रतिशत भूमि उपरोक्त उपयोग में आती है।

5. सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग :

सार्वजनिक कार्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, डाकघर, कार्यालय, पुलिस एवं अग्निशमक स्टेशन, रेल्वे तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के अन्तर्गत जिला टीकमगढ़ की औसतन 12 प्रतिशत विकसित भूमि मिलती है। जिन नगरों में जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय विकास खण्ड मुख्यालय हैं, उनमें यह भूमि उपयोग अधिक मिलता है।

6. मनोरंजन भूमि उपयोग :

अध्ययन क्षेत्र में पार्क एवं खेल मैदान तथा नगरों के विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत 4.71 प्रतिशत भूमि पायी जाती हैं। ऐसी भूमि 0.06 प्रतिशत से लेकर 15.8 प्रतिशत तक के बीच मिलती है। इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 4 नगरों में मनोरंजन भूमि नगण्य है। ये नगर है बड़ागाँव, कारी, बल्देवगढ़ तथा तरीचरकलाँ। इन नगरों तथा अन्य सभी नगरों में मनोरंजन के और अधिक साधनों को विकसित करने की नितान्त आवश्यकता है।

—0—

REFERENCES

1. Singh, K.N. (1966): Spatial Pattern of Central Places system in Middle Ganga Valley, Natonal Geographical Journal of India, P: 12.

2. Singh, J. (1979) : Central Places and Spatial Organisation in a Backward Economy, Gorakhpur Region-A study in Integrated Regional Development, Uttar Bharat Bhoogol Parished Goraphpur, U.P. PP : 5-11.

3. Berry, B.J.L. (1958) (a): A Note on Central place Theory and Range of Good, Economic Geography, London, P: 34.

4. Bronger, D. (1978): Central Place System, Regional Planning and Development in Developing countries- A case study of India Edited by Singh, R.L. et. al. Transportation of Rural Habitat in Indian Perspective- A Geographical Dimentsions; NG:SI, Varanasi P : 184.

5. Singh, J. and Ved Prakash (1973): Central Place and Spatial Integration, A Critical approach, National Geographical Journal of India VOL. XIX, P :270.

6. Nath, M.L. (1991) : The Upper Chambal Basin, A Geographical Study of Rural Settlements Northern Book Centre, New Delhi P : 42.

7. Andrede, P. et. al. (1974): A Geographical Appr-

oach to settlement Planning for Integrated Area Development Ford Foundation, (Mimeo), New Delhi P : 120.

8. Mishra, G.K. (1972) (a) : A Service Classification of Settlement in Miryalguda Taluka of Andhra Pradesh, Behavioural Science And Community Development, NICD, Hyderabad -6, PP : 64-75.

9. Asthama, V.K. (1975) : A study of Rural Settlements in Almora and its Environs, Paper Presented at I.G.U. Symposium on Rural Settlements, Banaras Hindu University 1-6 Dec.

10. Singh, R.L. (1975) : Meaning, Objectives and Scope of Settlement Geography, in Singh, R.L. and Singh, K.N. (Eds.) Reading in Rural Settlement, Geography, National Geographical Society of India Research Publications No. 14, Varanasi.

11. Mukerjee, A.B. (1960): Spacing of Rural Settlement in Andhra Pradesh; A Spatial Analysis, Geographical View Point, Chandigarh, 1.

12. Mather, E.C. (1944) : A Linear Distance Map of Farm Popualtion in United States, Annels A.A.A.G. 34, PP : 173-80

--0--

अध्याय नौ

सेवाक्षेत्रों का निर्धारण

- ✓ - विधिक दृष्टिकोण
- - प्रयोगात्मक उपागम
- ✓ - सैद्धान्तिक उपागम
- - सेवाक्षेत्रों का निर्धारण
- - अतिव्यापित एवं रिक्त क्षेत्र
- - सन्दर्भित ग्रन्थों की सूची

सेवा क्षेत्रों का सीमांकन : (DELIMITATION OF SERVICE AREAS.):

यद्यपि प्रत्येक केन्द्रस्थल का मुख्य और अनिवार्य कार्य समीपवर्ती क्षेत्र के लिए आवश्यकताओं एवं पदार्थों का विनिमय स्थान बनाना है, परन्तु उनके उद्भव आकार और विकास प्रारुप तथा अन्ततः उनके कार्य सम्पादन के अलग अलग स्तर एवं प्रकार, इत्यादि इन सभी विशेषताओं में विभिन्नताओं और समानताओं का होना स्वाभाविक है। इस प्रकार की विभिन्नताए हमारी व्यवहारिक आवश्यकताओं की प्रति पूर्ति करने में केन्द्रस्थलों को कई प्रकारों या भेदों में सीमांकित करने को बाध्य करती हैं, तथापि इस प्रकार का कोई भी वर्गीकरण का प्रयास कुछ न कुछ वास्तविक अवश्य होता है, क्योंकि केन्द्रस्थलों का क्रम सरल से जटिल की ओर अथवा छोटे से बड़े की ओर अधिक सतत अथवा निरन्तर होता है। अतः उनका विभाजन तर्कपूर्ण ढंग से संभव नहीं हैं, क्योंकि हमारे सेवाकेन्द्रों के सीमांकन के आधार वस्तुगत और निश्चित ढंग के नहीं होते और परिणामतः वर्गों को पृथक करने वाली सीमायें भी कृत्रिम, परिवर्तनशील और अनिश्चित होती हैं। क्यों और कैसे किसी सेवा केन्द्र को एक विशेष वर्ग में ही रखते हैं। अन्य में नहीं, इसका निश्चित और स्पष्ट उत्तर योजनाविदों को नहीं मिलता है।[1] केन्द्र स्थलों का सीमांकन भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणें द्वारा निम्नानुसार किया जा सकता है।

1. सेवा केन्द्रों के प्रमुख कार्य (Functions)
2. सेवाओं की केन्द्रीयता (Centrality) अर्थात सेवाकेन्द्रों के स्वरुप में उनका महत्व।
3. उद्भव, वृद्धि और विकास की विशेषतायें ।
4. जनसंख्या आकार (Population Size)
5. नगरीयकरण की प्रक्रिया ओर उनका विस्तार।
6. आकारिकी के प्रतिरुप और बाह्याकृति।

7. सेवाओं का आधार, सेवाकेन्द्रों का क्षेत्रीय धरातल (Site) और अवस्थिति।
8. सेवाकेन्द्रों का प्रशासकीय, राजनैतिक स्तर तथा मुख्यालयत्व।
9. सेवा केन्द्रों का समवाय, समूह या साहचर्य इत्यादि।

केन्द्रस्थलों को सीमांकन को प्रथम दो आधारों/दृष्टिकोणों में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि इनके कार्य इनके उद्भव, विकास और अस्तित्व के लिए अपरिहार्य अथवा अनिवार्य तत्व हैं तथा उनकी केन्द्रीयता केन्द्रस्थलों के रुप में उनके पूरे महत्व को प्रदेर्शित करती है। केन्द्रस्थलों के कार्य उनके जीवन तत्व हैं, जिनकी अनुपस्थिति में केन्द्रस्थलों की कल्पना ही असम्भव है। इन कार्यों का प्रभाव, उनकी केन्द्रीयता पर प्रत्यक्षत: पड़ता ही है, उनके सारे जीवन-संगठन ओर प्रारुप पर भी उनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन कार्यों के आधार पर केन्द्रस्थलों का सीमांकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

सेवा क्षेत्रों के सीमाकन में प्राविधिक दृष्टिकोण :

सेवाकेन्द्रों का आधारभूत कार्य अपने चतुर्दिक क्षेत्र को सेवायें प्रदान करना है, जिसमें व्यापक अर्थों में वाणिज्य अर्थात आवश्यकताओं, सेवाओं एवं वस्तुओं का परस्पर विनिमय सम्मिलित है, केवल स्थानीय जन सामान्य के लिए किये गये सभी कार्य अकेन्द्रीय या अप्राथमिक हैं। ये केन्द्रीय कार्य भी कई तरह के होते हैं और कुछ अन्य तरह के कार्य भी इसके साथ-साथ विकसित हो जाते हैं। केन्द्रस्थल बहुधा अनेक तरह के कार्य भिन्न-भिन्न मात्राओं और मिले जुले रुप में करते हैं। इसलिये सेवा केन्द्र को औद्योगिक वर्ग में रख देने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि अन्य तरह के कार्य उसमें विद्यमान नहीं होते, प्रत्युत यह कि क्षेत्रीय संदर्भ में अन्य कार्यों या कुछ अन्य केन्द्रों की तुलना में उद्योग का कार्य इसमें अधिक महत्वपूर्ण है। केन्द्रस्थलों के प्रमुख कार्य हैं वाणिज्य, उद्योग, यातायात, प्रशासन, शिक्षा, सुरक्षा के कार्य, चिकित्सा तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य इत्यादि। व्यवहारिक या निश्चित

परिणामात्मक आधारों पर इनका सीमांकन वाणिज्य केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों, बंदरगाहों, यातायात केन्द्रों, प्रशासकीय केन्द्रों, शिक्षा केन्द्रों, धार्मिक केन्द्रों, सामान्य केन्द्रों इत्यादि के रुप में किया जा सकता है।[2] कार्य साहचर्य (Functional Associations) के आधार पर इन्हें एक कार्य प्रधान केन्द्र, (Mono Functional) तीन कार्यों के केन्द्र (Tri Functional Centre)के रुप में सीमांकित कर सकते हैं।

केन्द्रीयता-केन्द्रीय कार्यों के सम्पादन की संख्या या मात्रा, तीव्रता ओर विस्तार (प्रभाव-क्षेत्र के रुप में) पर निर्भिर करती है और इसको परिमाणात्मक रुपों में कई विधियों से ज्ञात किया जा सकता है[3], जिनका सविस्तार वर्णन यहाँ पर न तो अपेक्षित ही है और न इच्छित ही। किसी स्थान की सापेक्ष केन्द्रीयता (Relative Centrality) प्रदेशों के अन्य केन्द्रों की तुलना में उस स्थान के महत्व को प्रगट करती है तथा उसकी निरपेक्ष केन्द्रीयता (Absolute Centrality) की तुलना निरपेक्षत: किसी भी केन्द्र से की जा सकती है। केन्द्रीयता या आकार के दृष्टिकोण से किसी प्रदेश के बृहत्तम केन्द्र या नगर को प्रमुख केन्द्र या प्राथमिक नगर (Primate or Primary City) कहते हैं जो प्रादेशिक राजधानी भी होता है। केन्द्रीयता के आधार पर केन्द्रस्थलों को बड़े से बड़े-छोटे की ओर क्रमशः इस प्रकार सीमांकित किया जा सकता है। (1) प्रादेशिक राजधानी या प्राइवेट केन्द्र (जो प्रदेश में सबसे बड़ा और संख्या में एक ही होता है। (2) बृहद् प्रादेशिक केन्द्र, (3) लघु प्रादेशिक केन्द्र, (4) उप प्रादेशिक केन्द्र और (5) स्थानीय केन्द्र।

केन्द्रस्थलों के उद्भव और विकास और वृद्धि की विशेषताओं ओर अवस्थाओं के आधार पर इनका विभाजन सम्भव है। इस तरह का सीमांकन विकास के उन भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक युगों में केन्द्रों को रखकर किया जा सकता है, जिनमें उनका जन्म केन्द्रस्थलों के रुप में हुआ अथवा जिनमें पूर्णतः या अधिकांशतः उनकी स्थापना, निर्माण या पुर्ननिर्माण किया गया। इस तरह के सीमांकन का आधार निम्न प्रकार से हो सकता है।

प्रागैतिहासिक केन्द्र, प्राचीन केन्द्र, मध्ययुगीन केन्द्र और आधुनिक केन्द्र। इस प्रकार सीमांकन की एक अन्य विधि इस तरह हो सकती है: **विकसित, विकासमान या वर्धमान केन्द्र** (Developed or Growing Centre) **स्थिर** *(Stagnant or Maintained)* केन्द्र ओर **ह्रासाभिमुख** *(Declining)* केन्द्र। जनसंख्या के आधार पर केन्द्रों के सीमांकन का एक नमूना भारतीय जनगणना 1961 से प्राप्त होता है, जिसमें नगरों का इस प्रकार सीमांकित किया गया है - 1. **प्रथम श्रेणी के नगर** (एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या के नगर) 2. **द्वितीय श्रेणी के नगर** (50,000 से 1,00,000), **तृतीय श्रेणी के नगर** (20,000से 50,000), 4. **चतुर्थ श्रेणी के नगर** (10,000 से 20,000), 5. **पंचम श्रेणी के नगर** (5,000 से 10,000) ओर 6. **षष्टम श्रेणी के नगर** (5000 से कम जनसंख्या के नगर) आदि। नगरीयकरण *(Urbanization)* की मात्रा और विस्तार के आधार पर इनका सीमांकन इस प्रकार किया जा सकता है:- 1. **महानगरीय प्रदेश** (मेगलोपोलिस), 2. **महानगर** (मेट्रोपोलिस[2]), 3. **बड़े प्रादेशक शहर**, 4. **उपप्रदेशीय बड़े नगर** (शहर), 5. **औसत शहर**, 6. **छोटे शहर**, 7. **बड़े कस्बे**, 8. **औसत कस्बे**, 9. **छोटे कस्बे**, 10. **बाजार केन्द्र और** 11. **बाजार ग्राम ओर** 12. **बाजार**। बाजार केन्द्र एक अर्ध ग्रामीण या अर्धनगरीय केन्द्र होता है और अन्तिम दोनों ग्रामीण केन्द्र होते हैं।

आन्तरिक प्रारुप के विभिन्न प्रतिरुपों तथा सम्पूर्ण वाह्यकृतियों को ध्यान रखते हुए भी केन्द्र स्थलों का सीमांकन सम्भव है। इन बाह्य स्वरुपों की विशेषताओं के आधार पर इस तरह से सीमांकन किया जा सकता है:- **आयाताकार, वृताकार, अर्धवृताकार, अरीय** (रेडिएल), **रेखीय** तथा **मिश्रित** या **नियमित प्रतिरुपों** के केन्द्र या नगर। इनकी आनतरिक संरचना में चेकबोर्ड या ग्रिड प्रतिरुप का सड़क-विन्यास प्राय: जयपुर जैसे सुनियोजित नगरों में मिलता है। आधारधरातल (*Site*) या स्थिति (*Situation*) के आधार पर केन्द्रों को इस प्रकार रखा जा सकता है:- नदी व तटीय नगर *(River Town)*, झील तटीय (*Lacustrine)* केन्द्र, बन्दरगाह *(Port)* या समुद्र तटीय *(Costal)* नगर, पर्वतीय नगर, पर्वत-पदीय नगर *(Piedmont Town)* मैदानी केन्द्र, पठारी केन्द्र इत्यादि

नगरों के प्रशासकीय स्तरों के आधार पर उनको नगर निगम (**Muncipal Corporation)** नगरपालिका, नगर क्षेत्र ***(Town Area)*** के नोटीफाइड क्षेत्र कैन्टोनमैंन्ट के नगर इत्यादि के रुप में रख सकते हैं। राजनैतिक या प्रशासकीय मुख्यालयों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी, प्रान्तीय राजधानी जिला मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय के नगर इत्यादि रुपों में सीमांकित कर सकते हैं। केन्द्रों के समवाय या समूह के आधार पर उन्हें हम भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं जैसे नगर समूह ***(Town Group)*** कोनवेर्शन, युगल नगर ***(Double Town)***युग्म नगर ***(Twin Town)*** नगरीय समवाय ***(Urban Agglomeration)*** इत्यादि। इसी प्रकार केन्द्रों के सीमांकन के और भी आधार हो सकते हैं।

सैद्धान्तिक उपागम :

केन्द्रीय स्थानों के क्षेत्रीय समांकलन और कार्यात्मक सहसम्बन्ध प्रादेशिक योजनाओं के आधारभूत लक्ष्य हैं। किसी क्षेत्र की मानवीय क्रियायें और क्षेत्रीय कार्य वहाँ की स्थिति से अनर्तसम्बन्धित होते हैं। वास्तव में क्षेत्रीय सम्बंधों की संकल्पना और उनका कार्यात्मक विश्लेषण स्थिति की संरचनात्मक विशेषताओं और मानवीय क्रियाओं द्वारा परस्पर सहसम्बन्धी कार्य है।[4] कार्यों का केन्द्रीय अथवा विकेन्द्रीकरण या नाभिक परस्परा भू-सतह पर क्षेत्रीय निर्माण कार्य एवं मानवीय व्यवहार के मूलभूत सिद्धांत हैं। क्षेत्रीय निर्माण की बाह्य संरचनायें जैसे- स्थान माँग, आर्थिकी का विकास और परिवहन मूल्य इससे सीधे सम्बन्धित है। कार्यात्मक ओर अन्रक्षेत्रीय मानवीय क्रियाऐं कुल समूह की ओर क्षेत्रीय संरचनाओं का निर्माण करती है। अतः अध्ययन क्षेत्र के केन्द्रीय कार्य जो बस्तियों द्वारा निर्मित किये जाते हैं। उनको समझने तथा उनकी केन्द्रीयता की व्यवस्था को सीमांकित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की केन्द्रीयता सेवा केन्द्रों विकास में राजनैतिक व्यवस्था प्रस्तुत करती हैं।

SETTLEMENT PATTERN
[Hexagonal Territory]
K=3
K=4
K=7
K=9
K=12
K=13
K=16
K=19
K=21
Central Places
Dependent Places Shared between Competing Central Places.
Dependent Places Entirely within the Territory of A Central Place
Source - LOSCH (1954)

Fig 9.1

चयनित कार्य (सेवा क्षेत्रों के सीमांकन के प्रथम आधार) :

बस्तियों को उनकी परम्परागत विशेषताओं और केन्द्रीय कार्यों के अनुसार आकारिकी में पृथक किया जा सकता है। केन्द्रीयकार्य वे है, जो कुछ स्थानों पर निर्मित होते हैं, किन्तु बहुत से स्थानों के लिये उपयोगी होते हैं। कार्यों की श्रेणियाँ बस्तियों के आकार एवं प्रतिरुप पर निर्भर होती हैं। सामान्यतः जनसंख्या आकार के आधार पर बस्तियों के आकारों को समझा जा सकता है जो कि प्रमुख क्रियाशील कारक है। जनसंख्या के उपरांत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारक जो विशेषकर सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रतिपादित करते हैं, इसके अन्तर्गत आते हैं।[5] जिला टीकमगढ़ में अध्ययन के लिये चुने गये कार्यों की यद्यपि समुचित स्थिति प्राप्त नहीं हैं, किन्तु स्थानिक प्रशासनिक स्थिति के कारण जिला मुख्यालय टीकमगढ़, तहसील मुख्यालयों, विकासखण्ड मुख्यालयों, राजस्व निरीक्षक मण्डलों एवं नगरीय केन्द्रों में कार्यें का तुलनात्मक क्षेत्र अधिक पाया जाता है, नगर एवं कस्बों के स्थान उन ग्रामीण क्षेत्रों का जो सड़क, दूर संचार एवं अन्य सेवाओं द्वारा जुड़े हुए हैं, अधिक कार्यों की श्रेणियाँ रखाते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे स्थित होने, सहकारी समितियों के पाये जाने से केन्द्रीय स्थानों की महत्ता बढ़ जाती है। अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण से यह पता लगा की कार्यों की संख्या और बस्तियों की संख्या के बीच ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अर्थात कार्यों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, ग्रामीण बस्तियों की संख्या उसी अनुपात में घटती जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय कार्यों के वितरण के केन्द्रीय स्थानों का प्रादुर्भाव होता है और यह परम्परा सेवाकेन्द्रों के सीमांकन की पद्धति में समूहों को जन्म देती है।

कार्यात्मक पदानुक्रम (सीमांकन की प्रमुख प्रक्रिया) :

केन्द्रीय स्थानों के निर्धारण के लिये कुछ तत्वों को चुना जाता है और इनसे कार्यात्क पदानुक्रम की स्थिति द्वारा सीमांकन के महत्व एवं उपयोगिता का अनुमान लगाया जा

Model For Village Planning
(Schematic)
(i) Socio-Economic Activities
(ii) Land Use Model
(iii) Proposed Pattern Of Transport Network
A
B
C
A Dependent Villages Partial/Total Range Of First Level-Functions
B Central Village Full Range Of Second-Level Functions
C Service Centre
Direction Of Dependency
A Source Of Raw Materials For Processing Unit At B
B Source Of By Products For Complex At C
C Industrial Complex At C
Direction Of Dependency
A–B All-Weather Strengthened Cart-Tracks
B–B All-Weather Macadam Road
B–C All-Weather Macadam/Metalled Road
After L·K·Sen
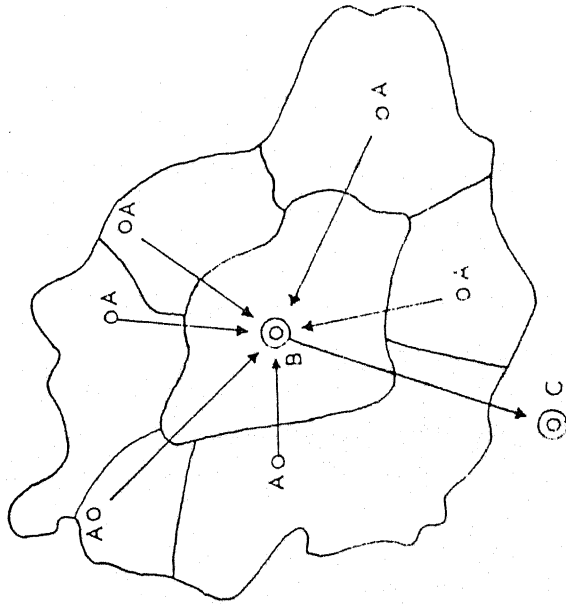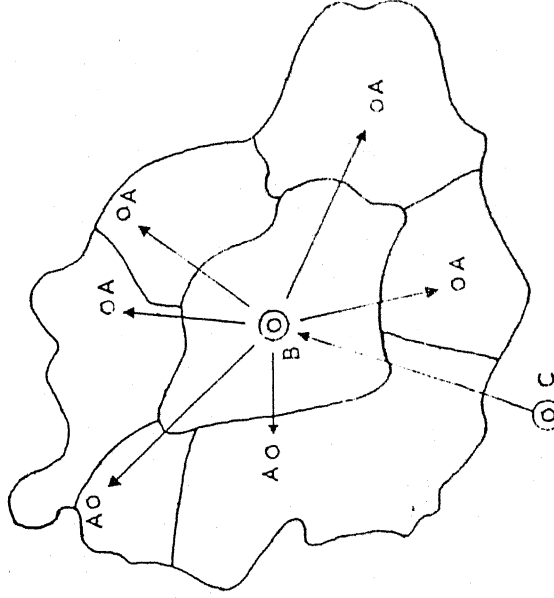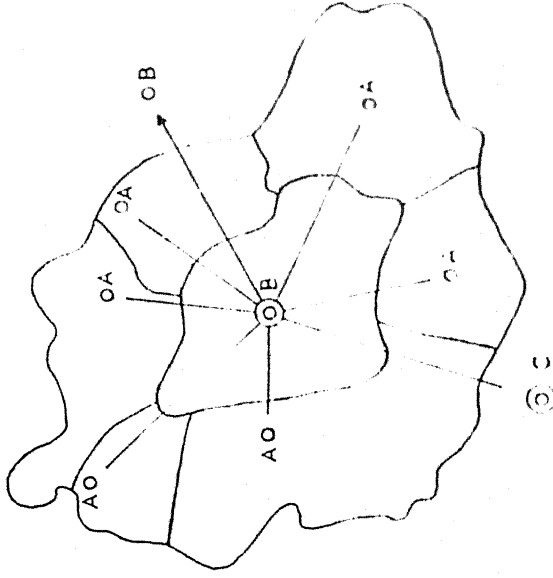
Fig 9.2

सकता है, जिला टीकमगढ़ में यह पाया गया कि कार्यों के वितरण में न तो समरुपता है और न ही एक जैसे कार्य सभी स्थानों पर वितरित पाये जाते हैं। यह अन्तर सम्पूर्ण क्षेत्रों में कार्यात्मक पदानुक्रम के माप को एक निश्चित स्वरुप प्रदान करते हैं। एक ही प्रकार के कार्य समूहों को उनके स्तरों के समान संबंधित महत्व प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिये प्राथमिक पाठशाला, पूर्व माध्यमिक शाला, माध्यमिक शाला, उच्चतर माध्यमिक शाला (विद्यालय) और महाविद्यालय समान कार्य विधि समूहों के आते हैं। इस प्रकार इन सभी को एक समूह में रखकर महत्वपूर्ण सम्बन्ध स्तर को निकाला जाता है। कार्यात्मक पदानुक्रम में कार्यों के सभी वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बस सेवायें, संचार व्यवस्था, वित्तीय सुविधायें, बाजार, फुटकर सेवायें, किराना, टेलरिंग, चाय, हार्डवेयर, कैमिस्ट एवं ड्रगिस्ट सम्मिलित हैं। प्रत्येक कार्यों के उपकार्यों को भी उनके स्तरों के अनुसार रखा जाता है। ऐसे कार्या जो अधिक महत्व के नहीं है, अन्य कार्यों के अन्तर्गत रखाना चाहिये। उपकार्यों के स्तर जो प्रत्येक वर्ग का पदानुक्रम निर्धारित करते हैं, अलग कार्यों के अन्तर्गत रखे जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र की कच्ची व पक्की सड़कों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। क्षेत्रीय रेल सुविधाओं, रेल्वे स्टेशनों, बस स्टॉप, प्रार्थना बस स्टॉप एवं प्राईवेट बस सेवा को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में नियोजन प्रदेशों का सीमांकन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इनकी सीमा निर्धारित करते समय क्षेत्र की भौतिक समरुयता प्राकृतिक संशिलष्टता एवं आर्थिक एकरुपता पर ध्यान दिया जाना परम आवश्यक है। जो निम्न लिखित है :-

1. नियोजन प्रदेश के सीमांकन में प्रायः हर स्तर की प्रशासनिक इकाईयों पर दृष्टि रखाना चाहिए, क्योंकि प्रादेशिक नियोजन के लिये वाहन सर्वेक्षण, आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं क्रियान्वयन के लिये उपयुक्त इकाईयों की आवश्यकता होती है। अतः इकाईयों सुविधाजनक एवं व्यावहारिक होनी चाहिये। वे एक दूसरे की सीमाओं को काटे नहीं स्वायत्त हो। अध्ययन क्षेत्र में इसी को ध्यान में रखते हुये इकाईयों का निर्धारण किया गया है।
2. नियोजन प्रदेशों को लंचीला होना चाहिये तथा प्रादेशिक विकास के लिए अन्य

विकल्प भी होने चाहिये।

3. योजनाओं का सुचारु रुप से क्रियान्वयन के लिये यातायात एवं व्यापार की व्यापक व्यवस्था रहनी चाहिये।

4. चूँकि नियोजन संसाधन विकास समस्याओं के समाधान की एक प्रक्रिया है अतएव उनके आदर्श नियोजन प्रदेश होते है, जहाँ समस्यायें पूर्णतः तर्क संगत एवं न्यायोचित है।

5. क्षेत्रीय नियोजन में सकेन्द्रीय बिन्दुओं का संगठन होना जरुरी है। इन संगठनों के माध्यम से प्रदेशों की आवश्यकतायें पूरी की जाती हैं। ऐसे केन्द्रों के अभाव किसी सामग्री के आदान-प्रदान में कठनाई होती है।

6. क्षेत्रीय नियोजन में पर्याप्त संसाधन विद्यमान होने चाहिये, जिससे क्षेत्र के उत्पादन की माँग को पूरा करने वाला तथा दूसरे क्षेत्रों से आदान प्रदान भी उपलब्ध हों।

सेवा क्षेत्रों के सीमांकन की प्रविधि :

सेवा क्षेत्रों के निर्धारण की विधियाँ बस्तियों की केन्द्रीयता मापन पर आधारित है। किसी स्थान का या बस्ती की केंन्द्रीयता केन्द्रीय कार्यों की संख्या का कुल योग है। सेवाकेन्द्रों के सीमांकन में सर्वत्र व्याप्त रहने वाली प्रकृति के रुप में किया गया है।[6] सेवा केन्द्रों के सीमांकन में सभी कार्यों को नहीं लिया जा सकता। अत: विभाजन के लिये अधिभार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दुर्भाग्य से यहाँ पर कोई भी सांख्यकीय विधि अथवा संवर्ग मापन लगभग अधिभार प्रदान करने के लिये विभिन्न स्तरीय कार्यों में नहीं पाये जाते, कुछ शोधकर्ताओं ने अधिभार कार्यों के मूल्य व निर्धारण को आधार माना है।[7] जबकि दूसरों ने जनसंख्या सीमांकन को कार्यों के लिये आधार माना है। पूर्व में ही अध्ययन क्षेत्र के जनसंख्या सीमांकन का अध्ययन किया जा चुका है। मूल्य निर्धारण विधि में कार्यों का सांख्यिकी मूल्य (अधिभार) उनके सापेक्ष महत्व के आधार पर दिया गया है।[8] जो कि व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्न-भिन्न होती है।

क्रिस्टालर[9] परिकल्पना स्थानों की केन्द्रीयता एक स्थान पर लगे टेलीफोन की संख्या पर आधारित है। ग्रीन[10] ने पश्चिमी इंग्लैण्ड के केन्द्रीय स्थानों की केन्द्रीयता बस सेवाओं के आधार पर निर्धारित की है। ब्रूस तथा ब्रेसी[11] ने केन्द्र के महत्व का निर्धारण निम्नलिखित तत्वों के आधार पर किया है।

1. व्यापारिक क्रियाओं एवं अन्य सेवाओं द्वारा सेवाकेन्द्रों का सीमांकन ।
2. किसी केन्द्र पर निर्भर क्षेत्र के लिये सामान तथा सेवाओं के निर्धारण द्वारा सेवाकेन्द्रों का सीमांकन।

गौडलुण्ड[12] ने फुटकर व्यापार में लगी जनसंख्या के आधार पर, तिवारी[13] ने केन्द्रीयता का आंकलन सेवाकेन्द्रों के द्वारा गोडलुण्ड के निम्नलिखित सूत्र में थोड़ा परिवर्तन करके किया है।

सूत्र $$C = \frac{P}{T} \times 100$$

जहाँ C = केन्द्रीयता

P = एक बस्ती के विभिन्न सेवाओं में लगे व्यक्तियों की संख्या।

T = कुल जनसंख्या ।

सिंह[14] ने वाणिज्यिक जनसंख्या और विभिन्न कार्यों में लगी जनसंख्या के आधार पर सूत्र प्रस्तुत किया है। सेन[15] द्वारा केन्द्रीय सूचकांक का निर्धारण कुल अंकों के आधार पर निम्नलिखित सूत्र में किया है।-

सूत्र $$C_i = \frac{AS}{MS} \times 100$$

जहाँ C_i = केन्द्रीयता सूचकांक.

AS = केन्द्रों के वास्तविक अंक.

MS = अधिकतम कुल अंक.

कार्यों और उपकार्यों के अधिभार के लिये जो अध्ययन क्षेत्र की बस्तियों में पाये जाते हैं, सूत्र का उपयोग कर ज्ञात किये गये है, इस सिद्धान्त के पीछे यह तकनीकि है कि जहाँ आवश्कयता बढ़ती है वहीं केन्द्रीयता के आधार पर कार्यों का महत्व बढ़ता जाता है। अत: अधिभार उच्च होगा। इस सिंद्धांत के सत्यापन के लिये अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया है।

सूत्र $$W_i = \frac{N}{Fi}$$

जहाँ

W_i = कार्यों का अधिभार.

N = बस्तियों की कुल संख्या.

F_i = बस्तियों के कार्यों की संख्या.

सेवाकेन्द्रों की सीमांकन में सेवित कार्यों के अधिभार के दोष :

अधिभार प्रदान करने में आने वाले दोष निम्नलिखित है -

1. एक गाँव में हाईस्कूल के साथ मिडिल स्कूल भी पाये जाते हैं तो दानों के लिए एक ही भवन होने के क़ारण एक ही अधिभार प्रदान किया जायेगा।
2. यदि एक बस्ती में एक समान दो कार्य पाये जाते हैं तो उसके लिए अधिभार भी दो होगें।
3. एक ही सेवा के लिये, अधिभार समान कार्य में समान नहीं होते।
4. सेवित बस्तियों के कार्यो का अनुमान उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर लगाया जाता है। वास्तविक सेवित जनसंख्या से लगाकर नहीं।

सेवाकेन्द्रों के सीमांकन हेतु पदानुक्रम वर्ग समीकरण :

ये पाँच समंक है जो बस्तियों के पदानुक्रम को सीमांकन के निर्धारण में विभिन्न वर्गो द्वारा सूत्रों में बाँटा गया है। इस संमकों का विश्लेषण निम्नलिखित है:

सेवाकेन्द्रों की कार्यात्मक समीपता :

विभिन्न कार्यों के अधीन बस्तियों की कार्यात्मक समीपता में किसी विशेष बस्ती को सम्मिलित किया गया है। एक बस्ती के सभी कार्यो को अधिभार दिये गये है, सभी कार्य की बस्तियों के अधिभार को उनका परस्पर अधिभार कुल अधिभार के अंकों की कार्यात्मक समीपता होती हैं।

$$Fpj = {}^{n}_{i=1} Fwi$$

जहाँ

Fpj = बस्ती की कार्यात्मक समीपता।

Fwi = बस्ती में कार्य की अधिभार।

n = बस्तियों की कुल संख्या।

उदाहरण के लिये एक गाँव में प्राथमिक पाठशाला, शाखा डाकघर, बीज भण्डार, बस स्टाप, ओर फुटकर दुकानें हैं तो इनकी कार्यात्मक समीपता होगी।

$$Fpj = 1.37+4.19+17.60+463+1.22 = 29.01$$

सेवाकेन्द्रों की कार्यात्मक आश्रितता :

विभिन्न कार्यो के लिये एक बस्ती विभिन्न बस्तियों पर निर्भर करती है, उसके कुल अधिभारों का योग कार्यात्मक आश्रितता होती है।

सूत्र $$Fdj = {}^{n}_{i=1} dwi$$

जहाँ Fdj = जो बस्ती की कार्यात्मक आश्रितता।

dwi = कार्यो का अधिभार, जिसके बस्ती आश्रित है।

उदाहरण के लिए एक बस्ती विभिन्न कार्यों के लिये जैसे - साप्ताहिक बाजार, बस स्टाप, चिकित्सा केन्द्र, हाईस्कूल, पोस्टआफिस, आदि के लिए दूसरी बस्तियों पर आश्रित हो तो उस बस्ती की कार्यात्मक आश्रितता होगी।

$$Fds = 11.00+4.69+11.00+29.3+4.19 = 60.15$$

सेवाकेन्द्रों की कार्यात्मक वस्तुस्थिति :

कार्यात्मक बस्तुस्थिति के आंकलन के लिये कार्यात्मक समीपता में से कार्यात्मक आश्रितता घटा देते हैं। अत: एक बस्ती की कार्यात्मक वस्तुस्थिति = कार्यात्मक समीपता - कार्यात्मक आश्रितता।

सूत्र $$Fs = Fpj - Fdj$$

$$Fs = 29.01 - 60.15 = -31.14$$

अर्थात उक्त बस्ती में कार्यात्मक वस्तुस्थिति है, जिसमें कार्यात्मक आश्रिततता अधिक पायी जाती है।

सेवाकेन्द्रों की कार्यात्मक अन्तआश्रितता :

किसी वस्तु या ग्राम द्वारा अपने चारोंऔर के गाँवों से विभिन्न कार्यो के लिये सुविधायें प्राप्त होती है, उसे बस्ती की अन्तआश्रित्ता कहते हैं। जैसे - कोई बस्ती चिकित्सा सुविधा को अपने चारों ओर से गाँवों को प्रदान करती है या पाँच गाँव के निवासी उस गाँव में चिकित्सा सुविधा हेतु आते हैं, तो इस बस्ती की अन्तआश्रित्ता होगी, जैसे - किसी बस्ती में चिकित्सा सुविधा का अधिभार 11.00 है तो अर्न्तआश्रित्ता 11x5 = 55 होगी। इसे निम्न सूत्र द्वारा आंकलित किया जाता है -

सूत्र $$Fd = \sum_{i=1}^{n} (Fpi \times ai)$$

जहाँ

Fd = कार्यात्मक अन्तआश्रित्ता अंक ।

Fpi = विभिन्न बस्तियों को प्रदत्त कार्य सेवाओं का अधिभार

ai = सर्वेक्षित बस्तियों की संख्या।

सेवाकेन्द्रों की सेवा सम्भाव्यता :

बस्तियों की आन्तरिक एवं बाहरी क्षमताओं को सेवा सम्भ्याव्यता के अन्दर सम्मिलित किया जाता है, वैसे किसी केन्द्र की अन्तर्आश्रितता सेवाकेन्द्र .को परिभाषित करने के लिये पर्याप्त होती है, किन्तु यह बाह्य सेवाओं को व्यक्त करती है। केन्द्र की आन्तरिक सेवाओं जैसे किसी बस्ती की जनसंख्या गणना की सेवाओं की सम्याव्यता पर आंकी जती है, इसलिए अन्तर्आश्रित्ता और कार्यात्मक वस्तुस्थिति केन्द्र की सेवा सम्भाव्यता के निर्धारण के लिए पर्याप्त होती है। सारणी 9.1 में अध्ययन क्षेत्र के उपरोक्त कार्यात्मक वर्णनों को दर्शाया गया है।

सीमांकित सेवाकेन्द्रों का स्थानिक वितरण :

1. सेवाकेन्द्रों की न्यून दूरी : (5.37 से कम)

इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में ओरछा, निवाड़ी, तरीचरकलॉ, नैंगुवाँ एवं पृथ्वीपुर रा.नि.मण्डलों के सेवाकेन्द्र आते हैं। इन राजस्व निरीक्षक मण्डलों के अन्तर्गत 22 सेवाकेन्द्र आते है।

2. मध्यम दूरी वाले सेवा केन्द्र (5.37 से 6.32 के मध्य)

इसके अन्तर्गत सिमरा, मोहनगढ़, लिधोरा, दिगोड़ा जतारा, टीकमगढ़ समर्रा, बड़ागाँव एवं बल्देवगढ़ रा. नि. मण्डलों के सेवाकेन्द्र आते हैं जिनकी संख्या 118 है।

3. उच्च दूरी वाले सेवा केन्द्र : (6.32 से 7.67 के मध्य)

इसके अन्तर्गत जिला टीकमगढ़ के पलेरा, कुड़ीला, खारगापुर, रा.नि.मण्डलों के सेवाकेन्द्र आते है। इन सेवाकेन्द्रों की संख्या 10 है।

सेवाकेन्द्रों का विस्तार :

अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का निम्नलिखित विस्तार पाया जाता है-

सारणी 9.1 : जिला टीकमगढ़ के सीमांकित सेवाकेन्द्रों का वितरण प्रतिरुप एवं विस्तार.

राजस्व निरीक्षक मण्डल	केन्द्रीयता सूचकांक C_i	कार्यात्मक सूचकांक W_i	सेवाकेन्द्रों की कार्यात्मक समीपता	कार्यात्मक आश्रितता	कार्यात्मक वस्तुस्थिति	सम्याव्यता	सेवा केन्द्रों का विस्तार		
							न्यून	मध्यम	उच्च
ओरछा	0.08	3.84	2.46	1.78	1.38	0.86	0.28	2.43	0.64
निवाड़ी	0.05	4.88	2.93	2.22	1.32	1.36	0.35	2.03	0.60
तरीचरकलाँ	0.04	5.37	3.76	2.50	1.50	1.72	0.41	3.07	0.70
नैगुँवा	0.04	5.37	2.98	2.50	1.19	1.72	0.53	0.90	0.55
सिमरा	0.03	6.32	3.50	2.86	1.22	2.26	0.75	0.85	0.55
पृथ्वीपुर	0.04	5.37	3.25	2.50	1.30	1.72	0.40	1.87	0.60
मोहनगढ़	0.03	6.32	4.44	2.86	1.55	2.26	0.46	3.43	0.70
लिधौरा	0.03	6.32	3.42	2.86	1.19	2.26	0.50	1.12	0.54
दिगौड़ा	0.03	6.32	3.90	2.86	1.36	2.26	0.50	2.08	0.62
जतारा	0.03	6.32	3.54	2.86	1.24	2.26	0.46	1.48	0.56
पलेरा	0.02	6.67	4.48	3.57	1.25	3.44	0.65	1.40	0.58
टीकमगढ़	0.03	6.32	3.66	2.86	1.28	2.26	0.47	1.70	0.58
समर्रा	0.03	6.32	3.65	2.86	1.42	2.26	0.57	1.38	0.58
बड़ागाँव	0.03	6.32	4.50	2.86	1.57	2.26	0.53	3.09	0.71
बल्देवगढ़	0.03	6.32	3.34	2.86	1.17	2.26	0.50	0.96	0.53
कुड़ीला	0.02	7.67	3.63	3.57	1.02	3.44	0.71	0.08	0.47
खरगापुर	0.02	7.67	3.96	3.57	1.11	3.44	0.65	0.60	0.51
जिला टीकमगढ़	**0.03**	**6.16**	**3.61**	**2.82**	**1.30**	**2.24**	**0.51**	**1.67**	**0.59**
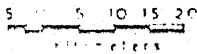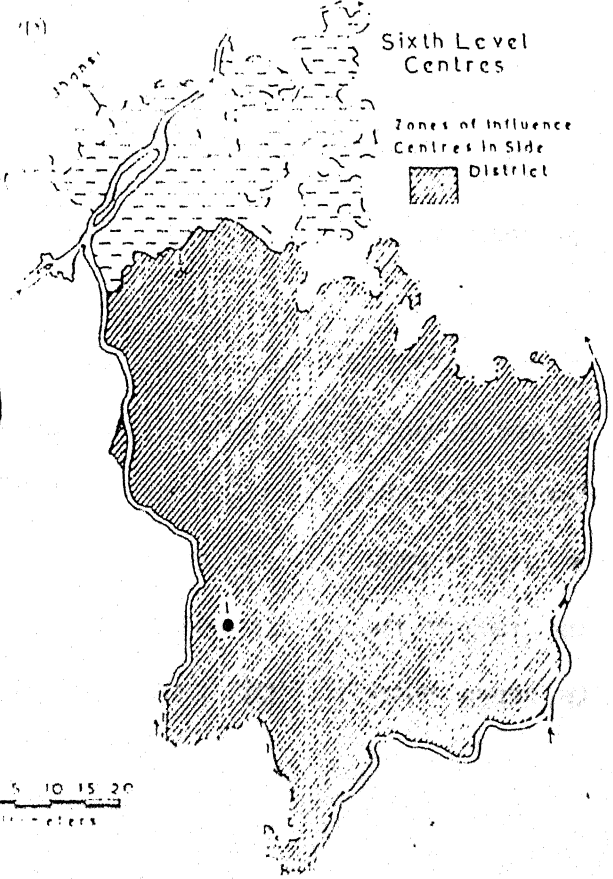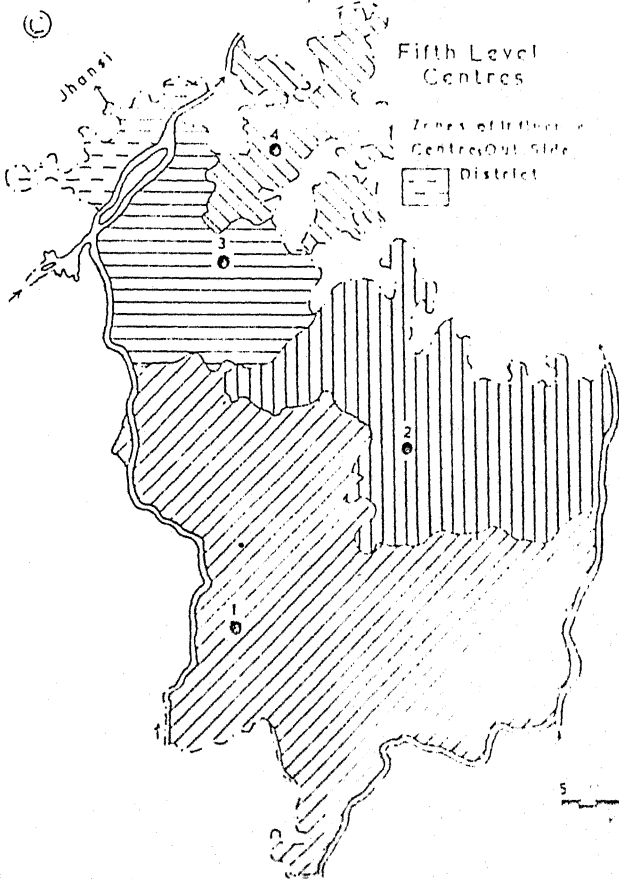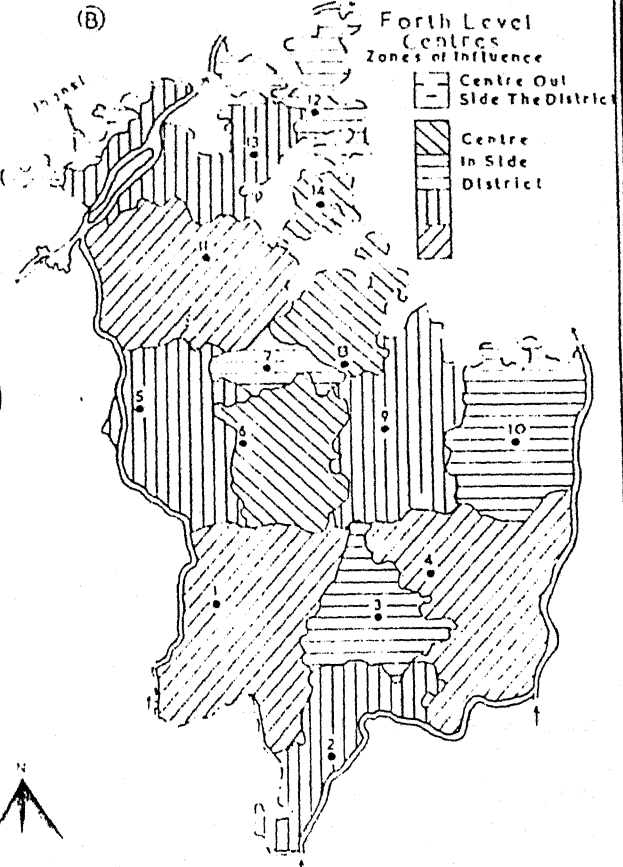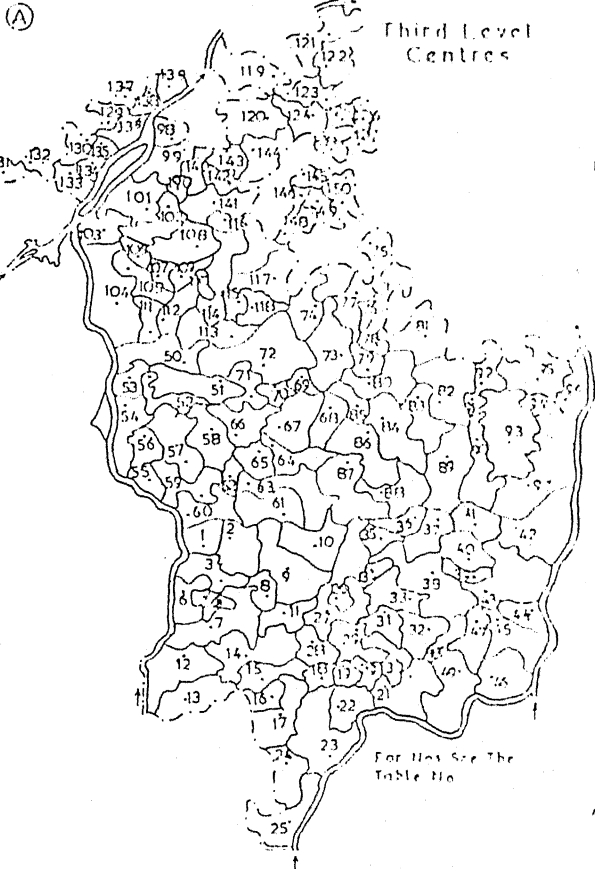
अतिनिम्न विस्तार के क्षेत्र :

इसके अन्तर्गत उन राजस्व निरीक्षक मण्डलों के सेवाकेन्द्रों को सम्मिलित किया गया है, जिनका मूल्य 1.19 से कम है इसके अन्तर्गत कुड़ीला, खरगापुर, बल्देवगढ़, नैगुवाँ एंव लिधौरा राजस्व निरीक्षक मण्डल आते हैं।

निम्न विस्तार के क्षेत्र :

इसके अन्तर्गत उन राजस्व निरीक्षक मण्डलों के सेवाकेन्द्र आते हैं, जिनका मूल्य 1.22 से 1.28 तक है। इनमें सिमरा, जतारा, पलेरा एवं टीकमगढ़ रा. नि.. म. है।

उच्च विस्तार वाले क्षेत्र :

इसके अन्तर्गत 1.30 से 1.38 तक के मूल्य वाले सेवाकेन्द्र आते हैं। ये सेवाकेन्द्र पृथ्वीपुर, निवाड़ी, दिगौड़ा एवं औरछा राजस्व निरीक्षक मण्डलों में आते हैं।

अति उच्च विस्तार वाले क्षेत्र:

जिन सेवाकेन्द्रों का मूल्य 1.42 से 1.57 तक है वह अति उच्च विस्तार वाले क्षेत्र के अन्तर्गत आते है, जिसमें सिमरा, तरीचरकलाँ, मोहनगढ़ एवं बड़ागाँव राजस्व निरीक्षक मण्डल आते हैं।

सांक्रेयात्मक अभिकल्पना द्वारा सेवाकेन्द्रों के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन :

किसी प्रादेशिक क्षेत्र में समान सेवाओं के लिये जनसंख्या एक केन्द्रीय ग्राम पर निर्भर करती है, केन्द्रीय सेवाकेन्द्र और उस आश्रित बस्तियों के बीच आकर्षक सेवाओं की प्रकृति का निर्धारण उसका प्रभाव क्षेत्र होगा।

सेवाकेन्द्रों का महत्व उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यं द्वारा निर्धारित होता है, चाहे यह कार्य आर्थिक ओर समाजिक ही क्यों न हो। प्रभाव क्षेत्र की सीमांकित करने के लिये भूगोल वेत्ताओं ने अलग अलग विधियों का प्रयोग किया हे उसमें रिलीज कनवर्स संकल्पना[16] यीट्स माडल[17] आदि प्रमुख है गोडलुन्ड ओर ग्रीन[18] ने परिवहन सेवाओं के (विशेषकर सड़क) के आधार पर, जबकि क्रस्टालर ने सम्बन्धित केन्द्र की केन्द्रीयता ओर पदानुक्रम को प्रभाव क्षेत्र को सीमांकन का आधार बनाया, ब्रेसो[19] ने ग्रामीण समुदायों की

केन्द्रीयता का नवीनतम उपयोग किया, बनमाली[20] और सेन[21] ने नवीन पहूँच मार्ग. निर्मित किये जो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं और सेवा केन्द्रों पर आधारित थी। अध्ययन क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन को निर्धारित करने के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधियों का उपयोग किया गया है।

गुणात्मक विधि द्वारा सेवाकेन्द्रों के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन :

सेवाकेन्द्रों के अध्ययन में आवश्यकतानुसार समस्त अध्यायों में इस विधि का प्रयोग किया गया है, क्षेत्रीय विशिष्टता के आधार पर ये केन्द्र को प्रमाणित करते हैं जो क्षेत्रीय विशिष्टताओं पर आश्रित होते हैं मध्य क्षेत्र में कार्यात्मक पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर को दर्शाने के लिये किया गया है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के केन्द्र एवं द्वितीय स्तर के केन्द्रों को सम्मिलित किया गयां है।

सेवाकेन्द्रों की सीमांकन में क्षेत्रीय कार्यात्मकता एवं अतिव्यायपन :

केन्द्रीय स्थानों के वर्तमान सीमांकन से यह स्पष्ट होता है कि इनमें वर्तमान में पर्याप्तता में क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक रिक्तता अधिक पायी जाती है। प्रति केन्द्र पर औसतन 5 बस्तियाँ निर्भर है, उत्तरी एवं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में यह अंन्तर बढ़कर 8 बस्तियाँ प्रति केन्द्रीय स्थान तक हो जाता है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में 4 बस्तियाँ प्रति केन्द्रीय स्थान तक पाई जाती है इन बस्तियों में एक से अधिक केन्द्रीय स्थानों के प्रभाव के कारण अतिक्रमण पाया जाता है। टीकमगढ़ बल्देवगढ़, जतारा, पलेरा, पृथ्वीपुर एवं निवाड़ी के पास की बस्तियाँ दो या दो से अधिक केन्द्रीय स्थानों के प्रभाव के कारण केन्द्रीय स्थानों का अतिक्रमण पाया जाता है इसी रिक्तता केा समाप्त करने के लिये टीकमगढ़ जिला के प्रतयेक 5 कि.मी. के अन्तराल से जो औसतन 2000 जनसंख्या को अपनी सेवायें प्रदान कर सके, सीमांकित किया गया है। इस हेतु यह आवश्यक है कि नये केन्द्रीय स्थानों का विकास किया जाना चाहिये, जो प्रति 10 कि.मी. की दूरी पर जो 5000 तक की जनसंख्या को अपनी सेवायें प्रदान कर सकें, बाजार, केन्द्र की स्थापना प्रति 20 कि.मी. की दूरी पर जो 20000 तक की जनसंख्या को अपनी सेवायें प्रदान कर सके।

A Relative Efficiency of Alter native Polygons
3-n
4-n
5-n
8-n
Maximum Radial Distance (in KM)
0.9
0.8
0.7
0.6
3-n
4-n
5-n
6-n
7-n
8-n
9-n
10-n
Circle
3
4
5
Perimeter (KM)
B Advantage of Hexagonal Territory
Unserved Service Areas Between Circles
Overlapping Of Service Areas Within Circles
Source : Regional Develoment and Planning in India, P. 24,
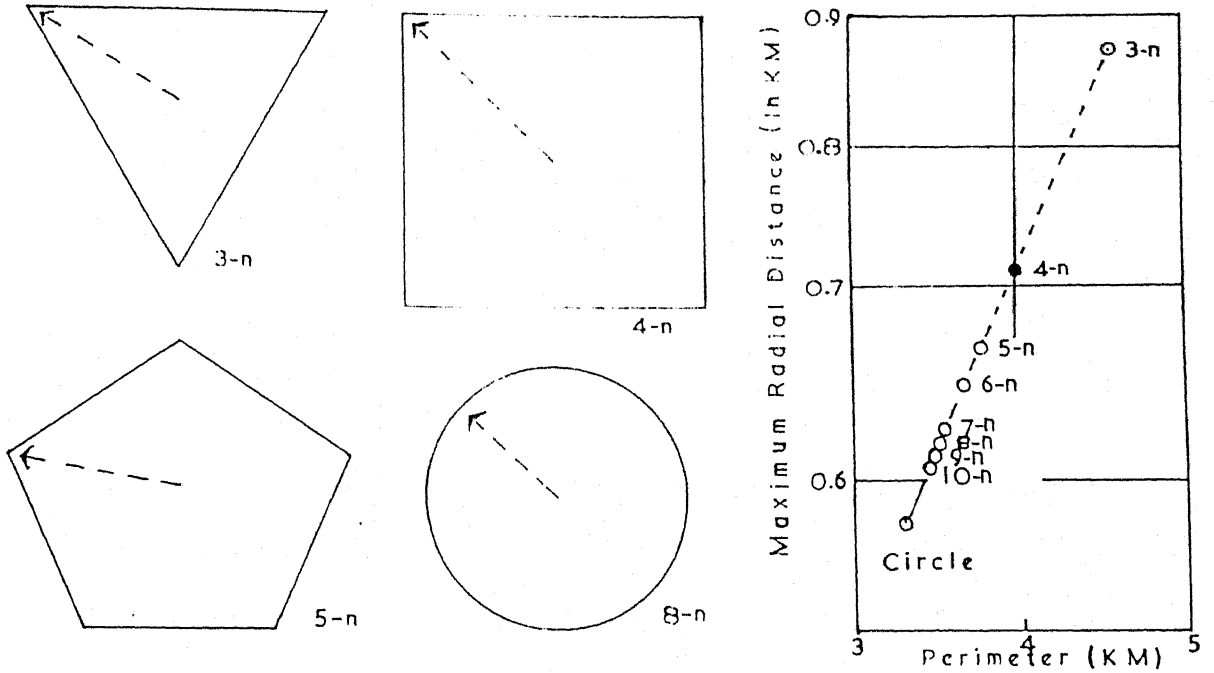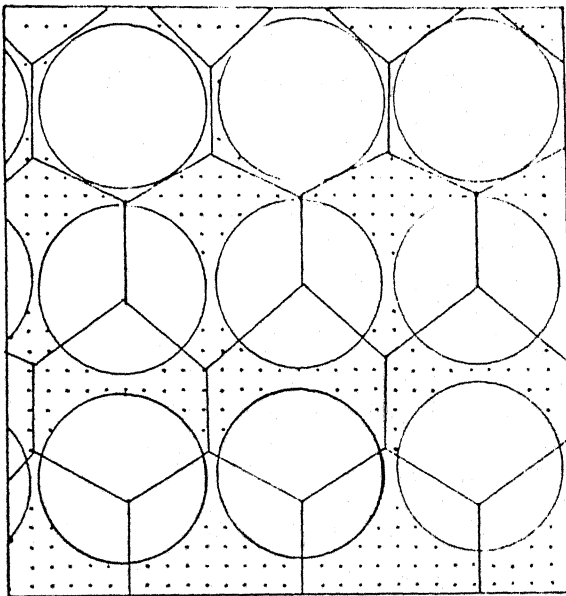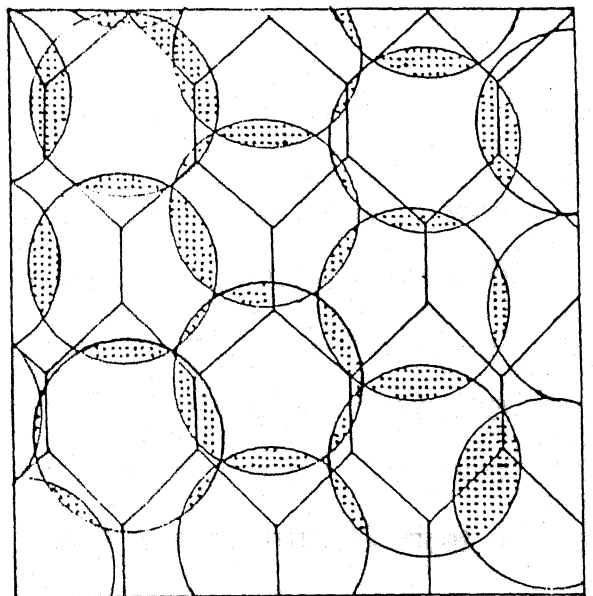
Fig 9.4

अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान में प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर के केन्द्रीय स्थानों का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे सम्पूर्ण ग्रामीण परिवेश को अपनी सेवायें प्राप्त करने में सुविधा हो सके, जनसंख्या सीमांकन विधि और बस्तुओं के विनमय के लिये सूक्ष्म स्तरीय नियोजन में योजनाविदों को पर्याप्त सहायता मिलती है। क्षेत्रीय प्रणाली में कार्यात्मक रिक्तता के निर्धारण के लिये जनसंख्या सीमांकन की संकल्पना की गई है, अधिवास जो अपनी इच्छित कार्य के लिये जनसंख्या सीमांकन कार्यात्मक रिक्तता के साथ अति व्यापक अवस्था प्रस्तुत करता है। इन कार्यात्क नियोजन की रिक्तता व्यापकता को निर्धारित करने के लिये एक सूची बनाकर सेवाकेन्द्रों के पुर्ननियोजन की आवश्यकता है, यह भी देखा गया है, कि अध्ययन क्षेत्र में राजनैतिक कार्य, अराजनैतिक कार्यों को अपनी ओर आकर्षित करते है। अतः कार्यात्मक रिक्तता को द्वितीय विधि द्वारा सीमांकन, कार्यों की दूरी एवं माँग के आधार पर निर्मित होता है। जैसे किसी छोटी बस्ती में किसी विशेष कार्य के लिये उसका सीमांकन नहीं किया जा सकता है और किसी विशेष कार्य के लिये उसकी माँग को सेवाहीन नहीं किया जा सकता है। इस माँग को निकटतम सेवा केन्द्र द्वारा पूरा किया जायेगा जो उस केन्द्रीय स्थान के प्रभाव क्षेत्र में होंगे, सेवा केन्द्रों की कार्यात्मक रिक्तता एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जनसंख्या सीमांकन सूचकांक होती है। प्रथम वर्ग द्वारा निर्धारित की गई है, टीकमगढ़ सूचकांक + 238223·03 कार्यात्मक सेवात्तर सूचकांक है, जिससे प्रथम वर्ग में रखा गया है। यह उल्लेखनीय है कि पहले दूसरे एवं तीसरे सेवा वर्गों में बहुत अन्तर है यह अन्तर इन सेवाकेन्द्रों में कार्याधिक्य एवं विभिन्न सेवा इकाईयों का पाया जाना है क्षेत्रीय रिक्तता इस कारण से कुछ कम हो गई है। किन्तु स्थितिकारक एक मूलकारक है, अतः विभिन्न वर्गो की कार्यात्मक रिक्तता दूर करने के लिये सूक्ष्म स्तरीय नियोजन द्वारा नियोजित विकास पद्धति को अपनाया जाना चहिये, जिससे सेवाकेन्द्र एवं उसके चारों ओर के क्षेत्र के बीच सामाजिक एवं आर्थिक रिक्तता कम की जा सके, क्योंकि कार्यो का अनियमित वितरण प्रदेश को आधुनिक एवं परम्परा वादी पक्षों में विभक्त करता है। अतः क्षेत्रीय कार्यात्मक रिक्तता की भरपाई के लिये नये सेवाकेन्द्रों की स्थापना, संभावित केन्द्रों या स्थानों पर की जानी चाहिए।

---- 0 ----

REFERENCES

1. Rushton, G. and Kohler, J.A. (1973) : Hueriotic Sollution to Multi facilities Location Problems on a Graphs in G. Rushton et. al. (Ed.) Computer Programmes for Location Allocation Problems, Deptt. of Geography, University of Iowa, U.S.A.
2. Singh, O.P. (1968) : Functions and Functional Classes of Central Places in Uttar Pradesh National Geographical Journal of India, Varanasi P :14.
3. Mayfield, R.C. (1967) : Central Place Hierarchy in Northern India, Quantitative Geography Pt.I, PP : 10-15.
4. Singh, O.P. (1971) : Towards Determining Hierarchy of Service Centres : A Methodology for Central Place Studies, National Geographical Journal of India, P-Varanasi P-17.
5. Singh, K.N. (1966): Spatial Pattern of Central Place System in Middle Ganga Valley, National Geographical Journal of India, Varanasi, P-12.
6. Hagget, P. (1970): Locational Analysis of Human Geography Edward Arnald Pub. Ltd., London, P-141.

7. Mishra, G.K. (1972) : Centrality Oriented Connectivity of Road Behavioural Science and Community Development VOL. VI, No.1,P:82.

8. Sundaram, K.V. et. al.(1972) : Spatial Planning for Tribal Region; Area study of Baster District (M.P.) Institute of Development Studies University of Mysore, P:40.

9. Christaller, W. (1933): Die Zentration Orte in Suddent Schland, Translated by C.W. Baskin (1966) : in the Central Places of South Zermany, Englewood, Cliffs.

10. Green, F.H.W. (1948) : Motor Bus Services in West England, Transactions, Institute of British Geogrphers-14, PP: 59-68.

11. Brush, J.E. and Bracey, H.E. (1967): Rural Service Centres in South Western Wisconsin and Southern England in Urban Geography. Edited by H.M. Mayer and C.F. Kohin, Allahabad, P : 213.

12. Godlund, S. (1956) : The Functions and Growth of Bus Traffic within the sphere of Urban Influecne, Land Studies in Geography, Series B, No. 18, PP: 13-20.

13. Tiwari, R.C. (1980): Spatial Organisations of Rural Service Centres in Pratapgarh

District National Geographer, No. XIX, 2, PP : 88-96.

14. Singh, K.N. et. al. (1985) : Service Centres and Development Strategy in Vindhyachal Baghalkhand Region : A Spatial and Functional Approach. The National Geographical Journal of India, Varanasi, Vol. XXXI, Pt.2, P : 73.

15. Sen, L.K. et. al. (1975) : Growth Centres in Raichur : An Integrated Area Development Plan for a District of Karnataka, NICD, Hyderabad P : 124.

16. Mishra, R.P., Sundaram, K.V. and Prakash Rao, V.L.S. (1976): Regional Development and Planning in India : A new Strategy, Vikas Publishing House, New Delhi, P : 202.

17. Green, F.H.W. (1948) : Op. cit. PP: 59-68.

18. Tiwari, R.C. (1980) : Op. cit. P-94.

19. Bracy, H.E. (1953) : Towns of Rural Service Centres, An Index of Centrality with Special Referecne to Somersett, Transaction, 19. PP: 95-105.

20. Wanmali, S. (1972) : Zones of Influence of Central Villages in Miryalguda Taluka : A Theortical Approach, Behavioural Science and Community Development, 6, PP : 1-10.

21. Sen, L.K. et. al.(1975) : Op.cit. PP : 140-155.

-0-

अध्याय दस

संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिये सेवाकेन्द्रों की रणानीति

- संतुलित विकास के लिये वृद्धि ध्रुव/केन्द्रों की रणनीति
- अध्ययन क्षेत्र में वृद्धि ध्रुव/केन्द्रों की प्रवेश रणनीति
- सेवाकेन्द्रों के प्रस्तावित पदानुक्रम मॉडल
- सन्दर्भित ग्रन्थों की सूची
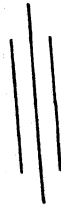
वृद्धिजनक केन्द्रों का स्थानीय विश्लेषण :(SPATIAL ANALYSIS OF GROWTH POLE CENTRES) :

वृद्धि ध्रुव सिद्धांत का प्राथमिक विचार पोस्कोसेविस्की[1] के आर्थिक वृद्धि सिद्धांत (1962), रोस्टोव[2] के सेवा वृद्धि में उत्थान सिद्धांत (1969), क्लार्क[3], तथा सिंह[4] का संचयी परिणामी सिद्धांत तथा हरमेनसेन[5] के असंतुलित वृद्धि सिद्धांत द्वारा मिलता है। वृद्धि ध्रुव सिद्धांत का फ्रांस में उस समय उद्भव हुआ, जब यहाँ आर्थिक विकास मन्द या तथा औद्योगिक विकास में असन्तुलन बढ़ा रहा था। अतः तत्कालीन आवश्यकता अनुसार औद्योगीकरण तथा नगरीयकरण पर विशेष बल देकर किसी प्रदेश को विकसित करने की बात कही गई, परन्तु वर्तमान समय में नगरीयकरण और औद्योगीकरण विकास की शक्ति के साथ गंभीर समस्या बन गया है। स्वस्थ्य औद्योगीकरण की चर्चा भी चल रही है, जिसमें वातावरण को शुद्ध एवं प्रदूषण रहित बनाया जा सके। अतः वृद्धि ध्रुव सिंद्धांत में अन्य कमियों को समाप्त करने के साथ साथ वातावरण की गुणवत्ता बनये रखाने पर भी ध्यान दिया जाना सम्प्रति विचारणीय है।[6]

परिवर्तन वृद्धि ध्रुव की विशेषतायें :

केन्द्रस्थल सिद्धांत के अन्तर्गत वाडबिले ने वृद्धि ध्रुव तथा स्थानिक बिखाराव सिद्धांत को समन्वय के आधार पर वृद्धिजनक केन्द्र की संकल्पना भारतीय परिवेश में मिश्रा[7] द्वारा की गई, इस संकल्पना की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित है -

1. प्रादेशिक विकास ओर नियोजन के लिये चुना गया वृद्धिजनक केन्द्र आकार तथा क्रिया में प्रादेशिक आवश्यकता एवं मापक के अनुसार बदलता है। ऐसे केन्द्रों की संख्या राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा उप प्रादेशिक आर्थिक तंत्र और स्थलाकृति के अनुसार बदलती है।
2. चुने गये वृद्धिजनक केन्द्र लघु-प्रदेश, उससे बड़ा केन्द्र मध्यम प्रदेश और सबसे

बड़ा केन्द्र सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र को सेवा प्रदान करेगा। इनका पदानुक्रम स्तर आर्थिक तर्क संगतता और राजनैतिक विचार के अनुसार वृहत स्तरीय हो सकता है।

3. सबसे छोटे स्तर का वृद्धिजनक केन्द्र सभी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसा- बाजार, मनोरंजन, शिक्षा, विस्तार सेवायें, संचार सेवायें, बैंक, वाणिज्य इत्यादि को एक स्थान पर उपलब्ध करायेगा।

4. सबसे छोटे स्तर के वृद्धिजनक केन्द्र का आकार इतना बढ़ा होना चाहिये कि वह आवश्यक माँग और पूर्ति को पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त यह माँग और पूर्ति के बीच सन्तुलन भी कायम रख सके।

5. छोटे स्तर के वृद्धिजनक केन्द्र पर सिर्फ प्रोसेसिंग और खाद्यान्न सेवओं की पूर्ति के केन्द्र होंगे। जो प्राय: कृषि पर आधारित होंगे। उदाहरणार्थ - चावल, दाल मिल, सब्जी विक्रय और फल संरक्षण।

6. मध्ययम स्तर के वृद्धिजनक केन्द्र पर छोटे स्तर के केन्द्रों की सभी विशेषतायें अधिक मात्रा और गुणों में उपलब्ध होंगी। इनकी वृद्धि अधिकांशत: द्वितीयक बस्तु निर्माण उद्योग जैसे - कपड़ा, चीनी, धातु, मशीन उद्योग इत्यादि पर निर्भर करेगा।

7. मध्यम स्तर के वृद्धिजनक केन्द्र पूर्ण विकसित या नये स्थापित नगर के रुप में स्थापित होंगे। ये केन्द्र वृद्धि अवरुद्ध करने वाली कर्मियों को दूर कर सकने में सक्षम होंगे।

8. मध्यम स्तर के वृद्धिजनक केन्द्र बृहद प्रदेशों को अपनी सेवायें प्रदान करेंगे, परन्तु यदि प्रदेश का आकार बहुत छोटा है तो पूरे प्रदेश में सिर्फ एक वृद्धिजनक केन्द्र ही हो सकता है। ऐसे केन्द्र की वृद्धि सम्भवता तृतीय आर्थिक क्रियाओं से प्ररम्भ होगी।[8]

वृद्धिजनक केन्द्रों का भारतीय दशा में पदानुक्रम :

मिश्रा एवं सुन्दरम[9], प्रकाश राव[10] ने भारतीय दशा में उपयुक्त पाँच स्तरीय वृद्धिजनक केन्द्रों को सुझाया है।

1. स्थानीय स्तर के केन्द्रीय ग्राम।

2. प्रादेशिक लघुस्तर पर सेवाकेन्द्र।
3. उप प्रादेशिक स्तर पर वृद्धि केन्द्र।
4. प्रादेशिक स्तर पर वृद्धि केन्द्र।
5. राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि ध्रुव।

1. **केन्द्रीय ग्राम :**

केन्द्रीय ग्राम अपने चारों तरफ लगभग 6 गाँवों को लगभग 6000 जनसंख्या को सेवा प्रदान करायेगा। यहाँ पर प्राईमरी स्कूल, डाकघर, सहकारी समितियाँ, इत्यादि होंगी। इन्हें इस प्रकार नियोजन करना है कि ये अन्य ग्रामीण बस्तियों को बाजार मनोरंजन और सामाजिक सेवायें प्रदान करने में सक्षम हो।

2. **सेवाकेन्द्र :**

सेवाकेन्द्रों की जनसंख्या औसत रुप से 5000 होगी। ऐसे केन्द्र अपनी जनसंख्या के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बसी 30,000 जनसंख्या को भी सेवायें उपलब्ध करायेंगे। चूँकि भारत में 2001 तक ग्रामीण जनसंख्या में विशेष परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। अतः 90 करोड़ जनसंख्या को सेवा प्रदान करने के लिये 25,000 सेवा केन्द्र विकसित करने की आवश्यकता है। यह सेवाकेन्द्र ग्रामीण नगरीय सुविधा समुदाय होंगे। इन सेवाकेन्द्रों पर निम्न सेवायें सुझायी गई हैं।

बाजार :

परचून की दुकानें, मरम्मत की सुविधा, दर्जी एवं नाई की दुकान, रेस्टोरेंट, विपणन समूह आदि।

आधारभूत सेवायें :

प्राईमरी और मिडिल स्कूल, उप डाकघर, सहकारी बैंक, अन्य बैंक कृषि विस्तार सेवायें, समुदाय केन्द्र के साथ यहाँ पर ऐसे अधिकारी भी होगें जो उपरोक्त संस्थाओं द्वारा प्राप्त सेवा क्षेत्रों की योजना प्राप्त कर सकेंगे।

प्रोसेसिंग क्रिया कलाप वाले केन्द्र :

चावल मिल, आटामिल, फल संरक्षण केन्द्र तथा कृषि पर आधारित अन्य इकाईयों ऐसे सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध ऐसी क्रियायें कृषि उत्पादों पर आधारित होंगी जो प्रत्येक केन्द्र पर भिन्न-भिन्न भी हो सकती हैं।

मनोरंजन स्थल :

पार्क, सिनेमाघर, क्लब, नृत्य संगीत, कला कार्यक्रम की सुविधायें ।

3 **वृद्धि बिन्दु :**

प्रत्येक वृद्धि बिन्दु लगभग 5 सेवा केन्द्रों को सेवा प्रदान करेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को सेवा उपलब्ध करायेंगे। वृद्धि बिन्दु की अपनी जनसंख्या 10,000 से 25,000 के बीच होगी। इन बिन्दुओं का स्तर कस्बा जैसा होगा। प्रत्येक वृद्धि बिन्दु 300 गाँवों को सेवा उपलब्ध करायेंगे। मिश्र एवं सहयोगियों के अनुसार यदि 4000 वृद्धि बिन्दुओं का विकास संसाधनों की कमी के कारण एक साथ संभव न हो तो उनको कई चरणों में विकसित किया जा सकता हैं।[11] वृद्धि बिन्दु उपप्रादेशिक स्तर पर नवीन कार्यक्रम और विकास को पहुँचाने वाले नरीय केन्द्र होंगे। ये सभी मौसमों में अन्य बिन्दुओं से राजमार्गों एवं सेवाकेन्द्रों से जुड़े होंगे। उत्खानन तथा कृषि पर आधारित उद्योगों में ये केन्द्र विशिष्ठता प्राप्त होंगे। उत्खानन के क्षेत्र में से खनिजों पर आधारित उद्योगों को समाहित करेंगे। इन केन्द्रों में प्रमुख क्रिया कलाप कृषि और डेयरी उत्पाद से सम्बन्धित होकर उत्पादन एवं व्यवसाय से भी मिलेंगे। वृद्धि बिन्दु अपने प्रदेश में उत्खानन, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य अन्तर्क्रियाओं में समन्वय का काम भी पूरा करेंगे। प्रत्येक बिन्दु पर पुलिस स्टेशन, विस्तार सेवाकेन्द्र, डाकघर, बैंक, बाजार, जूनियर हाईस्कूल, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाओं एवं मशीनों के विक्रय केन्द्र यथा ट्रेक्टर, लिफ्टपम्प, ट्रक, मोटर साईकिल आदि की मरम्मत करने वाले प्रतिष्ठान भी इन सेविक क्षेत्रों के मूल अंग होगें।

4 **वृद्धि केन्द्र :**

प्रत्येक वृद्धि केन्द्र के प्रभाव में आठ वृद्धि बिन्दु स्थित होगें। इन केन्द्रों
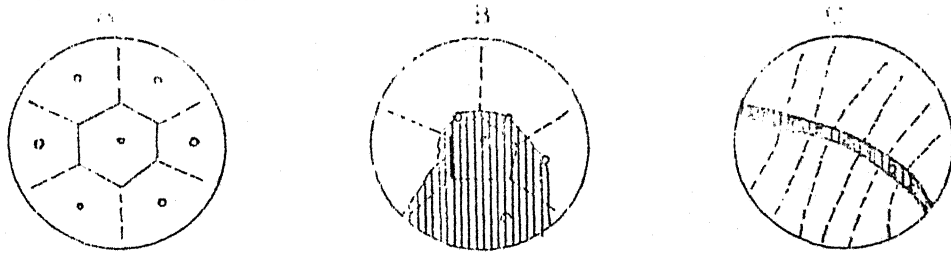
SEQUENCE OF SERVICE CENTERS PATTERNS ASSOCIATE WITH AN INCREASINGLY LOCACIZED RESOURCES
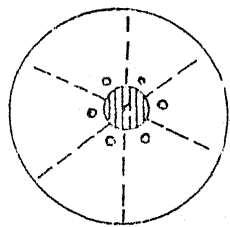
A÷ UNIFORM RESOURCES
B- ZONAL RESOURCES
C- LINEAR RESOURCES
D- Point Resources.
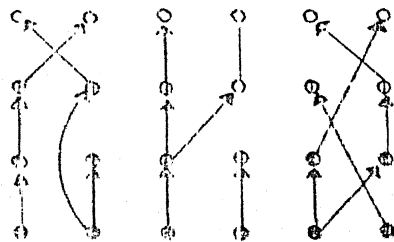
SERVICE CENTRES DIFFUSION MODEL
(A Hypothetical Case)
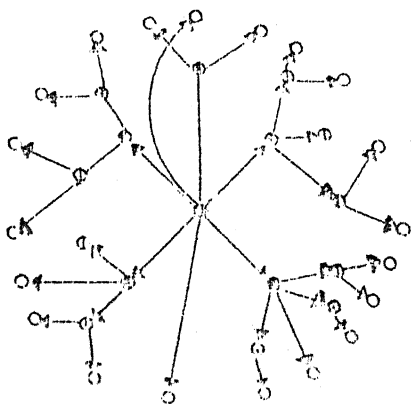
Mother Settlements
Ist Stage
2nd Stage
3rd Stage

D
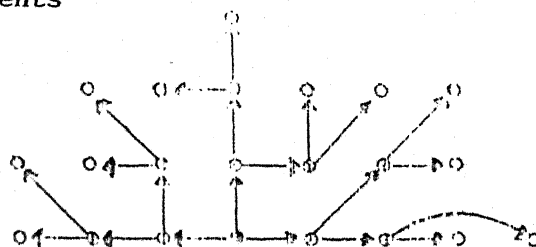
Source - BYLUND 1960

Fig 10.1

का सुदृढ़ आधार वस्तु निर्माण होगा। इनमें मुख्यतः द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण होगा। कृषि कार्य से बचे श्रमिकों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा जो वृद्धि बिन्दुओं पर उपलब्ध नहीं हैं। वृद्धि केन्द्र प्रदेश में औद्योगिक अभिकेन्द्र के रुप में कार्य करेगें। ये केन्द्र कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण, भण्डारण, तथा प्रोसेसिंग भी करेगें। कृषि से संबंधित आवश्यकतओं जैसे- खाद, कीटनाशक दवाओं और यंत्रों का उत्पादन भी करेगें। यहाँ रेडियो या टेलीविजन, स्टेशन, बैंक, स्नातक-स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शोध केन्द्र तथा अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हो सकती हैं। प्रत्येक वृद्धि केन्द्र अपने प्रदेश में कम से कम 12 लाख जनसंख्या को सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे।

वृद्धि ध्रुव :

वृद्धि ध्रुवों की जनसंख्या 5 लाख के बीच होगी। प्रत्येक ध्रुव लगभग 2 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या को सेवा उपलब्ध करायेगें। सम्पूर्ण प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाओं की अपेक्षा तृतीयक क्रियाओं का अधिक प्रभाव होगा। ध्रुव बृहत् प्रदेश में वित्तीय, शोध, उच्चतम् शिक्षा तथा दवाओं की पूर्ति के लिये यहाँ चतुर्थक क्रियओं का भी आविर्भाव होगा।

वृद्धि ध्रुव नीति हेतु आपरेशन डिज़ाइन :

किसी प्रदेश में वृद्धि ध्रुव की नीति मानव समूह के वर्तमान एवं भावी आवश्यकतओं, उनके आर्थिक तंत्र तथा स्थानिक व्यवहार के आधार पर बनाई जाती हैं। स्थानिक व्यवहार समाजिक-आर्थिक संदर्भ में मनुष्यों, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से निर्धारित होता है। वृद्धिजनक केन्द्रों में चुनाव के लिये कम से कम 15 वर्षों के अन्तराल में विकास के स्वरुप पर दृष्टिपात करना आवश्यक होता है। ये यातायात के शीर्ष बिन्दु पर स्थित होने चाहिये। इन केन्द्रों में सम्बन्धित सर्वाधिक महत्वपूर्ण रुप से यह निर्धारित करना होगा कि सेवा प्राप्ति हेतु कितनी दूरी, किस स्थान और किस साधन से लोग ऐसे केन्द्रों पर आयेंगे।

वृद्धि केन्द्रों पर उपलब्ध व्यापार की मात्रा वहाँ पर भ्रमण करने वालों की संख्या एवं प्रतिरुप तथा मनुष्यों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृद्धि केन्द्रों के चुनाव के लिये निम्न तथ्यों का विश्लेषण विचारणीय है-

1. मनुष्यों के भ्रमण व्यवहार की रुपरेखा।
2. किस तरह की सेवायें तथा उद्योग किस केन्द्र पर कितनी मात्रा में विकसित करना है तथा वर्तमान समय में ये कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं।
3. 10 या 20 वर्षों के अन्तर्गत आर्थिक तंत्र में कैसा परिवर्तन संभावित है और तीव्र विकास हेतु किन अवस्थापनाओं की कितनी आवश्यकता है।
4. समुदाय का अधिकतम आधार क्या है तथा वह कितनी सेवाओं और उद्योगों को विकसित कर सकता है। कितने उत्पादों के लिये माँग उपलब्ध एवं निवेशों को कितनी आपूर्ति चाहिये। वृद्धिजनक केन्द्रों की पहचान निम्न विधि द्वारा की जाती है-

क. प्रवाह प्रतिरुप की जाँच ।

ख. प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों पर क्रियाओं एवं सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर उनका अंक निर्धारित किया जाता है। जिस केन्द्र का जितना अधिक अंक होगा वह उतना ही अधिक उपयुक्त बनेगा।

ग. प्रत्येक नगर की जनसंख्या एवं वृद्धि दर का अवलोकन भी होना चाहिये। तीव्र या मन्द विकास के कारणों का ज्ञान भी आवश्यक है।

घ. प्रादेशिक औद्योगिक संसाधन, वस्तुओं की माँग किन विशेष उद्योगों को प्रोत्साहित करना उपादेय होगा, इन तत्वों का विश्लेषण भी आवश्यक है।

ङ. दो या तीन स्थितियों का चयन जिनमें से राजनैतिक प्रक्रियाओं के आधार पर अंतिम चुनाव किया जा सके।

वृद्धिजनक केन्द्रों के नियोजन द्वारा पिछड़े प्रदेशों को विकसित करना अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी उपागम है, परन्तु यह सरल कार्य नहीं है। वृद्धि जनक केन्द्रों का नियोजन इस तरह होना चाहिये जो राष्ट्रीय आवश्यकतओं और प्रादेशिक माँग में संतुलन स्थापित कर सके। इन केन्द्रों का नियोजन निम्न चार चरणों में किया जा सकता है-

1. प्रथम चरण में राष्ट्रीय आर्थिक तंत्र के प्रादेशिक स्वरुप का अध्ययन होना चाहिये। उपलब्ध वृद्धिजनक केन्द्रों तथा सम्भावित केन्द्रों की पहचान प्रत्येक स्तर पर की जानी चाहिये।

2. राष्ट्रीय योजना को दृष्टिगत रखाते हुए राष्ट्रीय उद्देश्य एवं लक्ष्य के संदर्भ में प्रत्येक प्रदेश एवं उसके वृद्धिजनक केन्द्रों की भूमिका निर्धारित की जानी चाहिये, निवेश की लागत और उसमें प्रत्येक मिलने वाले लाभ भी अंकित होना आवश्यक है।

3. राष्ट्रीय योजना के प्रत्येक खाण्ड या सेक्टर का प्रादेशिक आवश्यकता के संदर्भ में अध्ययन होना चाहिये। यदि संसाधम सीमित हैं, जिससे प्रत्येक सम्भव्य केन्द्र पर पूँजी निवेश नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे कुछ केन्द्रों का पहले चुनाव किया जाना चाहिये जो प्रत्येक प्रदेश का प्रतिनिघत्व कर सकें। इन केन्द्रों पर आवश्यक क्रियओं और सुविधाओं को निश्चित करना भी महत्वपूर्ण कदम है।

4. पूँजी निवेश करने के साथ ही योजनाओं की उपलब्धियों का परीक्षण भी करते रहना चाहिये। भविष्य की योजनओं का सामंजस्य भी करना आवश्यक है।

सन्तुलित क्षेत्रीय विकास हेतु रणनीति :

सन्तुलित विकास, सामाजिक, आर्थिक, आधारभूत संरचना, सम्पूर्ण समाजिक आर्थिक पक्षों और क्षेत्रीय योजनाओं को सम्मिलित करती हैं, जिसके द्वारा समाज के सामाजिक, आर्थिक सुविधाओं के प्रावधान समझाये जाते हैं।[12] भारत में वर्तमान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आवश्यक विकास कार्यक्रम है, जिससे सामाजिक, आर्थिक, प्रगति सम्भव होती है तथा

Model For
Spatio-Functional Organization Of Central Place
And
Balanced Regional Develoment
Area
Micro Level
Meso Level
Micro Level
Base Time
Space System
Rural Urban Continuum
Rural
Urban
Base Time
Function System
Retail Services
Ext-Services
Trade
Finance
Industry
Transport
Communication
Health
Education
Space Function Interaction
Distance
Over Size
Sud Standard
Settlement Type
Settlement Size
Settlement Rank
Man Power
Resources
Function Type
Function Size
Function Rank
Functional Gap
Under Size
Poor Ranking
Distance Minimization
Size Of Timization
Standardization
Population Control And Management
Ecological Balance Environmental Control And Management
Gap Filling
Addition And Synthe Sization
Rational Coordination
Feed Back
Feed Back
Feed Back
Feed Back
Spatio Functional Organization
Of Central Places
Time I
Time II
Time III
Balanced Regional Development
After R.N. Singh
Bases, Factors Of Integration And The Limitations Of The Concept Of Balanced Regional Development
Three Dimensional Concept Of Balanced Regional Development
Organizational Factor
Growth Factor
Transport Factor
Market Factor
Social
Economic
Spatial
Timal
Functional
Integration
Balanced Regional Development
Limitations
Bases
Selectivity
Decentralization
Want Of Planners
Problem Of Boundary Adjustment
Irrational Local Welfare
Inadequate Research
Least Knowledge
LEVELS
Macro Region
Meso Region
Micro Region
SECTIONS
Rural Artisans
Marginal Farmers
Small Farmers
Landless Labourers
Scheduled Tribes
Scheduled Castes
Agriculture
Industry
Health
Education
Transportation
Mining Forestry
SECTORS

Fig 10.2

व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने में सहायक होती है।[13] कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है -

1. समजिक सेवाओं की दूरियों में कमी करना।
2. प्रत्येक सामाजिक सुविधा पर जनसंख्या के दबाव को कम करना।
3. राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का प्रतिपादन करना।
4. गुणात्मक सामाजिक संरचना परिवर्तन में व्यक्तियों का सक्रिय योगदान आदि।

समन्वित क्षेत्रीय विकास योजना सामाजिक और आर्थिक विकास की अनियमितताओं को समाप्त किये बिना सफल नहीं हो सकता। वर्तमान भारतीय समाज में विडम्बना यह है कि स्कूल शिक्षा के लिये और अस्पताल स्वास्थ्य के लिये पूर्णतः अपर्याप्त हैं। अतः सुविधाओं को प्रदान करने के लिये तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए, किन्तु सामाजिक, आर्थिक, कार्यक्रम को प्रस्तावित योजनओं के साथ तत्काल लागू की जायें, जिससे क्षेत्रीय वितरण की रिक्तियों को पूरा किया जा सके। किन्तु इन प्रस्तावित योजनाओं का लाभ कमजोर वर्गों को प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसमें समाज के स्वरुप को बदलने में अधिक समय और कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यक्तिगत एवं शासकीय संस्थाओं, को चाहिए कि कमजोर वर्गों की सहायता कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ग्रहीतों को उससे होने वाले लाभों से परिचित कराकर उन तक पहूँचाने का प्रयास करें। माडल क्र. 10.1 में संतुलित विकास की अवधारणा को सिद्ध किया है। जिस में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बाजार, विद्युत आपूर्ति, विस्तार सेवायें और साख सुविधाओं का सन्तुलित सामाजिक, आर्थिक, आधारभूत संरचना निर्मित करने के लिये यहाँ सुझाव प्रस्तुत किये गये जिनका विश्लेषण निम्नानुसार है।

शैक्षणिक योजनायें :

एक दशक से पूर्व से आर्थिक विकास की योजनओं के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में अनेक समस्यायें रहीं हैं। जिनमें निर्धनता, शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी प्रमुख है।

दूसरे शब्दों में क्षेत्र के समग्र विकास के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ अनिवार्य शिक्षा को सर्व प्रमुख आवश्यकता है।[14] अतः शिक्षा के विकास के लिये उन समस्त कार्यक्रमों को अपनाया जाना चाहिए, जो समाज के नवीन स्वरुप को प्रस्तुत कर सकने में सक्षम हो तथा जिससे स्थानीय शिक्षित संस्कृति और विकसित सामाजिक वातावरण का विकास हो सके, हमारी शिक्षा योजनाओं का व्यय मात्रात्मक कार्यों पर निर्भर करता है। अभी तक क्षेत्रीय योजनाओं में परम्परागत शिक्षा के अतिरिक्त योजनाओं को उपयुक्त महत्व प्रदान नहीं किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में एक ओर जहाँ शिक्षा संस्थाओं की बहुत ज्यादा कमी है। वहीं दूसरी और वर्तमान में क्षेत्रीय वितरण में यह संस्थायें असंतुलित तस्वीर प्रस्तुत करती है।[15] टीकमगढ़ जिले में साक्षरता 19.16 प्रतिशत है; जो शासन की दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति का परिणाम है। यहाँ परम्परागत शिक्षा तो प्राप्त है। किन्तु स्त्री शिक्षा की कमी, तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षा संस्थाओं की कमी के कारण बेरोजगारी समस्या बीभत्स रुप धारण करती जा रही है।

शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिये ब्यूह रचना :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित संस्थाओं के विकास के लिये शैक्षणिक सुविधाओं का विकास अपरिहार्य है। जिससे भविष्य में क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। अध्ययन क्षेत्र में कम से कम इस कार्यक्रम के लिए सुझाव दिया जाता है कि 150 कि.मी. के अन्तर्गत प्राईमरी स्कूल होना चाहिए, प्रत्येक पाँच कि.मी. पर पूर्व माध्यमिक स्कूल और 8 कि.मी. पर हाईस्कूल होना चाहिए। योजना आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय रिक्त स्थानों जनसंख्या सीमाकन द्वारा न्यूनतम आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय स्थिति के सुझाव दिये गये हैं।

प्राथमिक पाठशालायें :

प्राथमिक पाठशालाओं की समुचित स्थिति के निम्नलिखित सुझाव दिये जाते है-

1 1.5 कि.मी. की दूरी पर प्रत्येक बस्ती में कम से कम एक प्राथमिक

पाठशाला अनिवार्य रुप से हो।

2. यदि बस्ती 1.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर हो और उस बस्ती की जनसंख्या कम से कम 300 हो तो वहाँ प्राथमिक पाठशाला होना अनिवार्य है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय :

1. प्रति 5 कि.मी. की दूरी पर प्रत्येक बस्ती में एक पूर्व माध्यमिक पाठशाला की स्थापना की जाए।
2. एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली प्रत्येक बस्ती में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनिवार्य रुप से हो।

हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज :

हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज के प्रस्ताव के लिये निम्नलिखित उपाय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित हैं - सामान्य केन्द्रीय स्थान योजना को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। समय और मूल्य दूरी के आधार पर भौतिक दूरी तैयार की जानी चाहिए। अध्ययन क्षेत्र में -

1. प्रत्येक बस्ती में 8 कि.मी. की दूरी पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए।
2. 2500 से अधिक जनसंख्या वाली प्रत्येक बस्ती में एक माध्यमिक विद्यालय हो।
3. तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की केन्द्रीय बस्तियों में इण्टर कालेज खोले जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त संयुक्त विद्यालयों, जैसे - प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं को माध्यमिक, तथा माध्यमिक विद्यालयों को इण्टर कालेज के साथ कार्यशील हों, जिससे अधिक व्यय को रोका जा सकता है।

परम्परा से हटकर शिक्षा की अध्ययन क्षेत्र में प्रबलतम सम्भावनायें हैं, क्योंकि प्रचलित पद्धति (शिक्षा) के कारण यहाँ परम्परा से हटकर शिक्षा का विकास कम से कम हुआ है, यही कारण है कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के बाद भी अध्ययन क्षेत्र में नगण्य लोग उक्त केन्द्रों में शिक्षा हेतु जाते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण शिक्षा में लोगों की रुचि नहीं रहती है, इसके साथ ही यहाँ बहुत सी संख्या में आज भी अनुसूचित जनजातियों के बच्चे

अशिक्षित हैं। अनुसूचित जाति कि लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं हैं। अतः प्राथमिक पाठशालाओं में अपने बच्चों को प्रवेश नहीं दिलाते हैं। यद्यपि इनके लिये शासन ने शिक्षा को प्रदान करने के लिये निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की है साथ ही अन्य आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था को उन समस्त जातियों के लोगों पर लागू किया जाना चाहिए, जिनकी आय 3000 रुपये वार्षिक से कम है। सीमांत कृषकों एवं कृषि मजदूरों तथा भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। परम्परा से हटकर शिक्षा के विकास की अध्ययन क्षेत्र में बहुत सम्भावनायें हैं -

1. 10 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को अलग-अलग शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
2. 15-25 वर्ष की माताओं को इस प्रकार की शिक्षा द्वारा परिचय हो जो अपने बच्चों को समुचित पोषण देने, कुपोषण से बचाने और परिवार नियोजन की सुविधाओं द्वारा विकसित हो सके।
3. युवक कृषकों, जिनकी उम्र 15-35 वर्ष हो अच्छे किस्म के बीजों के चयन को जानने, उर्वरकों की आवश्यकता को समझने, फसल चक्र की क्रिया को समुचित रुप से अपनाने और मशीनों के उपयोग का ज्ञान शिक्षा द्वारा प्रदान किया जाना चाहिये।
4. 35 से 50 वर्ष के प्रौढ़ पुरुषों तथा 25 से 50 वर्ष की प्रौढ़ महिलाओं को अलग-अलग कक्षा में क्रियात्मक साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाना चहिये। उन उपयोगी बातों को बताया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें और शिक्षा का समुचित लाभ ले सकें।

स्वास्थ्य :

स्वास्थ्य के लिए योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय और कार्यात्मक स्तर पर समन्वित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। क्षेत्र के स्वास्थ्य के अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिये सर्वाधिक प्रचलित बीमारियों जैसे- बुखार, मलेरिया, हैजा, टी.बी. आदि की रोकथाम के

लिए अन्वेषण करने की तत्काल आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषित जल पीने के कारण विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियाँ फैलती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर आज हैजा, टाईफाइड एवं छोटी चेचक पर काबू पा लिया गया है। अब ये बीमारियाँ पूरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करतीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ इनका प्रकोप रह गया है उसे निरंतर क्रियाओं द्वारा समाप्त करने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव स्वास्थ्य सेवा पद्धति के लिए एक समस्या है। शल्य चिकित्सा की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों अभी भी किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण निवासियों को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती है; तब कहीं उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिये रणनीति :

स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे -प्रतिरोधक दवाईयाँ, परिवार नियोजन कार्यक्रम, पोषण और गम्भीर बीमार व्यक्तियों को बड़े अस्पतालों में भेजने की सुविधा आदि को उच्च स्तर के केन्द्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के आधार पर लिया जाना चहिए। अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाये जाने पर बल दिया जाता है।

1. प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मण्डल में 2000 तक एक सवास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाना चाहिए।
2. सन् 2000 तक ही मैदानी क्षेत्रों में 2000 जनसंख्या वाले कस्बे अथवा नगर में या पर्वतीय क्षेत्रों में 1500 जनसंख्या वाले कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का होना अनिवार्य है।
3. सन् 2000 तक 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में एक स्वास्थ्य सुधारक समिति होनी चाहिये।
4. स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्वपूर्ण विशलेषण में अथवा राष्ट्रीय स्तर पर सुझाये

गये कार्यक्रमों में निम्नलिखित तीन स्वास्थ्य उपचार पद्धतियों का विकास किया जाना चाहिये।

क. वर्तमान समय में टीकमगढ़ नगर के अस्पताल को विकसित करके मेडीकल कालेज के रुप में परिवर्तित किया जाना चाहिये। पैडिमारिक, रेडियोलॉजी, अनस्थिमोलॉजी, सघन चिकित्सा यूनिट, ब्लड बैंक एवं कृत्रिम गुर्दा मशीन की सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही ब्लाक खण्ड स्तर पर जिला अस्पतालों जैसी सुविधा मुहैयाॅ कराई जानी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित कर परिवार नियोजन सुविधा केन्द्रों में परिणित किया जाना चाहिए, जिनमें कम से कम 25 शैयायें हों। गाँव के उन बीमारों को जो आसानी से यात्रा नहीं कर सकते हैं, उन्हें गाँव में ही उचित व्यवस्था कर उपचार प्रदान किया जाए, साथ ही उनको स्वास्थ्य केन्द्रों तक ले जाने की सुविधा प्रदान की जाये। अतः प्रत्येक गाँव में महिला और पुरुषों के लिये कम से कम पाँच बिस्तरों वाली शैयाओं की व्यवस्था हो।

ख. प्रत्येक केन्द्रीय ग्राम उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्रसव केन्द्र और परिवार नियोजन सुविधाओं की सेवाओं का लाभ प्राप्त होना चाहिए।

ग. प्रत्येक बस्ती में एक स्वास्थ्य सुधार समिति की स्थापना होनी चाहिए। तथा प्रत्येक गाँव में प्रशिक्षित दायी की भी सुविधा होनी चाहिये।

पेयजल की सुविधा :

अच्छे स्वास्थ्य के लिये सुरक्षित एवं विश्वसनीय पेयजल प्रदान किया जाना आवश्यक है। जिससे क्षेत्रीय विकास तेजी से होगा। पेयजल की पूर्ति में हमारा क्षेत्र अनेकों समस्याओं से होकर गुजर रहा है। आज इस कार्य में गम्भीरता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय विकास को उपयोगी दिशा देने के लिये क्षेत्रीय जलपूर्ति विकास कार्यक्रम की योजनाबद्ध सुविधाओं की आवश्यकता है।

अनुमानित पेयजल की माँग :

पेयजल पूर्ति योजना का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

की दर से उपलब्ध होना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम को अपनाकर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। जलपूर्ति की माँग को वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए और जलपूर्ति के स्तर को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 75 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से और 100 लीटर नगरीय क्षेत्रों में प्रदान किया जाना चाहिए।

पेयजलपूर्ति के लिये प्रस्ताव :

टीकमगढ़ जिले में पेयजल की पूर्ति को पुरा करने के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाये जाने चाहिए।

क. जलपूर्ति की योजनाओं को सुरक्षित, नियमित निरीक्षण और वितरण पद्धति के रख-रखाव को बनाये रखाना चाहिए।

ख. अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक कुंए की प्रतिवर्ष सफाई की जानी चाहिए, साथ ही उनमें आवश्यक कीटनाशक दवाईयाँ जैसे - ब्लचिंग पाऊडर आदि डाले जाने चाहिए

ग. पेयजल के लिए निर्मित कुओं के रख-रखाव का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए साथ ही ऐसे कुओं पर एक छत का निर्माण हो, जिससे प्रदूषण से बचा जा सके।

घ. पीने के पानी वाले कुँओं और अन्य कार्यों के उपयोग वाले कुँओं को अलग-अलग होना चाहिए।

च. समय-समय पर इन कुँओं के जल का निरीक्षण होना चाहिए। जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य को विकसित किया जा सके।

छ. क्षेत्र में जल निकास के लिए कच्ची तथा पक्की नालियों का निर्माण किया जाना चहिए। वर्तमान समय में जल निकास की समस्या अत्यंत गम्भीर होती जा रही है।

ज. प्रत्येक आवासीय बस्ती में प्रति 200 व्यक्तियों पर एक हैण्ड पंप लगाया जाना चाहिए।

संचार सेवायें :

अध्ययन क्षेत्र में संचार सेवाओं की कमी है। अतः शासन को चाहिए कि संचार सेवाओं की वृद्धि के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाये जाने चाहियेः-

अ) प्रत्येक 1000 से कम जनसंख्या वाली बस्ती में एक उपडाकघर हो, जिसमें प्रत्येक पोस्ट आफिस में 750 रुपये से अधिक व्यय न हो।

ब) डाक सेवाओं का वितरण बिना डाकघर वाली बस्तियों तक होना चाहिए।

स) प्रत्येक उपडाकघर को टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है।

द) प्रत्येक 1000 की जनसंख्या तक की बस्तियों को बस सेवा प्रदान की जानी चाहिए।

च) टीकमगढ़ नगर को रेलमार्गों से जोड़ा जाना चाहिए।

विद्युतीकरण :

कृषि उद्योग के विकास के लिए शक्ति की सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है। अपर्याप्त और अनियमित विद्युत शक्ति की पूर्ति स्थानीय कृषकों को लघु सिंचाई प्रणाली को अपनाने के लिये हतोत्साहित करती है, क्षेत्र में डीजल एवं जल विद्युत प्रमुख शक्ति के संसाधन है। दुर्भाग्य से दोनों शक्ति संसाधनों की पूर्ति अनियमित और अपर्याप्त है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि को देखते हुए जलशक्ति का उपयोग अधिक लाभदायक है। योजना आयोग की दृष्टि से टीकमगढ़ जिला में विद्युतीकरण के लिये निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित है -

1. वे बस्तियाँ जो वर्ष भर प्रवाहित नदियों के किनारे बसी है, सर्वप्रथम विद्युतीकृत किये जाने चाहिए।
2. क्षेत्र की सभी बस्तियों को विद्युतीकृत किया जाना चाहिए।
3. कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिये सस्ती दरों पर विद्युत प्रदान की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त गैर परम्परागत शक्ति के स्रोतों जैसे - बायोगैस, सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को विकसित किया जाना चाहिए।

बाजार :

समन्वित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की सफलता के लिये बाजार प्रणाली के क्षेत्रीय कार्यत्मक संगठन को संतुलित बनाया जाये। मानव क्रियाओं को विकेन्द्रित करने, ग्रामीण उत्पादों को वितरित करने की सुविधा प्रदान करने तथा अध्ययन क्षेत्र के समग्र विकास की प्रक्रिया बनाये रखने के लिये बाजारों की सुविधाओं को आवश्यक रुप से बनाये रखना चाहिए। मध्यस्थ जनसंख्या सीमांकन सेवा केन्द्र, पद्धति के विचार में निम्नलिखित बाजारों के विकास के नमूने प्रस्तावित हैं -

1. प्रत्येक केन्द्रीय नगर में एक समकालीन बाजार की सुविधा हो।
2. प्रत्येक केन्द्रीय ग्राम में जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है, प्रतिदिन के फुटकर बाजार हों ।
3. प्रत्येक 4000 से अधिक जनसंख्या वाले केन्द्रीय ग्राम में पशु बाजार भी होने चाहिये।

माडल क्रमांक 10.3 में बाजारों की योजना का चित्रण किया गया है।

विस्तार सेवायें एवं साख सुविधायें :

कृषकों के परम्परागत दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की कृषि वितरण सुविधाओं में अपेक्षित वृद्धि करने के लिये जिला कार्याक्रमों के अन्तर्गत शासकीय मशीनरी, क्रियाशील होती है, जिनसे नवीन कृषि आविष्कार और प्रतिरुप सामने आये हैं। आज कृषि उर्वरकों, कृषि उपकरणों, उन्नत किस्म के बीजों को प्राप्त करने के लिये कृषकों को लम्बी

दूरी तक यात्रा करने के लिये बाध्य होना पड़ता है जो सामान्यतः विकास खण्ड कार्यालय में पाये जाते हैं इन सेवाओं को और अच्छे योजनाबद्ध रुप से अपनाये जाने के लिये उद्यम हो जो कृषकों के पास सामान्य पहुँच तक विकसित हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधायें, बढ़ाये जाने से विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकास, कृषि उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य और अन्य प्रक्रियाओं को गति मिलेगी। उसी प्रकार सहकारी समितियाँ कृषि विकास को अध्ययन क्षेत्र में अधिक विकास बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं। वित्तीय समस्यओं को दूर करने के लिये साख सुविधाओं को सामान्य दरों पर ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे इस कार्यक्रम को अपनानें में यहाँ के कृषक तथा कृषि मजदूर रुचि लें, विस्तार सेवाओं और साख सुविधाओं की स्थिति और युद्ध स्तर पर अपनाये जाने के लिये प्रत्येक जनसंख्या सीमांकन के आधार पर प्रत्येक कार्य को सावधानीपूर्वक किया जाये। साथ ही सेवा केन्द्र और इन सेवाओं को प्रत्येक उस व्यक्ति तक शासकीय प्रणाली को सामान्य रुप में पहुँचना चाहिए।

क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक समन्वय के लिये योजनाएं :

क्षेत्रीय समांकलन की अधिवासों के अन्तर्गत कार्यात्मक परिपूर्णतः और अपरिपूर्ण कार्यों की प्रति पूर्ति के आधार पर होती है। कार्यों एवं अकार्यों के विभिन्न भागों के संयुक्तीकरण की पद्धति सम्बन्ध प्रतिरुपों में पाई जाती है, कार्य और बस्तियों दोनों पदानुक्रम के अनुसार एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होती हैं। बस्तियों को कार्यात्मक सहसंगठित बस्तियों के कार्यात्मक पदानुक्रम द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। अतः क्षेत्रीय समन्वय वृद्धि और उन विकसित क्रियाओं जिनमें बस्तियों क्षेत्रीय आधार पर जुड़ी रहती हैं, कि वृद्धि को सूचित करता है, जबकि कार्यात्मक समन्वय समस्त आर्थिक समन्वय और सामाजिक क्रियाओं को संदर्भित करता है, या इंगित करता है तो समुचित क्षेत्रीय ओर कार्यात्मक समन्वय के लिये अधिवासों का पूर्ण विकसित कार्यात्मक प्रतिरुप क्षेत्रीय ओर कार्यात्मक समन्वय के लिये अधिवासों का पूर्ण विकसित कार्यात्मक प्रतिरुप आवश्यक हो जाता है। अतः एक सेवा केन्द्र की योजना का प्रस्तुतीकरण रिक्त कार्यात्मक अवस्थितियों के आधार पर होना चाहिए।

A Model of Spatio-Functional Analysts of A Market Centre
(A) Origin and Development
(B) Temporal & Spatial Location
Society
Culture
Market Place
History
Environment
Man
Tue
Daily Market
Thu
Fri
-Sun-Wed-Sat-
(D) Elements of Layout
(C) Determinants of Market Size
Areal Shape and Size, Morphology Internal Layout of Functions.
Peoples, Number and Tyes of Establishments, Shop openig/opening Days, Goods and Services Numbers of Vehicles.
(E) Functions
(F) Special Charactsristics
Economic, Social, Religious, Administrative, Public Health, Publicity, Recreation and Enter tainment.
Urban or Rural Market, Ethnic Composition of People and Their Nationality, Place of Fair Or Religion, etc.
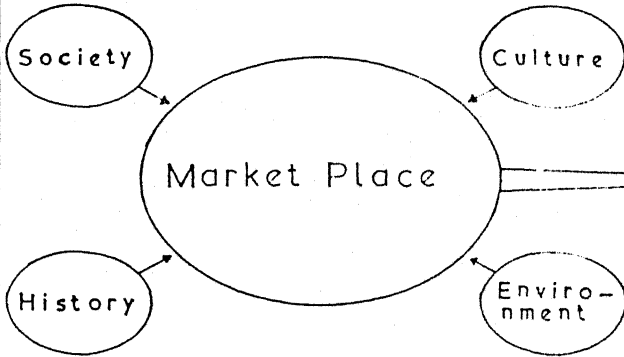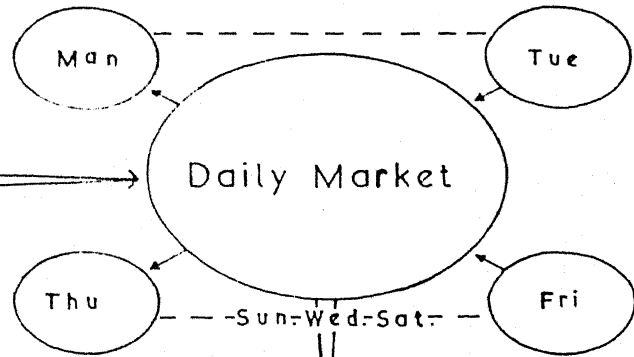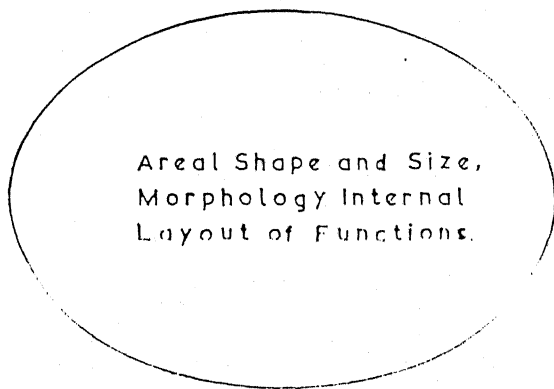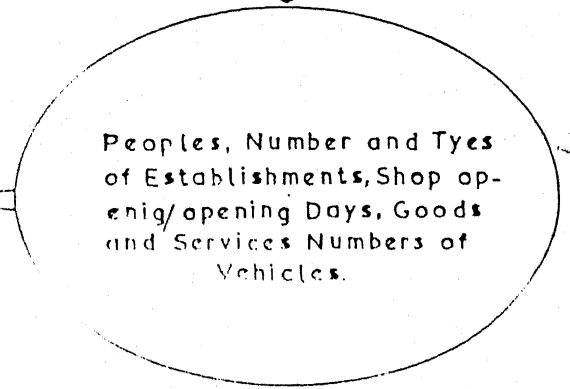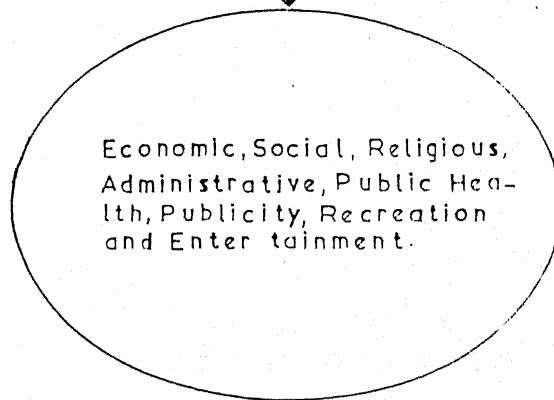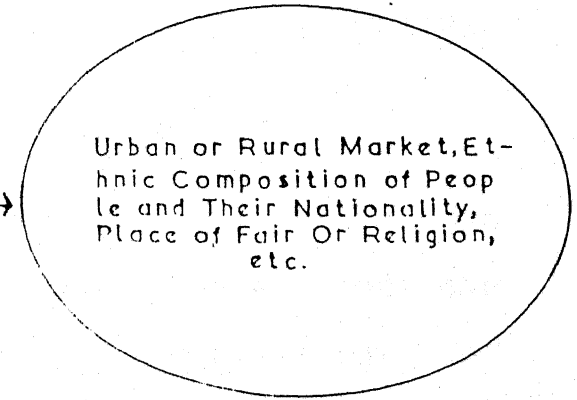
Fig 10.3

निम्नलिखित अवस्थाओं के आधार पर सेवाकेन्द्र योजना को संगठित किया जाना चाहिए।

1. ऐसे उपकार्य के केन्द्रों का चयन जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. सन् 2001 तक सेवाकेन्द्रों के क्षेत्रीय संगठन का प्रस्ताव।

अध्ययन में यह देखा गया है कि क्षेत्र में सेवाकेन्द्र व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः इन केन्द्रों के लिये तत्काल ध्यान देने की योजना प्रस्तावित है। चौथे वर्ग के केन्द्रों में ऐसे केन्द्र जो संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े हो, में सुविधायें प्रदान करने कृषि तथा अन्य क्रियाओं की सेवाएं प्रदान करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। समुचित मात्रा की तथा दूरी के आधार पर उपकेन्द्रों की उपयुक्त स्थिति को अनुमानित बस्तियों के लिये आंकलन किया जाना अपरिहार्य है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले और क्षेत्रीय कार्यात्मक रिक्तयों को कम करने वाले भागों में अच्छी सेवायें प्रदान की जानी चाहिए, जिससे ये केन्द्र सन् 2001 तक उपयुक्त प्रगति कर सकें। प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताओं और आर्थिक स्तर को सम्मिलित करने के लिये अन्य वर्ग के केन्द्रों में वृद्धि न करके, बल्कि वर्गों में अच्छी सुविधायें प्रदान करने के बजाय, क्षेत्रीय कार्यात्मक रिक्तियों को सेवाकेन्द्रों के दृष्टिकोणों से कम किया जाना चाहिए। सभी विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए यह पाया गया हे कि सन् 2001 तक 50 सेवाकेन्द्र प्रस्तावित किये जाते हैं। यह देखा गया है कि वर्तमान प्रणाली में 150 सेवाकेन्द्र हैं, इन समस्त सेवाकेन्द्रों को सम्मिलित करके 2001 तक वृद्धि परम्परा और क्षेत्रीय विशेषताओं द्वारा अन्य सेवाकेन्द्रों का विकास किया जाना चाहिये। परिवहन की आवश्यकता, जनसंख्या वृद्धि और सेवाओं की माँग, न्यून वर्गीय पदानुक्रम में सेवाकेन्द्र शक्तिशाली संकल्पना पर आधारित होना चाहिए।

उपरोक्त अध्ययन क्षेत्रीय संगठन प्रतिरुप विकास की प्रक्रियाओं की स्थानिक पद्धतियों को प्रस्तुत करता है, केन्द्रीय ग्राम के विकास की आवश्यकता के अंतर्गत जूनियर हाईस्कूल शाखा डाकघर, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, प्रार्थना बस स्टाप, साप्ताहिक बाजार, सहकारी साख समितियों, कुटीर और लघु उद्योगो, उर्वरकों के वितरण केन्द्र, उन्नतकिस्म के बीज तथा

कीटनाशक औषधि वितरण केन्द्र, कृषि उपकरण के मरम्मत की दुकानें आदि, इस प्रकार की सेवा इकाईयों औसतन आधार पर हो, जिससे सभी आश्रित ग्रामों का सामान्य परिवहन जालों से जुड़ा होना चाहिए। माडल 10.4 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये इसी संकल्पना को सिद्ध किया गया है।

प्रेरणात्मक पद्धति एवं विकास :

समन्वित क्षेत्रीय विकास का अपेक्षित लक्ष्य तीव्र प्रेरणात्मक पद्धति के बिना संभव नहीं है। प्रेरणात्मक पद्धति को तीव्र बनाने के लिये प्रशासकीय एवं सामाजिक स्तर पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। **कमजोर वर्गों का विकास**, छोटे किसानों, सीमान्त कृषकों और भूमिहीन मजदूर, समाज के गरीब से गरीब लोग है। भूमिहीन मजदूर क्षेत्रीय अर्थतंत्र को बनाये रखने में सहायक होते हैं।

समन्वित क्षेत्रीय विकास का उद्‌देश्य :

इस प्रकार के व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना जो निम्न आय वर्गों में आते हैं। वास्तव में वित्त सुविधायें छोटे और मझोले, भूमिहीन, मजदूरों के लिये उपलब्ध कराई जाती हैं जो स्थानीय आर्थिक और राजनैतिक शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाती है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों के असफल होने के मूल कारण यहीं हैं। क्षेत्रीय समाज के कल्याण के लिये कोई भी कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है, जब शासकीय मशीनरी बिना किसी स्वार्थ के और व्यभिचारहीन हो। अतः लघु सीमांत कृषकों के विकास के लिये एस.एफ.डी.ए. एवं एम.एफ.डी.ए. एजेन्सियाँ निर्मित की जानी चाहिये।

समन्वित क्षेत्रीय विकास को निर्मित करने के लिये राज्य शासन ने कुटीर एवं लघु उद्योग कृषि गृहों का निर्माण और पहूँच मार्गों को बनाये रखने के लिये अनुदान के सहित वित्त की व्यवस्था की है। किसी विशेष जाति या वर्ग ने उक्त कार्य को न अपनाकर समग्र

आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर सभी जाति एवं वर्ग के लोगों को लाभन्वित किया जाना चाहिए, उक्त कार्यक्रम से लाभान्वित व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे उन अधिकारियों एवं बिचौलियों का पर्दाफ़ास करें जो कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों से लाभ लेने की कोशिश करते हैं- टीकमगढ़ जिला में समग्र आर्थिक विकास के लिये निम्न लिखित सुझाव किये जाते हैं-

1. प्रत्येक केन्द्रीय ग्राम में एक सहकारी समिति की स्थापना हो जो निम्नतम व्याज पर ऋण उपलब्ध करा सके।
2. कपड़ों तथा दैनिक उपयोग की बस्तुओं को उत्पादन मूल्य पर प्रदान किया जाना चाहिये और लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित बस्तुओं को एकत्र कर उपयुक्त मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए।
3. स्थानीय भूमिहीन मजदूरों को कृषि कार्य के अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम क़े द्वारा तालाब, सड़कें, सहकारी भवन आदि निर्मित कराये जाने चाहिये।
4. गरीब व्यक्तियों में सामाजिक, आर्थिक जागुरुकता लाने के लिये परम्परागत और गैर परम्परागत शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए।
5. समाजिक संगठन जैसे सतगुरु सेवा संघ और बनवासी आश्रम द्वारा सुविधाएं बढ़ाकर पशु सम्प्रदा और स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित किया जाना चाहिए।
6. बहुजन समाज के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि प्रदान कर कब्जा दिलाना चाहिए।
7. कमजोर वर्गों में स्वागत अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिये मजदूर पद्धति से मुफ्त रखा जाना चाहिए।
8. सांस्कृतिक समन्वय के लिये उनके परम्परागत और उनकी कला को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

वातावरण की गुणवत्ता में वृद्धि :

एक ओर जहाँ उद्योगों की तीव्र, नगरीयकरण और हरित क्रान्ति के लिये त्वरित

आर्थिक विकास नीति की अपनाये जाने की अध्ययन क्षेत्र में तत्कालिक आवश्यकता है, तो दूसरी और प्राकृतिक वातावरण में सन्तुलन स्थापित भी करना चाहिये। जनसंख्या वृद्धि वातावरण को प्रदूषित करने का प्रमुख कारक हैं। जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर, प्राकृतिक संसाधनों की भी माँग करती है इससे मिट्टी, जल वनस्पति आदि संसाधनों पर दबाव बढ़ता है जिससे क्षेत्रीय पारिस्थितिक पद्वति में असंतुलन की स्थिति आती है। वनों की अंधाधुन्ध कटाई रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक एवं जीवाणुनाशक दवाईयों का प्रयोग, सतही एवं भूमिगत जल में दूषितता ऐसे प्रमुख कारक हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति के संरक्षण और सुरक्षा के लिये, पीने के लिये शुद्ध जल एवं भोजन प्रदाय हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों को अपनाया जाना चाहिये-

1. एक निश्चित अनुपात में रासायनिक खादों, कीटनाशक एवं जीवाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग होना चाहिये।
2. अच्छी प्रजाति के पौधों को सड़क तथा बस्तियों के खुले भाग में लगाया जाना चाहिये।
3. स्थानीय व्यक्तियों को मिट्टी, जल और जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिये प्रेरणा देनी चाहिये।
4. समस्त योजनाओं के स्तर को पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
5. विभिन्न क्षेत्रों और व्यक्तियों में असन्तुलन में वृद्धि को रोकने के लिये दोषपूर्ण योजनाओं और प्रयोगों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिये।

कार्य रणनीति :

योजना क्रियाओं राजनीति और प्रशासन में वर्तमान रणनीति के प्रयोजन में कुछ आधारभूत परिवर्तनों की आवश्यकता है, राजकीय पहूँच को सफलापूर्वक उपलब्ध आर्थिक

क्रियाओं के आधार पर पुनः वितरण किया जाये, जिससे सामाजिक एकता को अधिक से अधिक निकट लाकर समाप्त न करना पड़ें। विकास क्रियाओं को कमजोर वर्गो तक पहूँचाने के लिये अविकसित क्षेत्र के परम्परागत समाज को संस्थागत और आधारभूत परिवर्तनों की आवश्यकता है, जिससे उन्हें आर्थिक विकास की सुविधायें प्राप्त हो सके। प्रशासनिक और संस्थागत पुर्ननिर्माणों की आज तत्काल आवश्यकता है, जिससे सामाजिक न्याय प्रस्तुत किया जा सके। वृद्धिजनक केन्द्र की संकल्पना का प्रयोजन प्रादेशिक असन्तुलन, प्रशासनिक और संस्थागत पुर्ननिर्माण पर निर्भर होता है जो कि एकान्त निर्णयों के बनाने और अपनाये जाने पर जहाँ व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।

मानव शक्ति योजना :

अध्ययन क्षेत्र में मानव संसाधन का उपयोग निम्नतम हुआ है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से समुचित स्तर को प्राप्त करने में वह अक्षम रहा है। अध्ययन क्षेत्र में 35.08 प्रतिशत जनसंख्या कार्याशील जनसंख्या के ऊपर जीवन-यापन करती है। इसमें 5 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या एक वर्ष में सीमान्त मजदूरों के रुप में केवल छैः माह के लिये रोजगार प्राप्त कर पाती है। लगभग 25 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या के पास कृषि योग्य भूमि नहीं पायी जाती है। मजदूरों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये कार्य के घंटों का निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कार्य करने की स्थितियों में वृद्धि और अन्य सामाजिक सुरक्षा के कारगर उपाय किये जाने चाहिये। बड़ी संख्या में स्त्रियों को विकासशील गृह और कुटीर उद्योगों में आवश्यक रुप से रोजगार प्रदान किये जाना चाहिये।

शिक्षित नवयुवक, अकार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि करते हैं, इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुविधायें प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। जिला टीकमगढ़ में राष्ट्रीय रोजगार योजना " ग्रामीण युवकों को स्वतः रोजगार प्रदान करने के लिये प्रशिक्षण " को आवश्यक रुप से स्थापित किया जाना चाहिए।

——*——

REFERENCES

1. Pokshishevsky, V.V. (1962): Methods of Research in Economic Geography in Soviet Geography, Accomplishments and Tasks (ii) Ukraine.

2. Rostov, W.W. (1969): The stage of Economic Growth, University Press, Cambridge.

3. Ward, R.G., Clark, N. et. al.(1974): Growth Centres and Area Improvements in the Eastern High land district : A Report to the Central Planning Office, Popua New Guinea, Canberra.

4. Singh, R.L. (1975): Meaning, Objectives and Scope of Settlement Geography, in R.L.Singh and K.N. Singh (Eds.) Readings in Rural Settl-ement Geography, National Geographical Society of India, Research Publication No. 14, Varanasi.

5. Harmansen, T. (1972): Development Poles and Devel-opment Centres in Nainital and Regional Development: Elements of Theortical Frame work, in A. Kuklinsk;(Ed.) Growth Poles and Growth Centres in Regional Planning, Paris.

6. Sen, L.K. et. al. (1975): Growth Centres in Raichur: An Integrated Area Development

Plan for a District in Karnataka, N.I.C.D. Hyderabad.

7. Mishra, R.P. et. al. (1985): Rural Development Capitalists and Socialists Packs, Vol.1, Concept Publication Companny, New Delhi.

8. Mishra, R.P. and K.V. Sundaram (1979): Regional Development and Planing in India: A New Strategy, Vikas Publishing House, Pvt., Ltd., New Delhi.

9. Mishra, R.P. and K.V. Sundaram (1980): Multi Level Planning and Integrated Rural Development in India, Heritage Publications, New Delhi.

10. Prakash Rao, V.L.S. et. al. (Eds.) (1976): Regional Planing and Development, Golden Jubilee Volume, Indian Geographical Society, Dept. of Geography, University of Madras.

11. Sharma, A.N. (1983): Spatial Approach for District Planning: A case study of Karnal, Concept Publishing Companny, New Delhi.

12. Mishra, G.K. and Amitabh Kundu (1980): Regional Planning at the Micro Level: A study for Rural Electrification in Bastar (Chhatti-arh Region), Indian Institute of Publicat-

ion Administration, New Delhi.

13. Chandra Shekker, C.S. (1972): Balanced Regional Development and Regions, Census of India, Monograph No.7, New Delhi.

14. Bose, A.N. (1970): Institutional Bottleneck; The Main Barrier to the Development of Backward Areas, Indian Journal of Regional Science Vol. II No.1.

15. Tripathi, R.N. et. al. (1980): Block Plan in District Frame : A Development Plan for Madakastra Block in Anantpur District, Andhra Pradesh, N.I.C.D., Hyderabad.

----0----

अध्याय ग्यारह

सारांश एवं संस्तुतियाँ
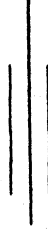
सारांश एवं संस्तुतियाँ : (SUMMERY AND CONCLUSION) :

अध्ययन क्षेत्र की स्थिति मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिम में हैं। बुन्देलखण्ड उच्च भूमि के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ियों एवं पठारों पर स्थित हैं, इसके उत्तर पश्चिम में बेतवा नदी, पश्चिम में जामनी नदी एवं पूर्व में धसान नदी प्रवाहित हो रही है। जिला टीकमगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 5048 वर्ग कि.मी. हैं एवं जनसंख्या (1991 के अनुसार) 9,40,609 व्यक्ति है। प्रशासनिक दृष्टि से क्षेत्र में 5 तहसील मुख्यालय, 6 ब्लाक खण्ड मुख्यालय, 17 राजस्व निरीक्षक मण्डल मुख्यालय, 295 पटवारी हल्का, 869 ग्रामीण बस्तियाँ, 12 नगरीय बस्तियाँ एवं 123 आबाद ग्राम हैं।

अध्ययन क्षेत्र के प्रथम अध्याय में क्षेत्रीय कार्यात्मक विश्लेषण की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ नगरीयकरण एवं समग्र विकास पर बल दिया गया है। इस क्षेत्रीय कार्यात्मक विश्लेषण में सेवाकेन्द्रों का विशेष महत्व हैं, क्योंकि यही केन्द्र एक शहर, नगर, कस्बे और बाजार के रुप में अपनी आन्तरिक जनसंख्या की मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ कार्य अपने चारों ओर स्थित क्षेत्रों के लिये भी करते हैं। सेवाकेन्द्र के रुप में न केवल नगरीय वरन् ग्रामीण बस्तियाँ भी कार्य करती हैं। इन की उत्पत्ति तथा विकास के आधार के साथ ही नियंत्रक कारक भी बताये गये हैं। केन्द्र स्थलों की संकल्पना में प्रत्येक अधिवास, का आकार, मात्रा की केन्द्रीयता या प्रभाव उनके आकार से मेल नहीं खाता है। अतएव विभिन्न अधिवासों या केन्द्रों की क्रियाओं के पदानुक्रम का विश्लेषण आवश्यक होता है। इसके पश्चात् स्थानिक संगठन की रणनीति पर ध्यान दिया गया है, जिसमें ग्रामीण कृषि आर्थिकी का पक्ष विकास के क्रियाकलाप को मूल आधार प्रस्तुत करती हैं। वृद्धि केन्द्र संकल्पना का आधार होती है। सेवित क्षेत्रों की 'वृद्धि' मानव के कल्याण के लिये प्रयोजनीय होती हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि प्रणाली को परिवर्तन करता हैं। विकास की रणनीति में यह उपागम परिवर्तित प्रभावों की उच्च सम्भावना आदि

प्रस्तुत करती है। इस संकल्पना का उद्‌देश्य अधिवासों, जनसंख्या, आर्थिक क्रियाओं, सेवाओं सुविधाओं तथा बाह्‌य संबंधों का विशिष्ट प्रतिरुप तैयार करना साथ ही संसाधनों की प्राप्ति के अनुसार उसके समुचित उपयोग की योजना प्रस्तुत करना है।

द्वितीय अध्याय अन्तर्गत भौगोलिक पृष्ट भूमि का वर्णन प्राकृतिक वातावरण के समावेश द्वारा किया गया है, जिसमें भू-वैज्ञानिक संरचना के अन्तर्गत कालक्रम के अनुसार तीन क्रमों में इसे विभक्त किया गया हैं। आद्यकल्प की चट्‌टानें (आद्य शैल समूह) (2) विन्ध्यन युग की चट्‌टानें (विन्ध्यन शैल समूह) (3) अति नूतन युग के जमाव (जलोढ़ अवसादी शैल) का वर्णन किया गया है। उच्चावच की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र बुन्देलखण्ड उच्च भूमि पर स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर स्थान-स्थान पर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ फैली हैं। अध्ययन क्षेत्र के धरातल की सबसे अधिक ऊचाई ककरवाहा की पहाड़ी 486.79 मीटर ऊँची हैं, जबकि निम्न धरातलीय क्षेत्र निवाड़ी तहसील के सेन्दरी गाँव के पास हैं औसत ऊँचाई 185.93 मीटर है। जिला का धरातलीय लक्षण पठारी है जो कि सामान्यत: टीकमगढ़ जिले को तीन प्राकृतिक भागों में बाँटता है।

अपवाह तंत्र के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र को निम्न भागों में बाँटा गया है। (1) बेतवा अपवाह तंत्र, जिसमें बेतवा और उसकी सहायक नदियाँ का प्रवाहित क्षेत्र है। (2)जामिनी अपवाह तंत्र, (3) धसान अपवाह तंत्र, (4) सपरार बेसिन, (5) उर बेसिन, (6) अन्त:स्थलीय अपवाह तंत्र। जिला टीकमगढ़ के चन्देल कालीन के 962 तालाब पाये जाते हैं, जो अधिकांश सिंचाई के लिये महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्र का ढाल उत्तरी-पूर्वी है। केवल जामनी नदी एवं धसान नदी के किनारे ढाल क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी हैं। मौसम के ऋतुओं के आधार पर वर्ष को तीन भागों में विभक्त किया गया है। (1) अर्द्ध वर्षा ऋतु - यह जून के अंतिम सत्पाह से शुरु होकर अगस्त माह के अंन्त तक होती है। जिले में सबसे अधिक वर्षा टीकमगढ़ तहसील में होती है, जबकि सबसे कम निवाड़ी तहसील में होती है। (2) शीत ऋतु- जैसे ही वर्षा सामाप्त होती है, शीत ऋतु प्रारम्भ हो जाती है। यह अक्टूबर माह से फरवरी के मध्य तक

चलती है। इस समय वायु में आर्द्रता बढ़ने लगती है। जनवरी माह का तापमान औसत रुप से 14.8^0 से.ग्रे. रहता है। (3) **ग्रीष्म ऋतु-** सूर्य के उत्तरायण होते ही मार्च से तापमान में वृद्धि होने लगती है जो जून के अन्त तक रहता है। मार्च से तापमान में वृद्धि होने लगती है जो जून के अन्त तक रहता है। मार्च में तापमान 21.5^0 से.ग्रे. से बढ़कर अप्रेल में 30.8^0 तथा जून में 32.7 से.ग्रे. तक औसतन जाता है। ग्रीष्म ऋतु प्रातः 10 बजे से गर्म हवायें चलने लगती है। इन हवाओं को " लू " कहते हैं। जैसे ही जून माह में वर्षा प्रारम्भ होती है। वैसे ही फसल चक्र प्रारम्भ हो जाता है। सर्वप्रथम खरीफ, उसके बाद रबी एवं बाद में जायद की फसलें बोई जाती हैं।

अध्ययन क्षेत्र की मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ नहीं है किन्तु तालाबों की अधिकता के कारण सिंचित क्षेत्र, अधिक होने से यहाँ गेहूँ का अच्छा उत्पादन होता हैं। अध्ययन क्षेत्र-मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ तालाबों, नदियों में मत्स्य पालन होता है, क्षेत्र में सबसे अधिक मछली मोहनगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में पकड़ी जाती है। जिले में मत्स्य उत्पादन के विकास के लिये चार मत्स्य प्रक्षेत्र जो टीकमगढ़ में दो, जतारा, पृथ्वीपुर में एक-एक हैं। एक मत्स्य सम्बर्धन केन्द्र धजरई में स्थापित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में 5.27 प्रतिशत भाग पर ही वन हैं। वनों के विनाश का प्रमुख कारण कृषि भूमि का विस्तार, वनों की आवैज्ञानिक कटाई, पशु चरण आदि हैं। जिला टीकमगढ़ में खनिजों का प्रायः अभाव पाया जाता है। यहाँ केवल पायरोफ्लाइट एवं डायस्फोर, ग्रेनाइट, रेत और मुरम प्रचुर मात्रा में खनिज अवश्यक ही उपलब्ध है। टीकमगढ़ में 1901 से 1991 तक जनसंख्या तीन गुनी बढ़ गई है 1921 में जनसंख्या में कमी आई जिसका कारण क्षेत्र में तत्कालीन समय में अकाल एवं महामारी थी। जिला टीकमगढ़ में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में काफी असमानता है। इसी तरह मिट्टियाँ, मैदानी भाग, खनिज आदि भौगोलिक कारकों ने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया है।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 160 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. पाया जाता

है, सबसे अधिक घनत्व टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल (249) में तथा सबसे कम कुडीला राजस्व निरीक्षक मण्डल (115) में पाया जाता है। इसी तरह कार्यिकी घनत्व 377 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. पाया जाता है। कृषि घनत्व 311 एवं पोषण घनत्व 427 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. पाया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में लिंगानुपात 884 हैं। साक्षरता की दृष्टि से जिला टीकमगढ़ काफी पिछड़ा है। 1991 में 23.10 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे, जिनमें 31-20 प्रतिशत पुरुष एवं 15 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर थी। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक साक्षरता है। जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन में 1991 की जनगणना अनुसार अध्ययन क्षेत्र में 72.94 प्रतिशत काश्तकार, 13.46 प्रतिशत कृषि मजदूर, 2.88 पारिवारिक उद्योग में संलग्न व्यक्ति, 10.73 पतिशत अन्य कार्यों में लगे हुये है। कुल जनसंख्या के 35.08 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या, 7.32 प्रतिशत सीमान्त कार्यकर्ता और 57.59 प्रतिशत अकार्यशील जनसंख्या पाई जाती है।

कृषि उत्पादकता एवं उसके मूल्यांकन के अध्ययन में शामिल किया गया है। कृषि उत्पादकता के स्तर अध्ययन क्षेत्र औसत 1.26 पाया जाता है। कृषि विकास स्तर और कृषि की स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन मूल्यांकन निम्न कारकों पर आधारित हैं। जिसे सिंचाई की तीव्रता, बहु फसलों का बोया गया क्षेत्र, कृषि में उपकरणों एवं मशीनीकरण का प्रयोग एवं प्रति एकड़ उपज आदि से ज्ञात किया जा सकता है। सिंचाई सूचकांक, द्वि-फसली सूचकांक, मशीनीकृत सूचकांक, उर्वरक सूचकांक उपज सूचकांक, औसत संयुक्त सूचकांक को प्रस्तुत करती है।

आधुनिक युग उद्योगों का युग कहा जाता है, जिस देश एवं प्रदेश सहित क्षेत्र में उद्योगों की संख्या कम है, अध्ययन क्षेत्र उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा जिला है, यहाँ बहुत ही कम संख्या में लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण में

धरातलीय संरचना, जलवायु, वन, जल, खनिज सम्प्रदा एवं जनसंख्या प्रभावित करती हैं, दूसरे मानवीय कारकों में कृषि, परिवहन, पूँजी, व्यापार एवं वाणिज्य, वैज्ञानिक समोन्नति आदि कारक प्रभावित करते हैं। प्रमुख उद्योगों में कृषि पर आधारित उद्योग की संख्या 840 है एवं उनमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति 8047 हैं। खनिजों पर आधारित उद्योगों की संख्या 2035 एवं इनमें रोजगार प्राप्त व्यक्तियों 8047 हैं। खनिजों पर आधारित उद्योगों की संख्या 48 है और रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 379 है, वस्त्र आधारित उद्योगों की संख्या 778 है एवं उनमें रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 8610 है। यॉत्रिकी आधारित उद्योगों की संख्या 49 एवं रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 469 है; रसायन आधारित उद्योगों की संख्या 98 एवं रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 1140 है। पशु आधारित उद्योगों की संख्या 572 एवं रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 1067 है। अध्ययन क्षेत्र के उद्योगों की मूल-भूत समस्यायें भी हैं, जिनमें कच्चे माल की कमी, परिवहन के साधनों की कमी, पूँजी की कमी, प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी, राजनैतिक प्रणाली एवं बड़े बाजारों की निकटता का अभाव पाया जाता है। इन समस्याओं के निराकरण के उपरान्त यहाँ औद्योगीकरण हो सकेगा।

आवत्संरचात्मक विकास मानवीय वातावरण के प्रमुख आधारों के रुप में प्रस्तुत किया गया हैं। जिसमें प्रमुख उपागमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, परिवहन, दूर संचार, बैंक सेवायें, विद्युत और विस्तार सेवाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा संस्थाओं में सर्वप्रथम प्राइमरी स्कूलों की संख्या 850 है जो 683 बस्तियों में कार्यरत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 803 प्राईमरी स्कूल, जबकि 47 स्कूल नगरीय बस्तियों में हैं। जूनियर हाईस्कूल 153 बस्तियों में 191 विद्यालय हैं। इसी प्रकार हाईस्कूल 64 बस्तियों में 79 विद्यालय हैं, जिनमें 62 हाईस्कूल ग्रामीण बस्तियों में, जबकि 17 विद्यालय नगरीय स्कूलों में हैं। इन्टर मिडिएट (10+2) 36 बस्तियों में 42 स्कूल हैं। जिले में 5 बस्तियों में 6 महाविद्यालय हैं जो सभी नगरीय बस्तियों में हैं। इसी तरह अन्य शिक्षण संस्थाओं की संख्या 2 है। जिला टीकमगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्तता हैं। यहाँ अस्पतालों की संख्या 14 हैं, जिनमें 7 ग्रामीण व 7 नगरीय बस्तियों में हैं, जिले में 16 डिस्पेंसरी हैं, इनमें से एक नगरीय

बस्ती में हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 17 हैं जो सभी ग्रामीण बस्तियों में हैं। पलेरा राजस्व निरीक्षक मण्डल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या सर्वाधिक हैं। जिले में परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या 6 हैं। यह भी ग्रामीण बस्तियों में हैं। महिला एवं बाल विकास केन्द्रों की संख्या 2 है ये दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। प्राइवेट केन्द्रों की संख्या 2 है, ये दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। प्राइवेट प्रेक्टिसन्स् चिकित्सक 15 हैं। इसी तरह प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5 हैं। ये भी ग्रामीण बस्तियों में कार्यरत हैं। बाल कल्याण केन्द्रों की संख्या एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या 3 है, स्वास्थ्य मानव समाज के विकास के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पूर्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। पेयजल पूर्ति विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जिनमें सबसे सर्व सुलभ कुंऐ पेय जलापूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। अध्ययन क्षेत्र में 2217 कुंऐ पेयजल पूर्ति के लिये पाये जाते हैं, टीकमगढ़ रा.नि.मण्डलों में सर्वाधिक कुंऐ पाये जाते हैं। पेयजल पूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण साधन हैण्ड पंम्प हैं जो अध्ययन क्षेत्र के 637 बस्तियों में 823 हैण्ड पम्प हैं। टीकमगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल में हैण्ड पम्पों की संख्या सबसे अधिक है। पेय जल पूर्ति का तीसरा साधन नल है जो जिले की 39 बस्तियों में सुविधा प्रदान करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई जीवन दायिनी शक्ति के समान है, जिले के कुल कृषि योग्य भूमि के 42.35 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा हैं। सिंचाई के साधनों में कुंआँ एवं तालाब महत्वपूर्ण हैं, सिंचाई करने वाले कुँओं की संख्या 59970 है। जिले में कुँओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र ओरछा राजस्व निरीक्षक मण्डल में है। टीकमगढ़ जिला तालाबों का जिला है, क्योंकि यहाँ छोटे-बड़े तालाबों की संख्या 962 है, नलकूप वर्तमान सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिले में इनकी संख्या 134 है जो कुल सिंचित क्षेत्र का 10.86 प्रतिशत भूमि की सिंचाई करती है। नदियाँ भी सिंचाई का साधन के रुप में उपयोगी हैं, अध्ययन क्षेत्र में धसान, बेतवा एवं जामनी नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती है। जिले में सिंचाई तीव्रता 42.35 है। सबसे अधिक सिंचाई तीव्रता सिमरा राजस्व निरीक्षक मण्डल में पाई गई है।

संचार सुविधाओं का वर्तमान समय मानव समुदाय में अपना अलग महत्व है,

अध्ययन क्षेत्र में मुख्य डाकघर टीकमगढ़ नगर में स्थित है। उपडाकघरों की संख्या 19 है, जिनमें 11 ग्रामीण बस्तियों में है, शाखा डाकघरों की संख्या 158 है, इनमें 3 नगरीय बस्तियों में हैं, टेलीफोन की सुविधा प्राप्त बस्तियों की संख्या 31 हैं। जिले में एक टेलीविजन केन्द्र हैं। अध्ययन क्षेत्र को कम्प्यूटर संचार एवं एस.टी.डी. की सुविधायें प्राप्त हैं। जिला टीकमगढ़ में 78 बैंक शाखायें कार्य कर रही हैं, जिनमें 87.87% बैंक शाखायें ग्रामीण बस्तियों में हैं, इलाहाबाद एवं सेंट्रल बैंक की एक-एक शाखा है तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 43 शाखायें हैं, इनमें 4 शाखायें नगरीय बस्तियों में हैं, भूमि विकास बैंक की 7 शाखायें हैं, जिला सहकारी बैंक की 17 शाखायें हैं, एवं सहकारी साख समितियों की संख्या 87 हैं, इनमें 81 समितियाँ ग्रामीण बस्तियों में हैं। अध्ययन क्षेत्र की शत प्रतिशत बस्तियों को विद्युतीकृत किया जा चुका हैं, यहाँ 1987-88 में प्रति व्यक्ति विद्युत वार्षिक उपभोग 620 हजार किलोवाट था। जिले में 849 बस्तियों में बिजली की सुविधा है, इनमें 103 बस्तियों में केवल गृहकार्य हेतु 295 बस्तियों में कृषि कार्य हेतु, 71 बस्तियों में उद्योग एवं व्यवसाय हेतु तथा 552 बस्तियों में सभी कार्य हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्ध है।

केन्द्रीय स्थानों के स्थानिक विश्लेषण में केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति, विस्तार व सीमायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस आधार पर अधिवास महत्वपूर्ण है, ये मानक बसाव की व्यवस्था को दर्शाते हैं, ये अधिवास एक या अधिक घरों के पाये जाने को कहते हैं। यहाँ अधिवासों का उद्भव एवं वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही अधिवासें के वितरण प्रतिरुप को सेवाकेन्द्रों के रुप में परीक्षण किया गया है। अधिवासों के प्रकारों में सर्वप्रथम ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास है जो क्रमशः 863 एवं 12 है। अन्तर्क्षेत्रीयता के द्वारा अधिवासों के प्रकारों में सघन अधिवास, उपसघन अधिवास, छोटे गाँव या पुरवा आदि अधिवास पाये जाते हैं। अधिवास प्रतिरुप में आयताकार प्रतिरुप, रेखीय प्रतिरुप, दुहरे ग्राम, एल आकृति प्रतिरुप, टी, आकृति प्रतिरुप, बृत्ताकार प्रतिरुप एवं बिखारी झोपड़ियों के रुप में पाये जाते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों पर स्थलाकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ा हैं, साथ ही सांस्कृतिक पर्यावरण प्रभाव सर्वाधिक है। अध्ययन क्षेत्र में आवासीय स्थलों के वितरण में

मकानों की संख्या 122660 है, परिवारों की संख्या 125273 हैं, जिले में मकानों एवं परिवारों का घनत्व क्रमशः 27-27 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सेवास्थलों का आकार भी कई प्रकार का है, जिसमें जनसंख्या आकार- इसमें अध्ययन क्षेत्र में 839 व्यक्ति प्रति अधिवास में आवासित है। सेवाकेन्द्रों का क्षेत्रीय आकार इसमें जिले के मध्यवर्ती भाग में सघन अधिवास पाया जाता है। आवासित गृहों की संख्या प्रति सेवाकेद्र 122 हैं, इसी तरह परिवारों का आकार भी प्रति सेवाकेन्द्र औसतन 125 हैं। सेवाकेद्र विस्तार के अन्तर्गत घनत्व 2.48 एवं प्रकीर्णन 2.60 पाया जाता है। यहाँ प्रति 100 वर्ग कि.मी. सेवित क्षेत्र पर घनत्व 19.65 एवं प्रति सेवाकेन्द्र पर औसत क्षेत्रफल 5.27 पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में 3.16 विखराव सूचकांक, 7.89 आवश्यक गुणांक सूचकांक एवं 0.34 प्रकीर्णन सूचकांक पाया जाता है।

केन्द्रीयता एंव केन्द्रीय स्थान के समीप स्थित चारों तरफ के क्षेत्रों के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक-सांस्कृतिक, आवश्यकताओं, सेवाओं तथा बस्तुओं के विनमय की भिन्न-भिन्न क्रियाओं के केन्द्र को केन्द्रस्थल या सेवाकेन्द्र कहते हैं। समीपवर्ती क्षेत्र केन्द्रस्थल में उपलब्ध बस्तुओं एवं सेवाओं पर निर्भर करते हैं। चूँकि बस्तुओं या सेवाओं का विनिमय मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिये प्रत्येक क्षेत्र या प्रदेश में सेवाकेन्द्र की उपस्थिति अनिवार्य है। सेवाकेन्द्र के लिये किसी स्थान में कुछ विशेषतायें होनी चाहिए, जिनमें एक स्थाई मानव बस्ती का निर्माण हो, बस्ती अपनी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के साथ समीपवर्ती क्षेत्रों की सेवा करती हो। प्रत्येक केन्द्रस्थल 'प्रादेशिक राजधानी' के रुप में कार्य करता है, इसलिये इसका अपना प्रभाव क्षेत्र अवश्य होता है। केन्द्रीय स्थानों के निर्धारण और चयन के लिये सर्वप्रथम यह देखा जाता हैं कि अध्ययन का क्षेत्र छोटा है या बड़ा। यदि बड़ा है तो मुख्य सेवाकेन्द्रों का ही चयन किया जाता है सभी का नहीं। सेवाकेन्द्रों के निर्धारण में केन्द्रीयता ज्ञात करना, चयन और प्रभाव क्षेत्रों का सीमांकन करना महत्वपूर्ण है अथवा अन्य विधि व्यक्तिगत सर्वेक्षण भी हो सकती है। केन्द्रस्थलों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न ही होता है, सेवाकेन्द्रों के कार्य, केन्द्रस्थलों की केन्द्रीयता, उद्भव, वृद्धि और विकास की विशेषतायें, जनसंख्या आकार, नगरीयकरण की मात्रा

और विस्तार, आकारिकी के प्रतिरुप और वाह्यकृति, सेवाकेन्द्रों का आधार धरातल और स्थिति, केन्द्रों का समवाय, समूह और सहचार्य आदि है। सेवाकेन्द्रों के प्रमुख कार्य वाणिज्य, उद्योग, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि हैं। केन्द्रीयता के आधार पर केन्द्रस्थलों को बड़े से छोटे की ओर क्रमशः इस प्रकार रख सकते हैं, प्रादेशिक राजधानी, वृहद् प्रादेशिक केन्द्र, लघु प्रादेशिक केन्द्र, उप प्रादेशिक केन्द्र एवं स्थानीय केन्द्र। केन्द्रस्थलों का वर्गीकरण समय के आधार पर निम्नानुसार हो सकता है, इनमें, प्रागैतिहासिक केन्द्र, प्राचीन केन्द्र, मध्ययुगीय केन्द्र और आधुनिक केन्द्र हैं। अध्ययन क्षेत्र के चयनित कार्य और वर्तमान केन्द्रों के पदानुक्रम को समझाया गया है। इसमें चयनित कार्य कार्यात्मक पदानुक्रम का माप एवं जनसंख्या सीमांकन विधि को आधार मान कर सेवाक्षेत्रों का निर्धारण सीमांकन किया गया है। कार्यों का पदानुक्रम स्तर अति निम्न, मध्यस्त, उच्च मध्यस्थ, उच्च, उच्चतम, पाँच वर्गों में विभक्त है। सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम स्तर के निर्धारण के लिये छः स्तरीय सेवा केन्द्र, सेवाकेन्द्र का वितरण में क्षेत्रीय कार्यात्मक रिक्तता के साथ अतिव्यापन स्थिति भी पाई जाती हैं। साथ ही वृद्धिजनक केन्द्रों का स्थानीय विश्लेषण और परिवर्तित वृद्धि ध्रुव की विशेषतायें इनके विवरण को प्रभावित करती है। वृद्धिजनक केन्द्रों को भारतीय दशा में पदानुक्रम पाँच स्तरीय वृद्धिजनक केन्द्र, इनमें केन्द्रीय ग्राम, सेवाकेन्द्र, वृद्धि बिन्दु, वृद्धि केन्द्र एवं वृद्धि ध्रुव के रुप में अध्ययन क्षेत्रों में स्थानिक वितरण प्रतिरुप निर्धारित किया गया है। इसी के साथ वृद्धि-ध्रुव नीति के निर्धारण हेतु आपरेशन डिज़ायीन का निर्माण भी अध्ययन में सम्मिलित हैं।

वर्तमान सेवाकेन्द्रों और उनके नियोजन के प्रस्तुतीकरण में जब कोई केन्द्र, (जिसमें कुछ निश्चित महत्व के कार्य जो वहाँ की जनसंख्या को और चारों ओर के क्षेत्र को अपनी सेवायें प्रदान करते हैं) प्रादेशिक नाभिक बिन्दु कहलाते हैं और यही नाभिक बिन्दु जहाँ सामाजिक, आर्थिक, क्रियायें परस्पर मिलती हैं, सेवाकेन्द्र के रुप में कहलाती हैं। सेवाकेन्द्रों की संकल्पना बहुत से शोधकर्ताओं ने की है। क्षेत्रीय उपयोगी क्रियाओं का अस्तित्व, परिवहन मूल्य एवं मापन का अर्थशास्त्र प्रमुख है। जिला टीकमगढ़ लगभग ग्रामीण क्षेत्र है,

जहाँ वाणिज्यिक जनसंख्या केन्द्रीय स्थानों के परिचय के लिये अप्राप्त है, इसलिये व्यक्तिगत चुनाव और बाह्य एवं आंतरिक सेवा क्षमता विधि प्रयोग की गई हैं। सेवाकेन्द्रों के निर्धारण के लिये जिला टीकमगढ़ में विभिन्न कार्यों के प्रवेश बिन्दु इस प्रवेश बिन्दु के ऊंपर के सेवाकेन्द्रों की संख्या के साथ, जनसंख्या सीमांकन सूचकांक प्रस्तुत किया गया है। इसमें सेवाकेन्द्रों की कार्यात्मक समीपता, कार्यात्मक आश्रितता, कार्यात्मक वस्तु स्थिति, कार्यात्मक अन्तर्आश्रित्ता एवं सेवा सम्भाव्यता का आंकलन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों का वितरण प्रतिरुप एवं अन्तरण के अन्तर्गत सेवाकेन्द्रों का घनत्व, अभिकलित अन्तर सेवाकेन्द्र से दूरी, वास्तविक सेवित क्षेत्र की दूरी, आपेक्षित माध्य दूरी, यादृच्छिकता सूचकांक, प्रसरण विश्लेषण, मानक त्रृटि, यादृच्छिकता के प्रसामान्य प्रसरण सूचकांक एवं प्रसामान्यीकृत सूचकों का आंकलन किया गया है। इन सभी के विश्लेषण द्वारा सेवाकेन्द्रों का विकासक्रम एवं आकारिकी को समझाया गया है।

साँक्रियात्मक अभिकल्पना द्वारा सेवाकेन्द्रों के प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन को निर्धारित करने के लिये गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधियों का प्रयोग प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है। सेवाकेन्द्रों के अध्ययन में आवश्यकतानुसार समस्त अध्यायों में जनसंख्या सीमांकन विधि का प्रयोग किया गया, जबकि निकटतम पड़ोसी विधि द्वारा विश्लेषण करने पर जिले में कुछ बड़े आकार के सेवाकेन्द्रों का विकास गुणात्मक दृष्टि से पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का मात्रात्मक वितरण असमान पाया जाता है, निवाड़ी राजस्व निरीक्षण मण्डल में सेवाकेन्द्रों का सेवास्तर सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि नैगुंवा राजस्व निरीक्षक मण्डल में सबसे कम पाया जाता है। सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम स्तर को चार भागों में विभाजित किया गया हैं, इनमें लघुस्तरीय सेवाकेन्द्र (तृतीय स्तर के सेवा केन्द्र), बाजार सेवाकेन्द्र (चौथे स्तर के सेवाकेन्द्र), पाँचवे स्तर के सेवाकेन्द्र एवं छठें सतर के सेवाकेन्द्रों का विश्लेषण है। साथ ही अतिरिक्त कार्य सूचकांक, व्यापार वाणिज्य एवं सेवा सूचकांक का वर्गीकरण कर सेवा क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है।

आर्थिक विकास के लिये विपणन सेवाकेन्द्र अपना अलग ही महत्व दर्शाते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में स्थाई विपणन सेवाकेन्द्रों की संख्या 22 हैं, इनमें 16 ग्रामीण बस्तियों में पाये जाते हैं। पशु विपणन सेवाकेन्द्रों की संख्या 11 हैं, इनमें 6 नगरीय बस्तियो में हैं। इसी तरह साप्ताहिक विपणन सेवाकेन्द्रों की संख्या 157 बस्तियों में 180 हैं, इनमें 151 ग्रामीण बस्तियों में 168 साप्ताहिक विपणन सेवाकेन्द्र पाये जाते हैं। राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर सर्वाधिक साप्ताहिक विपणन केन्द्रों की संख्या तरीचरकलाँ में नैगुँवा रा.नि.म. में सबसे कम है। विपणन केन्द्रों का पदानुक्रम स्तर के अन्तर्गत पाँच प्रकार के सेवाकेन्द्र पाये जाते हैं। इन पाँचों प्रकार के सेवाकेन्द्रों में 151 सेवास्थल एवं बस्तियाँ सम्मिलित पाई गई हैं। इन सेवाकेन्द्रों का क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक वर्गीकरण कर नियोजन हेतु तमाम सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

नियोजन इकाईयों का निर्धारण में वर्तमान समय का सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं राजनैतिक उद्‌देश्यों की पूर्ति के क्रियान्वयन का परिणाम अध्ययन क्षेत्र में नियोजन की आवश्यकता के प्रमुख कार्य, कृषि एवं सम्बन्धित बस्तुओं का विकास, क्षेत्रीय कच्चे माल की प्राप्ति, मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विकास, ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न कार्य आदि हैं। नियोजन का मूलभूत तात्पर्य मानव समाज को संगठित कर प्रगति प्रदान करना है। उक्त उद्‌देश्य को ध्यान में रखाकर प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रादेशिक नियोजन की आधारभूत आवश्यकतायें प्रस्तुत की गई हैं। प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्रादेशिक नियोजन की सहायता से संसाधनों के नियोजन हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। नियोजन प्रदेशों का सीमांकन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसकी सीमा निर्धारित करते समय भौतिक समरुपता, प्राकृतिक संश्लिष्टता एवं आर्थिक एकरुपता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। जिस क्षेत्र का नियोजन करना होता है, उस क्षेत्र के लिये अनेक विधियाँ प्राप्त की गई है। इसके द्वारा प्रभाव क्षेत्र को सीमांकित किया गया है, जिससे गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधि का प्रयोग उल्लेखानीय है। अध्ययन क्षेत्र की नियोजन इकाईयों को चार पदानुक्रम स्तरों में बाँटा गया है, इनमें तृतीय क्रम के नियोजन इकाई केन्द्र हैं, इसमें 150 सेवाकेन्द्र 875 बस्तियों को सेवायें प्रदान करते हैं।

चौथे स्तर के नियोजन इकाई केन्द्रों में 14 सेवाकेन्द्र अध्ययन क्षेत्र के अन्दर की 860 बस्तियों में सेवायें प्रदान करती हैं। इसमें एक सेवाकेन्द्र अध्ययन क्षेत्र से बाहर का (झाँसी) है। पाँचवे स्तर के नियोजन इकाई क्षेत्र में कुल 5 सेवाकेन्द्र हैं, जिनमें एक अध्ययन क्षेत्र से बाहर का है। छठें स्तर के नियोजन इकाई केन्द्र में 2 सेवाकेन्द्र हैं। जिला टीकमगढ़ का विस्तृत और उवत्संरचात्मक अध्ययन हेतु संसाधनों का नियोजित आधार प्रस्तावित किया गया है। इसमें वर्तमान में उपलब्ध सेवायें एवं नियोजित सेवाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें परिवहन, संचार सेवायें, बाजार सुविधायें, साख सुविधायें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा सुविधायें, वन सम्प्रदा, मत्स्य संसाधन, उद्योग, विद्युत आदि सुविधाओं का नियोजन प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजन में कृषि के अन्तर्गत उन्नतशील बीज, उर्वरक, मशीनों की संख्या, सिंचाई सुविधायें एवं क्रय-विक्रय केन्द्र नियोजन प्रक्रिया निर्धारित करते है। ग्रामीण उद्योगों में कच्चे माल की उपलब्धता, पूँजी, श्रमिकों को प्रशिक्षण, अनुदान एवं विपणन केन्द्रों की सुलभता द्वारा नियोजित संरचना दी गई। परिवहन में पहुँच मार्गों की सुगम्यता, सड़क व बस की सुलभता, ऊर्जा विकास हेतु प्रयास, पशु सम्बर्न्धन हेतु योजना, ग्रामों के सामाजिक वातावरण की गुणवतता में वृद्धि, ग्रामीण पर्यावरण विकास के प्रयास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को अधिकाधिक अवसर, महिला एवं बाल विकास योजनायें और जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों से परिलक्षित करने पर बल दिया गया है। साथ ही नगर नियोजन हेतु नगर के नवीन क्षेत्रों के पुनः डिजायन करना, नगर के पुराने क्षेत्रों का पुनर्नियोजत करना, जिसके अन्तर्गत नगरीय संरक्षण, नगरीय नवीनीकरण एवं नगरीय पुर्नविकास की योजना प्रस्तुत की गयी है। नगरीय भूमि उपयोग में आवासीय भूमि, वाणिज्यिक भूमि, औद्योगिक भूमि, सड़क निर्माण हेतु भूमि मनोरंजन भूमि के लिये नियोजित आधार की रुपरेखा अध्ययन में सुझाई गई है।

वर्तमान में यह अनुभव किया जा रहा है, कि समन्वित क्षेत्रीय विकास, की योजनाकालीन आवश्यक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ही समाज के ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े वर्गों का विकास किया जा सकता है, इसका मूलभूत उद्देश्य क्षेत्रीय निवासियों का जीवनस्तर ऊँचा करना

है। इस हेतु संसाधनों का विकास इस प्रकार योजना बद्ध होना चाहिये, जिससे कि उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। इसमें अधिकतम भूमि उपयोग क्षमता हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये है, यहाँ की भूमि दो प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है। एक तो मृदा अपरदन और दूसरे मिट्टी में उत्पादकता की कमी। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिये भूमि संसाधन योजना सुझाई गई हैं। समन्वित क्षेत्रीय विकास हेतु जल एक आवश्यक आधारभूत संसाधन है, इसमें सतही एवं भूमिगत जल के संरक्षण की आवश्यकता है। मत्स्य उत्पादन हेतु जलाशयों के लिये योजनायें सुझाई गई हैं, क्योंकि मत्स्य भोजन के अतिरिक्त दवाईयों एवं अन्य कार्यों में भी उपयोग होती हैं। मत्स्य उत्पादन हेतु जलाश्यों में वर्षभर जल उपलब्ध होना आवश्यक हैं। इसके लिये छोटे छोटे बाँधों की योजनायें प्रस्तुत की गई है, इनमें वन संसाधनों का संरक्षण, सामाजिक वानिकी हेतु अनेक सुझावों का समावेश किया गया है।

संस्तुतियाँ :

अध्ययन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु संसाधनों का नियोजिन आधार निम्नानुसार संस्तुतियाँ प्रस्तावित की जाती है।

परिवहन : वर्तमान स्थिति :

1. अध्ययन क्षेत्र के 165 बस्तियों को बस सुविधा प्राप्त है।
2. क्षेत्र में निवाड़ी ओरछा एवं टेहरका में रेलवे स्टोशन की सुविधा प्राप्त है।
3. अध्ययन क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कों की संख्या 39 है।
4. टीकमगढ़ नगर में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की सब डिपो स्थापित है।

प्रस्तावित :

1. क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी वाले शेष 293 में बस सुविधा उपलब्ध हो।

2. टीकमगढ़ नगर को रेल्वे लाइन से जोड़ा जाना चाहिये।

3. सारणी में वर्णित सभी निर्माणाधीन सड़कों को पूरा कर डामरी करण किया जाए। साथ ही मार्ग में पड़ने वाली पुलियों का निर्माण किया जाए।

4. टीकमगढ़ नगर में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन का डिपों स्थापित होना चाहिए, साथ ही टीकमगढ़-झाँसी मार्ग, टीकमगढ़-छतरपुर मार्ग, टीकमगढ़-ललितपुर मार्ग पर प्राइवेट बसों की जगह राजकीय परिवहन की बस सेवायें चलाई जाए।

संचार सेवायें : वर्तमान स्थिति :

1. टीकमगढ़ नगर में एक मुख्य डाकघर कार्यरत है।
2. जिला में उप डाकघरों की संख्या 19 है।
3. क्षेत्र में शाखा डाकघरों की संख्या 158 है।
4. टेलीफान की सुविधा प्राप्त बस्तियों की संख्या 31 है।
5. टेलीफोन एक्सचेंज टीकमगढ़ में स्थापित है।
6. दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र टीकमगढ़ नगर में हैं।
7. रेडियों स्टेशन की सुविधा अध्ययन क्षेत्र में नहीं है।

प्रस्तावित :

1. तहसील मुख्यालय पर प्रधान डाकघर की सुविधा होनी चाहिये; जिसमें निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा एवं बल्देवगढ़ नगर प्रमुख है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में जिन बस्तियों की जनसंख्या 1000 से अधिक हो, वहाँ 10 नये उपडाकघर स्थापित किये जाये।

3. पटवारी हल्का स्तर पर शाखा डाकघर स्थापित किए जाए, इस प्रकार कुल शाखा डाकघरों की संख्या 295 हो जाएगी।

4. 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण बस्तियों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही प्रत्येक नगरीय बस्तियों को एस.टी.डी. एवं पी.सी.ओ. की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
5. प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मण्डल मुख्यालय स्तर पर टेलीफोन एक्स्चेंज की स्थापना की जाए।
6. निवाड़ी एवं जतारा नगरों में दूरदर्शन के हल्के पावर के श्याम-श्वेत केन्द्र स्थापित किये जाये।
7. टीकमगढ़ नगर (जिला मुख्यालयय) में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना की जाए।

बाजार सुविधायें : वर्तमान स्थिति :

1. अध्ययन क्षेत्र में साप्ताहिक बाजारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों 168 एवं नगरीय क्षेत्रों में 12 बाजार हैं।
2. दैनिक उपभोग की बस्तुओं के बाजार ग्रामीण बस्तियों में 16 एवं 6 नगरीय बस्तियों में हैं।
3. पशु बाजारों की संख्या 11 है, जिनमें 5 पशु बाजार ग्रामीण बस्तियों में हैं।
4. कृषि उपज मण्डी की सुविधा 6 नगरीय बस्तियों में है।

प्रस्तावित :

1. साप्ताहिक बाजार ग्रामीण स्तर पर 1000 से अधिक आबादी वाली 76 नई बस्तियों में सुविधा हो।
2. दैनिक उपभोग की बस्तुओं के बाजार ग्रामीण स्तर पर 1000-1999 तक आबादी वाले 5 बस्तियों में 2000 से 4999 तक आबादी वाले 10 बस्तियों में

एवं 5000 से अधिक आबादी वाली एक बस्ती में इन बाजारों की सुविधा प्राप्त हो।

3. पशु बाजार ग्रामीण स्तर पर 10 नई बस्तियों में स्थापित हों।

4. कृषि उपज मण्डी अध्ययन क्षेत्र में प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मण्डल मुख्यालय पर स्थापित हो।

साख सुविधायें : वर्तमान स्थिति :

1. भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें ग्रामीण बस्तियों में 4 एवं नगरीय बस्तियों में 5 शाखायें है।

2. इलाहाबाद बैंक की टीकमगढ़ नगर में एक शाखा हैं।

3. सेन्ट्रल बैंक की टीकमगढ़ नगर में एक शाखा है।

4. बुन्द्रेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ग्रामीण बस्तियों में 39 एवं 4 नगरीय बस्तियों में शाखायें हैं।

5. भूमि विकास बैंक की ग्रामीण बस्तियों में 2 एवं 5 नगरीय बस्तियों में शाखायें हैं।

6. जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक की ग्रामीण बस्तियों में 11 एवं 6 नगरीय बस्तियों में शाखायें हैं ।

7. सहकारी साख समितियों की संख्या ग्रामीण स्तर पर 81 तथा 6 नगरीय स्तर है।

8. भारतीय जीवन बीमा निगम की एक शाखा जिला मुख्यालय टीकमगढ़ में कार्यरत है।

प्रस्तावित :

1. भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें 500 से 4999 तक की जनसंख्या वाली 10 नई बस्तियों में 5000 से 'अधिक आबादी वाली 2 बस्तियों में एवं एक शाखा

खारगापुर नगर में स्थापित की जाए।

2. इलाहाबाद बैंक शाखा तहसील मुख्यालय पर की जाए जिसमें- निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा एवं बल्देवगढ़ नगर आते हैं।

3. सेन्ट्रल बैंक की शाखायें ब्लाक खण्ड मुख्यालय पर स्थापित किए जाये, जिसमें निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा एवं बल्देवगढ नगर आते हैं।

4. बुन्देलखण्ड ग्रामीण बैंक की शाखायें 500 से 999 तक आबादी वाले 4 ग्रामों में, 1000 से 1999 तक आबादी वाले 2 ग्रामों, में 3000 से 4999 तक आबादी वाले 5 ग्रामों में एवं 5000 से अधिक आबादी वाले एक ग्राम में इसी तरह 2 नगरीय बस्तियों में इस बैंक की शाखायें स्थापित किए जाये।

5. भूमि विकास बैंक की ग्रामीण शाखायें ग्रामीण स्तर पर 2000 से 4999 तक आबादी वाली 2 बस्तियों में, 5000 से अधिक आबादी वाली 2 बस्तियों में एवं एक शाखा खारगापुर में स्थापित की जाए।

6. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाऐं, ग्रामीण स्तर पर 1000 से 1999 तक आबादी वाली 3 बस्तियों में 2000 से 4999 तक आबादी वाली 3 बस्तियों में शाखायें स्थापित की जाए।

7. जिला सहकारी साख समिति की शाखायें ग्रामीण स्तर पर 200 से 499 तक आबादी वाली 5 बस्तियों में, 500 से 999 तक आबादी वाली 7 बस्तियों में, 1000 से 1999 तक आबादी वाली 10 बस्तियों में, 2000 से 4999 तक आबादी वाली 15 बस्तियों में एवं 5000 से अधिक आबादी वाली एक बस्ती में शाखायें स्थापित की जाए।

शैक्षणिक सुविधायें वर्तमान स्थिति :

1. अध्ययन क्षेत्र में 683 बस्तियों में प्राईमरी स्कूल की सुविधायें हैं।

2. क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 191 है।

3. हाईस्कूलों की संख्या 79 है।
4. उच्च माध्यमिक विद्यालयों (10+2) की संख्या 42 है।
5. क्षेत्र में 5 नगरों में 6 महाविद्यालय है।
6. अन्य शिक्षण संस्थाओं की संख्या 2 है।

प्रस्तावित :

1. प्राईमरी स्कूल प्रत्येक 200 से अधिक आबादी वाली 74 बस्तियों में स्थापित किये जायें।
2. अध्ययन क्षेत्र में 1000 से अधिक आबादी वाली 86 नई बस्तियों में स्थापित किये जायें।
3. क्षेत्र में हाईस्कूल 2000 से अधिक आबादी वाली 25 नई बस्तियों में स्थापित किए जाए।
4. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (10+2) ग्रामीण स्तर पर 2000 से 4999 तक आबादी वाली 10 बस्तियों में एवं 5000 से अधिक आबादी वाली एक बस्ती में स्थापना की जाए।
5. बल्देवगढ़, खारगापुर में कला संकाय महाविद्यालय एवं पलेरा में विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किए जाए।
6. टीकमगढ़ नगर में इन्जीनियरिंग कालेज, शिक्षा महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाए।
6. प्रत्येक शिक्षा संस्था का अपना एक खेल मैदान, खेलों की सामग्री, बिजली, पानी, एवं संचार की सुविधायें में टेलीफोन सेट की सुविधा उपलब्ध हो।

स्वास्थ्य : **वर्तमान स्थिति :**

1. अध्ययन क्षेत्र में 7 अस्पताल ग्रामीण बस्तियों में एवं 7 अस्पताल नगरीय बस्तियों में है।

2. क्षेत्र में 15 चिकित्सालय ग्रामीण बस्तियों में एवं एक चिकित्सालय नगरीय क्षेत्र में हैं।
3. जिला में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जो सभी ग्रामीण बस्तियों में हैं।
4. परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या 6 है जो सभी ग्रामीण बस्तियों में है।
5. महिला एवं बाल विकास केन्द्रों की संख्या 2 है वे भी ग्रामीण क्षेत्रों में है।
6. प्राइवेट प्रेक्टीशनरों की संख्या 15 है जो वे भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
7. प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या 15 है जो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में है।
8. बाल कल्याण केन्द्रों की संख्या एक है। यह भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं।
9. अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में 2 केन्द्र है जो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हैं।

प्रस्तावित :

1. क्षेत्र मे अस्पतालों की सुविधा ओरछा, दिगौड़ा समर्रा, बड़ागाँव, बल्देवगढ़, एंव कुड़ीला राजस्व निरीक्षक मण्डलों में नहीं हैं, अतः इन राजस्व निरीक्षक मण्डलों मे मुख्यालयों में एक-एक अस्पतालों की स्थापना आवश्यक है।
2. चिकित्सालयों की सुविधायें ओरछा, निवाड़ी, पलेरा, बड़ागाँव, बल्देवगढ़, एवं खरगापुर राजस्व निरीक्षक मण्डलों में नहीं हैं। अतः इन राजस्व निरीक्षक मण्डलों में कम से कम एक-एक चिकित्सालयों की सुविधायें प्रदान की जानी चाहये।
3. जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वितरण असमान है। अतः तरीचरकलाँ, सिमरा, पृथ्वीपुर, मोहनगढ़, दिगौड़ा, टीकमगढ़, समर्रा, रा.नि.मण्डलों में एक एक बस्तियों में इन की सुविधायें होनी चाहिये।
4. परिवार नियोजन केन्द्र राजस्व निरीक्षक मण्डल मुख्यालय पर होने चाहिये।
5. 200 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक बस्तियों में एक प्राइवेट प्रेक्टीशनर होना चाहिये ।

6. बाल कल्याण केन्द्र तहसील मुख्यालय पर होना चाहिये।

7. अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्ड मुख्यालय पर होने चाहिये, इसी तरह इन्हीं केन्द्रों पर एक-एक नर्सिंग होम की सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है।

पशु औषधालय : वर्तमान में :

1. क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की संख्या 9 है जो 3 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 6 नगरीय क्षेत्रों में हैं।

2. पशु औषधालयों की संख्या 46 है इनमें 42 ग्रामीण बस्तियों में एवं 4 नगरीय बस्तियों में है।

3. अध्ययन क्षेत्र में 4 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं जो क्रमशः टीकमगढ़, बल्देवगढ़, लिधौरा एवं निवाड़ी में स्थापित हैं।

4. क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रों की संख्या 36 हैं जो 35 ग्रामीण स्तर पर एवं एक नगरीय क्षेत्र पृथ्वीपुर में है।

प्रस्तावित :

1. 5000 से अधिक जनसंख्या वाली तीनों ग्रामीण बस्तियों में पशु चिकित्सालयों की सुविधायें होनी चाहिये जो क्रमशः कारी, लिधौरा एवं चंदेरा में हो।

2. पशु औषधालय ग्रामीण स्तर पर कारी ग्राम में एवं नगरीय स्तर पर टीकमगढ़ एवं खारगापुर में स्थापित होनी चाहिए।

3. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र जिला में पृथ्वीपुर, जतारा, बल्देवगढ़, खारगापुर एवं पलेरा नगरों में स्थापित किये जाने चाहिये।

4. कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रों की संख्या बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में 10 एवं 5 नगरीय क्षेत्रों में की जानी चाहिये।

वन सम्पदा : वर्तमान स्थिति :

1. अध्ययन क्षेत्र में 9 नर्सरी हैं जो बरीघाट, विन्ध्वासनी, डूडांघाट, पिपरट, गोवा, विन्दुपुरा, बिरोराघाट, परसा एवं नोटघाट में हैं।
2. वन परिक्षेत्र जिला में टीकमगढ़, जतारा, ओरछा, निवाड़ी में हैं।
3. सब रेंजों की संख्या 19 है जो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में है।
4. वनवीटों की संख्या 106 है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

प्रस्तावित :

1. नर्सरी की संख्या बढ़ाकर प्रत्येक नगरीय स्तर पर हो।
2. वन परिक्षेत्र विकास खण्ड मुख्यालय पर प्रस्तावित किये जाते हैं, जिनमें, पृथ्वीपुर पलेरा एवं बल्देवगढ़, नगरों में स्थापित किए जाए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में ही सब रेंजों की संख्या बढ़ाकर 19 से 25 की जानी चाहिये।
4. वन वीटों की स्थापना पटवारी हल्का मुख्यालय पर की जानी चाहिए।

मत्स्य संसाधन : वर्तमान स्थिति :

1. अध्ययन क्षेत्र में मत्स्य प्रक्षेत्र केन्द्र धजराई ग्राम में स्थापित है।
2. मत्स्य संवर्धन केन्द्र टीकमगढ़, जतारा, बल्देवगढ़, एवं पृथ्वीपुर नगरों में हैं।
3. मत्स्य विभाग द्वारा जिला के 20 तालाबों एवं मत्स्य समितियों के माध्यम से 61 तालाबों में मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है।

प्रस्तावित :

1. मत्स्य प्रक्षेत्र केन्द्र तहसील मुख्यालय पर की जानी चाहिए, जिसमें टीकमगढ़, बल्दवगढ़, जतारा, निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर नगर हैं।
2. मत्स्य सम्बर्धन केन्द्र विकासखण्ड मुख्यालय पर प्रस्तावित की जाती है।
3. अध्ययन क्षेत्र में सभी बड़े तालाबों में मछलियाँ का उत्पादन समितियों के माध्यम से किया जाए।

उद्योग : वर्तमान स्थिति :

1. अध्ययन क्षेत्र में बृहुद उद्योगों का अभाव है।
2. अध्ययन क्षेत्र में प्रतापुरा ग्राम (निवाड़ी तहसील) में औद्योगिक केन्द्र का विकास किया जा रहा है।
3. मध्यम श्रेणी के उद्योगों की संख्या 48 है।
4. लघु एवं कुटीर उद्योगों की संख्या 4494 है।

प्रस्तावित :

1. कृषि उत्पादों पर आधारित बृहद उद्योगों की स्थापना की जाए, जिसमें पुट्ठा एवं गन्ना मिल उद्योग, मैदा मिल की पर्याप्त सम्भावनायें हैं।
2. क्षेत्र के तीव्रतम विकास के लिये मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना की जाने की आवश्यकता है। जिसमें सोयाबीन प्लांट, जिंजर प्लांट एवं ग्रेनाइट क्रेशर आदि उद्योग लगाये जाने हेतु प्रस्ताव किया जाता है।
3. प्रतापपुरा औद्योगिक केन्द्र में उद्योगों की स्थापना हेतु शासन से वित्तीय अनुदान एवं सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

4. लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना ग्रामीण अधिवासों में अधिक की जाए, जिसमें बीड़ी उद्योग, हस्तकरघा, बाँस उद्योग, फर्नीचर निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण, साबुन निमाण, ग्रामीण तेल धानी आदि लघु एवं कुटीर उद्योगों का अधिक विकास किया जाए।

विद्युतीकरण : वर्तमान में :

1. अध्ययन क्षेत्र की 849 बस्तियाँ विद्युतकृत हैं।
2. क्षेत्र में विद्युत का प्रतिव्यक्ति उपभोग 64.20 हज़ार किलोवाट है।

प्रस्तावित :

1. अध्ययन क्षेत्र की शेष 26 बस्तियों में विद्युत सुविधायें प्रदान की जाना चाहिए।
2. विद्युत का अधिकाधिक उपभोग लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ कृषि में प्रदान किया जाना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु योजनायें :

अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपना जीवनयापन करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजन के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तुत किये जाते हैं।

कृषि :

जिला टीकमगढ़ कृषि प्रधान होने के कारण कृषि संबंधि अनेकों समस्यायें विद्यमान रहती हैं। इन समस्याओं को दूर करके ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता हे जिनमें उन्नतशील एवं परिष्कृत बीज का उपयोग किया जाना आवश्यक है। जिसकी सुविधा सहकारी

साख समितियों पर उपलब्ध रहती है एवं बीज प्रमाणीकरण केन्द्र कुण्डेश्वर में स्थित है। उन्नतशील बीज के साथ उर्वरक भी आवश्यक हैं। जिला टीकमगढ़ उर्वरकों के उपयोग में मध्य प्रदेश में अग्रणी स्थान रखता है। अध्ययन क्षेत्र के कृषक उर्वरकों का क्रय सहकारी साख समितियों से या व्यक्तिगत खाद विक्रेताओं द्वारा कर लेते हैं। उर्वरकों में सबसे अधिक उपयोग यूरिया, डी.ए.पी. एवं अन्य रसायनिक खाद का उपयोग किया जाता है इसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में कम्पोस्ट खाद का भी उपयोग किया जाता है।

उत्पादन वृद्धि में कृषि मशीनों का महत्वपूर्ण योगदान है जिनमें ट्रेक्टर, ट्राली, हैरो, कल्टीवेटर, थ्रेसर, हारवेस्टर, कटिया मशीन, विद्युत व डीजल पम्प आदि का उपयोग किया जा रहा है। इनके विक्रेता टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा, पृथ्वीपुर, बल्देवगढ़, आदि नगरों में उपलब्ध हैं। कृषि उत्पादन के लिये, सिंचाई की आवश्यकता पड़ी हैं जिसकी पूर्ति नदियाँ, तालाबों कुओं एवं बांध बनाकर उनसे नहरों के माध्यम से की जाती है। कहीं कहीं ट्यूबवेल भी लगाये जा रहे हैं। कृषि उत्पादन को बेचने के लिये कृषि उपज मण्डियों की सुविधायें हैं। जो क्षेत्र में टीकमगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, खारगापुर एवं बल्देवगढ़ में हैं जिसमें कृषक अपना कृषि उत्पादन उचित दामों में बेच देते हैं।

ग्रामीण उद्योग :

अध्ययन क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिये ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास आवश्यक है। जो निम्न लिखित तत्वों पर निर्भर करता है-

कच्चे माल की उपलब्धता :

उद्योगों के संचालन के लिये कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती हैं ग्रामीण लघु उद्योगों में बीड़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, बाँस उद्योग, कृषि यंत्र निर्माण आदि के लिये कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जिसकी पूर्ति अध्ययन क्षेत्र के ही प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा हो सकती है।

पूँजी :

लघु उद्योगों के लिये पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता पड़ती है जो 3000 से 45000 तक हो सकती हैं जिसकी पूर्ति बैंकों के द्वारा या सेठ - साहूकारों के द्वारा होती है। उद्योगों के विकास के लिये निरन्तर पूँजी की आवश्कयता पड़ती है जिसकी पूर्ति आवश्यक है तथा लघु उद्योग विकसित हो सकते हैं।

बेरोजगारों को प्रशिक्षण :

ग्रामीण लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को किसी विशेष उद्योग हेतु प्रशिक्षित किया जाये जिससे उस व्यक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। परिणामस्वरुप उद्योग गतिमान रहता है क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधा जिला मुख्यालय टीकमगढ़ पर उपलब्ध है।

अनुदान :

लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष अनुदान की आवश्यकता पड़ती है जैसे भूमि अनुदान ब्याज में छूट एवं पूंजी में कुछ प्रतिशत अनुदान दिये जाये तो ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास किया जा सकता है। इस अनुदान को समय समय पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न योजनाअें के माध्यम से लिया जाता है।

विपणन केन्द्रों की सुलभता :

ग्रामीण लघु उद्योगों के विकास के लिये बड़े बाजारों की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर उत्पाद निर्मित वस्तु बेच सकें एवं कच्चा माल खरीद सके। क्षेत्र में टीकमगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा, खरगापुर, बल्देवगढ़, लिधौरा आदि प्रमुख विपणन केन्द्र है।

ग्रामीण परिवहन :

ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है जिसमें पहूँच मार्गों की सुविधा को प्रत्येक ग्राम में होना चाहिये, साथ ही बस की सुविधा भी लगभग सभी बस्तियों में उपलब्ध हों। जहाँ पहूँचमार्गों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाये एवं मार्ग में पड़ने वाली पुलियों का निर्माण आवश्यक है। इतनी सुविधा हो जाने से ग्रामीण लोगों का सम्पर्क अध्ययन क्षेत्र के बाहर हो सकेगा।

ग्रामीण ऊर्जा विकास हेतु प्रयास :

वर्तमान युग में शक्ति का बहुत महत्व है किन्तु शक्ति के प्रमुख साधनों जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें एवं अणुशक्ति का उत्पादन सीमित होने से ग्रामीण ऊर्जा के निकास पर बल दिया जाना चाहिये। जिसमें सौर ऊर्जा जो सूर्य का किरणों के माध्यम से किसी यंत्र में संचित की जा सकती है। इसी तरह पवन ऊर्जा एवं गोवर गैस संयंत्रों का निर्माण शक्ति के प्रमुख स्रोत है। अध्ययन क्षेत्र में गोबर गैस संयंत्रों का प्रचलन करीब दो दशकों से हो रहा है जो विकास के क्रम में है।

पशु संवर्धन योजना :

दुग्ध व्यवसाय के लिए स्वस्थ्य पशु आवश्यक है जिनकी चिकित्सा गर्भधारण केन्द्र, नस्ल सुधार योजना आवश्यक है।

ग्राम के सामाजिक वातावरण की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास :

ग्रामों के अधिकांश युवक बेरोजगार होने से असमाजिक तत्वों को बढ़ावा देते है जिससे अपराधों में वृद्धि होती है। इन असमाजिक तत्वों को दूर करने के लिये बेरोजगार

युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। सामाजिक कार्यों के लिये प्रेरित किया जाये, धर्म निरपेक्षता के गुण बताये जाये आदि उपायों से सामाजिक वातावरण की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकेगी।

ग्राम के पर्यावरण के विकास के प्रयास :

स्वच्छ पर्यावरण से ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इसके लिये पर्यावरण विकास के प्रयास आवश्यक है; जिसमें ग्राम के मध्य पक्की नालियों को बनाया जाये। ग्रामों में ही वृक्षारोपण किया जाये, पीने के पानी का कुँआ अलग होना चाहिये जो ऊपर से ढंका हो तथा समय समय पर कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग होता हो, ग्राम के बाहर पशुओं के गोबर रखाने के स्थान हो; मलेरिया से बचने के लिये घरों में डी.डी.टी., बी.एय.सी आदि दवाईयों का छिड़काव किया जाये। इन सभी प्रयासों से ही ग्राम के पर्यावरण का विकास सम्भव है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रोजगार के अवसर :

ग्रामों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का संख्या अधिक होती है। सभी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक एवं शारीरिक रुप से कमजोर होते हैं। इन सब दोषों को दूर करने के लिए उनको रोजगार के साधन मुहैया कराये जाये जो ग्राम में ही लघु उद्योग चला सकें एवे नौकरी में वरीयता प्रदान की जाये तभी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सम्भव हो सकेगा।

बाल विकास योजना :

आज के बालक कल के नागरिक है अतः बालाकों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें विशेष रुप से ग्रामों के बालकों के लिये दूग्ध, दवाईयाँ एवं शिक्षा तथा खेलकूद के साधन उपलब्ध हों।

प्रौढ़ शिक्षा :

अध्ययन के क्षेत्र की बहुत अधिक आबादी आज भी अशिक्षित है जिसमें विशेष रुप से 20 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अधिक है अतः साक्षरता बढ़ाने के लिये इन 20 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों के लिये प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता है। जो प्रत्येक ग्राम में आवश्यक है तथा इनको अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाये।

जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों से परिचय :

जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा अभिशाप है जिससे सारी प्रगति रुक जाती है, क्योंकि हमारे पास सीमित प्राकृतिक संसाधन हे उनका अधिक से अधिक उपयोग करके हम विकास की ओर बढ़ते हैं किन्तु जनसंख्या विस्फोट से अधिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरुप हम विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा और भी कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है जिसमें खाद्यान्न की समस्या आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आवश्यक साधनों से दूर रहना पड़ता है अतः जनसंख्या वृद्धि को रोककर या कम करके ही हम सुखी रह सकते हैं। इस वृद्धि को रोकने में प्राकृतिक संयम नसबंदी, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन के साधन एवं लड़कियों को लड़कों के समान दर्जा देना आदि ऐसे साधन है जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ सकेंगी।

नगर नियोजन :

नगर नियोजन के अन्तर्गत नगर की समस्याओं का समाधान ढूंड़ा जाता है।

सेवा केन्द्रों का क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक नियोजन :

किसी प्रदेश का विकास सेवा केन्द्रों द्वारा त्वरित रुप से किया जा सकता है। कार्यों एवं आकार्यों के विभिन्न भागों के संयुक्तीकरण की पद्धती संबंध प्रतिरुपों में होती है और क्षेत्रीय कार्य एवं बस्तियों दोनों पदानुक्रम के अनुसार एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होती हैं।

1. ऐसे उपकार्य केन्द्रों का चयन जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. सन् 2001 तक सेवाकेन्द्रों के क्षेत्रीय संगठन का प्रस्ताव।

यह देखा गया है कि अध्ययन क्षेत्र में केन्द्रीय ग्राम व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः तत्काल इन केन्द्रों के लिये ध्यान देने की आवश्यकता है, तृतीय वर्ग केन्द्रों को ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों जोड़ा जाए, जिनमें कृषि एवं अन्य क्रियाओं की सेवायें तत्काल प्रदान की जाती है। तीव्र जनसंख्या वाले क्षेत्रीय कार्यात्मक रिक्तियों को कम करने वाले भागों में अच्छी सेवाएं प्रदान की जाती है। जिससे ये केन्द्र सन् 2001 तक उपयुक्त प्रगति कर सकें। क्षेत्रीय प्राकृतिक विशेषताओं और आर्थिक स्तर को ऊँचा करने के लिये अन्य वर्ग के केन्द्रों में वृद्धि न करके बल्कि वर्तमान वर्गों में अच्छी सुविधायें प्रदान करने के बजाय क्षेत्रीय कार्यात्मक रिक्तियों को केन्द्रीय स्थानों के दृष्टिकोण से कम किया जाना चाहिए, सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर सन् 2001 तक 300 सेवाकेन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।

अध्ययन क्षेत्र में सभी सेवाकेन्द्र ग्रामीण स्तर पर पाये जाते हैं। अतः इन सभी वर्ग के केन्द्रों में क्षेत्रीय विशषताओं के साथ वृद्धि परम्परा का निर्वाह सन् 2001 तक किया जाना चाहिए, परिवहन की आवश्यकता जनसंख्या वृद्धि और सेवाओं की माँग न्यून वर्ग पदानुक्रम में सेवाकेन्द्र शक्तिशाली संकल्पना पर आधारित हो, उक्त अध्ययन सेवाकेन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय संगठन विकास की प्रक्रियाओं की स्थानिक पद्धतियों को प्रस्तुत करता है। केन्द्रीय ग्रामों के विकास की आवश्यकता के अन्तर्गत माध्यमिक शाला, उ.मा. विद्यालय, शाखा डाकघर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस स्टौप, साप्ताहिक बाजार, सहकारी साख समितियाँ, कुटीर एवं लघु उद्योग, उर्वरक वितरण केन्द्र बीज एवं कीटनाशक वितरण केन्द्र, कृषि उपकरण मरम्मत की दुकानें आदि सेवा इकाईयों का न्यूनतम आधार हो, जिससे सभी आश्रित ग्रामों की आवश्यक आवश्यकतओं की पूर्ति की जा सके। अनत में समस्त आश्रित ग्रामों को सामान्य परिवहन के लिये पहूँच मार्गों से जोड़ा जाना चाहिए।

स्थानीय बाजार स्थानीय आर्थिक सम्बद्धता के द्योतक होते हैं। बाजारों का नियोजन क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक जागरुकता को दर्शाता है और क्षेत्रीय कार्यात्मक विश्लेषण में ग्रामीण आर्थिकी को और ऊँचा उठाने में स्थानीय बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजारों के नियोजन द्वारा हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योग और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को आवश्यक कार्य प्रणाली के द्वारा सुदृढ़ करना है। जिला टीकमगढ़ के बाजारों के विकास के लिये निम्नलिखित योजना प्रस्तुत की जाती है:-

1. समस्त ग्रामीण बाजार केन्द्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों को विकसित करने के लिये एक बाजार अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो बाजारों के समग्र विकास के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु योजनायें प्रस्तुत कर सके।
3. बाजारों के निर्धारित स्थल सुविधाजनक स्थान पर हो तथा शासकीय अनुदान द्वारा इन्हें सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये।
3. सप्ताह में दो बार लगने वाले बाजारों को दैनिक बाजार के रुप में विकसित किया जाना आवश्यक है, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र की जनसंख्या को समुचित सेवायें प्रदान की जा सकें।
5. नवीन बाजारों को पहूँच मार्ग द्वारा बस सेवा से जोड़ा जाना चाहिये, जिससे वे और तेजी से विकास कर सकें।

----0----

BIBLIOGRAPHY

Ackroyed, W.R. (1963): The Nutritive value of the India Food and Planning for Satisfactory Diets, I.C.M.R., New Delhi.

Alber, R, J.S. Adams and P. Gould (1971) : Spatial Organisation. The Geographer's view of the World, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.

Andrew, S.P. and P. Roy (1969): Preliminary Report on Pilot Project for Integrated Area Development Ford Foundation and Counsil of Social Development, New Delhi.

Asthana, V.K. (1975): Study of Rural Settlements in Almora and its Environs, Paper presented at I.G.U. Symposium on Rural Settlements, Banaras Hindu University, 1-6 December.

Awasthi, S.C. (1966) : Bundelkhand its economic Resources (Unpublished Report) Geological Survey of India, Annual Meeting, Madras.

Ayyer, N.P. (1969) : Crop Regions of Madhya pradesh. A study in Methodology, Geographical Review of India.

आनंद अनीता (1984) : औरतें और विकास- एवं पुनर्विचार (अनुवादक वीणा शिवपुरी) महिला विकास के आयाम कुछ समस्यायें कुछ समाधान, एच.एफ.एस.सी. (ए. एफ. ओ., 55 मैक्समूलर मार्ग, नाई दिल्ली.

Barlowe, R and V.M. Johnson (1954) : Land Problem and Policies Mc-graw Hill Companny, New York.

Berry, B.J.L. (1967): Geography of Merket Centres and Retail Distribution Printice Hall, England, London.

Banerjee, B. (1964): Changing Crop Land of West Bengal, Geographical Review of India, No.1.

Bhat, L.S. (1981): Conceptual and Analytical Frame work for Rural Development in India, Paper presented to the National Symposium on Regional Planning and Rural Development, G.B. Pant Social Science Institute Allahabad.

Bhat, L.S. and A.N. Sharma (1974): Functional Spatial Organization of Human Settlement for Integrated area study, 13th Indian Economic Conference, Ahamadabad.

Bhat, L.S. *et. al.* (1976): Micro Level Planning A Case study of Karnal Area Haryana, India.

Bhatia, S.S. (1965): Pattern of Crop Concentration and Diversification in India, Economic Geography Vol. 41, No.1.

Bhatia, S.S. (1968): A New Measures of Crop Efficiency in Uttar pradesh, Geography, Vol. 43, No.3.

Bose, A.N. (1970): Institutional Bottleneck. The Main Barrier to the the Development of Back ward

areas Indian Journal of Regional Science Vol. II, No.1.

Brecy, H.E. (1953): Towns as Rural Service Centres, Transactions 2 papers of the British Institute of Geographers.

Brush, J.E. (1955): The Hierarchy of Central Places in Southern Western Wisconsin Geographical Review 43 and 45.

Buck, J.L. (1937): Land Uitlization, China, Nonking University Press.

Burman Roy, B.K. (1972): Towards an Integrated Regional Frame-Economic and Social Cultural Dimensions of Regionalization, Census of India. Mnograph No. 7, New Delhi.

Carter, H.C. (1955): Urban Grades and Spheres of Influence in South West Wales, Scottish Geographical Magazine IXXI.

Chandra Shekhar, C.S. (1972): Balanced Regional Development and Regions, Census of India, Monograph No.7, New Delhi.

Chaturvedi, R.P. (1984): Spatio-functional Re-organisation of Central Places of Chhibraman Tahsil (Farukhabad Distt., U.P.) A case study of Micro-Level Planning.

Chaudhary, B.D.N. (1977): Natural Reources and its utilization of Resources Published in Indian Science Congress.

Christaller, W. (1966): Central Places of Southern Germany Tr. Baskin, C.W.

Christaller, W. (1966): Die Zentrale Ortiem Suddentschl and Jena G. Fisher (1933) Translated by C.W. basking Englewood Cliffs, N.J.

Clarks, P.J. and F.C. Evans (1954): Distance to Nearest Neighbour as a measure of spatial Relationship in Population Ecology, 35.

Cooley, C.H. (1974): The Theory of transporttion in Hurst MEE (Ed.) Transportation Geography.

Datye, V.S. (1983): Methodology for Identifiying Micro-Level Agricultural Planning Regions. A case study of Poona District, Maharashtra.

Dhar, N.R. (1972): Influence of Organic Matters in Green Revolution if Every mans Science, India Science Congress Association, Vol. VIII. No.3, Aug./Oct.

Dixit, R.S. (1979) : Market Centres and Their Spatial Development in the Upland of Kanpur, Unpublished Ph.D. Thesis Allahabad University.

Dixit, R.S. (1983): Role of Markets in Regional Development and their Spatial Planning in the Metropolition Region of Kanpur.

Doi, K. (1959): The Industrial Structure of Japanese Profecture proceedings of I.G.U. (1957).

Duckhan, A.N. (1967): Weather and Farm Management Decision, Weather and Agriculture Ed. James A.

Taylor Oxford pergaman.

Firedman, J. (1972): A General Theory of Polerised Development in hausen, N.M.(Ed) Regional Economic Development, The free press New York.

Gilbert, A. (1976): The Late Emergence of Spatial Planning in the Third World Hackinson, Jacmoiley, London.

Godulund, S. (1956) : The Functions and Growth of bus traffic within the sphere of Urban Influence Land Studies in Geography Series, B.No.18.

Green, F.H.W. (1948): Motor Bus Service in West England Transactions Institute of British Geographers 19.

Gupta, R.P. (1970): Gandhi Sagar Dam on Chambal River in M.P. is a case of short Duration 1965-66 and 1966-67, which were the years of short rainfall, Reservoirs also rain short of water for irrigation and power production. Agricultural price in a Backward Economy.

Haggett, P. (1966): Locational Analysis in Human Geography, Edward Arnold, London.

Hagerstand, T. (1967): Innovation of Diffusion as spatial process Tr. by Allen Pred. Chikago University Press.

Harpstead, M.I. and F.D. Hole, (1989): Soil Science Simplified Scientific Publishers, Jodhpur.

Isard, W. (1960): Methods of Regional Analysis Messachussetts, U.S.A.

Jafferson, M. (1931): The Distribution of World's Chief Fold Geographical Review, Vol. XXI.

Johnson, B.C. (1958): Crop Combination Regions of West pakistan, Pak. Geographical Review.

Johnson, O. (1925): Agricultural Regions of Europe Economic Geography I and II.

जोशी यशवन्त गोविन्द ¦1972¦ : नर्मदा बेसिन का कृषि भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल.

Kabra, K.N. (1977): Planning Processes in a District J.I.P.A., New Delhi.

Kayastha, S.L. and R.B. Singh (1981): Regional Development through Social Planning: A Micro-level study from India; Indian Journal of Regional Science Vol. XIII.

Kendal, M.G. (1939): The Geographical Distribution of Crop Productivity in England, Journal of Royal Statistical Society, Vol. 162.

Kendrew, W.G. (1953): The Climates of the Continents IV (Ed.) Oxford University, London.

Krishna, G. (1971) : Distribution and Density of Population in Upper bari Doab national Geographer, Vol. VI.

Luward, C.E. (1907): Orchha State Gazetteer.

Maithini, B.P. (1986): Spatial Analysis in Micro-level Planning Omsons publication, Gauhati.

Mathur, E.C. (1944): A Linear Distance of Farm Population in the United States, A.A.A.G., Vol. 34.

Mehto, K. (1974): Pattern of Population Growth in Bihar, Indian Geographic Studies Research Bulletion No. 2.

Mehta, J.C. (1977): Habitat, Human Settlements and Environmental Health (A System Approach) New Asian Publishers, Delhi-6.

Mishra, S.P. (1985): Integrated Area Development and Planning A Geographical Study of Kerakat Tahsil, District Jaunpur, (U.P.).

Mishra, R.P. and K.V. Sundaram (1979): Regional Development and Planning in India. A New Strategy Vikas Publication House Pvt. Ltd., New Delhi.

Mishra, R.P. and K.V. Sundarama (1980); Multi-level Planning and Integrated Rural Development in India, Heritage Publications, New Delhi.

Mishra, G.K. and Amitabh Kundu (1980): Regional Planning at the Micro-level a study for Rural Electification in Bastar and Chhatarpur, Indian Institute of Publishing Administration New Delhi.

Mishra, R.P. et. al. (1985) Rural Development Capitalist and Socialists Packs, Vol. No.I, Concept Publication Company, New Delhi.

Mukerjee, A.B. (1969) : Spacing of Rural Settlements in Andhra Pradesh, A Special Interpretation, Geographical Outlook, 6 and Spacing of Rural Settlement in Rajasthan (1970) Geographical View Point 1.

Mukerjee, B. (1966): The Community Development in India, Orient Longman, Calcutta, (W.B.).

Mumford, L. (1961): The City in History London.

Muthaiyah, B.C. and Others (1982): The Rural Dis-advantages. A Pscho-Social Study in Punjab and Madhya Pradesh Journal of Rural Development, 1(2).

Mohammad Noor (1981): Perspectives in Agriculture Geography Land use and Planning Vol. 3.

Moor, L.V. (1973): The concept of Integrated Rural Devlopment in the report of Govt. of Pakistan, International Conference on Integrated Rural Development, Lahore.

Nath, M.L. (1989) : The Upper Chambal Basin, A Geography of Rural Settlements Northern Book Centre, New Delhi.

पाण्डेय, जे.एन. (1969) : पूर्वी उत्तर प्रदेश के शस्य संयोजन प्रदेश-उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, दाऊदपुर, गोरखपुर।

Patel, M.L. (1975): Dilemma of Balanced Development in India, Bhopal.

Pokshishevskiy,V.V. (1962): Methods of Research in Economic Geography in Soviet Geography, Accomplishments and Tasks (ii).

Powell, J.W. (1969): Crop Combination for Western Victoria 1861-91, Australian Geography.

Prakash Rao, V,L.S. (Eds.) *et. al.* (1976): Regional Planning and Development, Golden Jubilee Volume, Indian Geographical Society, Dept. of Geography Madras.

Prasad, M. and H.L. Singh (1981): Rural Development and Micro-level Planning. A case study of Koilwar Block, District Bhojpur, Bihar.

Rafinllah, S.M. (1965): A New approach to functional classification of towns,The Geographer No.12.

Rao, R.V. (1978): Rural Industrilization in India. The Changing profile, Concept publishing Company New Delhi.

Rao V.K.R.V.(Eds.)(1978): Planning in Perspective, Allied Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

Reilly, W.J. (1929): Methods of the study of Retail Relationship Res: Monograph No.4, Beaurau of Business Research, University of Texas Bulletin.

Rostov, W.W., (1969): The Stages of Economic Growth University Press, Cambridge.

Roy, P. and B.R. Patel (1977): Mannual for Block Level Planning. The Mac-Million Company of India, Ltd., New Delhi.

Saxena, N.P. and R.P. Tyagi (1975): Criteria for Determining Centrality in Micro Regions. The Geographical Obsever, 2.

Scott. P. (1964): The Hierarchy of Central Places in Tasmania, The Australian Geographer, 9.

Sen, L.K. et. al. (1976): Regional Planning for a Hill Area: A case study of Pauri Tahsil in Pauri Garhmal District, NICD, Hyderabad.

Sen, L.K. et. al. (1975): Growth Centres in Raichur: An Integrated Area Development Plan for a Distict in Karnataka NICD, Hyderabad.

Sharma, A.N. (1983): Spatial Approach for District Planning: A Case Study of Karnal, Concept Publishing Company New Delhi.

Singh, J. (1979): Central Places and Spatial Organisation in a Backward Economy: Gorakhpur Region- A study in Integrated Regional Development, Uttar Bharat Bhoogol Parished, Gorakhpur.

Singh, Jasbir and S.S. Dhillon (1984): Agricultural Geography, Tata Mc Graw-Hill, New Delhi.

Singh, O.P. (1968): Functions and Functional Classes of Central Places in Uttar Pradesh, National Geographical Journal of India, 14.

Singh, O.P. (1971): Towards Determining Hierarchy of Service Centres: A Methodology for Central Place Studies, National Geographical Journal of India, 17.

Singh, O.P. (1979): Nagariva Bhoogol (Urban Geography) Varanasi.

Singh, O.P. and D.C. Pandey (1986): Development Planning: Theory and Practice, Gyanodaya Publications, National.

Singh, K.N. (1966): Spatial Pattern of Central Place Systems in Middle Ganga Valley, National Geographical Journal of India, 12.

Singh, K.N. (1959): Functions and Functional Classification of Towns in Uttar Pradesh, National Geographical Journal of India, 5.

Singh, R.L. (1975): Meaning Objectives and Scope of Settlement Geography, in R.L. Singh and K.N. Singh (Eds.), Readings in Rural Settlement Geography, National Geographical Society of India, Research Publication No.14, Varanasi.

Smalies, A.E. (1944): The Urban Hierarchy in England and Wales, Geography, 29, 41-51.

Symons, L. (1967): Agricultural Geography, London.

Taaffe, E.J. (1973): Nodel Accessibility in Geography of Transportation.

Taaffe, E.J., Mooril R.L. and P.R. Gould (1974): Transport Expension in under developed Countries, A Comparative Analysis Geographical Review 63

Thompson, I.B. (1966): Some Problem of Regional Planning in Predominantly Rural Environment. The fench experience in concise Scottish Geography, Magazine Vol.85.

Tiwari, P.C. (1988): Regional Development and Planning in India, Criterion Publications, New Delhi.

Tiwari, R.C. & S. Tripathi (1985): Integrated Rural Development and Central Place Theory Govind Vallabh Pant Social Science Institute Allahabad Paper read in National Conference, Allahabad.

तिवारी, आर.सी. एवं एस. त्रिपाठी, (1989): समन्वित ग्रामीण विकास-एक भौगोलिक दृष्टिकाण- सम्पादक प्रमोदसिंह एवं अमिताभ तिवारी, ग्रामीण विकास संकल्पना एवं उपागम नई दिल्ली।

Tripathi, K.P. 1983 : Location and Distribution of Large Scale Industries in Orissa Uttar Bharat Parishad, Gorakhpur.

त्रिपाठी सत्येन्द्र (1987): ग्रामीण विकास एवं असमानता, पोस्ट काँग्रेस सैशन-21, वर्ल्ड काँग्रेस आफ सोशियोलाजी, समाजशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी।

Tiwari, P.C., J.S. Rawat and D.C. Pandey (1983): Centrality and Ranking of Settlements: A Comparative Study of Hills and Tarai-Bhabar Region, District Nanital, U.P. Himalaya, The Deccan Geography, 21, 391-401.

Tripathy, R.N. et. al. (1980) : Block Plan in District Frame: A Development Plan for Madakastra Block in Anantapur District, Andhra Pradesh, NICD, Hyderabad.

Ullman, E.L. (1956): The Role of Transportation and the Bases for Interaction, in W.L. Thomas (Ed.), Man's Role in Changing the Face of the Earth, University of Chicago Press, Chicago.

Vining, R. (1955): A Description of Certain Spatial Aspects of an Economic System, Economic Development and Cultural Change, 3.

Van Theuneu, J.H. (1926): Location Theory in Geography Germany.

Vatsa, P.C. & S. Singh (1976): Geomorphic Influence on settlement A Quantitative Approach, Deccan Geographer, Vol. 14, No.1.

Vashishtha, V.K. (1987): Indian Economy and Rural Development, Pratikasha Publication, Jaipur (Raj.).

वर्मा, एस.सी. (1980) : लघु कृषकों के लिये ग्रामीण बाजारों का विकास: को-आपरेटिव न्यूज बुलेटिन डाइजैस्ट, अंक 3। संख्या 3, भोपाल।

Wakely, R.E. (1961): Types of Rural and Urban Community Centres, in Upstate, New York, Ithaca, Mimeograph Bulletin, No.59.

Wanmali, S. (1972a): Central Places and their Tributary Population: Some Observations, Behavioural Science and Community Development, NICD, Hyderabad, 6, 11-39.

Wanmali, S. (1972b): Zones of Influence of Central Villages in Miryalguda Taluka: A Theoretical Approach, Behavioural and Community Development, NICD, Hyderabad, 6, 1-10.

Vidyanath, V. (1985): Crop Productivity in Relation to Crop land in Andhra Pradesh A spatial Analysis Transactions Institute of Indian Geographers,Vol.7. No.1.

Wadia, D.N. (1949): Geology of India IVth edition Bundelkhand Crises Occurs in the type area of Bundelkhand.

Weaver, J.C.(1954): Crop Combination Regions in the Middle West G.R., Vol. 44.

Yeats, N. (1963): Hinter Land Determination, A distance miorionizing Approach, professional Geographer, Vol.15.

Zimmerman, E.W. (1967): World Resources and Industries.

Zipf, G.K. (1949): Human Behaviour and the Principle of Least Effort, Addision-Wesley Press,New York.

----*----

GEOGRAPHICAL JOURNALS

Deccan Geographer, Pune (MS)

ग्लोव - मध्य भारत भूगोल परिषद, इन्दौर, (म.प्र.)

Journal of Geographical Society Stackney University, Vol. VIII.

National Geographical Society of India, Varanasi,(U.P.)

The Geographer, Aligarh Muslim University, Aligarh.

Transactions, Indian Council of Geographers, Utkal University Vani Vihar, Bhubneshwar (Orissa).

उत्तर भारत भूगोल पत्रिका,गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर.

Geographical Observer-Dept. of Geog. Meerut University, Meerut, (U.P.)

Transactions- Indian Institute of Geographers, Pune.

'Geographical Society' of India, Calcutta.

----*----

UNPUBLISHED Ph. D. THESIS

Agnihorti, M.C. (1988): Integraed Area Development and Planning case study of Karwi Tahsil, Bundelkhand University, Jhansi, U.P.

अवस्थी, एन.एम. (1986): सिंचित कृषि का ग्रामीण विकास पर प्रभाव, जिला टीकमगढ़ का प्रतीकात्मक अध्ययन, अ.प्र. सिंह विश्व विद्यालय, रीवा, (म.प्र.).

Chaturvedi, K.K. (1993): Micro-level Planning a case study of Prithvipur Block, Tikamgarh District (M.P.) A.P.S. University, Rewa, (M.P.)

Dixit, R.S. (1979): Market Centres and their Spatial Development in the upland of Kanpur, Allahabad University, Allahabad.

मिश्रा अशोक कुमार (1990): समाकलित क्षेत्रीय विकास एवं योजनायें, गोहाण्ड विकास खाण्ड जिला हमीरपुर का एक प्रतीकात्मक अध्ययन-बुन्देलखाण वि.वि.,झाँसी,(उ.प्र.).

Saxena, J.P. (1967): Agricultural Geography of Bundelkhand, Dept. of Geography, Dr. H.S. Gour University, Sagar, (M.P.).

Singh, O.P. (1971): A study of Central Places in U.P., Dept. of Geography, Banaras Hindu University, Varanasi.

Tiwari, R.P. (1979): Population Geography of Bundelkhand, Vikram University, Ujjain, (M.P.)

----0----

OTHER PUBLICATIONS

जिला सांख्यिकी पुस्तिका, 1991, टीकमगढ़ (म.प्र.)

प्राथमिक जनगणना सार - जिला टीकमगढ़ 1991. (कम्प्यूटर प्रति)

ग्राम एवं नगर निदेशीनी - जिला टीकमगढ़ 1991. (कम्प्यूटर प्रति)

टीकमगढ़ दर्शन - मंगल प्रभात - ग्वालियर 1970.

जिला साख योजन - 1991, 1992, 1993, 1994 तथा 1995 टीकमगढ़ (म. प्र.).

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए. 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, टीकमगढ़ वार्षिक प्रतिवेदन।

Orchha State Gazetteer, 1907.

Govt. of India Draft Five Year Plan 1978-89. Planning Commission, New Delhi, 1978.

Annual Report on Water Resource Development 1990 Published by Department of Irrigation (Water Resource Development) Madhya Pradesh, Tikamgarh District, (M.P.)

"Elected Works of Mahatma Gandhi". Navjiwan Publishing House, Ahmedabad, Vol. VI.

Toposheets No. 54-L/11, 54-L/12, 54-L/13, 54-L/14 and 54-P/1, 54-0/5, 54-P/2, 54-0/6 Published from Survey of India Dehradun.

National Atlas Lucknow Plate No.29 and Nagapur Plate No.82.

Yojna, Publications Division, Patiyala House, New Delhi Vol. 34, No.9 May, 1990.

District Gazetteer, Tikamgarh, State Government Publication, Bhopal.

---*---